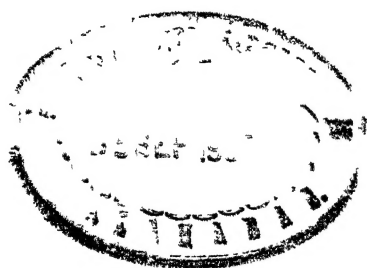


अमरीका में सहकारिता



अमरीका में सहकारिता

लेखक

जेरी वूरहिस

[संयुक्त राज्य कांग्रेस के भूतपूर्व सदस्य, अमरीकी सहकारी
लीग के कार्यकारी निदेशक]

अनुवादक

श्यामू सन्यासी



प्रकाशक

गर्ग ब्रदर्स

१ कंटेरा रोड, प्रयाग

AMRIKA MEN SAHKARITA

[Hindi Version of American Cooperatives]

BY
JERRY VOORHIS

TRANSLATED BY
Mr. Shyamu Sanyasi

Price Rs. 3 00

Copyright (c) 1961, by Jerry Voorhis

प्रथम हिन्दी संस्करण—१९६४—मूल्य ३.००

मुद्रक
प्रेम प्रेस, कटरा
प्रयाग ।

विषय-सूची

१—सघर्षमय ससार	१
२—नये युग के अनुरूप नये ढंग का व्यवसाय	१४
३—जनता का स्वास्थ्य	३०
४—घर और पड़ोस	५४
५—अमरीका के गाँवों में बिजली कैसे पहुँची	७१
६—एकाधिकारी शक्ति और स्वतंत्रता की आशा	९०
७—आधुनिक अमरीका की सबसे बड़ी कमजोरी	१०६
८—तेल के व्यापार में जनता	१३३
९—जनता का पैसा	१४६
१०—उपभोक्ताओं की संगठित क्रय-शक्ति	१९८
११—कमजोरियाँ और गलतियाँ	२२९
१२—वर्तमान और भविष्य	२५३
१३—सहकारिता और शान्ति की आशा	२७५

— — — — —

१ | संघर्षमय संसार

हम एक विचित्र प्रकार की नई दुनिया में रहते हैं। हमारे विचार उलझे हुए और हम भयभीत हैं। हम नहीं जानते कि यह मानव-जाति का विनाशकाल है अथवा मनुष्य के स्वर्णिम युग का सबेरा।

धर्म से आश्वासन और मार्ग दर्शन पाने की तीव्र, गहन और उत्कटतम आवश्यकता हम अनुभव करते हैं, लेकिन उसकी आशा भी कैसे की जाए, जब कि भगवान् की सृष्टि का ही विध्वंस करने वाली विद्याओं एवं तकनीकों में हम निरन्तर पारगत हो रहे हैं।

हमारे किशोर एक-दूसरे की हत्या करते हैं, आपसी गिराव बन्दियाँ कर शहर की सड़कों और गलियों में मारा-मारी और गुण्डागिरी करते हैं। हमें उनके इन कृत्यों पर आश्चर्य होता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि उनकी अपराधी-वृत्तियों को उकसाने की जिम्मेवारी हमी पर है—हमी ने तो अपने समाचार-पत्रों को यह अनुमति दे रखी है कि वे हिंसा की हर कारवाही को चटपटे शब्दों में, गरमागरम शीर्षक देकर भडकीले ढंग से छपा करे; हमी ने तो टेलीविजन वाली को यह अनुमति दे रखी है कि वे प्रायः ऐसे ही कार्यक्रम प्रसारित करे जिनका केन्द्रीय आय किसी-न-किसी प्रकार की हिंसा पर आधारित हो। और सबसे बुरी बात तो हमारा यह भूल जाना है कि इस तरह के अपराध करने वाली पीढ़ी भी वही है जिससे हर रोज यह कहा जाता है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, और यदि छिड़ गया तो उस सभ्यता को ही नष्ट कर देगा जिसका सम्मान करने की सीख हम उन्हें क्षीण स्वर में देते रहते हैं। पुरानी पीढ़ी के हम बुजुर्गों ने ऐसे दिन देखे हैं जब शान्ति को कोई खतरा नहीं था और अपने भावी जीवन के बारे में हम पूर्णतः निश्चिन्त और आश्वस्त थे। लेकिन हमारे बेटों और पोतों ने तो अपने सारे जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाना जब सर्वग्राही विनाशक युद्ध की सम्भान

बना सिर पर मँडराती न रही हो। एक बार मैंने अपने सबसे छोटे बेटे और जूनियर हाई स्कूल के उसके दो सहपाठियों से पूछा कि अगर तुम्हारी सिर्फ एक ही इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती हो तो बताओ, तुम क्या चाहोगे ? उन्होंने केवल क्षण-भर सोचा और तब तीनों ने एक स्वर में यही कहा कि हम आज की तिथि से दस बरस तक जीवित रहना चाहेंगे।

आज तो भला और बुरा सब गड़ड़-मड़ड़ हो गया है। मनुष्य अपने वैज्ञानिक कौशल में चन्द्रमा को जीत कर उसे आबाँद कर लेगा। लेकिन साथ ही मजे की बात यह है कि उसका सामाजिक और राजनैतिक पिछड़ापन—जिसे समाजशास्त्री सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं—पृथ्वी को, चन्द्रमा जिसका केवल उपग्रह है, विनाश से बचाने में पूर्णतः असमर्थ है।

हम तकनीकी प्रगति के व्यापक विकास के युग में जी रहे हैं; अपने-आप चलने वाले यन्त्र और परमाणु ऊर्जा तो उस विकास के केवल मुख्य उपादान हैं। अमरीकन कृषि में उत्पादकता १९४७ से १९५७ के बीच प्रतिक्रम-घटा ८७ प्रतिशत बढ़ी और उद्योग में ३४ प्रतिशत। इस अल्प समय में विद्युत्-शक्ति की हमारी खपत दुगुनी से भी अधिक हो गई। दूसरे कई देशों में भी ऐसे ही परिवर्तन हुए हैं। मानव-इतिहास में प्रथम बार पृथ्वी के सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकने लायक उत्पादन सम्भव हुआ है। लेकिन हमने वस्तुओं और सम्पत्ति का वितरण-पद्धतियों में तदनुरूप प्रगति नहीं की, इसलिए जो विक नहीं पाता ऐसे 'अतिरिक्त उत्पादन' पर हाथ मलते और सिर धुनते हैं, अपने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए कोसते हैं और मनुष्य-जाति के तृतीयांश को हर रात भूखे पेट सोने के लिए विवश देखते रहते हैं।

बीमारियों पर विजय पाने, आयु-सीमा में वृद्धि करने और अकाल एवं बाल-मृत्यु का निवारण करने की दिशा में आधुनिक विज्ञान ने चमत्कारिक कार्य किया है। लेकिन इस दीर्घायुष्य का हम क्या करें, यह हमारी समस्या में नहीं आता, यह दीर्घायु हमारे लिए 'समस्या—बुढ़ापे की समस्या' बन गई है। और जनसंख्या में इतनी तेज गति से इतनी अधिक वृद्धि की सम्भावना हमें इसलिए भय-विकसित कर देती है कि वही इतने विशाल जन-समुदाय का पेट भरने के लिए इस धरती के साधन ही कम न पड़ जाएँ।

भविष्य जो भी हो, परन्तु आज तो इस तथ्य को स्वीकार करना ही होगा कि हमारा संसार एक सम्पूर्ण दुनिया है। केवल ध्रुव प्रदेशों को छोड़ कर भौगोलिक सीमाएँ कहीं भी नहीं रह गई हैं। टेलीविजन के बावजूद 'पश्चिम' कहो रहा ही नहीं। अब वह जमाना नहीं रहा कि अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग पल्ला झाड़ कर कहीं और जा बसे। कैलिफोर्निया शीघ्र ही अमरीका का सबसे घनी आबादी वाला राज्य हो जाएगा, परन्तु अपने सामने उसे प्रशान्त महासागर के पार बहुत अधिक जनसंख्या वाले जापान और चीन पहले से ही दिखाई दे रहे हैं।

आज जहाँ यह आवश्यक हो गया है कि अपने-आपको विनाश से बचने के लिए हम मिल-जुल कर शान्तिपूर्वक रहना सीखें, वही यह परिस्थिति भी परिपक्व हो गई है कि हम जहाँ हैं वही डटे रह कर अपनी समस्याओं का सामना करें और उनका समाधान ढूँढ़ें।

हमारी समस्याओं के समाधान की चाभी अब भूगोल के नहीं, समाज-शास्त्र के हाथ में है। किसी समय हमारे देश में स्वतन्त्रता और आरम्भिक ढग के आर्थिक न्याय की गारंटी यहाँ की मुक्त भूमि हुआ करती थी, जो न तो आबाद होती थी और न जिसका कोई स्वामी होता था। अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए लोग ऐसे ही नये क्षेत्रों में जा बसते थे। लेकिन आज तो हमें अपनी स्वतन्त्रता और आर्थिक न्याय की रक्षा और सवर्द्धना सजग, विवेकपूर्ण एवं सुनियोजित सामाजिक प्रयासों से ही करनी होगी। जनता की स्वतन्त्र होने और आर्थिक अवसर एवं न्याय की स्थापना तथा उनके परिदृश्यों की दृढ़ इच्छा शक्ति को ही नये क्षेत्रों में जाकर बसने के उपायों और प्रभावी को स्थानापन्न बनाना होगा।

दुनिया के इतिहास में पहली बार लोगों को अपने वर्तमान पड़ोसियों से भाग कर नये पड़ोसियों की खोज में जाने के स्थान पर, वही जमे रहकर पुरानों के ही साथ मिल-जुल कर काम करना होगा।

यह तो मानना ही होगा कि आज दुनिया बहुत-सी बातों में एक मुहल्ले की तरह हो गई है। आज पृथ्वी के कोने-कोने में, एक साथ और तत्काल, सूचनाएँ भेजने के लिए संचार-व्यवस्था है। लोगों को उसी समय मालूम हो

जाता है कि और-और जगहों के लोगों के साथ क्या हो रहा है। और यह जानने के लिए उनका लिखा-पढ़ा होना भी आवश्यक नहीं है। आतायात भी संचार की ही भाँति द्रुत और त्वरित है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगभग उतनी ही जल्दी पहुँच सकते हैं जितनी देर में एक स्थान से दूसरे स्थान को खबरें भेजी जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना-यात्राएँ और व्यक्तियों का आदान-प्रदान आज एक सामान्य बात हो गई है। जिन लोगों को सैकड़ों वर्षों से बाहर की दुनिया के ज्ञान से वंचित रखा गया था उनमें शिक्षा और साक्षरता की माँग बहुत तेजी से बढ़ रही है। मानव इतिहास में ऐसा बवसर भी प्रथम बार ही उपस्थित हुआ है जब विश्व के सभी राष्ट्र और सभी लोग ज्ञान और सूचनाओं का परस्पर आदान-प्रदान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान समय का सबसे शुभ संकेत यह है कि आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों को अपने प्रत्यक्ष हित एवं कर्तव्य के सम्बन्ध में सहसा यह ज्ञात हुआ है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के साथ उन्हें अपनी तकनीकी जानकारी का हिस्सा बाँटाना चाहिए। औपनिवेशिक काल की सारी विचार-पद्धति ने ससार को दो भागों में बाँटा हुआ मान लिया था—एक ओर तो तकनीकी दृष्टि से उन्नत, विनिर्माता और निस्सन्देह 'शोषण करने वाले' राष्ट्र और दूसरी ओर तकनीकी दृष्टि से अविकसित, कृषि-प्रधान और शोषित राष्ट्र। 'तकनीकी' सहायता की नई सुझ ने इस समूची विचार-पद्धति को ही बदल दिया और सर्वथा नये प्रकार के उपयोगी सम्बन्ध स्थापित कर दिए।

लेकिन साथ ही इस विडम्बना को भी स्वीकार करना होगा कि हमने विश्वव्यापी त्वरित संचार-विज्ञान पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन यही नहीं जानते कि संचार किसका करे। इन संचार-साधनों के द्वारा किसी हिटलर, स्तालिन या पेरों के उग्रातिउग्र भाषण भी लाखों श्रोताओं तक पहुँच सकते हैं और शान्ति के दूतों की मधुर वाणी या कोई उपयोगी तथ्य या सांस्कृतिक अनुभूतियाँ भी। वास्तव में आज तो स्थिति इन नए संचार-साधनों के समुचित उपयोग के विरुद्ध ही जाती है। दुनिया के लगभग तिहाई हिस्से की जनता को वहाँ की तानाशाही सरकारों ने ऐसे तथ्यों अथवा विचारों को पढ़ने या सुनने के मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया जो वहाँ की सर-

कारों द्वारा मान्य नहीं। तथा कथित 'स्वतन्त्र दुनिया' में भी 'जन-अभिप्रेरण,' में प्रवीण चतुर व्यक्तियों को प्रति वर्ष अरबों डालर उनका स्वयं प्रचारित उस योग्यता के लिए दिये जाते हैं जिसके बल पर वे लोगों से जो बात मनवाना चाहें, मनवा सकते हैं, और उन वस्तुओं को खरीदने के लिए लोगों को तैयार कर सकते हैं जिनकी ओर खरीदारों को अभिप्रेरित करने के लिए उत्पादकों की ओर से उनको पारिश्रमिक आदि दिया जाता है। हमारे पास संस्कृति, ज्ञान, सौन्दर्य और पारस्परिक समझ उत्पन्न करने के विश्वव्यापी प्रचार के साधन मौजूद हैं। लेकिन हमने शायद ही कभी सोचा होगा कि हमें इन कार्यों को करना भी चाहिए अथवा नहीं। अभी तो हमें यही सीखना है कि इन साधनों का समुचित प्रयोग कैसे किया जाए और खतरनाक, अनुचित या अति सामान्य कोटि के कामों में इनके प्रयोग को कैसे रोका जाए।

हमारे विश्वयुद्ध और उसके बाद की हलचलों के कारण तथा नए विश्वव्यापी संचार एवं सम्बन्धों के फलस्वरूप पन्द्रह अरब लोगों की मनःस्थिति तथा दृष्टिकोण में जबर्दस्त परिवर्तन हुआ है। ये विश्व के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोग हैं। सदियों से ये अदेय ऋणों के बोझ-तले दबे, या तो बचपन में ही या फिर अकाल मृत्यु का शिकार होते और घिसट-घिसट कर जिन्दगी के दिन काटते रहे हैं; इस दुरवस्था को ही ये बेचारे अपना भाग्य मान बैठे थे।

लेकिन आज वे इस तरह के दुर्दशा ग्रस्त जीवन को अपना भाग्य नहीं मानते। उन्होंने दूसरे देशवासियों के अपने से बिल्कुल भिन्न प्रकार के जीवन के बारे में सुना है और थोड़ा-बहुत उसे देख भी लिया है। और उन्हें विश्वास हो गया है कि स्वयं उनका जीवन भी कुछ-कुछ तो वैसा ही हो सकता है। हजारों वर्षों में पहली बार उनके मन में यह विश्वास जागा है कि वर्तमान से भविष्य भिन्न हो सकता है; और अपने उस भविष्य को सँवारने के लिए वे कृत सकल्प भी हैं। अपनी इस 'नई आशाओं की क्रान्ति' को जैसे भी हो साकार रूप देने का वे निश्चय किये बैठे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ प्रगति भी की है। उनमें से करोड़ों ने राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त कर ली है। कुछ ने अपनी आय और रहन-सहन के स्तर में थोड़ी-बहुत उन्नति भी

की है। संयुक्त राष्ट्र संच, बांदूंग, तथा अन्य स्थानों में उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना जाने लगा है।

नई आशाओं की क्रान्ति के इस अभियान के पीछे सबल प्रेरणा इसलिए भी है कि उन लोगों को यह बात मालूम हो गई है कि हमारी दुःखदायी भूख के साथ-साथ कुछ देशों में कथित 'अधिशेष' भरे पड़े हैं। इस दुःखद तथ्य को तो स्वीकार करना ही होगा कि हमारे युग की तकनीकी क्रान्ति ने तकनीकी सहायता कार्यक्रमों, विदेशी मदद और तत्सम्बन्धी सभी प्रयत्नों के बावजूद धनी और निर्धनों के बीच की खाई को पाटने के स्थान पर चौड़ा ही किया है। दूसरे विश्व-युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों तथा जापान में उत्पादन जनसंख्या की वृद्धि से काफी आगे निकल गया है। किन्तु दूसरी ओर, उदाहरणार्थ, भारत में, जनसंख्या प्रति वर्ष २ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती जाती है और उसकी तुलना में खाद्योत्पादन केवल ३ प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाया जा सका है। बहुत-से देशों में तो इससे भी कम प्रगति हुई है। एशिया, अफ्रीका और विश्व के कुछ अन्य देशों के १५ अरब लोगों की प्रति व्यक्ति आय से अमरीका की प्रति व्यक्ति आय तीस गुना से भी अधिक है।

इस तरह की स्थिति अधिक दिनों तक सहन नहीं की जा सकती-विश्व-व्यापी संचार-साधनों वाली दुनिया में तो कदापि नहीं। यह ज्यादा दिन नहीं चल सकता कि आधी मानव-जाति तो अमीर हो और आधी गरीब; दुनिया के आधे लोग 'अधिशेष' की शिकायत करते रहे और आधे उसके लिए तरसते रहें। नई आशाओं की क्रान्ति, जैसे भी होगा, अपना काम करके रहेगी।

मानव-जाति के लम्बे इतिहास में इस पृथ्वी के अधिकांश लोग निरक्षर रहे और अपने गाँव से परे के जीवन, घटनाओं एवं परिस्थितियों से प्रायः अज्ञ भी। जिसे जनता की सामान्य शिक्षा कहते हैं उस तरह की चीज तो दूसरे विश्व-युद्ध के समय तक पश्चिम के कुछ गिने-चुने देशों में ही और सो भी केवल आंशिक रूप में दिखाई देती है। लेकिन आज यह स्थिति बदल रही है 'नई आशाओं की क्रान्ति' का एक पहलू सारी दुनिया के लोगों में शिक्षा, साक्षरता और जानकारी की निरन्तर बढ़ती हुई माँग भी है। यूनेस्को ने सब देशों में साक्षरता-प्रसार और शैक्षिक सुविधाओं के लिए विश्व-व्यापी

कार्यक्रम शुरू किया है। यह तकनीकी सहायता को सक्रिय रूप देने वाले विचार का ही एक अंग है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। अब एक नई किस्म का प्रचारक (मिशनरी) पिछड़े हुए देशों में इसलिए जाता है कि वहाँ लोगों को साक्षर बनाने में सहायता करे। लेकिन यह सब होने के पहले से ही लाखों की संख्या में लोग रेडियो से लाभ उठा रहे हैं। विश्व के दूरस्थ प्रदेशों में यदि शिक्षा नहीं तो कम-से-कम जानकारी तो अवश्य ही पहुँच रही है।

अतएव यह कहा जा सकता है कि जिन लोगों के लिए भूतकाल में अपने यहाँ स्वतन्त्र और लोक तन्त्रात्मक राजनैतिक संस्थाओं का निर्माण करना असम्भव था, वहाँ धीरे-धीरे और कठिन परिश्रम के द्वारा अब इस प्रकार की संस्थाओं को चलाने की नींव रखी जा रही है।

लेकिन इसके साथ ही दुनिया में इस समय जनतन्त्रात्मक (जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित) राज्यतन्त्र का अन्त कर उसके स्थान पर अधिनायक-तन्त्र (तानाशाही) की स्थापना करने के लिए सुगठित शक्तियों का प्रबल अभियान भी चल रहा है। एकसत्तात्मक राज्य की संकल्पना हमारे ही समय में आविर्भूत हुई और आज करोड़ों की आस्था और विश्वासों का मुख्य सैद्धान्तिक आधार बनी हुई है। जो राष्ट्र अभी भी स्वतन्त्र राज्य-तन्त्र को अपनाये हुए हैं उनमें भी राज्य के ऐसे स्वरूप की माँग निरन्तर बढ़ती जा रही है जो स्वतन्त्रता के स्थूल रूप को चाहे हानि न पहुँचाता हो स्वतन्त्रता की भावना के लिए तो निस्सन्देह हानिकारक है।

लगभग सभी देशों में शासन-सत्ताएँ अधिक बड़ी और शक्तिशाली होती जा रही हैं; जहाँ इसके लिए कोई और कारण नहीं वहाँ एकसत्तात्मक राज्यों की निर्विरोध केन्द्रीय शक्ति के प्रति सन्तुलन के ही लिए ऐसा हो रहा है। अपने देश (अमरीका) की तरह के देशों में आर्थिक शक्ति अधिकाधिक केन्द्रित होती जा रही है, यहाँ तक कि कुछ बहुत बड़े व्यवसाय-निगम हमारी अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्र पर पूर्ण रूपेण छाते जा रहे हैं और इस दृष्टि से उनका रूप बहुत-कुछ साम्यवादी देशों के सरकारी उद्योगों के समान होता जा रहा है। प्रेस, रेडियो और टेलिविजन पर मुट्ठी भर लोगों का नियन्त्रण

बढ़ता जा रहा है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि हाइड्रोजन बम के वास्तविक आतंक के कारण सामान्य व्यक्ति इस विश्वास को खोता जा रहा है कि वह किसी महत्वपूर्ण विषय में ऐसे निर्णय ले सकता है जो उसके भाग्य के लिए नियामक हों अथवा समकालीन इतिहास को प्रभावित कर सके।

पचास साल पहले अमरीका में बहुत ही कम लोगो ने लाओस, वियतनाम या कोरिया का नाम सुना होगा। और इस बात की चिन्ता तो और भी कम लोगो को थी कि इन 'विचित्र नामों वाले दूरस्थ प्रदेशों' में क्या हो रहा है। आज हम सीरिया और लेबनान यहाँ तक कि जार्डन और यमन तक की घटनाओं के बारे में बहुत अधिक चिन्तित हैं। हम कोरिया में युद्ध कर चुके हैं और बहुत-कुछ अशो में वियतनाम में भी। इसका सीधा-सादा कारण यही है कि हम चाहें या न चाहें, आज सारा विश्व एक है और हमारे देश का और हर महत्वपूर्ण देश का हित और चिन्ता सारे विश्व से सम्बद्ध है। हमारी इस सभ्यता के जीवित रहते विश्व के किसी भी स्थान में अब कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घट सकती जिसकी जानकारी विश्व के अन्य सभी स्थानों के लोगों को तुरन्त न मिल जाए और जो उनके जीवन और भाग्य को प्रभावित न करे।

इसके बाद यह कहना विरोधाभास ही होगा कि आज विश्व जितना बँटा हुआ है उतना पहले कभी नहीं था। लेकिन ये गहरे मतभेद भी इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि आज की दुनिया के सारे देश अन्योन्याश्रित हैं। आज से पचास साल पहले अमरीका और रूस के बीच आज की ही तरह सशस्त्र प्रतिद्वन्द्विता और तीव्र विरोध हो सकते थे, और ससार के शेष देशों को उनके तनावपूर्ण सम्बन्धों के बारे में कोई खास चिन्ता भी न होती। क्योंकि पचास साल पहले यदि अमरीका और रूस आपस में युद्ध करते तो उससे मानव-जाति का विनाश भी न होता, लेकिन आज तो सर्वनाश के सन्देह की पूरी-पूरी सम्भावना है।

आज विश्व के समस्त देश सारी मानव-जाति के लिए अच्छे जीवन की खोज में अन्योन्याश्रित सम्बन्धों से बँधे हुए और एक हैं। विश्व-विनाशक मृत्यु के भय और आशंका में भी वे उसी तरह एक-दूसरे से बँधे और एक हैं। जो

विज्ञान समस्त मानव-जाति की भलाई के लिए समुद्र के पानी से अपरिमित शक्ति उत्पन्न करने का वचन देता है उसी विज्ञान ने ऐसे शस्त्रास्त्रों का निर्माण किया है जो देशों की सामूहिक हत्याओं का कारण भी बन सकते हैं।

आज तो हालत यह हो गई है कि दुनिया के सभी स्त्री पुरुष और बच्चे हर रात इस आशका को मन में लेकर सोते हैं कि शक्तिशाली शस्त्रों से सजग दो देशों में कहीं युद्ध न छिड़ जाए। इसका कारण व्यक्ति जानता है और वह यह कि अमरीका और रूस के पास ऐसे आयुध हैं जिन्हें यदि पूरे पैमाने के युद्ध में प्रयुक्त किया गया तो वे पृथ्वी के समस्त जीव धारियों का अन्त कर सकते हैं। ऐसी अथवा इससे मिलती-जुलती सम्भावना आज से पहले कभी भी नहीं थी।

विगत आधी शताब्दी में, विशेष रूप से पिछले पच्चीस वर्षों में, तकनीक, भौतिक विज्ञान, जीवन के सभी विशुद्ध भौतिक क्षेत्रों और युद्धास्त्रों के निर्माण में जो प्रगति हुई है वह सर्वथा चमत्कारिक ही है। लेकिन इसकी तुलना में मानव-सम्बन्धों, सामाजिक विज्ञान, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सस्थाओं के विकास और शान्ति के निर्माण में जो प्रगति हुई है वह खेदजनक रूप से मन्द रही है। समाजशास्त्री इसे 'सांस्कृतिक पिछड़ापन' कहते हैं; और यह सांस्कृतिक पिछड़ापन ही तो हमारी मुख्य समस्या है।

बड़े-बड़े नगर, बड़े-बड़े निगम, बड़ी-बड़ी व्यापार शृंखलाएँ, बड़े-बड़े संगठन, बड़ी-बड़ी सरकारें और बड़े-बड़े बम हम पर हावी हैं और हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। हम भयभीत ही नहीं, स्तम्भित और जड़ भी हो गए हैं। हम में से अधिकांश नितान्त हताश होकर यह कहते हैं कि "मैं इस सम्बन्ध में कर ही क्या सकता हूँ।" कितने खेद की बात है कि हम विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के पारस्परिक दौरों पर अपनी आशा लगाये रहते हैं। और उससे भी अधिक खेद की बात तो यह है कि हम उनके साथ सवाददाताओं और फोटोग्राफरों की बड़ी-बड़ी पलटने भेजते हैं। क्योंकि शान्ति की हमारी समस्त आशाएँ इन 'बड़े आदमियों' के हिसाब-किताब से बोले गए शब्दों अथवा वाक्यों, उनकी नपी-तुली मुस्कराहटों, यहाँ तक कि उनके श्वासोच्छ्वासों पर टिकी और अटकी रहती हैं। राष्ट्राध्यक्षों के पारस्परिक वार्तालापों के खोखले प्रति-

वेदनों में हम अपने लिए आश्वासन खोजा करते हैं और उन्हींसे अपनी मानसिक जड़ता को मिटाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इसीलिए उनके द्वारा मिलन की आशा लगाये रहते हैं। हम में से अधिकांश को कभी यह ख्याल ही नहीं आता कि विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष मानव-जाति की रक्षा के नये और महत्वपूर्ण कार्य केवल तभी आरम्भ करेंगे जब लाखों क्रुद्ध व्यक्ति एक स्वर में उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य कर देंगे।

हम लोग, यानी विश्व की जनता, अपने उत्तरदायित्व से परागमुख हो रहे हैं और साथ ही अपनी स्वतन्त्रता से भी हाथ धोते जा रहे हैं।

इसका एक कारण तो यह है कि हमारी नैतिक दृष्टि धुंधली पड़ गई है। हमने वैभव-लिप्सा और मुनाफे के लिए अन्धी दौड़ को उन धार्मिक शिक्षाओं के चौखटे में बिठाने का प्रयत्न किया है जो हमसे पश्चात्ताप, विनम्रता, त्याग और पड़ोसी के प्रति सौहार्दपूर्ण आचरण की अपेक्षा रखती हैं। अपने व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय जीवन में हमें कोई प्रेरणा अथवा शाश्वत अनुभूति इसलिए प्राप्त नहीं होती कि आधुनिक अमरीकी भौतिकवाद की 'प्रचुरता-पूजा' का ईसाई धर्म अथवा किसी भी प्राणवान् धर्म का विशिष्टताओं (अच्छाइयों) से मौलिक विरोध है।

युद्धोत्तर वर्षों में नैतिक दृष्टि और आत्म निर्देश की भावना उत्तरोत्तर मन्द पड़ती गई है।

शिकागो विश्वविद्यालय के एपिस्कोपल चर्च के माननीय पादरी विलियम एच० बार ने दिसम्बर १९५७ में 'एडवांस' पत्रिका में लिखते हुए निम्न विचार प्रकट किये हैं :

“कारखानों और मैन स्ट्रीट में ही नहीं, अपनी शिक्षा संस्थाओं में भी हम 'श्रौद्योगिकी' नामक एक झूठे भगवान की स्थापना कर रहे हैं। 'मुझे विश्वास है कि श्रौद्योगिकी हमारी रक्षा करेगी'—आज के विश्व की सबसे व्यापक आस्था का यही मूलमन्त्र हो रहा है और इस तथ्य को अस्वीकार करना मूर्खता ही होगी।

“रस्किन ने 'वेनिस-निवासियों' की कला के द्रुतहास के सम्बन्ध में बड़ी सुन्दर बात कही है। उसने कहा है कि उनके पास असमान्य कौशल और आश्चर्यजनक तकनीक था। लेकिन ये दोनों ही निःप्रयोजन थे। महान् प्रतिभा के धनी होने के बावजूद वेनिस-निवासियों के पास देने की कोई सन्देश नहीं था।

“इससे हम शिक्षा ले सकते हैं। हम अपनी सभ्यता को बचाने के लिए कृत संकल्प हैं। हमें टैकनी शिपनों एवं शिल्पियों की आवश्यकता है। लेकिन यदि हमने थोड़े-से पियानो-

वादक कुछ गायक, थोड़े-से कार्य, कुछ धर्म-मर्मज्ञ और इतिहासकार आदि पैदा नहीं किये तो जिस सभ्यता की रक्षा की हम इतनी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं वह रक्षा के इन प्रयत्नों के आरम्भ होने से पहले ही मर जायगी।

“किसी भी विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में उन सभ्यताओं पर जो बड़े-बड़े निर्माण कार्यक्रमों, विशाल वैभव और निरर्थक युद्धों के शोर-शरावे में चुपचाप समाप्त हो गई, हजारों पुस्तकें मिल जाएँगी।

“यदि कार्यनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष न हो तो इतिहास के ये सारे ग्रन्थ धूल की मोटी तहों के नीचे दबे पड़े रह जायेंगे, क्योंकि न तो कोई उन्हें पढ़ने वाला है और न कोई उन सभ्यताओं की चिन्ता करने वाला।”

दूसरे विश्व-युद्ध की समाप्ति के कुछ समय बाद ही अमरीका के एक बड़े शहर के समाचार पत्र ने परमाणु बम पर सम्पादकीय लेख लिखते हुए निम्न बात कही थी :

“हमारे सामने आज यह नैतिक प्रश्न ज्वलन्त रूप में उठ खड़ा हुआ है कि हमारे राष्ट्र को या किसी भी राष्ट्र को पृथ्वी पर से समस्त जीवधारियों का अन्त करने वाली संहारक शक्ति को अपने हाथ में रखने का अधिकार है ?”

सम्पादकीय में आगे चल कर विश्व-शान्ति और विश्व-व्यापी निरस्त्रीकरण को अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता मान कर उनके लिए अथक अभियान करने की अपील की गई थी।

कुछ ही समय बाद, १९५२ में, उसी समाचार पत्र ने हाइड्रोजन बम पर सम्पादकीय लिखा और उसमें कहा :

“अत्यधिक भयानक होते हुए भी इस नये शस्त्र का विकास और निर्माण अवश्यम्भावी हो गया था। यह तो हमारे ही अपने हित की बात है कि हमी ने सबसे पहले इस हथियार को बनाया और इसका पहला विस्फोट भी हमी ने किया।”

‘नैतिक प्रश्न’ का यहाँ कोई उल्लेख नहीं किया गया। सम्पादकीय को केवल यह कह कर समाप्त कर दिया गया कि ‘कुशलतापूर्ण वार्ताओं’ के द्वारा शान्ति बनाये रखने में ही मानव-जाति के भाग की आशा निहित है। १९५२ के आते-आते हम पृथ्वी पर से प्राणि-मात्र का अन्त करने वाली घातक शक्ति को अपने पास रखने के इतने अभ्यस्त हो गए कि मानव-जाति के बृहदांश के नाश के लिए रूस के साथ हम भी उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं, इस सम्भावना की हमें कोई खास चिन्ता नहीं रह गई।

१९५५ में इसी समाचारपत्र ने बड़े साहस के साथ ‘परमाणु-विकीरण का मानव-जाति पर सम्भावित प्रभाव’ शीर्षक एक लेखमाला प्रकाशित की, जिसमें

बहुत खरो-खरी भयोत्पादक बाते वही गईं। उन लेखों में यह चेतावनी दी गई कि यदि किसी चमत्कार से अधिकांश मानव-जाति बम की आग में झुलसने से बच भी जाए तो आनेवाली अनेक पीढ़ियों में दैत्याकृति मानवों की सख्या उत्तरोत्तर अधिक और सामान्य मानवों की सख्या उत्तरोत्तर कम होती जाएगी। अन्त में उस लेखमाला पर यह सम्पादकीय टिप्पणी लिखी गई थी :

“विकीरण के खतरों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखते हुए हमें परमाणु शस्त्रों के अपने कार्यक्रम में वास्तविकता को भुलाकर काट-छाँट करने की बात कदापि नहीं करनी चाहिए। अमरीका और स्वतन्त्र विश्व की शान्ति-सुरक्षा के लिए हमें परम्परागत सावधानी के साथ परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के परीक्षण जारी रखने चाहिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गोर्डन डीन के शब्दों में, ‘हमें अधिक प्रक्षेपीय, अधिक बड़े और अधिक अच्छे शस्त्रों का निर्माण करने के लिए निरन्तर परीक्षण करते रहना चाहिए।’”

इस तरह न केवल नैतिक प्रश्न को भुला दिया गया, बल्कि हमारी पीढ़ी द्वारा मानव-जाति के लिए उत्पन्न किये गए अत्यन्त भयानक और सर्वग्राही सकट को समाप्त करने के प्रयत्न भी छोड़ दिये गए। यह समाचार पत्र अथवा परमाणुओं की उर्जा आयोग केवल यही सुझाव दे पाये कि ‘हमें अधिक प्रक्षेपीय, अधिक बड़े और (भगवान् बचाएँ) अधिक अच्छे शस्त्रों का निर्माण करना चाहिए।’ अधिक अच्छे से यहाँ तात्पर्य उस हाइड्रोजन बम से ज्यादा अच्छे बम से है, जिसके एक ही विस्फोट में ३० से ५० लाख आदमियों का अन्त कर दिया था और जिसने प्रयोगात्मक विस्फोट के स्थान से दो सौ मील की दूरी पर एक जापानी मछुए की जान ले ली थी।

१९५५ के बाद के वर्षों में कुछ अच्छे परिवर्तन हुए। इक्का-दुक्का लोगो को अमरीकावासियों की हास्यास्पद मन-स्थिति का मजाक उड़ाते हुए सुना जाने लगा। माननीय पादरी बार के लेख की तरह के और भी कई लेख लिखे गए। कभी-कभी लोगों ने यहाँ तक कहा, “अपने बच्चों को जीवित रहने का अवसर देने की शिष्टता ही हमारी पीढ़ी का मुख्य काम होना चाहिए।” और अन्त में उन्होंने पूछा : “हम इसके लिए क्या कर रहे हैं ?”

हम यह तो मानने ही लगे हैं कि हम पथ-भ्रष्ट हो गए हैं, हमारा नैतिक-निर्देशन नष्ट हो चुका है और अपने धर्म के वास्तविक सन्देश से, मूल प्रयोजन से, हमारा सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है।

में ऐसा सोचता हूँ या सम्भवतः यह मेरी मूर्खता-भिलाषा ही है कि हम इस अपरिहार्य सत्य को भी गम्भीरता से लेने लगे हैं कि बीसवीं शताब्दी के मध्य की

यह पीढ़ी इन दो प्रश्नों का अवश्य निर्णय करेगी कि क्या मानव-जाति जीवित रहेगी या समाप्त हो जाएगी और यदि जीवित रही तो क्या वह स्वतन्त्र भी रहेगी ?

और हम यह भी अनुभव करने लगे हैं कि यदि अपने वर्तमान मार्ग पर ही चलते रहे तो हम निश्चय ही इन दोनों प्रश्नों के गलत निर्णय पर पहुँचेंगे।

बीसवीं सदी के छठे दशक के अन्तिम वर्षों में हम इतना तो समझने लगे हैं कि अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए कुछ बातें बहुत आवश्यक और अनिवार्य हैं।

यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में नैतिक प्रयोजन की भावना, आश्रय चाहें तो उसे धार्मिक प्रयोजन की भावना भी कह सकते हैं, पुनः स्थापित करें।

यह आवश्यक है कि अपने भविष्य के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय करने की लोगों की इच्छा को पुनः जाग्रत किया जाए।

यह आवश्यक है कि ऐसे उपायों की खोज की जाए जिससे बड़ों की दुनिया में छोटे लोग आत्मसम्मान और महत्त्व बनाये रख सकें।

यह आवश्यक है कि ऐसी सस्थाएँ स्थापित की जाएँ जो इस विश्व में शान्ति की स्थापना उसका कार्यान्वयन और अनुरक्षण कर सकें।

ये आवश्यक कार्य, जो स्वतन्त्र मानव की अस्तित्व रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक हैं, ऊपर के स्तर के व्यक्तियों से शुरू होकर पूरे नहीं किये जा सकते। नेताओं के उग्र भाषण स्वतन्त्रता की इच्छा को पुनर्जाग्रत नहीं कर सकते। आधुनिक ढंग का निरंकुश शासन, चाहे वह साम्यवादी हो अथवा पूँजीवादी, व्यक्ति के आत्मसम्मान को अथवा इस भावना को कि औसत व्यक्ति का भी कुछ महत्त्व है, पुनः स्थापित नहीं कर सकता। इसी प्रकार केवल सन्धियों, समझौतों और अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं से शान्ति कायम नहीं की जा सकती।

सभी मानवी प्रगतियों की तरह, हमारे युग को जिस प्रगति की आवश्यकता है उसकी जड़ें भी विश्व-भर के हजारों समुदायों और लाखों समूहों में रहनेवाले सामान्य लोगों के जीवन और रहन-सहन में निहित होनी चाहिए। इसलिए ऐसे उपायों की खोज करना आवश्यक है जिनसे लोग निर्णय लेने का, आत्मगौरव, स्वाभिमान, सहयोगभावना और अपने साथियों के साथ सक्रिय, शान्तिपूर्ण सम्बन्धों का सुखद अनुभव प्राप्त कर सकें।

इस पुस्तक में इसी प्रकार के उपायों की चर्चा की गई है।

२ | नये युग के अनुरूप नये ढंग का व्यवसाय

सभ्य समाज की स्थापना के लिए पहला प्रयत्न कब और कैसे आरम्भ हुआ इसका हमें कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। सम्भवतः यह निम्नलिखित ढंग से हुआ हो:

सर्दी का मौसम था और उस दिन कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। एक पेड़ पर बिजली गिरी और वह जल उठा। विभिन्न दिशाओं से कोई एक दर्जन डरे हुए आदिमानव उस आग के पास गर्मी पाने के लिए चोरी-चोरी आये। उन सभी के दिल में एक-दूसरे का डर समाया हुआ था। वास्तव में वे एक-दूसरे से इतना अधिक डरे हुए थे कि उस कीमती आग को यो ही जलकर खत्म हो जाने देते और पुनः ठण्ड तथा अँधेरे का शिकार हो जाते, क्योंकि अभी उन्हें आग जलाना आता नहीं था।

तभी एक महान् घटना घटी। आग के चारों तरफ खड़े उन आदिमानवों में से किसी एक ने बाकी लोगों के सामने एक बहुत ही साधारण सुझाव पेश किया, जिसमें सभ्यता के निर्माण की प्रक्रिया के सारे बुनियादी तत्त्व समाये हुए थे। प्रस्ताव यह था कि वे एक-दूसरे पर आक्रमण करने के बजाए आग को सबके हित में बनाये रखने के लिए मिल-जुलकर काम करने को राजी हो जाएँ।

किसी समय कहीं-न-कहीं इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, पारस्परिक सहायता और सहकारिता का जन्म हुआ और मानव-जाति सभ्यता की ओर अग्रसर हुई।

उस दिन से लेकर आज तक मनुष्यों के बीच स्वेच्छापूर्ण पारस्परिक सहायता की प्रथा ही सभ्यता को विकसित करनेवाली महान् शक्ति, मानव-जाति की दशा सुधारने वाला महान् प्रभावशाली माध्यम और समस्याओं को सुलझाने का प्रमुख साधन रही है।

दुनिया के इतिहास में पहले-पहल खेती करने वालों ने यदि पारस्परिक सहायता को न अपनाया होता तो खेती का शुरू हो पाना असम्भव ही था। उस समय का कोई भी अकेला एक किसान खानाबदोश कबीलों की लूट-मार से अपनी खेती

को रक्षा नहीं कर सकता था। लेकिन यदि घाटी के सभी किसान साथ मिलकर अपने बोये हुए धरती के ऊबड़-खाबड़ टुकड़ों की रक्षा के लिए तैयार हो जाते तभी वे अपनी फसल को काटने का अवसर पाते थे।

यदि पारस्परिक निर्भरता न होती तो न अमेरीका को बसाया जा सकता था और न किसी नये क्षेत्र को ही। शुरू शुरू के वे अक्खड़ वाशिन्डे एक-दूसरे की सहायता के बल-बूते ही वहाँ जाकर बसे और उन नये क्षेत्रों को आबाद किया। अपने अनगढ़, भोंडे मकानों को बनाने के लिए उन्हें पारस्परिक सहायता की आवश्यकता होती थी और अपने खलिहान तथा अन्न-भंडार बनाने के लिए भी। पारस्परिक सहायता के बिना न तो वे दुर्दान्त दस्युओं के बर्बर आक्रमणों को परास्त कर जोविज बच पाते, न हेारी-त्रोमारी का सामना करके और न कठोर शीत से अपनी रक्षा कर के ही।

रोम के पतन के बाद के युगों में हिमाओर उत्पातों का जो दौर चला उसमें कुछ लोगों ने यदि पारस्परिक सहायता के आधार पर मठा में रहकर ज्ञान तथा सस्कृति के उद्धार और संरक्षण का कार्य करने का निश्चय न किया होता तो प्राचीन काल का समस्त ज्ञान-विज्ञान एवं सांस्कृतिक परम्पराएँ सम्भवतः नष्ट हो जाती।

यूरोप की वर्तमान जातियों और राष्ट्रों की जड़े वहाँ के मध्यकालीन नगरों में समायी हुई हैं। और उन नगरों का विकास हुआ है उस समय की लगातार होनी रहनेवाली छोटी-छोटी लड़ाइयों के अशान्त और विक्षुब्ध वातावरण में। शान्तिपूर्वक रहने का अवसर पाने के लिए उस समय के दस्तकारी और व्यापारियों की सुरक्षा के निमित्त पारस्परिक सहयोग की एक खास पद्धति को अपनाता पड़ता था। कालान्तर में इस पद्धति ने पर कोटे वाले नगरों में पास-पास रहने का रूप ग्रहण कर लिया। और अन्त में इन्हीं नगरों के निवासियों ने ऐसी केन्द्रीय सरकारों की स्थापना पर जोर दिया जो नागरिक शान्ति को बनाये रख सके ; और वे इसमें सफल भी हुए।

इस तरह के अगणित उदाहरण दिये जा सकते हैं, जो प्रायः अनावश्यक ही हैं।

आतंक, दमन, भूख और भय से मानव-जाति की रक्षा के साधन के रूप में पारस्परिक सहायता और सहकारिता की बंशावली काफी लम्बी और उजागर है। हमारे युग के श्रेष्ठतम समाजशास्त्रियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है।

श्री एशले माटेंगू ने अपनी पुस्तक 'आन विहग ह्यूमन' में कहा है :

"मनुष्य का जन्म प्रतिद्वन्द्विता अथवा पारस्परिक संघर्ष के लिए नहीं सहकारिता के लिए हुआ है। आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व नाज़रेथ के एक ईसा ने यही खोज की थी। आधुनिक विज्ञान इसका समर्थन करता है क्योंकि उसकी बुनियादी खोज भी यही है। संक्षेप में कहें तो यह प्रेम का सिद्धान्त है— मानवता का सिद्धान्त, एक ही विश्व और वसु-धैव कुटुम्बकम् का सिद्धान्त है जो समस्त मानव-जाति को आवद्ध किये है।

हमारे युग के समाजशास्त्री माटेंगू के विचारों का अनुसरण करे यह सर्वथा उचित ही है; क्योंकि आज मानव-जाति के सामने केवल दो ही रास्ते हैं—विश्व-व्यापी सहकारिता अथवा विश्व व्यापी विनाश।

सम्भव है कि मनुष्य-जाति ऐन वक्त पर अपने सही रूप की पहचान ले; कम-से-कम आशा तो हमें यही करनी चाहिए।

और वह 'ऐनवक्त' अधिक दूर भी नहीं है।

तब तक परम्परा से प्राप्त दाय सर्वथा रक्षणीय है; और इस दाय का सबसे मूल्यवान अंश है परस्पर अभीप्सित लक्ष्यों के लिए जन-समूहों की स्वेच्छा से संयुक्त होकर काम करने की क्षमता।

पारस्परिक सहायता-सहकारिता ने भी अन्य सभी मानवी आवेगोंकी भाँति अनेक प्रकार के संस्थागत रूप अपना लिये हैं। इसका पहला संस्थागत रूप हमें परिवार में दिखाई पड़ता है, उसके बाद वंश में, फिर कबीले में, तब नगर, राज्य और फिर राष्ट्र में। मानव-इतिहास में जितने भी 'शान्ति दल' हुए वे सब शान्ति को बनाये रखने और स्वयं अपने अस्तित्व के लिए भी स्वैच्छिक पारस्परिक सहायता पर ही मूलतः निर्भर करते रहे। कोई भी पुलिस दल कितना ही बड़ा क्यों न हो अकेला कभी इस काम को नहीं कर सकता।

हमारे युग के सहकारी व्यवसाय वास्तव में मानव-जाति के दैनिक आर्थिक क्रिया-कलापों में पारस्परिक सहायता की भावना एवं सिद्धान्त का संस्थागत निरूपण ही है।

आगे चल कर सहकारी व्यावसायिक उद्यमों के जिन नये और अद्यतन रूपों की चर्चा की जाएगी उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वे हमारे युग की समस्त व्याधियों की अचूक चिकित्सा है।

हमारे पूर्वजों ने अपने 'रक्त, स्वेद और अश्रुओं' से स्वतन्त्रता एवं वैधानिक जनतन्त्र की जिन सस्थाओं का विकास किया उन्हें भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ जाने के घनघोर मघर्ष में आज हम जुटे हुए हैं।

हम सफल होंगे ही इसका कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

कम-से-कम तीन बातें पूरी हों तभी हम सफलता पा सकते हैं :

पहली तो यह कि लोगों के अपने भाग्य-निर्णय के अधिकार को सुरक्षित किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि विधिपूर्वक निर्मित और अपने विधानों के द्वारा मनुष्य के मौलिक अधिकारों की गारंटी करने वाली सरकारें पनपनी चाहिए।

दूसरी यह कि जिन सस्थाओं की स्वतन्त्रता इस प्रकार बुनियादी तौर पर सुरक्षित कर दी गई है उनके द्वारा आत्मनिर्णय, आत्म-निर्देशन और मूल विषयों पर निर्णय करने के अपने अधिकार को कार्यान्वित करने की लोगों की इच्छा भी अवश्य होनी चाहिए। तात्पर्य यह कि अपने भाग्य और भविष्य का निर्णय करने की इच्छा तो जनता में होनी ही चाहिए।

इस अधिकार का अधित्याग करने वाले कभी स्वतन्त्र नहीं रह सकते।

निर्णय करने के अधिकार से जब जनता थोड़ा झुझुख हो जाती है तो एक ऐसी कुण्ठा और असहायता प्रतिफलित होती है जो इस दुःखद विश्वास को बढ़ा मूल कर देता है कि सामान्य नरनारी के लिए स्वयं अपने भाग्य निर्देशन अथवा अपने बच्चों के भविष्य-निर्माण का कोई भी व्यावहारिक मार्ग नहीं रह गया है।

इसलिए मानवी सम्भ्यता में जो श्रेष्ठतम है उसकी सुरक्षा के लिए तीसरी आवश्यक शर्त है इस तरह के व्यावहारिक साधन जिनके द्वारा साधारण नरनारी अपने सम्बन्ध में स्वयं निर्णय कर सके।

और जीवन की दैनन्दिन समस्याओं में, हमारे अस्तित्व के जिन आर्थिक कार्य-व्यापारों से हमारी इतनी सारी सस्थाएँ बनी हैं, नये प्रकार के सहकारी व्यवसाय और आर्थिक सस्थाएँ बिल्कुल ऐसा ही साधन हैं।

आज संयुक्त राज्य अमेरिका में सहकारी व्यवसायों के स्वामी अपने लिए और अपने समुदायों के लिए अनेक प्रकार के सेवा कार्य कर रहे हैं।

वे प्रसव करवाते हैं, कफन-दफन का इन्तजाम करते हैं, खेतों और फारमों पर रोशनी का प्रबन्ध करते हैं, कृषि यन्त्रों को चलाने के लिए बिजली देते हैं, गृह-निर्माण करते हैं, खेतों में नई तरह के तरल खाद डालते हैं, मोटरों की मरिंस (सफाई और दुस्ती) करते हैं और किसानों की उपज को बेचते हैं। वे उपभोक्ताओं के लिए विशाल सर्ववस्तु भण्डार (सुपरमार्केट) चलाते हैं और स्वतन्त्र पनसारियों के लिए किराना माल का थोक काम करते हैं। वे तेल के कुओं से तेल निकालते हैं, फास्फेट की खदानें खोदते हैं, बोज उगाते हैं, काफी पीसकर तैयार करते हैं और पानी गरम करने तथा दूध दुहने की मशीनें बनाते हैं। वे लोगों के बचाये हुए धन-बचती को जमा करके साख (उधार) संघ, सहकारी बीमा कम्पनियाँ और सहकारी कृषि साख समितियाँ शुरू कर देते हैं और इस तरह लोगों को अपनी बचत कारोबार में लगाने और अपने को ही ब्याज देने के योग्य बनाते हैं। और जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, वे हर प्रकार की छोटी और बड़ी स्वास्थ्य योजनाएँ भी चलाते हैं जिससे आधुनिक-चिकित्सा-विज्ञान के चमत्कारिक लाभ सर्व साधारण को सुलभ हो सके।

सहकारिता के आज के इन विभिन्न रूपों को देखकर इसके प्रवर्तक और पुरोगामी कार्यकर्ता अपनी कर्त्रों में पड़े अकुला रहे होंगे। उनकी व्याकुलता सही भी है, क्योंकि इनमें से कुछ तो सही अर्थों में 'सच्ची सहकारी संस्थाएँ' हैं भी नहीं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य योजनाएँ हैं, जो सरक्षण-धन वापसी (patronage refund) नहीं देती, लेकिन जिनका दिया जाना सहकारिता के चार बुनियादी सिद्धान्तों में से एक है। ऊपर बताये उद्यमों में से कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें उपभोक्ता नहीं होते—फुटकर विक्रेताओं की सहकारी थोक किराना समितियाँ और किसानों की सहकारी विक्रय समितियाँ ऐसी ही संस्थाएँ हैं। फिर कुछ राज्यों में शासपत्री (स्टेट-चार्टर्ड) साख-संघ हैं, जिनमें प्रतिपत्री (प्राक्सी) मतदान की प्रथा है, जब कि यह प्रथा 'हिस्से कितने ही क्यों न हों, एक व्यक्ति, एकमत' वाले 'रोशडेल सिद्धान्त' का स्पष्ट उल्लघन करती है। इसके अतिरिक्त वृहत्तर न्यूयार्क की स्वास्थ्य बीमा योजना-जैसी सहकारी संस्थाएँ भी हैं, जहाँ मतदान होता ही नहीं। और फिर उपनगरों

मे परिवर्तनशील 'कृषि आपूर्ति सहकारी समितियाँ' हैं, जिनके बहुसंख्यक सदस्यों को, जो प्रायः गैर-किसान हैं अभी तक पूरी तरह मतदान का अधिकार नहीं मिल पाया है, और यों वे एक प्रकार से द्वितीय कोटि के सदस्य हैं।

इस प्रकार हमारे आधुनिक विश्व की ही भाँति आज के और विशेष रूप से अमरीका के सहकारी उद्यम द्रुतगति से परिवर्तनशील और विकासोन्मुख अवस्था में हैं। सहकारिता वास्तव में एक नये प्रकार का व्यवसाय है, जो ऐसे नये युग की आवश्यकताओं के सर्वथा अनुरूप है जिसमें पुराने किसी भी युग की अपेक्षा हम ज्यादा अच्छी तरह जीवन-यापन करते हैं, लेकिन जिस तथ्य को न तो इस नये युग के अधिकांश वाचाल हितैषी और न इसके शोर-शरापा करने वाले अधिकांश शत्रु ही अभी तक ठीक से समझ पाये हैं।

सहकारिता के आधुनिक विभिन्न रूपों और प्रकारों के कारण जो उलझन और गड़बड़ पैदा हो गई है उसे कुछ लोग यह कहकर सुलझाने का प्रयास करते हैं कि अब सहकारी और दूसरे किसी भी प्रकार के व्यवसाय में विशेष अन्तर नहीं रह गया है। लेकिन वे गलत हैं।

कुछ लोग पिछली शताब्दी की आवश्यकताओं के उपयुक्त, और नई स्थितियाँ और नई आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य-संचालन की रूपान्तरित विधियों वाले सहकारी संगठनों के पारस्परिक अन्तर पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं।

वे भी गलत हैं, या कम-से-कम भूले हुए तो हैं ही।

तीसरी तरह के भी कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि किसी भी प्रकार का उद्यम यदि अपने को सहकारी कहना चाहे तो उसका वैसा ही वर्गीकरण कर देना चाहिए—लेकिन इसमें मुश्किल यह है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के ऐसे अनेक उद्यम हैं जो यही चाहते हैं कि उन्हें भी सहकारी समझा जाए।

इसलिए ऐसे लोग तो और भी ज्यादा गलत हैं।

क्योंकि प्रकार की एक ऐसी बुनियादी विशिष्टता तो अवश्य है जिसके विद्यमान होने पर ही किसी व्यवसाय, उद्यम अथवा संस्था का स्वरूप सहकारी हो पाता है; अन्यथा मुनाफा करने के इच्छुक किसी भी संगठन में कितने ही तर्क-वितर्क से सहकारिता के प्राण नहीं फूँके जा सकते।

यह विशिष्टता उस उद्यम के प्रयोजन और स्वामित्व के उसके प्रकार

में पायी जाती है और स्वामीत्व का वह प्रकार उसके प्रयोजन से अवश्यम्भावी रूप से मेल खाने वाला होना चाहिए।

यही भिन्न प्रयोजन और स्वामीत्व का यही भिन्न प्रकार तो सहकारी को दूसरे ढंग के आर्थिक सगठनों से पृथक् और वैशिष्ट्य प्रदान करता है।

तो पहली बात यह कि अपने जिन ग्राहकों और उपभोक्ताओं की सेवा में वह रत है उन्हें आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक न्यूनतम असल कीमत पर उनकी आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ, जिस रूप में और जिस कोटि की वे चाहे, उपलब्ध करना जिस उद्यम का प्रयोजन हो वही सहकारी है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब ग्राहक अथवा सेवाओं के उपभोक्ता ही उस व्यवसाय के स्वामी और एकमात्र स्वामी हों।

जो व्यवसाय, उद्यम या संस्था उन्हीं लोगों के अधिकार में हो जिनको कि सामान सेवा देने का कार्य वह प्रमुख रूप से करती है और जिसके अस्तित्व का प्रयोजन भी उसी जन-समुदाय की किसी-न-किसी आवश्यकता को पूरा करना हो, सही अर्थों में उसी को सहकारी कहा जा सकता है।

थोड़े से विवेचन से ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। यदि कोई व्यवसाय एक जन-समुदाय के यानी अपने स्टाकधारियों के लाभ के लिए दूसरे जन-समुदाय को यानी अपने ग्राहकों को माल या सेवाएँ बेचता है तो वह सहकारी नहीं है। इसी प्रकार जिस व्यवसाय के संरक्षक अथवा सेवाओं के उपभोक्ता उस व्यवसाय के स्वामी नहीं हैं, उसे भी सहकारी नहीं कहा जा सकता। ऐसे व्यवसाय को सहकारी बनाने के लिए आवश्यक है कि उसके वर्तमान स्टाकधारी अपने सारे हिस्से (स्टाक) उस व्यवसाय के ग्राहकों को बेच दे और व्यवसाय का पूरा नियन्त्रण भी 'एक व्यक्ति और एक, केवल एक वोट' के आधार पर उन्हीं ग्राहकों को सौंप दिया जाए।

इसका यह अभिप्राय तो कदापि नहीं कि हमारे देश की तथाकथित स्वतन्त्र अर्थ-प्रणाली में व्यवसाय के दूसरे प्रकार के संगठन अच्छे, उपयोगी और आवश्यक नहीं हैं। न यही कहा जा रहा है कि अमरीकी अर्थ-व्यवस्था में निकट भविष्य में सहकारी ढंग के व्यापारी सगठनों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संगठन प्रमुखता प्राप्त करेंगे ही नहीं। उल्टे जोर तो इस बात पर है कि

लाभ अभिमुखी निर्धारित अन्य व्यवसायों की कड़ी प्रतियोगिता सहकारियों के हित में ही है, क्योंकि ऐसी स्थिति के न रहने पर सहकारियों का विकास सम्भवतः अवरुद्ध हो जाएगा ।

यह सही है कि सभी सहकारी सहकारियों के जैसा ही आचरण नहीं करते । लेकिन यह बात तो ठीक उसी प्रकार हुई जिस प्रकार कि सभी आदमी हमेशा भले आदमियों की ही तरह आचरण नहीं करते, या जिस प्रकार मेथोडिस्ट चर्च के सभी अनुयायी अच्छे मेथोडिस्टों के जैसा या ईसाई धर्म के किसी भी फिरके से सम्बद्ध लोग हमेशा अच्छे-भले ईसाइयों-जैसा ही आचरण नहीं करते ।

एक साधारण से उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाएगी । हिस्सा-पूँजी से बनी ज्वाइट-स्टाक बीमा कम्पनियाँ एक तो अपने हिस्सेदारों (स्टाकधारियों) के लिए लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से व्यवसाय करती हैं और दूसरे, उन बीमा कम्पनियों के पालिसीधारी उनके स्वामी नहीं होते, इसलिए हिस्सा-पूँजी से बनी कोई भी पब्लिक या प्राइवेट ज्वाइट-स्टाक बीमा कम्पनी सहकारी पद्धति का व्यावसायिक उद्यम नहीं है । इसके विपरीत पारस्परिकता के आधार पर बनी बीमा कम्पनियाँ हर दृष्टि से सहकारी सस्थाएँ हैं, क्योंकि एक तो उनका व्यावसायिक उद्देश्य अपने पालिसीधारियों को न्यूनतम असल कीमत पर, जो व्यावहारिक भी हो, बीमा-सुरक्षा उपलब्ध करना होता है दूसरे, इस कौटि की सभी बीमा कम्पनियों का स्वामित्व किसी दूसरे में नहीं, उनके पालिसी-धारियों में ही निहित रहता है । अब यह सर्वथा दूसरी बात है, और इस समय हम यहाँ उस पर विचार भी नहीं कर रहे हैं, कि पारस्परिकता के आधार पर बनी बहुत-सो बीमा कम्पनियाँ पारस्परिक अथवा सहकारी सस्थाओं जैसा आचरण नहीं करती ।

तो सहकारी अपनी सेवाओं का उपयोग करने वालों के ही पूरे अधिकार में उपभोक्ता-स्वामीत्व कृत ग्राहक-स्वामीत्व-कृत सरक्षक-स्वामीत्व-कृत व्यवसाय है । न केवल इतना ही, बल्कि यह भी कि आप कोई भी क्यों न हों यदि थोड़े से समय तक इस व्यवसायों से खरीदते रहें तो अपने-आप इनके स्वामी बन सकते हैं ।

सहकारी वितरण-अभिमुखी, आवश्यकता-अभिमुखी और उपभोक्ता-अभि-

मुखी व्यवसाय है। प्रायः यह कहते सुना जाता है कि 'उपभोक्ता-अभिमुखता' में तो दूसरे ही व्यवसाय सहकारियों से बाजी मार ले जाते हैं। वे अपने उपभोक्ताओं से तरह-तरह की अपीले करते हैं और उन्हें बड़े जोर-शोर से एवं विस्तारपूर्वक यह बतलाते हैं कि नये उत्पादनों की शोध-खोज और विकास पर उनके द्वारा कितने लाख खर्च किया जाता है। यह सब एक अंश तक सच है। और यह भी सच है कि सहकारी सस्थाओं को नये उत्पादकों की शोध-खोज पर जितना वे अभी खर्च कर रही हैं उससे कहीं अधिक करना चाहिए; और यदि उनके पास रुपया हुआ तो वे करेगी ही। लेकिन इस तर्क की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि दूसरे व्यवसाय उपभोक्ताओं के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन तो खूब करते हैं, यहाँ तक कि इस काम को प्रायः सनसनीखेज और कभी-कभी तो बीभत्स भी बना डालते हैं, लेकिन नितान्त आवश्यक हो जाने के अतिरिक्त कीमतों को कभी कम नहीं करते; और यह तो कभी कहते ही नहीं कि सारा असल लाभ ग्राहकों की सम्पत्ति है जो वर्ष के अन्त में उन्हें चुकाया ही जाना चाहिए।

सहकारी ये दोनों ही काम करते हैं।

वे इससे भी ज्यादा करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उनका समस्त उत्पादन और वितरण उनके सरक्षकों की आवश्यकता और माँग के अनुसार ही होता है। लेकिन दूसरे व्यवसाय पहले स्वयं तय कर लेते हैं कि उन्हें किस चीज का उत्पादन करना है और कीमत भी तय करली जाती है और तब उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए प्रवृत्त किये जा सकने के अनुसार ही उनका उत्पादन होता है।

सहकारी वास्तव में उपभोक्ता-अभिमुखी व्यवसाय है। वे उपभोक्ता-निर्देशित वस्तुओं और सेवाओं का ही उत्पादन और वितरण करते हैं। और यही बुनियादी बात सहकारी को 'नये युग के अनुरूप नये प्रकार का व्यवसाय' बनाता है, जिस पर आगे और भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।

अधिकांश सहकारी सस्थाओं के सम्बन्ध में और कारण भी हैं; क्योंकि अधिकांश सहकारियों के स्वरूप, सिद्धान्तों और कार्यविधियों की ज्यादा ठीक तरह से परिभाषाएँ की जा सकती हैं। लेकिन वे सब गौण और हैं अभी तक

जिन अन्तर्निहित मौलिक विशेषताओं पर विचार किया गया है उन्हीं का अनुसरण करने वाली और उन्हीं पर निर्भर है।

१९२० के बाद की दशाब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में किसानों को, विशेष रूप से कुछ मध्यवर्ती पश्चिमी राज्यों में, आवश्यक मात्रा में, उपयुक्त मूल्य पर सन्तोषजनक कोटि के उर्वरक प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। जो उर्वरक वे खरीदते थे उनकी किस्म के सम्बन्ध में सामान्यतः उन्हें 'विश्वास' पर ही निर्भर करना पड़ता था। ग्राहकों को उर्वरक का कोई विश्लेषण या सूत्र भी नहीं दिया जाता था।

तब उनमें से कुछ किसानों ने नया व्यवसाय—अपना ही सहकारी व्यवसाय आरम्भ करने का निश्चय किया। शुरू-शुरू में काम करने का ढंग बड़ा ही सरल और सीधा-सादा था। सबका रुपया जमा करके जहाँ भी अच्छे भावों पर मिल जाता वही से वे सब के लिए एक साथ उर्वरक खरीदने लगे। इस सीधे-सादे ढंग से ही उन्हें उर्वरक १० प्रतिशत सस्ता पड़ने लगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में उन किसानों को उपयुक्त मूल्य पर विश्लेषण युक्त उर्वरक आवश्यक मात्रा में प्राप्त होने में कठिनाई होने लगी। तब स्थानीय 'कृषि आपूर्ति' सहकारी संस्थाएँ उर्वरक-उत्पादन की अपनी निजी सुविधाएँ जुटाने लगीं। इसके लिए सबसे पहले किसानों का अपने इन सहकारी उद्यमों में पैसा लगाने को तैयार होना आवश्यक था। पूँजी निवेश के लिए निर्धारित राशि के हिस्से निकाले गए और प्रति किसान कम-से-कम एक हिस्से के हिसाब से किसान सहकारी के सदस्य बन गए। इस प्रकार किसानों के धन ने उन्हीं किसानों के हाथ बेचने के लिए उर्वरक का उत्पादन करने वाले कारखानों का निर्माण किया। ये कारखाने बहुत ही बढ़िया उर्वरक बनाने लगे, और क्यों न बनाते, जब कि वह स्वयं उन्हीं के उपयोग के लिए होता था। उर्वरक-उत्पादन व्यवसाय में इन सहकारियों के प्रवेश का परिणाम यह हुआ कि खुले सूत्र वाले उच्च विश्लेषण युक्त उर्वरक का उत्पादन खूब बढ़ गया। अब तो इस व्यवसाय में इस तरह का खूले सूत्र वाला उच्चकोटि का उर्वरक बहुत सामान्य बात हो गई है।

तो सहकारी लोगों का ऐसा समुदाय है जो एक-जैसी आवश्यकता से

प्रेरित होकर यह निर्णय करते हैं कि उस आवश्यकता की पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ या एकमात्र उपाय ऐसे नये व्यवसाय का सगठन है जो सीधे उस आवश्यकता को पूरा करे। निवेश पूँजी जमा करने के लिए स्वेच्छा से सम्मिलित होकर वे इस काम को करते और यों अपने उद्यम के स्वामी, नियन्त्रणकर्ता और संरक्षक बनते हैं।

सहकारी के स्वामी और संरक्षक बनने के कार्य में जितने ही अधिक लोग हिस्सा लगे उन सब की हालत भी उतनी ही अच्छा होगी। एक सहकारी उर्वरक व्यवसाय को आरम्भ करने वाले किसान यदि उस उद्यम के स्वामीत्व और संरक्षण के लिए दुगुने सदस्य बना सके तो व्यापार तो दुगुना होगा ही लाभ भी सभी को होगा। इसीलिए तो सहकारी सगठन वर्ग, पन्थ, वर्ग और आस्था-विश्वासों के भेदभाव के बिना सभी को अपना सदस्य बनाते हैं। सहकारिता का यही पहला सिद्धान्त है। पन्थगत धार्मिक और पक्षगत राजनैतिक विवादों से अपने-आप को पूरी तरह अलग रखकर सहकारी सगठन इस सिद्धान्त की रक्षा ही नहीं करते, बल भी पहुँचाते हैं।

सहकारी सगठनों का अस्तित्व निवेश पूँजी पर ऊँचे प्रतिलाभ उपार्जित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना निर्माण करने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के ही लिए होता है। इसी से सहकारिता के अगले दो सिद्धान्तों अर्थात् सिद्धान्त दो और तीन की अनिवार्य निष्पत्ति होती है। वे हैं . एक सदस्य के पास हिस्से कितने ही क्यों न हों उसके द्वारा एक और केवल एक ही मत दिये जाने का सिद्धान्त, और निवेश पूँजी पर सीमित प्रति लाभ का सिद्धान्त जो प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत से क्वचित् ही अधिक होता है।

अपना उर्वरक अपने को ही बेच कर किसान अथवा अपना किराना अपने को ही बेच कर उपभोक्ता मुनाफा कमाने की कोशिश करे यह एक ऐसी बात है जो न किसान की समझ में आ सकती है और न उपभोक्ता को ही। इसलिए चौथे सिद्धान्त में 'संरक्षण-धन वापसी' का प्रावधान किया गया। इस युक्ति के द्वारा सहकारी अपने सदस्यों और सम्बन्धकों को लागत मूल्य पर माल और सेवाएँ प्रदान करने के अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। लेखा-अवधि के अन्त में, व्यवसाय की सारी लागत चुका कर, आवश्यक अथवा

प्राप्त आरक्षित निधियाँ जमा करके और शिक्षा तथा कल्याण कार्यों के लिए धनराशियाँ निकाल कर जो निधि बचती है वही 'शुद्ध बचत' है। सामान्य व्यवसाय में इसको शुद्ध लाभ कहते हैं जो स्टॉकधारियों को उनके निवेशों के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है लेकिन सहकारी सगठन तो लाभार्जन के लिए होने नहीं हैं, न अपने लिए और न अपने स्टॉकधारियों के ही लिए, इसलिए यह सारी शुद्ध बचत उनके संरक्षकों में संरक्षण के अनुपात से वितरित कर दी जानी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक संरक्षक को कुल क्रय में उसके क्रय का जितना अनुपात होता है मूल बचत का उतना ही प्रतिशत मिल जाता है। 'संरक्षण धन-वापसी' का यह विचार मूलतः उन पुरोगामियों की अद्भुत देन है जो इंग्लैण्ड के रोशडेल नामक स्थान के निवासी थे और जिन्होंने १८४४ में टोडलेन में अपना छोटा-या भण्डार खोलकर इस विचार को कार्यान्वित किया था। इंग्लैण्ड के महान उदारवादी प्रधान मंत्री विलियम ई० ग्लैडस्टन ने 'उन्नीसवीं सदी का महान आर्थिक आविष्कार' कह कर इसकी प्रशंसा की है।

यह तो हुई बुनियादी सिद्धान्तों की बात। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में इन बुनियादी सिद्धान्तों का विनियोग ही सहकारियों को जुड़े प्रयोजनों एवं जुड़ी परिस्थितियों में सगठित व्यवसायो से पृथक् करता है।

सहकारियों की कराधान स्थिति भी इन्हीं बुनियादी सिद्धान्तों से निरूपित होती है। जिस तरह वे कर चुकाते हैं उसका कारण यह नहीं है कि उन्हें कोई विशेष सुविधाएँ प्राप्त हैं, अथवा उनके लिए विशेष प्रकार के कर-सम्बन्धी नियम बने हुए हैं, उसका सीधा-सा कारण यही है कि उन्हें एक खास ढंग से अपना व्यवसाय करना पड़ता है।

सहकारी सगठन बिल्कुल थोड़े-से और अत्यन्त ही महत्त्वहीन अपवादों के साथ बिल्कुल उन्हीं सधे-बँधे कर-कानूनों के अन्तर्गत वे सारे ही कर चुकाते हैं जो उनके प्रतियोगी व्यावसायिक सगठनों द्वारा चुकाये जाते हैं। कई देहाती क्षेत्रों में तो सहकारी व्यवसाय ही अपने कस्बे का सबसे बड़ा करदाता होता है। सभी सहकारी सगठन पाठशाला-कर, उत्पादन-कर, समाज-सुरक्षा कर, सम्पत्ति-कर और दूसरे सभी प्रकार के कर ठीक उसी तरह चुकाते हैं

जिस तरह उनके प्रतियोगी चुकाते हैं।

मुनाफा करने का उद्देश्य न होते हुए भी कुछ सहकारियों को तो मुनाफा होता ही है और यदि होता है तो उसके एक-एक सेंट पर पूरा-का-पूरा सघीय आय कर चुकाते हैं। लेकिन न्यायालयों ने लगातार उचित ही निर्णय दिये हैं कि सहकारी या दूसरा कोई भी व्यवसाय अपने सरक्षकों को 'सरक्षण धन वापसी' के लिए बचनबद्ध हो और इस तरह की अदायगियों करे तो उसे उस व्यवसाय की आय नहीं समझा जाना चाहिए, वास्तव में वह सरक्षक की सम्पत्ति है और उसी से उसका कर वसूला जाना चाहिए, जैसा कि किसी भी करदाता से उसकी कर-योग्य सम्पत्ति पर लिया जाता है।

इसका कारण एकदम स्पष्ट है। देयता (देनदारियाँ) आस्तियाँ (परि-सम्पत्ति) नहीं हैं। जिस धन के लिए व्यवसाय किसी का ऋणि हो वह देयता उस व्यवसाय की कर-योग्य आय नहीं हो सकती। वह बुनियादी तरीका तो हम देख ही आये हैं कि जिसके द्वारा सहकारी अपने सदस्यों और अधिकतर मामलों में अपने सभी सरक्षकों के लिए निर्लाभ ढंग से काम कर पाते हैं। वह तरीका है उस निधि को जो दूसरे व्यवसायों में सदस्यों और सरक्षकों के लिए लाभ है, सहकारियों द्वारा अपने सरक्षकों को उनके सरक्षण अनुपात के अनुसार सरक्षण-धन वापसी के रूप में लौटाने के लिए बचनबद्ध होना। ये दायित्व सहकारी व्यवसायों के लिए बन्धनकारी देनदारियाँ हैं। इन दायित्वों से विमुख होकर न तो उनका रूप सहकारियों का रह जाता है और न वे सहकारी कहलाने की योग्यता ही रख सकते हैं। यदि सहकारी दूसरे व्यवसायों की अपेक्षा कम आयकर देते हैं तो इसका कारण केवल यही है कि उनकी कर-योग्य आय ही कम होती है। और कर-योग्य आय के व्यय होने का कारण यह है कि उस आय का काफी बड़ा हिस्सा सहकारियों का नहीं उसके सरक्षकों का होता है। वास्तव में वह सरक्षक की आय है, जिसका वह जो चाहे करे। उस धन के निर्वर्तन का अधिकार सहकारी को नहीं है। इसीलिए वह धन सहकारी की आय नहीं हूँ सकता।

यह तो कोई भी नहीं कहेगा कि घटा देने वाले व्यवसाय को उस लाभ पर भी आय कर देना चाहिए जिसे वह कर सकता था, लेकिन किया

नहीं। न कोई यही सुझाव देगा कि सहकारी व्यवसायों को, जिन्हें उनके स्वामी विमर्शपूर्वक ही निलोभ आधार पर चलाने का निश्चय करते हैं, इस निर्णय के लिए दण्ड दिया जाना चाहिए। सहकारियों से सरक्षण धन वापसी पर आय कर लेना ठीक इसी प्रकार का दण्ड होगा। यह तो अमरीकन ना रिक् के बिना लाभ बनाये व्यवसाय करने के अधिकार पर करारोपण होगा। कोई भी राष्ट्र जो सही अर्थों में स्वतन्त्र हो इस तरह का कर ददाति नहीं कर सकता।

यदि सरक्षण धन वापसी पर यों दण्ड-शुल्क देना पड़े तो मानी हुई बात है कि सहकारी उनसे बचने का उपाय भी कर ही सकते हैं। उनका व्यावसायिक अस्तित्व ही होता है अपने सदस्यों को लाभ पहुँचाने के लिए, न कि अपना निज का लाभ करने के लिए, इसलिए वे निस्सन्देह लागत मूल्य पर बिक्री करने का प्रयत्न करके सरक्षण धन वापसी को अदायगियों से बच सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर तो उनके विशिष्ट सहकारी स्वरूप का ही अन्त हो जाएगा।

इसलिए सहकारिता के सभी, और सरक्षण धन वापसी वाला चौथा तो विशेष रूप में मूलभूत सिद्धान्त है।

कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करने की सहकारियों में अपेक्षा की जाती है और अधिकांश उनका पालन करते भी हैं। पहला नियम है नकद व्यवहार। अपने ग्राहकों का पैसा बचाने वाले किसी भी व्यवसाय के लिए यह नियम बहुत जरूरी है, क्योंकि उधार का कारवार बड़ा महंगा सौदा है। हमारे देश में ऐसे बहुत-से सहकारी संगठन भरे पड़े हैं जो नकद व्यवहार की नीति के पास भी नहीं फटकते। और कुछ धंधे तो ऐसे भी हैं जिनमें प्रतियोगियों द्वारा उधार देने की व्यवस्था के कारण सहकारियों को भी यह व्यवस्था चालू करनी पड़ी है। लेकिन नकद का व्यवहार ही एक ऐसा नियम है जिसको अपना कर सहकारी व्यवसाय अपने सरक्षकों के लिए ज्यादा-से-ज्यादा बचत कर सकते हैं और उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा फायदा पहुँचा सकते हैं।

दूसरा नियम है सहकारियों का एक विचारपूर्ण नीति अपना कर सामान्यतः अपने माल और सेवाओं को बाजार भाव पर बेचना और जो भी

अतिरिक्त आय ही उसे संरक्षण धन वापसी के द्वारा लौटा देना। यदि सहकारी शुरू से ही अनुमानित लागत मूल्य पर बेचने का प्रयत्न करे तो उन्हें आर्थिक वर्षों में ही बन्द हो जाना पड़े। क्योंकि लागत मूल्य का अनुमान गलत हो सकता है और तब उन्हें कारबार में बुरी तरह घाटा होने लगेगा। इसलिए लागत मालूम हो जाने पर ही सदस्यों को लागत मूल्य पर व्यावसायिक लाभ पहुँचाना अच्छा होता है, न कि पहले।

तीसरा नियम है स्वस्थ ढंग से अपना विस्तार करते जाना; क्योंकि सभी सहकारियों के सफल होने की आशा की जा सकती है। 'विस्तारित न होना' सहकारियों के लिए, जो आवश्यक रूप से अपने सदस्यों की दिलचस्पी और निष्ठा पर निर्भर करते हैं, दूसरे सामान्य व्यवसायों की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक है और इसी पर चल कर अधिकांश सफल सहकारियों का निर्माण हुआ है।

चौथा नियम है निरन्तर शिक्षा, जो लम्बे अनुभव के उपरान्त सहकारियों की व्यावसायिक सफलता के लिए अपरिहार्य सिद्ध हुई है। जब तक सदस्य और सामान्य जनता दोनों ही सहकारियों की कार्य प्रणाली को नहीं समझते और उनका उचित ढंग से सही-सही मूल्यांकन नहीं कर पाते उलझने अवश्यम्भावी हैं और उस समय तो और भी अधिक जब कि बचत बहुत कम हो रही हो।

तो ये हैं सहकारिता के सिद्धान्त :

१. खुली सदस्यता।

२. जनवादी नियन्त्रण—प्रत्येक सदस्य-स्वामी को केवल एक मत देने का अधिकार, हिस्से उसके पास कितने ही क्यों न हों।

३. निवेश पूँजी पर सीमित प्रतिफल।

४. सम्पूर्ण वास्तविक बचत का संरक्षण के अनुपात से वितरण।

और ये हैं सहकारिता के नियम :

१. यथा सम्भव नकद व्यापार।

२. चालू बाजार भाव पर बिक्री।

३. सतत विस्तार।

४. निरन्तर शिक्षा ।

इन सिद्धान्तों और नियमों पर चलते हुए कई देशों में सौ वर्षों से भी अधिक समय से सहकारी संगठन कारबार कर रहे हैं ।

तो फिर हम सहकारियों को 'नये युग के अनुरूप नये ढग का व्यवसाय' क्यों कहते हैं ? कुछ तो इसलिए कि अमरीका अभी तक सहकारियों को सही-सही पहचान नहीं पाया है । कम-से-कम नगरवासी अमरीका ने तो इन्हें नहीं ही समझा है । और कुछ इसलिए भी कि आज के हमारे श्रेष्ठतम सहकारी व्यवसाय मन्दी के जमाने के अपने परबर्ती सहकारियों से नितान्त भिन्न प्रकार के उद्यम हैं ।

लेकिन इस अध्याय का यह शीर्षक रखने का मुख्य कारण है हमारे देश की अर्थ व्यवस्था में कुछ ऐसी चिन्तनीय प्रवृत्तियों का होना जिनकी ओर बहुत ही कम ध्यान जा पाया है । सहकारी व्यवसायों के संगठन का कारण भी उन्हीं में की कुछ प्रवृत्तियाँ हैं । और इसलिए भी कि हमारे कुशल-क्षेम और हमारी स्वतन्त्रता पर सकट बन कर छाई हुई उन प्रवृत्तियों के विरुद्ध स्वैच्छिक स्वतन्त्र उद्यम के ढग की प्रतीकारात्मक और सशोधक शक्ति के रूप में सहकारियों की आज आवश्यकता है ।

३ | जनता का स्वास्थ्य

बोमार पड़ोसी की सुश्रूषा कर उसे स्वस्थ करना मानव-इतिहास के सभी युगों में और सर्वत्र एक मौलिक सद्गुण और बड़े परोपकार का कार्य माना जाता रहा है। ऐसे कृत्यों से ही स्नेहपूर्ण मानवी सम्बन्धों की उत्पत्ति हुई और नये स्थानों में मच्चों बिरादरी के विकास का शुभारम्भ। आज भी इन कृत्यों का यही परिणाम होता है। लेकिन अब तो आधुनिक अमरीका और अन्य विकसित देशों के देहातों में भी, इस तरह की बातें बहुत कम देखने को मिलती हैं, और हमारे बड़े नगरों में तो शायद ही कभी।

इस परिवर्तन के कई कारण हैं और वे सब बुरे भी नहीं हैं। मुख्य कारण तो यही है कि आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान रोगियों को अच्छा करने की दिशा में चमत्कार कर दिखाता है, जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता।

आज से पचास वर्ष पहले रोगी डाक्टर के पास बिल्कुल ही नहीं जाता या चला भी जाता तो दोनों ही स्थितियों में उसके रोग-मुक्त होने की सम्भावनाएँ प्रायः एक-जैसी ही होती थी। क्योंकि बीमार को अच्छा करने को तरकोत्रे किमो अच्छे डाक्टर को भी लगभग उतनी ही मालूम होती थी जितनी किसी और को।

आज ये दोनों ही बातें नहीं रही। आज तो बीमार होने पर उसी रोग का विशेषज्ञ निपुण डाक्टर यदि मिल सके तो उसके पास जाने और न जाने में जीवित रहने और मरने तक का अन्तर हो सकता है।

आधुनिक चिकित्सक अच्छी दशाओं में चिकित्सा और सुश्रूषा का पूरा-पूरा अवसर मिलने पर न केवल किसी भी रोग को अच्छा कर सकते हैं, बल्कि लोगों को निरोग और स्वस्थ भी बनाये रख सकते हैं।

हमारे आधुनिक समाज में बीमारी के समूय पड़ोसी की प्रायः निरर्थक-सी सहायता के स्थान पर जहाँ भी सम्भव होता है निपुण डाक्टरों, परिचारिकाओं

और दूसरे-दूसरे पेशेवर तकनीशियनों को बुलाया जाता है, और इसमें आश्चर्य की कोई बात भी नहीं है।

सामाजिकदृष्टि से हमने कुछ मूल्यवान् खोया अवश्य है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से जीवन और स्वास्थ्य की अपेक्षाओं के रूप में हमने काफी कुछ प्राप्त भी किया है।

यदि चिकित्सक, परिचारिकाएँ, जन-स्वास्थ्य कार्यताओं और चिकित्सकों तथा परिचारिकाओं के काम में हाथ बँटाने और उनके कार्यों की अनुपूर्ति करने वाले छोटे और बड़े सब तरह के तकनीकी कौशलों में दक्ष नाना विधि लोग काफी सख्या में हों, और यदि जनता इन सारी सेवाओं के लिए पैसा दे सके तो हमारे राष्ट्र का स्वास्थ्य इतना अच्छा और उन्नत हो सकता है जिसकी हम स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते।

लेकिन दुर्भाग्य से अभी इनमें से एक भी बात नहीं है।

१९०० से १९५० के बीच की अवधि में अमरीका में डाक्टरों की संख्या में केवल ५८ प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि जनसंख्या में १०० प्रतिशत वृद्धि होती रही। और अब भी यही हाल है। यह सही है कि पेशेवर परिचारिकाओं, ओषध-कारकों और अन्यान्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक डाक्टर के समय का ज्यादा अच्छा उपयोग होने लगा है। लेकिन ज्यादा अच्छे ढंग का स्वास्थ्य-परिचर्या सेवा की जितनी माँग और मानवोचित आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो बहुत ही कम हो पाती है। और इसलिए ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को परिचर्या-सेवा करने की सक्षमता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ऐसे विधि-विधानों पर कांग्रेस में विचार होता रहता है।

डाक्टरों की कमी का एक कारण तो यह है कि लाखों परिवार इतने समर्थ नहीं हैं कि आधुनिक चिकित्सा परिचर्या का मूल्य और विशेष रूप से आपत्-मेवा-शुल्क दे सकें। उदाहरण के लिए बहुत देहाती क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी है, क्योंकि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वहाँ जाकर बसने वाला डाक्टर अच्छी कमाई कर सके। औसत रूप से अमरीकी परिवार चिकित्सा और स्वास्थ्य परिचर्या पर अपनी वार्षिक आय का लगभग ५ प्रतिशत व्यय करते

है। लेकिन एक तो इस धन का अधिकांश बड़ी बेतरतीबी से खर्च किया जाता है और दूसरे लाखों परिवार निम्न आय वाले हैं इसलिए हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मध्यम कोटि से ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता।

इस स्थिति में सुधार करना अनेक कारणों से आवश्यक हो गया है।

एक कारण तो सीधे उन जबर्दस्त परिवर्तनों से सम्बन्धित है जो अमरीकी जनता के रोजगार के रूपों में होते जा रहे हैं। इतिहास में सम्भवतः पहली ही बार हमें बड़े पैमाने के उत्पादन उद्योगों में तेजी बढ़ती हुई और व्यापक औद्योगिकीय बेकारी की स्थिति और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति असन्दिग्ध रूप में हमारी अर्थ-व्यवस्था के उन सभी विभागों में पाई जाती है जो सेवाओं के विपरीत माल (वस्तुओं) का उत्पादन करते हैं।

इस सम्बन्ध में थोड़े से ही उदाहरण काफी होंगे।

देश का प्रत्येक बड़ा वायुमार्ग अपने विमान-चालकों की संख्या में निरन्तर कमी करता जा रहा है। कारण यह है कि विशाल जेट विमान दुगुने यात्रियों को आधे समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देते हैं इसका अर्थ हुआ विमान-चालकों के उड्डयन घण्टों का सिर्फ एक चौथाई रह जाना, क्योंकि बड़े हुए यातायात के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाता।

मोटर (आटोमोबाइल) मजदूर संघ की सदस्यता कुछ ही वर्ष पहले १५ लाख के लगभग थी। इस संघ की भावी योजनाएँ इस धारणा पर आधारित हैं कि मोटर उद्योग में लगे कर्मचारियों की संख्या आगे कभी भी १० लाख से अधिक नहीं होगी।

अमरीका में कपड़ा उद्योग में लगे श्रमिकों की संख्या १९४७ में ११,४६,३००; १९५४ में ९,४७,००० और १९५८ के मार्च महीने में ८,२०,००० थी। यह निन्तर घटती ही जा रही है।

अगर हमारे आर्थिक विकास की गति को मन्द कर दिया जाए तो हमें बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिकीय बेकारी का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में तो जब तक इस गति को तेज नहीं किया जाता यह समस्या अधिकाधिक गम्भीर ही होती चली जाएगी।

इसके अतिरिक्त उन बेकार मजदूरों की काफी बड़ी संख्याको उप-

भोक्ताओं को बेचे जाने वाले माल का अधिक उत्पादन करने के काम पर लगाने की सम्भावनाएँ तो प्रायः निराशा जनक ही हैं। जब तक हम इस न्याय सगत बात को जल्दी-से-जल्दी नहीं सीख लेते कि हमारे बच्चे बगैर भोड़-भाड़ वाली कक्षाओं में उचित वेतन पाने वाले ऐसे शिक्षकों से, जो कार्याधिक्य से क्लान्त नहीं हो जाते, अच्छी शिक्षा पाने के अधिकारी हैं, जब तक हम यह नहीं सोचने लगते कि गन्दों बस्तियों का उन्मूलन और नगरों का पुनर्विकास लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि देश के चौथाई भाग को कक्रोट की पक्की सड़कों से पाटना; जब तक हम स्वास्थ्य-सेवाओं के विस्तार की ओर तत्काल ध्यान नहीं देने लगते और जब तक हम इस बात को नहीं समझ लेते कि अब आगे से सबको यथा सम्भव पूरा काम या नौकरी देना केवल जन-कल्याणकारी सेवाओं से सीधे रूप से सम्बन्धित क्षेत्रों के तेज विकास पर ही निर्भर करता है, हम अपने-आप को बराबर कठिनाइयों के ज्वाल में फँसा पाएँगे।

कोई भी महान् सम्यता भौतिक साधनों और तुष्टियों के उपभोग की सीमा-तीत वृद्धि पर ही कभी निर्मित नहीं की जा सकी है। हमारा देश अपवाद नहीं हो सकता।

नौकरी या काम देने के अवसर का अमरीकी जनता के स्वास्थ्य-मान का अभिवृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार करने से अधिक युक्तियुक्त और व्यापक रूप से मान्य दूसरा कोई उपाय सोचा भी क्या जा सकता है? यह तो सच है कि वस्त्रोद्योग के सभी विस्थापित श्रमिक डाक्टर नहीं बन सकते। लेकिन १९०० में जहाँ प्रत्येक पाँच पेशेवर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में तीन डाक्टर होते थे, १९५० में अपने पड़ोसियों के स्वास्थ्य को उन्नत करने के कार्य में लगे प्रति पाँच व्यक्तियों में केवल एक ही डाक्टर होता था। वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को बनाये रखने और उन्नत करने वाला व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें उच्चकोटि की प्रवीणता प्राप्त डाक्टर से लेकर निपट अकुशल अर्दली तक सभी तरह के लोगों को काम पर लगाया जाता है।

स्वास्थ्य-सेवाओं को विस्तारित और स्वास्थ्य मानों को उन्नत करने का कम-से-कम एक उपाय तो यह हो ही सकता है कि जिस अमूल्य सामाजिक हेतु से अनु-

प्राणित होकर किसी जमाने में पुरोगामी महिला पड़ोसी की झोपड़ी में उसके बीमार बच्चे की सुश्रूषा के लिए जाया करती थी उस अभिप्रेरणा का इस जमाने में आधुनिक ढंग से उपयोग किया जाए। इससे अवश्य ऐसी तरकीबें समझ में आ सकती हैं जिनको अपनाने से अमरीकी जनता द्वारा आज चिकित्सा परिचर्या पर जितना व्यय किया जाता है उतनी ही धनराशि में ज्यादा सक्षम सेवाएँ और अधिक उत्तम कौटि की सुरक्षा प्राप्त की जा सकती हैं।

और जो एक-एक परिवार के लिए अकेले-अकेले सम्भव नहीं उसे परिवारों के समूह सहकारिता के लिए राजी होकर कर सकते हैं और वास्तव में इस दिशा में काफी अच्छा कार्य कर भी रहे हैं।

लेकिन इसके लिए सबसे पहले रोगी और निरोग दोनों ही तरह के परिवारों को अपनी वर्तमान और भावी आवश्यकताओं का तथा अपनी मासिक आय के एक अंश का निकाय करने का फैसला करना होगा।

जब लोग किसी सामूहिक स्वास्थ्य योजना के सदस्य बनते या उसमें सम्मिलित होते हैं तो बिल्कुल यही करते हैं। इस तरह की कुछ योजनाओं को सहकारी योजनाओं के नाम से पुकारा जाता है, जो सर्वथा उचित ही हैं; कुछ सामुदायिक योजनाएँ कहलाती हैं; कुछ श्रमिक स्वास्थ्य योजनाओं के नाम से जानी जाती हैं। नाम जो भी हों, सभी में कुछ मूलभूत विशेषताएँ तो अवश्य एक-जैसी हैं। और स्वास्थ्य के लिए निर्धारित धनराशि का ये सभी योजनाएँ निश्चित ही सदुपयोग करती हैं।

चीन के गाँवों के सम्बन्ध में एक कहानी कही जाती है कि वहाँ के लोगों ने एक बार यह नियम बनाया कि यदि साल-भर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहा तो गाँव के चिकित्सक को हर परिवार की ओर से एक निर्धारित रकम दी जाएगी। लेकिन यदि परिवार में कोई बीमार हो जाता तो डाक्टर का पारिश्रमिक उसी अनुपात से कम कर दिया जाता था। लोगों को स्वस्थ बनाये रखने के लिए डाक्टर को पुरस्कृत करना ही इसमें मुख्य बात थी।

यह कहानी सच है या झूठ, इससे हमें कोई मतलब नहीं; लेकिन इसमें रोग को अच्छा करने के व्यवसाय और निरोग बनाये रखने की योजनाओं के मूलभूत अन्तर पर काफी अच्छा प्रकाश पड़ता है।

यह अध्याय स्वास्थ्य को बनाये रख और उसमें उन्नति करने की योजनाओं के सम्बन्ध में है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जन-समुदाय इस दिशा में स्वतन्त्र-प्रेरणा से क्या कर सकत है। यह अध्याय कुछ ऐसी उपयुक्त विधियों के प्रयोग के सम्बन्ध में है जिन्हें अपना कर अधिकाधिक लोग आधुनिक ढंग की सर्वोत्तम स्वास्थ्य परिचर्या को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय अमरीका के सहकारी स्वास्थ्य आन्दोलन के बारे में भी है। अमरीका में इस आन्दोलन को आमतौर पर सामूहिक स्वास्थ्य आन्दोलन कहते हैं। यहाँ के समस्त विधि-विधानों में 'सामूहिक स्वास्थ्य' यह ही प्रयुक्त होता है और इस क्रम में सलग्न अधिकांश संगठन भी इसी पद का प्रयोग करते हैं। 'सामूहिक स्वास्थ्य' जिसका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों ही वैयक्तिक स्वास्थ्य से उसके अन्तर को व्यक्त करते हैं।

लेकिन चूँकि यह पुस्तक आधुनिक जीवन में सहकारिता के मूल्यों के सम्बन्ध में है इसलिए हम इस आन्दोलन को 'सहकारी स्वास्थ्य आन्दोलन' ही कहेंगे; और हमारा ऐसा कहना यथार्थ भी होगा। क्योंकि उत्कृष्ट कोटि का यह सम्पूर्ण उपक्रम मूल रूप से लोगों के एक समूह के इस निर्णय पर निर्भर करता है कि पूरे समूह को महँगी बीमारी के आर्थिक दुष्परिणामों से बचाने के साथ ही सभी के स्वास्थ्य-स्तर को समुन्नत करने के लिए वे सब मिल-जुलकर सहकारिता से काम करेंगे।

इस मूलभूत निर्णय के पश्चात् ही इन सहकारी समूहों को सब तरह के सम्बद्ध प्रश्नों का स्वयं निपटारा करने का अवसर प्राप्त होता है। वे प्रश्न हैं : दवाइयों और नुस्खों का हम कितनी कीमत दें; क्या अपने लिए दन्त-परिचर्या का प्रावधान हमारी भी करे; हमारे खयाल में डाक्टरों का कौन सा समूह बहुत बढिया और पूरी लगन से सेवा कर सकता है; इस बात का निश्चय कैसे किया जाए कि वे डाक्टर अच्छी-से-अच्छी दवाओं का ही अच्छी-से-अच्छी दशाओं में प्रयोग करे और आर्थिक दृष्टि से उनके व्यावहारिक परिणाम भी बहुत ही अच्छे निकले; बूढ़ों की स्वास्थ्य-समस्याओं के बारे में क्या किया जा सकता है; हमें प्रतिमास कितना धन देना चाहिए कि अपेक्षित स्वास्थ्य-परिचर्या निश्चित रूप से उपलब्ध होती रहे और हमारी योजना आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनी रहे, दिवालिया न हो जाए। फिर यह प्रश्न भी है कि क्या हम अपना निजी अस्पताल बनाएँ,

सामुदायिक अस्पतालों के साथ प्रबन्ध कर ले या अपने सदस्यों का ब्लूक्रास बीमा करवा दे ?

सहकारी स्वास्थ्य योजनाएँ जन-समूहों को अपने पारिवारिक स्वास्थ्य से सम्बद्ध अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का स्वयं निर्णय करने की सम्भावनाएँ प्रदान करती हैं जो जनता और जन-स्वास्थ्य दोनों के ही हित में अच्छी बात है।

अब प्रश्न उठते हैं कि यह आन्दोलन कब और कहाँ आरम्भ हुआ, दूसरा फ़ैलाव कितना है, इसने कौन-से रूप ग्रहण किये और इसका भविष्य क्या है ?

इसके आरम्भ को निश्चित तिथि बताना तो मुश्किल ही है। सम्भवतः बेजामिन फ्रैकलिन ने १७५२ में अमरीका में पहली पारस्परिक अग्नि बीमा कम्पनी संगठित कर उसके पालिसीधारियों को आग से अपने स्वास्थ्य का बचाव करने के लिए मिल-जुलकर काम करने को प्रोत्साहित किया था। इस बात के लिए प्रोत्साहित तो उन्होंने अवश्य ही किया था कि अकेले न तो से आग से लड़ सकते हैं, न उसका निवारण कर सकते हैं और न उसके द्वारा की हुई हानि का भुगतान ही; लेकिन अगर मिल-जुलकर जोखिम को फैला ले और संयुक्त रूप से संरक्षण के लिए पैसा दे तो अवश्य ऐसा कर सकते हैं। १८५१ में सैनफ्रांसिस्को में फ्रांसिसी आप्रवासियों ने फ्रेंच म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी (फ्रांसिसी पारस्परिक हित संवर्धन समिति) बनाई, जिसने एक अस्पताल स्थापित किया और पूर्व अदायगी (अग्रिम शुल्क की योजना प्रचलित की। कुछ वर्षों बाद सैनफ्रांसिस्को में जर्मन आप्रवासियों ने और टाम्पा में क्यूबा के स्पेनवासियों ने भी इसी तरह का काम किया। ये सब योजनाएँ अब भी चल रही हैं।

इन सब योजनाओं में एक ही राष्ट्रीयता के कारण सन्निकट आये हुए समान हितों वाले भ्रातृत्वपूर्ण समूह मिल-जुलकर अपने आप के लिए स्वास्थ्य परिचर्या और स्वास्थ्य सुरक्षा क्रय करते हैं।

या सम्भवतः १८८२ में 'नार्दन पैसिफिक बेनिफिशियल एसोसिएशन' द्वारा संस्थापित पहले रेलरोड अस्पताल से ही इस आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ ही। उन रेल श्रमिकों ने रोशडेल बुनकरों का नाम भी नहीं सुना था, फिर भी समूहगत आवश्यकताओं और आर्थिक मोलभाव का सामूहिक शक्ति के बलपर उन्होंने मालिकों से हानिपूर्ति के एक अंश के रूप में अपने लिए अस्पताल

सेवाओं की सुविधा का समझौता किया और उसे प्राप्त भी कर लिया। किसी अकेले रेल मजदूर के लिए यह कदापि सम्भव नहीं था।

१९१३ में इण्डर नेशनल लेडीज गारमेण्ट वर्कर्स यूनियन ने न्यूयार्क सिटी में अपने सदस्यों के लिए अमरीका के इतिहास में सबसे पहला श्रमिक सघ-संचालित स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया। सघ के सदस्यों में से किसी को कोई चल रोग हो जाता तो उन्हीं के धन से इस केन्द्र में बाहरी रोगी के रूप में उनकी परिचर्या की जाती थी। आज यह और ऐसे बीसियों स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

या फिर १९२९ में ओक्लाहोमा के एल्क सिटी में इस आन्दोलन का प्रारम्भ माना जा सकता है। उस समय वही के एक डाक्टर, माइकेल शैडिङ ने वहाँ की चार कठिनाइयों का उपाय सोच निकाला और दूसरों को भी उसी ढंग से उनके निवारण के लिए प्रोत्साहित किया। उनमें से पहली कठिनाई थी पश्चिमी ओक्लाहोमा के किसानों की अत्यधिक गरीबी, वे डाक्टरों का बिल और विशेष रूप में आपत्कालीन डाक्टरी सेवा का बिल तो और भी अधिक, मुश्किल से ही चुका पाते थे। दूसरे, उस क्षेत्र में दूर-दूर तक कोई अस्पताल नहीं था। तीसरे, डाक्टरों को न तो यही भरोसा था कि वहाँ अच्छी आम-दनी हो सकेगी और न यही विश्वास कि जिन अच्छी दवाइयों का ये प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें रोगी ले ही लेंगे। और चौथे यह कि लोग इन कठिनाइयों की ओर से नितान्त उदासीन सब कुछ चुपचाप सह जा रहे थे।

डाक्टर शैडिङ ने सुझाव दिया कि अन्तिम कठिनाई से आरम्भ करके इन चारों पर एक साथ हमला बोलना चाहिए। जिन लोगों को चिकित्सा-परिचर्या की अभी आवश्यकता है या आगे हो सकती है वे सब यदि एक ऐसे सघ का सदस्य बनना स्वीकार कर ले जो व्यवस्थित ढंग से अस्पताल और चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर सके तो अपने अत्यल्प साधनों के बावजूद वे अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। और यदि वे इस उपक्रम को आरम्भ करने के लिए प्रारम्भिक शुल्क देने को प्रस्तुत हो जाएँ और उसके बाद हर महीने केवल अत्यन्त आवश्यक प्रकार की परिचर्या का मूल्य चुकाने भर को डालर देते रहे तो परिचर्या प्रदान करने वाले डाक्टर उनके साथ

आने को राजी हो जाएँगे और उन डाक्टरों को निर्भरता-योग्य आय का कुछ विश्वास भी हो जाएगा। हो सकता है कि वे अपना अस्पताल भी बना ले, जिसके सदस्य ही स्वामी होंगे और जो उस सारे क्षेत्र के लिए चिकित्सा-केन्द्र का काम देगा।

उन्होंने यही किया।

काम अवश्य आसान नहीं था। लेकिन डाक्टर शैडिड ने स्वयं काफी रकम उधार दी और इस तरह अमरीका की पहली सहकारी स्वास्थ्य योजना का, यही उसका नामकरण किया गया, जन्म हुआ। इसका जीवन काफी उथल-पुथल वाला रहा है। एल्क सिटी के कम्युनिटी हास्पिटल क्लिनिक (सामुदायिक अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र) की कुछ बातें आज भी ऐसी हैं जिनकी स्वास्थ्य समस्याओं के विद्यार्थी प्रायः आलोचना करते हैं।

लेकिन एल्क सिटी का सहकारी स्वामित्व वाला, सुयोग्य डाक्टरों से लैस अस्पताल पश्चिमी ओक्लाहोमा के कई जिलों का चिकित्सा-केन्द्र है; और इसके कुछ डाक्टर तो जिला और राज्य की चिकित्सा समितियों के पदाधिकारी भी हैं।

और सबसे बड़ी बात तो यह कि इस अस्पताल ने उस क्षेत्र के बहुत से लोगों को अपने परिवारों की अच्छे ढंग की चिकित्सा-परिचर्या के लिए पैसा खर्च करने का अवसर भी दिया।

इसके बाद ही तरह-तरह की योजनाएँ सभी स्थानों में और सब तरह के लोगों के बीच अस्तित्व में आई और विकसित हुई। उनमें से कुछ तो सभी दृष्टियों से पूर्णतः सहकारी सगठन हैं जैसे कि महानगर की पथ प्रदर्शक योजना—ग्रुप हेल्थ एसोसिएशन आफ वॉशिंगटन (वाशिंगटन डी० सी० का सामूहिक स्वास्थ्य संघ)—और ग्रुप हेल्थ कोओपरेटिव आफ पगेट साउण्ड (पगेट साउण्ड का सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी संघ, (एवं टूहारवर्स,) मिनो-सोटा) का हेल्थ एसोसिएशन सामुदायिक स्वास्थ्य संघ)। इनकी सदस्यता सब के लिए खुली है, जो भी चाहे सदस्य बन सकता है; संचालन और नियन्त्रण, एक व्यक्ति केवल एक ही मत के आधारे पर, सदस्यों के ही हाथ में है; सारी सुविधाओं का स्वामित्व सदस्यों में निहित है; और पूरी योजना

को वास्तव में लाभहीन आधार पर चलाया जाता है। पूरे वर्ष के कारोबार के अन्त में यदि अधिक आय पायी भी गई तो भी सदस्यों को सरक्षण वन वापसो अदायगियाँ नहीं की जाती। स्वास्थ्य योजनाओं में और दूसरे सहकारी उद्यमों में यही मुख्य अन्तर है। रूढ़िगत व्यवसायों में जो लाभ है वह दूसरे सहकारी उद्यमों में सदस्यों और सरक्षक-स्वामियों का प्राप्तव्य है, जिसे वर्ष के अन्त में सरक्षण के अनुपात से उनमें वितरित कर दिया जाता है। लेकिन, नैतिक दृष्टि से, स्वास्थ्य योजना को तो किसी के भी यहाँ तक कि सदस्यों के भी लाभार्जन के लिए नहीं चलाया जा सकता। यदि अधिक आय होती भी है तो या तो सदस्यों में लिया जानेवाला मासिक गुल्क घटा दिया जाता है, या डाक्टरों और अन्य सेवा-नियुक्त कर्मचारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि कर दी जाती है, या फिर उस राशि को भवननिधि में जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि कर दी जाती है, या फिर उस राशि को भवननिधि में नया कक्ष बनाने के लिए जमा कर दिया जाता है।

इन 'विशुद्ध' सहकारी योजनाओं के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की दूसरी योजनाएँ भी हैं, लेकिन दो बुनियादी विशेषताएँ उन सभी में समान रूप से पायी जाती हैं। एक तो यह कि उन सभी योजनाओं में लोगों का एक समूह स्वास्थ्य-परिचर्या को अपनी आवश्यकता के निकाय का, और रोगी निरोग दोनों से एक-सी राशि के आधार पर, समूह के रूप में धन देने का और चिकित्सकों के दल एवं अन्य पेशेवर तथा गैर-पेशेवर कार्यकर्ताओं से, जो उनके लिए अपेक्षित स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कर सके, व्यवस्था करने का फैसला किये रहता है। दूसरे यह कि ये सभी सामूहिक स्वास्थ्य योजनाएँ व्यक्तिगत विचार-परम्परा पर आधारित होती हैं, जो सार रूप में इस प्रकार हैं :

(१) आज औसत अमरीकी परिवार के समक्ष परमाणु युद्ध के खतरे के अतिरिक्त स्वास्थ्य का आर्थिक पक्ष ही वास्तव में सबसे गम्भीर समस्या है। यह कुछ तो इसलिए है कि बीमारी से कष्ट और पीड़ा होती है, और कुछ इसलिए भी कि पर्याप्त स्वास्थ्य-परिचर्या का मूल्य एक तो पहले से मालूम नहीं हो पाता और फिर बड़ी तेजी से बढ़ता भी रहता है।

(२) लेकिन यदि परिवारों को उचित समय उचित प्रकार की चिकित्सा-परिचर्या, जिसमें निरोधिक परिचर्या भी सम्मिलित है, उपलब्ध हो सके तो अधिकांश बीमारियों की रोक-थाम की जा सकती है। और यदि परिवार स्वास्थ्य परिचर्या के लिए हर महीने छ या हर हफ्ते निर्धारित किस्त अग्रिम जमा करवा सके या जैसा कि अर्थशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली में कहेंगे 'वजारत आवर्ती पूर्व अदायगी' के आधार पर पैसा दे सके तो बीमारी के अधिकांश आर्थिक दुष्परिणामों को टाला भी जा सकता है।

(३) पारिवारिक डाक्टर के शुल्क के अतिरिक्त आपत्कालीन मामलों में या कठिनाई के समय बुलाये गए विशेषज्ञों की फीस शायद ही कोई परिवार दे सकता है। वास्तव में औसत परिवार डाक्टरों के चुनिन्दा दल का सामूहिक प्रैक्टिस के सिवाय चिकित्सा-सेवा में विशेषज्ञता से लाभान्वित हो ही नहीं सकता।

(४) सेवा के लिए आयातित शुल्क के आधार पर पैसा देने की कोशिश करके भी औसत परिवार को आधुनिक चिकित्सा-परिचर्या उपलब्ध नहीं हो सकती; क्योंकि एक तो इस प्रणाली में मूल्य नियन्त्रित नहीं होते और दूसरे, न यही पहले से बताया जा सकता है कि कितना मूल्य देना होगा। परिणाम स्वरूप औसतन काफी पैसा खर्च करके भी आज लोगों को पर्याप्त चिकित्सा-परिचर्या उपलब्ध नहीं हो पाती।

(५) बीमार पड़ने पर अमरीकी जनता आयातित चिकित्सा परिचर्या के लिए इतना अधिक पैसा देती है कि यदि सही ढंग से खर्च किया जाए तो उस रकम से उन्हें स्वस्थ बनाये रखने वाली व्यापक परिचर्या बड़ी आसानी से मिल सकती है। राष्ट्र की स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में नियुक्त राष्ट्रपति के आयोग ने और अन्य विश्वसनीय अधिकारियों ने जो आँकड़े निकाले हैं उनसे पता चलता है कि हम अपनी आय का ५ प्रतिशत चिकित्सा-परिचर्या पर खर्च करते हैं। अमरीका की औसत पारिवारिक आय पाँच हजार डालर प्रतिवर्ष है; इसका ५ प्रतिशत २५० डालर होता है।

(६) पूर्व अदायगी की पद्धति सारी समस्या का सीधा-सा समाधान है। इस पद्धति के अन्तर्गत लोग प्रतिमास एक निर्धारित धन राशि जमा कर-

वाते रहते हैं, जिसके बदले में जब भी आवश्यक हो उन्हें चिकित्सा-परिचर्या उपलब्ध हो सके। और एक परिवार से प्रति वर्ष २५० डालर इतनी बड़ी रकम है कि यदि उसे चुने हुए डाक्टरों को 'सामूहिक प्रैक्टिस वाली पूर्व अदायगी स्वास्थ्य योजना' के अन्तर्गत अच्छे ढंग से खर्च किया जाए तो परिवारों को सम्पूर्ण और व्यापक चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध हो सकती है।

(७) अस्पताल परिचर्या के लिए पूर्व अदायगी अच्छी बात है; लेकिन समय पर स्वास्थ्य की जाँच-पड़ताल और निरोधक उपायों वाली सेवाओं के लिए पूर्व अदायगी और भी अच्छी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसा करने से अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आती। दूसरे शब्दों में यह कि हमें आवश्यकता है व्यापक परिचर्या के लिए पूर्व अदायगी की, जो लोगों को अस्पताल में दूर रखती और इस तरह चिकित्सा-परिचर्या का मूल्य भी कम करती है। हमें अपने डाक्टरों को निरोधक औषधियाँ का प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए और इसके लिए उनसे समय-समय पर मिलते रहना, बीच-बीच में अपने स्वास्थ्य की जाँच-पड़ताल करवाते रहना और साधारण तथा गम्भीर, सभी प्रकार के लक्षणों के सम्बन्ध में उनकी सलाह लेते रहना बहुत जरूरी है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब इस तरह की सेवाओं के लिए किसी सामूहिक स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत हमने पहले से पैसा दिया हो।

(८) काफी सख्या में सभी तरह के लोगों के सम्मिलित हुए बिना इस तरह की योजना न तो बन सकती है और न कार्यान्वित ही की जा सकती है। कोई भी योजना सफल कैसे हो सकती है ? यदि उसमें चन्दा देने वाले सभी लोग तत्काल चिकित्सा सेवा पाने वाले ही हों। इसलिए ऐसी योजनाओं में स्वस्थ लोगों को भी काफी सख्या में सम्मिलित करना चाहिए।

(९) लोकतन्त्र में लोगों का आवश्यकता से अधिक सरकार पर निर्भर करना कदापि उचित नहीं; अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें स्वतः प्रेरणा को विकसित करना और उसी पर निर्भर करना चाहिए। अपने लिए काम करना वैसे भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए चिकित्सा परिचर्या के आर्थिक पहलुओं, उसके मूल्यों और अदायगी के तौर-तरीकों पर उपभोक्ता का कुछ-न-कुछ नियन्त्रण और उपभोक्ता पर इन सब की कुछ जिम्मेवारी लोक-

तन्त्र का एक अच्छा ढग है।

(१०) डाक्टरों की सामूहिक प्रैक्टिस, पूर्वं अदायगी, व्यापक परिचर्या, जोखिम का बराबर-बराबर बँटवारा और उपभोक्ता के स्वतः प्रेरणा को मिला कर सामूहिक-स्वास्थ्य-पूर्व अदायगी-योजना बनाई जाए तो चिकित्सा-सम्बन्धी आर्थिक समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है और इस तरह आधुनिक चिकित्सा से छोटे समुदायो एवं सामान्य आय वाले परिवारों को भी लाभान्वित किया जा सकता है।

कुछ लोग और उनके डाक्टर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहकारी ढग से काम करने को कैसे प्रवृत्त हुए इसकी कहानी सघर्ष, अन्तर्विरोध, सन्देह, निराशा और क्रमशः अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते जाने की कहानी है।

ओक्लाहोमा के निवासियों ने जो कुछ किया उसके समाचार शीघ्र ही मन्दोग्रस्त देश में चारों ओर फैल गए। अब जो दूसरी महत्त्वपूर्ण योजना बनी वह थो वाशिंगटन डी० सी० का सामूहिक स्वास्थ्य सघ (Group Health Association of Washington DC)। सरकारी कर्मचारियों के एक समूह ने १९३७ में इसकी स्थापना की। आरम्भ से ही यह सघ सभी दृष्टियों से पूरी तरह सहकारी रहा है। कोई भी इस योजना का सदस्य बन सकता है। नियन्त्रण सदस्यों का ही है और एक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार है। सदस्य ही इसकी समस्त साधन-सामग्री और सम्पत्ति के स्वामी हैं और इसके संचालक-मण्डल का चुनाव भी वे ही करते हैं। १९६० में, साधारण और विशेषज्ञ डाक्टरों के इसके विशाल और सुयोग्य चिकित्सक दल ने वाशिंगटन क्षेत्र के लगभग ४५ हजार लोगों को चिकित्सा-परिचर्या प्रदान की। इसमें विशाल ट्राजिट वर्क्स यूनियन के सदस्य भी सम्मिलित हैं, जिन पर १९५९ में काफी विचार-विनिमय के बाद इस योजना को लागू किया गया। बड़ी हुई सदस्य संख्या की समुचित देख-भाल के लिए इस यूनियन ने वाशिंगटन सामूहिक स्वास्थ्य सघ की शाखा के रूप में एक नये स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण भी कर दिया है।

इस स्वास्थ्य सघ को सघर्ष भी कई करने पड़े। आरम्भ के वर्षों में चिकित्सा समिति ने इस योजना से सम्बद्ध डाक्टरों के नाम वर्ज्य सूची में डाल दिये और

सामूहिक स्वास्थ्य सघ के डाक्टरों और रोगियों को अपने अस्पतालों का उपयोग करने से रोक दिया। पाँच वर्ष तक मुकदमा चलता रहा। अन्त में संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से चिकित्सा समिति के एकाधिकारी व्यवहारों को रोका गया, सामूहिक स्वास्थ्य सघ के डाक्टरों के लिए चिकित्सा समिति की सदस्यता फिर से खोल दी गई और अस्पतालों के उपयोग की सुविधा पुनः प्रचलित कर दी गई। यह फैसला १९४३ में हुआ और एक अच्छी मजोर बन गया। सामूहिक स्वास्थ्य योजनाओं को 'संगठित चिकित्सा' द्वारा अपने डाक्टरों के साथ भेदभाव करने पर जब भी न्यायालयों में जाना पड़ता है तो १९४३ में हुए उक्त फैसले के उदाहरण स्वरूप उनकी बराबर जीत ही होती है।

१९४१ से प्रारम्भ होने वाली शताब्दी में ग्रेट प्लैन्स के दर्जनों छोटे-छोटे देहाती कस्बों के निवासियों ने अपने-अपने सहकारी अस्पताल सघ बनाये। इनमें से कईयों ने तो वास्तव में बहुत सारे अस्पताल बना भी डाले और वेस्ट टेक्सास जैसे कुछ क्षेत्रों में तो सबसे अधिक अस्पताल बनाये गए। कहीं-कहीं पूर्व अदायगी योजनाएँ भी शुरू की गईं। लेकिन मामिक चन्दा प्रायः सर्वत्र बहुत ही कम रखा गया। जो संधन-सुविधाएँ जुटाई गईं वे अक्सर बहुत अच्छी बनी हुई और सुनियोजित भी नहीं थी। चिकित्सा समिति के विरोध के कारण बहुत से डाक्टर डर कर भाग गए। परिणाम यह हुआ कि इनमें से अधिकांश अस्पतालों को सामुदायिक स्वामित्व का रूप दे देना पड़ा, अधिकांश पूर्व अदायगी योजनाओं को बन्द कर देना पड़ा और केवल अस्पताल की इमारतें ही सद्प्रयत्नों के स्मारक के रूप में बची रह गईं, यह कहने के लिए कि जो प्रयत्न किये गए उनमें जल्दबाजी की मात्रा बहुत ही अधिक और दूर-दर्शिता एवं योजनाबद्धता की मात्रा बहुत ही थोड़ी थी।

इस प्रकार एल्क सिटी और वाशिंगटन डी० सी० के अतिरिक्त सहकारी स्वास्थ्य योजनाओं का सारा ही विकास द्वितीय महायुद्ध के काल में ही हुआ है। यह बिल्कुल नया आन्दोलन है और इसका जन्म हुआ है अमरीकी जनता की निरन्तर बढ़ती हुई स्वास्थ्य चेतना और उनके इस अभिज्ञान के फल-स्वरूप कि चिकित्सा परिचर्या की लगातार मूल्य-वृद्धि उनकी सबसे बड़ी और

पहले नम्बर की आर्थिक विपत्ति है। पाँच लाख अमरीकी परिवारों पर प्रति वर्ष चिकित्सा-बिलों का जितना बोझा पड़ता है वह उनकी सम्पूर्ण वार्षिक आय के बराबर हो जाता है। दस लाख परिवारों पर उनकी वार्षिक आमदनी की आधी रकम के बराबर चिकित्सा-व्यय का कर्ज हो जाता है। लाखों लोगो ने ब्लूशिल्ड, ब्लूक्रास और व्यापारी कम्पनियों के अन्तर्गत किसी-न-किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है। १९५८ तक अमरीका की लगभग तीन-चौथाई जन सख्या किसी-न-सिकी प्रकार के स्वास्थ्य-बीमा से रक्षित हो चुकी थी।

लेकिन इस प्रकार के बीमों की कुल अदायगियाँ तो स्वास्थ्य बीमा करवा कर 'अपने को रक्षित' समझने वाले अमरीकी परिवारों के चिकित्सा बिलों के चतुर्थांश के लिए भी पर्याप्त नहीं होती। कुछ भी न होने से तो यह अवश्य ही अच्छा है। लेकिन यह कुछ बहुत अच्छा सरक्षण तो है नहीं और न स्वास्थ्य को उन्नत करने की दिशा में ही इससे कुछ हो पाता है। दूसरी ओर जो परिवार सहकारी ढंग की सामूहिक-प्रीविटस वाली-पूर्व अदायगी-स्वास्थ्य योजनाओं के सदस्य हैं उन्हें सरक्षण का लाभ नकद अदायगियों में नहीं डाक्टरों और नर्सों की परिचर्या के रूप में प्राप्त होता है; और प्रयत्न किया जाता है कि वह परिचर्या ज्यादा-से-ज्यादा प्रकार की बीमारियों के लिए और रोग-निवारण के अधिक-से-अधिक उपायों वाली भी हो।

१९४४ में मिनेसोटा के टूहारबर्स नामक छोटे से नगर में मुख्यतः रेल-भागों और इस्पात श्रमिकों ने मिल कर एक सहकारी योजना आरम्भ की। इस योजना ने नगर के एकमात्र अस्पताल को बन्द होने से बचा लिया, नगर के तीन-चौथाई परिवारों को अपना सदस्य बनाया, कई साहसी डाक्टरों को जन-परिचर्या के लिए आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की और अन्त में, १९५६ में अपने डाक्टरों के लिए चिकित्सा समिति की सदस्यता के रूप में मान्यता भी प्राप्त कर ली।

१९४५ में सेंट लुई में लेबर हेल्थ इंस्टीट्यूट श्रमिक स्वास्थ्य सस्था (Labor Health Institute) बनाई गई। यह सस्था केवल एक स्थानीय श्रमिक सघ के सदस्यों और उनके परिवारों तक ही सीमित थी और आज सारे संयुक्त

राज्य को किसी भी श्रमिक प्रायोजित योजना से सम्बद्ध अपने १५,००० सदस्यों को व्यापकतम परिचर्या प्रदान करती है। मालिक स्वास्थ्य और कल्याण-निधि में जो अशदान करते हैं उससे इस योजना को चलाया जाता है। इस सस्था के सदस्यों का अस्पताल के विलो का खर्च ब्लू क्रॉस बीमा करवाने के खर्च में कहीं कम होता है, क्योंकि सस्था का यह अनुभव है कि आवश्यकता पड़ते ही चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध हो जाने वालों को दूसरों की अपेक्षा कम बार अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है।

यदि गम्भीरता से विचार किया जाए तो यह बात आश्चर्यजनक नहीं, उचित ही प्रतीत होगी।

१९४६ में युनाइटेड माइन वर्कर्स वेलफेयर एण्ड रिटायरमेंट फण्ड (सयुक्त खनि श्रमिक कल्याण एवं निवृत्ति निधि (United Mine Workers Welfare and Retirement Fund) को खान से निकाले गये प्रतिटन कोयले पर ४० सेंट मिलने लगा। निधि में यह अशदान मालिकों की ओर से किया जाता था और आज भी किया जाता है। लेकिन कोयला खोद कर निकालते तो मजदूर ही हैं। खनिकों एवं उनके आश्रितों को उच्च कोटि की चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने एवं निधि के धन का दुरुपयोग रोकने के बारे में अनेक प्रकार से आश्वासन दिये गए। अन्त में यही उपाय ठीक समझा गया कि निधि में काम करने के लिए ऐसे ही डाक्टरों का चुनाव किया जाए जो भले, निर्भरता योग्य और शुद्ध अन्तःकरण वाले हों, लापरवाह और काम करने में अक्षम बूढ़ों को छोड़ दिया जाए। निधि के इस सही निर्णय ने बहुत से राज्यों की चिकित्सा समितियों में खलबली मचा दी। कुछ राज्यों की विधान सभाओं ने तो ऐसे कानून बनाने की धमकियाँ दे डाली कि यदि कोई डाक्टर खनिकों की परिचर्या करेगा और निधि से इस काम का पैसा लेगा तो उसे जेल में बन्द कर दिया जाएगा।

लेकिन न तो ऐसा कानून बना और न बनने की सम्भावना ही है।

इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि खनिक निधि ने देश के उन हिस्सों में जहाँ चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएँ बहुत कम या नहीं के ही बराबर थी, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी प्रशसनीय काम किया है। आपला-

चियान (Appalachian) के पहाड़ी प्रदेश में जहाँ पहले एक भी अच्छा अस्पताल नहीं था निधि ने दस बड़े ही खूबसूरत बढ़िया अस्पताल निर्मित किया।

१९४७ बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष था। उसी वर्ष (हेल्थ इन्श्योरेंस प्लान आफ ग्रेटर न्यूयार्क (वृहत्तर न्यूयार्क की स्वास्थ्य बीमा योजना, Health Insurance Plan of Greater New York) ने, जिसे अंग्रेजी में 'हिप' (HIP) भी कहते हैं, अपने सदस्यों की सेवा प्रारम्भ की। और उसी वर्ष महःद्वीप से उस ओर पगेट साउण्ड में ग्रूप हेल्थ कोऑपरेटिव्स (सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी) योजना शुरू की गई। आज ये दोनों ही योजनाएँ अपने-अपने क्षेत्र की लग-भग ५ प्रतिशत जनता को व्यापक चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर रही हैं।

सीटल योजना भी वार्शिंगटन के सामूहिक स्वास्थ्य संगठन की ही तरह एक सच्चा सहकारी उद्यम है। इसके स्वास्थ्य केन्द्र और एक बढ़िया नया अस्पताल भी हैं और इनमें अधिकतर पूँजी सदस्यों की ही लगी हुई है।

न्यूयार्क की योजना 'हिप' वृहत्तर न्यूयार्क के सारे क्षेत्र में अपने पाँच लाख से भी अधिक सदस्यों को अपेक्षित सेवाएँ प्रदान करने के लिए डाक्टरों के समूहों से करार करती है। इन डाक्टर-समूहों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाता है:—समूह-विशेष को चुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रति वर्ष इतने डालर !

जैसे-जैसे समय बीतता गया अधिकांश दूरदर्शी श्रमिक संघ स्वास्थ्य केन्द्रों की सख्या में अभिवृद्धि करते गए, जिससे उनके सदस्यों का वहाँ रोग-निदान और मामूली किस्म के चल रोगों की परिचर्या की जा सके।

१९५१ में फिलाडेल्फिया का अमरीकी श्रमिकों के महासंघ की चिकित्सा सेवा योजना ने (American Federation of Labor Medical Service Plan of Philadelphia) उस बाधा को तोड़ दिया जो श्रमिक संघों की स्वास्थ्य योजनाओं को एक ही श्रमिक संघ के सदस्यों तक सीमित करने-वाली थी। इस योजना को प्रारम्भ ही इसलिए किया गया था कि इसमें हिस्सा लेने वाली किसी भी स्थानीय यूनियन की सेवा की जा सके। पहले आठ वर्षों के कार्यकाल के अन्त में इस योजना से तीस से भी अधिक स्थानीय श्रमिक संघ और कोई ६० हजार लोग परिचर्या प्राप्त कर रहे थे। और

१९५५-५६ के आस-पास इसी से मिलती-जुलती एक योजना श्रमिक सघ स्वास्थ्य सेवाएँ (Union Health Services Inc.) शिकागो में आरम्भ की गई।

यह पुस्तक लिखी जा रही थी उस समय (१९६१) डेट्रोइट के प्रमुख नागरिकों का एक समूह मुख्यतः युनाइटेड आटो मोबाइल श्रमिकों पर निर्भर करते हुए एक ऐसी समुदाय-व्यापी पूर्व अदायगी स्वास्थ्य योजना बनाने का प्रयत्न कर रहा था जिसमें डाक्टरों के कई समूहों की सेवाओं का और विद्यमान अस्पतालों का उपयोग किया जा सके।

१९६० तक संयुक्त राज्य के पचास लाख से भी अधिक लोगों ने सह-कारिता के मोटे-मोटे तरीकों को अपना कर अपने स्वास्थ्य से सम्बन्धित आर्थिक समस्याओं को काफी हद तक हल कर लिया था।

इनमें की कोई भी दो योजनाएँ एक-जैसी नहीं हैं। कुछ की खुली सदस्यता है: व्यक्ति, परिवार अथवा समूह, सब के लिए। कुछ की सदस्यता सीमित है, उनकी सेवाएँ केवल किसी एक ही स्थानीय श्रमिक सघ के सदस्यों को उपलब्ध हैं। अधिकांश तो सेवा-मुविधाएँ ही प्रदान करती हैं, जैसे कि निदान, चिकित्सा, सुश्रूषा, निरोध-निवारण आदि; लेकिन दो-एक ऐसी भी हैं जो सेवाओं के बदले क्षतिपूर्ति की नकद रकमे देती हैं—डाक्टरों से इनका यह समझौता रहता है कि वे क्षतिपूर्ति रकमे को अपनी सेवाओं के पारिश्रमिक की पूरी अदायगी समझ कर स्वीकार कर ले। कुछ ऐसी हैं जिनकी परिचर्या में कई रोगों का समावेश नहीं होता, तो कई ऐसी हैं जो अपने सदस्यों अथवा ग्राहकों की चिकित्सा-सम्बन्धी हर आवश्यकता को पूरा करती हैं। कुछ का नियन्त्रण उनके सदस्यों द्वारा जनतन्त्रात्मक ढंग से होता है; कुछ का नियन्त्रण संचालक मण्डल करते हैं, जो सदस्यों के प्रतिनिधि तो होते हैं, परन्तु उनके द्वारा निर्वाचित नहीं; और कुछ ऐसी भी हैं जिनका कार्य-संचालन और नियन्त्रण श्रमिक सघों की स्वास्थ्य एवं कल्याण निधि के व्यासधारियों द्वारा किया जाता है।

कुछ थोड़ी-सी डाक्टरों के समूहों द्वारा नियन्त्रित और उन्हीं के स्वामीत्व में 'उत्पादक ढंग की सहकारी योजनाएँ' हैं। कुछ को ऐसे लोक-समूहों ने आरम्भ

किया जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता थी, कुछ श्रमिक सघों के पदाधिकारियों द्वारा शुरू की गई, कुछेक को सार्वजनिक कार्यवर्तियों ने, और कुछ को केवल डाक्टरों ने ही आरम्भ किया। लेकिन कोई भी सरक्षण-धन वापसी की अदायगी नहीं करता।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'सहकारी स्वास्थ्य योजनाएँ' सहकारी शब्द के सही अर्थ में तो पूरी तरह सहकारी नहीं ही हैं। कुछ हैं तो खुली सदस्यता वाले सहकारी सिद्धान्त की अवहेलना करती हैं, कुछ जनवादी नियन्त्रण के सिद्धान्त को भग करती हैं; और सरक्षण धन वापसी वाली कसौटी पर तो एक भी खरो नहीं उतरती।

लेकिन मूलतः अपने सारभूत रूप में वे सभी निस्सन्देह सहकारी ही हैं, क्योंकि उन सभी में सहकारिता की एक अत्यन्त आवश्यक विशेषता सदैव ही विद्यमान रहती है।

वे ऐसे उत्तम हैं जिनके स्वामी ही उनको सेवाओं के उपभोक्ता भी हैं। इसलिए वे उद्यम न तो किसी व्यक्ति-विशेष के और न उस उद्यम के ही आर्थिक लाभ के लिए होते हैं। वे होते हैं एक जन-समूह की, कहना चाहिए कि अपने स्वामियों की न्यूनतम शुद्ध मूल्यों पर, जो व्यावहारिक भी हैं, सेवा-यहाँ अभिप्राय है स्वास्थ्य-सेवा करने के लिए। और वे हैं पारस्परिक सहायता की परिकल्पना और सिद्धान्त को आचरण द्वारा अभिव्यक्त करने वाले ठोस, मूर्त रूप।

एक प्रकार से तो वे उक्त सिद्धान्त की सर्वाधिक प्रभावशाली अभिव्यक्तियाँ हैं; क्योंकि किसी भी सामूहिक स्वास्थ्य योजना की सफलता अनिवार्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी निधि में पैसा देने वाले स्वस्थ लोग भी काफी संख्या में रहे, जिससे उनके रोग ग्रस्त साथी सदस्यों की परिचर्या का मूल्य चुकाया जा सके।

और यदि थोड़ा विचार किया जाए तो पता चलेगा कि यह विचार कितना श्रेष्ठ और कितना उदात्त है।

संक्षेप में यह कि इन योजनाओं के द्वारा एक परिवार अपना पैसा बीमारी को अच्छा करने के बजाय बीमारी से बचने और स्वास्थ्य को अच्छा बनाये

रखने में खर्च कर सकता है। इन योजनाओं का उद्देश्य ही होता है ऐसे निरोधक उपायों को व्यवहार में लाना जिससे लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत ही न पड़े; यह तो कदापि नहीं कि वे अस्पताल जाते रहे और वहाँ के बिलों का भुगतान करते रहे। पिछले तीस वर्षों में केवल अस्पताल के ही नहीं सामान्यतः स्वास्थ्य-चिकित्सा-सम्बन्धी सभी वस्तुओं के मूल्यों में लगभग तीन गुनी वृद्धि हुई है, इसलिए स्वास्थ्य-परिचर्या पर पारिवारिक व्यय को कम करने का सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है कि लोगों को यथा सम्भव अस्पताल से दूर रखा जाए—किसी के वहाँ जाने की नौबत ही न आने पाए।

लेकिन अधिकांश व्यावसायिक बीमा योजनाएँ, यहाँ तक कि ब्लू क्रॉस और ब्लू शील्ड भी, लोगों को अस्पताल जाने के लिए सचमुच प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि अनेक मामलों में उन्हें अपने बीमा से पैसा तभी मिलता है जब वे अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं।

सहकारी ढंग का स्वास्थ्य योजनाओं की कार्य-पद्धति इसकी ठीक उलटी है। वे चूँकि पैसा नहीं देती, जब, जहाँ और जैसी आवश्यकता हो उसी के अनुसार चिकित्सा-परिचर्या प्रदान करती हैं, इसलिए उनके ये प्रयत्न अत्यन्त स्वाभाविक ही हैं कि एक तो वे अपने ग्राहकों को जितना भी हो सके भला-चगा रखें; दूसरे, उन्हें अस्पताल में भर्ती किये बिना ही श्रेष्ठ डाक्टरों की सहायता द्वारा जितना सम्भव है अधिक-से-अधिक और अच्छी-से-अच्छी परिचर्या प्रदान करें; और सबसे अधिक तो यह कि उनके स्वास्थ्य का संरक्षण करके गम्भीर रोगों का निवारण करें।

और इस सम्बन्ध में तथ्यों का जादू तो और भी सर पर चढ़ कर बोलता है। १९५६ में देश व्यापी पैमाने पर ब्लू क्रॉस के प्रति हजार बीमाधारी ग्राहकों ने औसत ९९५ दिन अस्पताल-परिचर्या का उपयोग किया। मिचिगन में यह संख्या प्रति हजार बीमाधारी ११०० दिन थी। लेकिन इसके विपरीत पगेट साउण्ड के सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी के सदस्यों को प्रति हजार सदस्य केवल ५६२ दिन अस्पताल परिचर्या की आवश्यकता हुई; और वाशिंगटन डी० सी० के सामूहिक स्वास्थ्य संघ में तो सिर्फ ५४६ दिन। न्यूयार्क सिटी में ब्लू शील्ड के प्रति १०० ग्राहकों में से औसत १० को प्रति वर्ष अस्प-

ताल में भर्ती होना पड़ता है जबकि वृहत्तर न्यूयार्क की स्वास्थ्य बीमा योजना के ग्राहकों का यह औसत केवल ८ प्रतिशत ही है।

इतना ही नहीं, ये योजनाएँ दूसरे ढंग से मूल्यों का नियन्त्रण भी करती हैं। उदाहरणार्थ अस्पताल परिचर्या के कुल बिल का २१ प्रतिशत तो दवाइयों का मूल्य ही होता है और इस अनुपात में निरन्तर वृद्धि होती जा रहा है। फिर बिल की दूसरी भी बहुत-सी कीमतें जबरदस्ती बढ़ा-चढ़ा कर लिखा जाती हैं, जो सरासर ज्यादाती हैं और जिसे जबरिया बसूली ही समझना चाहिए, क्योंकि उन वृद्धियों का दवाइयों अथवा कर्मचारियों की श्रेष्ठता अथवा सेवा के विस्तार और उन्नति से रच-मात्र भी सम्बन्ध नहीं होता।

इन दवाइयों की कीमत इतनी अधिक तो कदापि नहीं होनी चाहिए जितनी कि लगाई जाती है; और यह बात अमरीकी सीनेट की कैफ़ेयर समिति के समक्ष १९५९ और १९६० में दिये गए बयानों से बहुत ही अच्छी तरह सिद्ध भी हो चुकी है।

सहकारी स्वास्थ्य योजनाएँ इस सम्बन्ध में बहुत-कुछ कर सकती हैं। उदाहरणार्थ, पगेट साउण्ड की सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी का अपना ही औषधालय (फारमेसी) है। इस औषधशाला ने १९५८ में जितने नुसखे बनाये उनका औसत मूल्य प्रति नुसखा १.१५ डालर हुआ, जब कि राष्ट्रीय औसत मूल्य २.६२ डालर था। इस प्रकार इस सहकारी के सदस्यों को दवा-दारू पर लगभग आधे की बचत हुई, जो उन्हें इस व्यवस्था के न होने पर दूसरी जगह अवश्य ही देनी पड़ती। अपने लिए नुसखे बनाने का व्यवसाय आरम्भ करने का निर्णय करके ही वे यह सारी बचत कर सके।

उतने ही मूल्य की दवाई के यदि देने दाम देने पड़े तो वह सारी अतिरिक्त रकम निरोधक परिचर्या, पुनर्वास सेवाओं, दन्त चिकित्सा, मनोरोग चिकित्सा आदि के विस्तार अथवा विकास पर या लोगों की स्वास्थ्योन्नति के दूसरे किसी भी काम में खर्च करने के लिए उपलब्ध हो जाती है।

एक बुधवार के दिन तीसरे पहर शहर के सम्पन्न उपनगर में किसी महिला का हाथ डिब्बे का ढक्कन काटते समय बुरी तरह से कट गया। उन्होंने डाक्टर को बुलाने का प्रयत्न किया। सम्भ्रान्तों की उस बस्ती में डाक्टरों की

कमी नहीं थी। सारे देश की तरह वहाँ भी डाक्टरों का औसत प्रति व्यक्ति दो डाक्टर था। लेकिन बुधवार को डाक्टर लोग छुट्टी रखते और गोल्फ खेलने चले जाते हैं। पीड़ित महिला को बड़े प्रयत्नों के बाद एक डाक्टर के सचिव से टेलीफोन पर सम्पर्क हो पाया। उसने सलाह दी कि वे दस मील दूर दूसरे उपनगर में अपनी मोटर से चली जाएँ; वहाँ एक अस्पताल है और सम्भवतः बुधवार की शाम को भी कोई-न-कोई चिकित्सा कर्मचारी उन्हें वहाँ मिल जाएगा।

यदि वे महिला दूहार वर्स, (मीथ्रोसोटा) के कम आय वाले समुदाय के साथ निवास करती होती तो उन्हें अपने लहू-लुहान हाथ को लिये मोटर चलाकर दस मील न जाना पड़ता। बहुत अधिक सम्भावना तो इसी बात की थी कि उनका परिवार दूहार वर्स की सामुदायिक स्वास्थ्य योजना का सदस्य स्वामी होता। लेकिन वे सदस्य भी न होती तो भी सहकारी चिकित्सालय को टेलीफोन कर सकती थी और उन्हें कोई-न-कोई डाक्टर बुधवार के दिन भी ड्यूटी पर या टेलीफोन पर अवश्य मिल जाता।

क्योंकि जहाँ भी इस तरह की योजना प्रचलित होती है साल के हर दिन चौबीसों घण्टे कोई-न-कोई डाक्टर ड्यूटी पर रहता ही है।

कितना बड़ा अन्तर है? सम्पन्न उपनगरों में सेबालो शुल्क दो, आपात चिकित्सा, हर डाक्टर और हर रोगी अपने-अपने भरोसे वाली बड़ी पुरानी पद्धति अभी तक चली आ रही है। इसके विपरीत लेकर सुपीरियर के बोरान किनारों पर बसे रेलरोड ओर इस्पात श्रमिकों के अपेक्षाकृत विपन्न नगर में चिकित्सा परिचर्या पर खर्च किये गए थोड़े से डालरों से लोगों के लिए अधिक अच्छी और अधिक निर्भरता योग्य चिकित्सा परिचर्या क्रय की जाती है।

इसका कारण यही है कि लोगों ने पारस्परिक सहायता के—अपनी ही स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अपनी ही स्वास्थ्य परिचर्या पर मिल-जुल कर खर्च करने के महत्त्व की समझा ही नहीं है अजमा कर देख भी लिया है।

स्वास्थ्य सूचना प्रतिष्ठान (Health Information Foundation) की सूचना के अनुसार १९५८ में निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर औसत पारिवारिक

खर्च २९४ डालर था। इतनी रकम खर्च करके भी अधिकांश परिवारों को केवल मध्यम कोटि की ही स्वास्थ्य परिचर्या मिल रही थी। वे यह सारी रकम आयाती आधार पर चुका रहे थे—प्रायः बहुत अधिक बीमार हो जाने के बाद ही, जब डाक्टर के पास गये बिना कोई चारा नहीं रह जाता।

लेकिन २८० डालर कम नहीं होते। इतनी रकम में तो देश की किसी भी श्रेष्ठतम और अत्यधिक व्यापक किस्म की सहकारी स्वास्थ्य योजना की वार्षिक सहायता का पूरा चन्दा बड़े मजे में दिया जा सकता है। कुछ योजनाओं का चन्दा तो २८० डालर से भी कम है। हाँ, कुछ का अधिक भी है।

अमरीकी जनता के काफी बड़े हिस्से को अधिक अच्छे प्रकार की स्वास्थ्य-परिचर्या मिल सके और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चमत्कारी लाभ उन्हें सुलभ किये जा सके इस के लिए न तो अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है और न सरकार के द्वारा कानून ही बनाये जाने का।

वास्तव में इसके लिए आवश्यकता है लोगों के समझदार और दूरदर्शी होने की, उनके द्वारा सामूदायिक विचार और दृष्टिकोण के अपनाये जाने की एवं अपनी स्वास्थ्य-परिचर्या-सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा उनका मूल्य चुकाने के लिए अपने रूपयों का मिल-जुलकर निकाय करने की।

उन चिकित्सा चमत्कारों को बहुजन सुलभ बनाने के लिए वास्तव में आवश्यकता है हम में से अधिकाधिक लोगों द्वारा उस हेतु को आधुनिक ढंग से अपने आचरण में उतार लेने की, जिससे अनुप्राणित होकर पुरोगामी महिला पड़ोसी की झोंपड़ी में बीमार बच्चे की सुश्रूषा के लिए पहुँच जाया करती थी।

ठीक इन्हीं उद्देश्यों को कार्यान्वित करने वाला एक राष्ट्रीय संगठन भी है। उसका नाम है अमरीकी सामूहिक स्वास्थ्य सघ (Group Health Association of America)। देश की बड़ी-बड़ी सहकारी, सामूदायिक और श्रमिक स्वास्थ्य योजनाएँ इस सघ की सदस्य हैं। सघ का कार्यक्रम है सामूहिक प्रैक्टिस, पूर्व अदायगी, व्यापक रूप की तात्कालिक सेवा-परिचर्या और उपभोक्ता के स्वतः प्रेरणा को प्रोत्साहित करना। इसीलिए अमरीकी सामूहिक स्वास्थ्य सघ की प्रगति ही वह पैमाना है जिससे अमरीका को अधिक स्वस्थ बनाने की दिशा में उठाये गए इन सुविचारित कदमों की प्रगति को नापा जा सकेगा।

विशाल जन-सहायता वाला यह संगठन ही १९५९ से चिकित्सा परिचर्या के उप-भोक्ताओं का प्रमुख, एक मात्र कहना ज्यादा सही होगा, हित संरक्षक और प्रवक्ता है। क्योंकि १९५९ में ही दो संगठनों ने मिलकर इस अमरीकी सामूहिक स्वास्थ्य सघ का निर्माण किया था। उनमें से एक था अमरीकी श्रमिक स्वास्थ्य संघ; (American Labour Health Association); संयुक्त राज्य की प्रायः सभी श्रमिक-संघ प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के प्रशासक एवं प्रतिनिधि इस संगठन के सदस्य थे। दूसरा था अमरीका का सामूहिक स्वास्थ्य महासघ (Group Health Federation of America), यह ज्यादा बड़ा और ज्यादा पुराना संगठन था और १९४६ में कुछेक श्रमिक स्वास्थ्य योजनाओं और संयुक्त राज्य तथा कनाडा की दो-एक को छोड़कर अधिकांश महत्वपूर्ण सहकारी एवं सामूदायिक स्वास्थ्य योजनाओं को सम्मिलित कर सहकारी स्वास्थ्य महासघ (Co-operative Health Federation) के नाम से इसकी नींव डाली गई थी।

४ | घर और पड़ोस

हमारी अर्थ व्यवस्था में आज ऊपर से सब-कुछ ठीक होने की जो स्थिति-आर्थिक स्वास्थ्य-दिखाई देती है वह नितान्त भ्रामक है। वास्तव में हमारी अर्थ-व्यवस्था को गहरी बीमारी लग चुकी है। जिस मूल्य पर बेचने के आग्रह के साथ अमरीकी उद्योग जो उत्पादन कर रहा है उसकी निकासी का बाजार बहुत ही नगण्य है; क्योंकि हमारा उद्योग उसी परिमाण में जनता की क्रयशक्ति को पैदा नहीं कर पा रहा है। समग्र मूल्यों और समग्र सार्थक माँग के बीच की खाई वास्तव में बहुत चौड़ी है। यह खाई पैदा हुई है हमारी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक माल के 'व्यवस्थापित' अधिमूल्यन की रीति और व्यवसाय के अन्दर से ही पूँजीगत खर्चों के लिए उनका लागत माल के उपभोक्ता मूल्य में जोड़कर, आन्तरिक वित्तीय-प्रबन्ध की पद्धति से।

संयुक्त राज्य इस्पात कारपोरेशन (United States Steel Corporation) ने 'इस्पात और मुद्रा स्थिति से सम्बन्धित तथ्य एवं कपोल कल्पनाएँ' नामक अपने एक वक्तव्य में स्वयं ही कहा है कि हमारी अर्थ व्यवस्था में सभी कीमतों का ८८ प्रतिशत 'व्यवस्थापित' है।

जहाँ पर सपत्र (प्लेट) के लिए निवेश की वित्त-व्यवस्था आन्तरिक स्रोतों (साधनों) से, अर्थात् व्यवसाय से निःसृत निगम अधिशेषों से की जाती है, वहाँ यह एक साधारण-सा तथ्य है कि ऐसे सपत्रों की लागत उन उद्योगों के उत्पादनों के उपभोक्ताओं द्वारा ही चुकाई हुई होती है। एकाधिकारी लाभ उत्पादित माल के समग्र मूल्यों एवं उपभोक्ताओं की सार्थक क्रय शक्ति के बीच की खाई के विस्तार का निर्धारित करते हैं; और नई पूँजी जमा किये बिना सपत्र के लागत की वित्तीय व्यवस्था उस खाई का एक घटक है।

उस खाई को बहुत-कुछ अंशों में निम्न उपायों से पाटने का प्रयत्न किया जा रहा है : सारे सैनिक खर्चों और उपभोक्ता ऋण में वृद्धि और बन्धक तथा लम्बी

अवधि के ऋण में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि और स्थानीय, राज्य की अथवा मध्य की सरकार के घाटे और वे हानियाँ जो छोटे एवं प्रतिस्पर्धी व्यवसायों को लागत से कम मूल्य पर अपना माल बेचने की विवशता के कारण होती हैं, जैसा कि हमारे किसानों को आमतौर पर मजबूर होकर करना पड़ता है।

लेकिन इतनी बड़ी आर्थिक सहायता के बावजूद हमारे निर्माताओं को अपने माल के द्वारा प्रवाह उत्पादन को खपाने के लिए बहुत बड़े पैमानों पर बहुत खर्चीले और अजीबोगरीब विज्ञापनों एवं विक्री बढ़ाने के अन्य अनेक साधनों को काफी अधिक मात्रा में अपनाना पड़ता है।

यही स्थिति बनी रहती तो हमारी अर्थ-व्यवस्था का शीघ्र अन्त हो जाता।

और सच तो यह है कि यदि उपभोक्ता ऋण का इतना अधिक फैलाव न होता और हमारी जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि न हो रही होती तो अन्त कभी का ही भी जाता। अमरीकी परिवार इतने विलासप्रिय और शौकीन तो हैं। ही सकते हैं और सम्भव है भी जो यह सोचें कि उनमें से हर एक के पास दो-दो मोटरे, दो-दो टेलीविजन, एक बहुत बड़िया रेफ्रिजरेटर और उपनगर में काफी महंगा मकान होना चाहिए। लेकिन आज या आगे कभी भी कोई भी परिवार तीन या चार मोटरे, चार या पाँच टेलीविजन सेट, एक से अधिक रेफ्रिजरेटर या पचास हजार डालर से अधिक महंगा मकान नहीं खरीद सकता। विलास वस्तुओं की खपत की भी अपनी सीमाएँ हैं। एक सीमा तो यही कि औसत युवा परिवार पारिवारिक ऋण का बोझ केवल एक हद तक ही बढ़ा सकता है, उससे अधिक नहीं। दूसरी सीमा है जिस उपहासास्पद वस्तु-पूजा के फेर में हमारी वर्तमान अर्थ व्यवस्था ने हमें डाल रखा है उसके प्रति स्वस्थ, स्वाभाविक विरक्ति का भाव, जिसके चिन्ह अब निश्चित रूप से दिखाई देने लगे हैं। और जहाँ तक मोटरों का प्रश्न है वे तो अधिक इसलिए नहीं विक पाती कि खरीदार के लिए उन्हें खड़ा रखने की जगह पाना सचमुच ही असम्भव होता जा रहा है। इसी कष्ट के कारण तो लोग सार्वजनिक यातायात का अधिकाधिक उपयोग करने लगे हैं और बहुत कुछ पैदल आवागमन का भी।

सौभाग्य से इस असन्तुलन को काफी हद तक सुधारने का उपाय है और उसकी उपयुक्तता प्रमाणित भी हो चुकी है। सुधार का वह उपाय है व्यवसाय के स्व-

यौतव को लाखीं लोर्गों में वलुतारलत कर देना । लससे लोर्ग ऐसे कुछ औद्योगलक सपत्रों के स्वामी बन सकते हैं ललनकी कीमत वास्तव में वे स्वयं ही चुका रहे होते हैं । यह लोक समूहों द्वारा व्यावसायलक उद्यमों का ऐसा सगठन है ललसका सुनलश्चित प्रयोजन उन्हीं लोर्गों की माँर्गों को पूरा करना है । यह उपभोक्ता-दलदे शलत उत्पादन और वस्तुओं तथा सेवा का वलतरण है । सुधार का यह उपाय अधलकाधलक मात्रा में एक प्रकार की ऐसी प्रतलद्वलद्वलता को ल्ज्म देता है ललसे एकाधलकार न तो डरा पाता है और न खरीद ही सकता है, बललक जो वर्तमान स्थलतल की बहुत बड़ी खराबलियों को केवल लसललए ठीक कर सकती है, कल वह होती ही है लोर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के ललए, न कल उनकी सनको से अनुचित लाभ उठाने के ललए । व्यावसायलक सगठन के ललस रूप के द्वारा लस सुधार को कार्यान्वित कलया जाता है वह सहकारी अथवा पारस्परलक व्यवसाय कहलाता है ।

उदाहरण देना ठीक रहेगा ।

१९६० की १६ फरवरी को न्यूयार्क के गवर्नर नेल्सन राक फेलर ने यह घोषणा की कल ल्ज्मैका (लाग आइलैण्ड) के घुडदौड मार्ग पर ६३०० गृह-इकाइयों शीघ्र ही निर्मित की जाएगी । उन्हींने यह भी घोषणा की कल लस बस्ती का नाम रोशडेल (इगलैण्ड) में, १८४८ में, पहली उपभोक्ता सहकारी स्थापलत करने वाले २८ गरीब बुनकरो के सम्मान में रोशडेल ग्राम रखा जाएगा । गवर्नर महोदय ने अपनी घोषणा में यह भी बताया कल लस निर्माण-योजना के ललए आवश्यक बन्धक पूँजी की व्यवस्था मुख्य रूप से ललन तीन स्रोतों से की जाएगी वे हैं . राजकीय शलक्षा-कों की नलवृत्तल नलधल से २ करोड़ ८० लाख डालर; राजकीय कर्मचारियों की नलवृत्तललवलधल से भी लगभग इतनी ही रकम; और राजकीय गृह एव अवास ललभाग से १ करोड़ ८० लाख डालर ।

. उन्हींने यह भी कहा कल देश और सम्भवतः वलश्व की लस सबसे बड़ी सहकारी गृहनिर्माण योजना का प्रयोजक, निर्माता और उन्नायक सयुक्त आवास प्रतलष्ठान (United Housing Foundation) रहेगा ।

गवर्नर महोदय की घोषणा को २४ घण्टे भी पूरे नहीं हो पाये थे कल संयुक्त आवास प्रतलष्ठान के पास दो हजार से भी अधलक आवेदन-पत्र पहुँच

गए। ये उन लोगों ने भेजे थे जो ६२९९ अन्य परिवारों के साथ रीशडेल ग्राम में रहने और उसके स्वामी बनने के इच्छुक थे। इन लोगों ने इमारतों के नकशे अथवा चित्र नहीं देखे थे। इन्हें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि अपने नये मकानों में रहना शुरू करने पर उन्हें पहली बार नकद और बाद में मासिक कितनी रकम देनी होगी। और अधिकतर लोग तो पहली बार की नकद रकम उसी समय देने को तैयार थे।

इसका कारण क्या था ?

कुछ तो यह कि सयुक्त राज्य में मध्य और निम्नवित्त परिवारों की अच्छे पड़ोस में अच्छे मकान पाने की विशिष्ट आर्थिक माँग आज भी पूरी नहीं हो पाई है।

और कुछ यह कि रीशडेल ग्राम सयुक्त आवास प्रतिष्ठान द्वारा हाथ में ली जाने वाली दूसरी गृह निर्माण योजना थी और जनता का इस प्रतिष्ठान में विश्वास था और लोग जानते थे कि जो मकान बनाये जाएँगे वे मुनाफे पर बेचने के लिए नहीं होंगे, बल्कि ज्यादा-से-ज्यादा परिवारों को अच्छे पड़ोसियों वाले अच्छे मकान इतने लागत मूल्य पर दिये जाएँगे जो उन्हें भारी नहीं पड़ेगा।

साथ ही न्यूयार्क सिटी के निवासियों को यह अनुभव भी हो चुका था कि उद्योगोत्पादक प्रायोजित सहकारी निर्माण योजना के अन्तर्गत जो मकान बनाये जाते हैं वे लोगों की गृह-सम्बन्धी माँग को पूरा करने के अतिरिक्त और किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं होते। इस प्रकार का गृह-निर्माण उपभोक्ता-निर्देशित उद्योग का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। इस ढंग पर जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वे उत्पादन के पूर्व ही बिक जाती हैं, जैसा कि रीशडेल ग्राम के उन मकानों का हुआ जिनका अभी अस्तित्व भी नहीं था।

यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण आवश्यक है।

आज कोई १ लाख ४० करोड़ अमरीकी परिवार या तो रईस या फिर गन्दे बस्तियों वाले मकानों में रहते हैं। और बहुत से परिवार तो अपना मकान खरीदने के लिए सामर्थ्य से बहुत अधिक पैसा खर्च करके ही इस दुर्भाग्य से बच पाये हैं। फिर भी हमारी कुछ महानगरियों में मकान बनाने सम्बन्धी रोजगारों में बहुत ज्यादा बेकारी है।

इस सब के दुहरे कारण हैं। एक तो यह कि हम काफी सख्या में नये मकान नहीं बना रहे और न महानगरो के कलक स्वरूप गन्दी बस्तियो को ही साफ करने की दिशा में काफी-कुछ कर रहे हैं। दूसरे यह कि जो भी मकान बनाये गए उनमें से अधिकतर बहुत महँगे और विलास की चीज हो गए हैं। १५ हजार डालर से कम कीमत वाले मकान अपेक्षाकृत बहुत ही थोड़े हैं—लगभग नहीं के बराबर। उतना महँगा मकान खरीदने के लिए एक परिवार की कम-से-कम वार्षिक आय ७ हजार डालर होनी चाहिए, जब कि इतनी आय वाले परिवार अमरीका में अल्प सख्या में ही हैं।

हमारा गृह-निर्माण उद्योग जैसे मकान चाहता है बनाता है, जो कीमत चाहता है वसूल करता है; आम तौर पर वह इस बात की परवाह ही नहीं करता कि लोग क्या चाहते हैं और कितना दे सकते हैं।

इसलिए कुछ बुद्धिमान लोगो ने इस सारी प्रक्रिया को ही उलटने और ऐसे मकान बनाने को सोची जिनकी लोगों को जरूरत है और कीमत भी उनकी पहुँच से परे न हो। इसको करने का एकमात्र सही ढंग यही है कि जिन लोगों को मकानों की आवश्यकता है उन्हीं को इस सम्बन्ध में निर्णय भाँ करने दिया जाए। दूसरे शब्दों में यह कि मकान चाहने वालों की सहकारिता स्स्था बनाई जाए, उनकी आवश्यकता और जब का पूरा-पूरा ध्यान रख कर मकान बनाये जाएँ और जब मकान बनकर तैयार हो जाएँ तो सहकारिता के आधार पर उन्हीं को उनका कब्जा दे दिया जाए।

ऐसी हालतों में बिक्री के लिए ऐंडी-चोर्ट का जॉर लगाने की कोई जरूरत न होगी। बनने से पहले ही वे मकान उनमें रहने वाले परिवारों के होजाते हैं।

न्यूयार्क के निचले ईस्ट साइड का एक पूरा हिस्सा इसी पद्धति का अद-लम्बन करके गन्दी बस्ती से सुन्दर मकानों वाली शरीफ आदिमियों और भले पड़ोसियों को आबादी में बदल दिया गया है। इन मकानों को बनाने की लागत व्यावसायिक ढंग पर बने मकानों की अपेक्षा २५ से ३० प्रतिशत कम हुई है। इन सहकारियों में चार कमरों वाले हिस्सों का औसत मासिक शुल्क सारी लागत (खर्च) जोड़ कर ६० से ७० डालर है, जो ७२० से ८०० डालर प्रति वर्ष हुआ। जिन परिवारों की वार्षिक न्यूनतम आय ४ हजार डालर है वे सिर पर

बहुत अधिक कर्ज ओढ़े बिना इतने मूल्य के मकान आसानी से ले सकते हैं।

इस पर थोड़ा और विचार करने की जरूरत है। मान लीजिए कि हर एक महानगर में न्यूयार्क की ही तरह के सक्षम सेवा सगठन हों, जो मकान चाहने वाले लोक-समूहों को सलाह और निर्देशन का कार्य तत्परता एवं सुयोग्यता से करे जिससे उन्हें अपेक्षित मकान गृह निर्माता सहकारियों के द्वारा उपलब्ध हो सके तो सहकारी आधार पर बने वे सारे ही मकान लोगों की आवश्यकताओं एवं आर्थिक स्थितियों के सर्वथा अनुकूल होंगे। लेकिन तब दूसरे मकान-निर्माता क्या करेंगे ? वे अवश्य प्रतियोगिता करेंगे। वे भी ठीक वैसा ही करने का—सहकारियों से ज्यादा अच्छा काम कर दिखाने का प्रयत्न आरम्भ कर देंगे। और बहुत सम्भव है कि उनमें से कुछ इसमें सफल भी हो जाएँगे।

तो इस प्रकार सरकार की आर्थिक सहायता के बिना लोगों के अपने ही प्रयत्न, अपने ही पूँजी-निवेश और अपनी ही बुद्धि के बल पर अमरीकी जनता को आवास समस्या हल होती दिखाई देगी।

इतना ही नहीं, सार्थक माँग और उसकी आपूर्ति के बीच एक ऐसा सन्तुलन भी स्थापित हो जाएगा जो गृह निर्माण उद्योग को काफी समय के लिए पूरा काम और पूरा रोजगार देने की उचित गारंटी कर सकेगा।

मूल्य के स्फीतीकरण को भी रोकने का यह एक प्रभावशाली ढंग होगा। क्योंकि बहुत-सी व्यावसायिक प्रतियोगिता तो ऐसे ही सगठनों द्वारा की जाएगी जिनके स्वामी ही उनके उत्पादन के देयक की अदायगी कर रहे होंगे।

संयुक्त राज्य अमरीका में सहकारी गृह-निर्माण १९२६ में आरम्भ हुआ, जिसे अधिक समय नहीं कहा जा सकता। अमलगामेटेड क्लोदिंग वर्कर्स यूनियन (समामेलित पोशाक मजदूर मंच-Amalgamated Clothing Workers Union) के कुछ सदस्यों और पदाधिकारियों के बुद्धिमत्तापूर्ण निश्चय से यह काम शुरू होता है। उस समय वे लोग मन्दो और गरीबी की भार से उतने ही परेशान थे जितने कि राशडेल के वे २८ बुनकर जिन्होंने १८४८ में इंग्लैण्ड के रोशडेल नामक स्थान में पहली उपभोक्ता सहकारी शुरू की थी, या फिर कोनेक्टिकट के उन दूध उत्पादक किसानों की तरह जिन्होंने १८०४ में संयुक्त राज्य अमरीका में किसानों की पहली सहकारी विक्रय समिति बनाई थी।

सबसे पहले तो इन पोशाक मजदूरी ने यह हिसाब लगाया कि जित खस्ताहाल कमरों में वे अभी अपने परिवारों के साथ रहते हैं उनको कुल किराया कितना देना पड़ता है। सम्मिलित किराये की इस रकम को उन्होंने अपनी पूँजी बनाया। फिर उन्होंने यह पता लगाया कि न्यूयार्क क्षेत्र में रिहायशी कमरों वाली इमारतें बनाने की लागत क्या बैठती है। उन्होंने यह भी मालूम किया कि बन्धक पूँजी की दरे क्या है। इस सारी खोज-बीन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि हमी अपने गृह-स्वामी बन सके अर्थात् स्वयं मकान बनाये और स्वयं ही उनके स्वामी बन जाएँ तो रहने को बढिया मकान भी मिलेगा और पैसा भी बचेगा। अन्त में योजना को विधिवत रूप देने और विशेष रूप से यह पता करने के लिए कि रुपया कहाँ से उधार मिल सकता है, उन्होंने एक समिति नियुक्त कर दी। सौभाग्य से इस सारे उद्यम की व्यवस्था करने के लिए उन्हें अब्राहम ई० कजान मिल गए, जो कद में तो अवश्य छोटे परन्तु सूझ-बूझ और दूरदर्शिता में पर्वताकार हैं। पोशाक मजदूरी ने उन्हीं को अपना व्यवस्थापक चुन लिया।

कजान जो आजकल संयुक्त आवास निगम के अध्यक्ष हैं, तभी से अमरीका में सहकारी गृह निर्माण अध्यवसाय की मुख्य प्रतिभा और प्रमुख प्रेरणा रहे हैं।

उस पुरोगामी प्रयत्न का प्रतिफल हुआ अमल्गामेटेड हाउसिंग कारपोरेशन की स्थापना के रूप में, इसी निगम ने वान कार्ट लैण्ड पार्क के किनारे रिहायशी कमरों वाली इमारत प्रायोजित और निर्मित की। एक सहानुभूति रखने वाली बैंक, जो इस योजना के महत्त्व को समझती थी, उसने बन्धक पर कर्ज देना स्वीकार कर लिया। बैंक के लिए यह निवेश बड़ा ही सुरक्षित और बिना जोखिम का सिद्ध हुआ। आगे चल कर उसने ऐसे और भी बहुत से निवेश किये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न्यूयार्क के किसी भी सहकारी गृह-निर्माण संघ ने एक भी किस्त चुकाने में कभी देर नहीं की—ब्याज और पूरा मूल धन उनके द्वारा हमेशा ठीक समय पर चुकाया जाता रहा है।

यह अमल्गामेटेड निर्माण योजना बहुत ही सफल रही। बहुत ही कम लागत पर इसने अच्छे मकान ही उपलब्ध नहीं किये, अमरीका के सबसे बड़े नगर के बीच में सच्चे पड़ोसियों और अच्छे पड़ोस का भी सृजन किया। इसने

अच्छे पड़ोसियों वाली एक ऐसी बस्ती का निर्माण किया जहाँ सभी विषयों पर विचार-मोष्ठियाँ और भाषाण-मालाएँ आयोजित की जाती हैं, जहाँ बच्चों के लिए बाल मन्दिर और सैर-सपाटों (समर कैम्प) का प्रबन्ध किया जाता है, जहाँ पड़ोसी ही पड़ोसियों के पारस्परिक लाभ के लिए सहकारी खाद्य भण्डार, साख-सघ और बीमे का काम संचालित करते हैं। उद्यानों, निकुर्जों और इमारतों पर चढ़ी अगूरी लताओं पर यहाँ के परिवारों को बड़ा नाज है। अपनी बस्ती को साफ सुथरा रखने और उसको देख-भाल करने में यहाँ के निवासी बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। इसीलिए सहकारी स्वामीत्व वाली इमारतों के रख-रखाव का खर्च प्रायः किराये पर उठाई गई मालिकाना इमारतों अथवा सरकारी स्वामीत्व वाले निवास भवनों की अपेक्षा आधा ही पड़ता है।

लेकिन अमलगामेटेड के गृह-स्वामियों और उनके-जैसे अन्य गृह-समूहों के सम्बन्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात है वह यह कि वहाँ अपराध अथवा अपचार बहुत ही कम मात्रा में पाये जाते हैं। वान कार्टलैण्ड पार्क के वर्तमान निवासियों में सेतीन चौथाई परिवार या तो वेही हैं अथवा उनके वंशज जो १९२६ में यहाँ रहने के लिए आये थे। मगर वहाँ पर भीषण अपराध का एक भी मामला या बाल अपचार का कोई भी गम्भीर काण्ड आज तक नहीं हुआ।

सहकारी गृह स्वामीत्व अपने पड़ोसियों पर गर्व और अभिमान की भावना को जन्म देता है। विलकुल स्वाभाविक भी है। अच्छे मकान और अच्छे पड़ोस उपलब्ध करने में पारस्परिक सहायता की भावना असंदिग्ध रूप से एक ऐसी सामूहिक नैतिकता। और आचरण संहिता के ऐसे मानों का सृजन करती है जिनके सामाजिक मूल्यों को आँकना सरल नहीं है।

जैसे-जैसे समय बीतता गया अमलगामेटेड आवास निगम अपने मूल भवन-समूह में कई नये भवनों की वृद्धि करता चला गया।

इस पहले प्रयत्न की सफलता से प्रोत्साहित होकर न्यूयार्क सिटी के अन्य भागों में भी धीरे-धीरे ऐसे कई प्रयत्न प्रारम्भ हुए। उन आरम्भिक प्रयत्नों का प्रयोजन अमलगामेटेड क्लोदिग मजदूर सघ ने किया और उन्हें वित्तीय सहायता दी सेविग बैंकों ने, जिनका कजान महाशय पर पूरा-पूरा विश्वास था।

लेकिन द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद के वर्षों तक इस आन्दोलन के

विकास की गति में तेजी नहीं आ पायी। फिर इटर नेशनल ब्रदर हुड आफ इलेक्ट्रिकल वर्क्स और इटर नेशनल लेडीज गारमेण्ट वर्क्स जैसे शक्तिशाली श्रमिक संगठनों ने इसमें रुचि लेना आरम्भ किया। कुछ बड़े-बड़े साखसघ और अन्य सहायता-संगठन भी इस ओर झुके। और इन सब की रुचि केवल निर्माण-योजनाओं की प्रायोजित करने तक ही सीमित नहीं रही, ये बन्धक वित्त की व्यवस्था भी करने लगे। कुछ बीमा कम्पनियाँ भी निर्माण योजनाओं के लिए वित्तीय प्रबन्ध करने के कार्य में सम्मिलित हो गईं। अधिकांश निर्माण-कार्य निम्न ईस्ट साइड के कोरलियर्स हूक विभाग में ही केन्द्रित रहे। किसी जमाने में यह घनघोर गन्दी बस्तियों वाला क्षेत्र था, लेकिन १९६० तक सहकारी ग्राम (कोआपरेटिव विलेज) के नाम से सुविख्यात चहल-पहल और सुषमा-सौन्दर्य से भरी सहकारी बस्ती में परिवर्तित हो गया; ५ हजार परिवार इसके रिहायशी कमरों के स्वामी हैं; कई साख-सघ उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, सहकारी स्वामित्व का बहुत ही बढ़िया वृहद् भण्डार (सुपर मार्केट) है और बच्चों के लिए कई शानदार क्रीडागण भी।

दूसरा महायुद्ध आरम्भ होने से पहले ही न्यूयार्क के निवासियों के मन में यह बात घर कर गई थी कि सहकारी गृह-निर्माण बहुत ही बढ़िया बात है।

लेकिन युद्ध के दिनों में गृह-निर्माण का कार्य कुछ भी नहीं हो पाया, जो स्वाभाविक हो था। हर महीने आवश्यकताएँ बढ़ती गईं; और साथ ही बहुत से परिवारों की बचत राशियाँ भी। इसलिए जैसे ही शान्ति स्थापित हुई इस दिशा में क्रियाशीलता को लहर-सी उमड़ पड़ी। लेकिन निर्माण-कार्य अब भी न्यूयार्क सिटी में ही केन्द्रित रहा। ओहियो के डैटन, इंडियाना के साउथ बैण्ड, टेक्सास के डल्लास और कुछ अन्य स्थानों में सामरिक श्रमिकों के लिए निर्मित सरकारी मकानों में रहने वाले किरायेदारों ने अपने-अपने सहकारी संघ बनाकर उन किराये के मकानों को सरकार से खरीद लिया। लेकिन जितने अच्छे और सुविधाजनक कानून न्यूयार्क में थे वैसे और कहीं नहीं थे। न न्यूयार्क के अतिरिक्त कहीं पर खाली जमीन को आनन्दित पड़ोसियों को सुख-वैनवाली बस्तियों के रूप में परिवर्तित करने वाली सहकारी गृह निर्माण की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण ही उपलब्ध था; और न कहीं

पर कोई कजान ही था।

लोगों को रुचि ने इतना व्यापक रूप ग्रहण कर लिया कि सहकारी गृह-निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक सगठन बनाने की कोशिशें की गईं। लेकिन इस तरह के सारे प्रयत्न दुराशा ही सिद्ध हुए। मुख्य रूप से दो विचार धाराएँ सामने आईं। एक के प्रबल समर्थक थे श्री ए० ई० कजान और उनके निकटस्थ साथी जो सहकारिता के अपने सम्यक् सिद्धान्तों में परिवर्तन या समझौता करने को रच-मात्र भो तैयार नहीं थे, क्योंकि वे बार-बार इन सिद्धान्तों की आचरण को कसौटी पर कस चुके थे, और न वे इसी बात के लिए राजी हुए कि सिद्धान्तों और कार्यक्रम को इतना व्यापक बना देना चाहिए जिससे हाथ में लो हुई उनको हर निर्माण-योजना के लिए निर्धारित मान-दण्ड ही खतरे में पड़ जाएँ। उनकी दुनिया और उनका कार्य क्षेत्र न्यूयार्क सिटी तक ही सीमित था। दूसरी ओर वे लोग थे जो कजान और उनके सहयोगियों के कार्य और सफलताओं के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी इस बात को बड़ी तीव्रता से अनुभव करते थे कि सहकारी गृह-निर्माण से न्यूयार्क के बाहर के लोगों को भा लाभान्वित किया जाना चाहिए; और इसीलिए उनका कहना था कि यदि अधिकाधिक मात्रा में मकान उपलब्ध किये जा सकें तो शुद्ध सहकारी प्रणालियों के अपनाये जाने पर इतना अधिक जोर नहीं भी देना चाहिए।

अन्त में परिणाम यह हुआ कि तीन सगठन बन गए—तीनों का केन्द्र न्यूयार्क ही रहा और तीनों एक-दूसरे से सर्वथा स्वतन्त्र और बहुत-कुछ भिन्न ढंग से अपना-अपना काम करने लगे।

इनमें सबसे पहला और शक्तिशाली सगठन था युनाइटेड हार्जिसिंग फाउण्डेशन (संयुक्त आवास प्रतिष्ठान) जिसके अंगे चल कर ए० ई० कजान अध्यक्ष बने। न्यूयार्क की महानगरी में एक के बाद एक निर्माता सहकारियों को विकसित करने में जो नीतियाँ बार-बार परखी जाकर सफल प्रमाणित हो चुकी थी उन्हीं पर यह संगठन चलता रहा। इस प्रतिष्ठान का अधिकांश काम-काज नगर के निम्न ईस्ट साइड में ही केन्द्रित रहा।

१९५९ तक न्यूयार्क के १२ हजार परिवार बहुत ही बढ़िया और साथ ही रिहायशी कमरों वाली अत्यन्त सस्ती इमारतों में बसा दिये गए और वे

ही परिवार उन इमारतों के स्वामी भी थे, जो सयुक्त आवास प्रतिष्ठान के प्रयत्नों का ही सुफल था। साफ दिखाई दे रहा था कि आगामी कुछ वर्षों में यह सख्या तिगुनी हो जाएगी। अमलगामेटेड श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिक संगठनों ने भी इस काम में रुचि दिखाई। इटर नेशनल लेडीज गारमेण्ट वर्कर्स यूनियन ने निम्नतर ईस्ट साइड में इल्वु ग्राम नामक एक निर्माण योजना प्रायोजित की और उसके लिए डेढ़ करोड़ डालर का बन्धक ऋण भी प्रदान किया। १९५६ में जब यह ग्राम अपने सरक्षकों को सौंपा गया तो उस उद्घाटन समारम्भ में, न्यूयार्क से सयुक्त राज्य की सीनेट के दोनों सदस्य, नगर के महापौर (मेयर), नगर परिषद् के अध्यक्ष (Borough Council), अनेक कांग्रेसमैन, अमरीकी श्रमिक महासंघ (American Federation of Labour) के अध्यक्ष, श्रीमती फ्रैकलिन डी० रूजवेल्ट एव राज्य तथा राष्ट्र के अनेक नेतागण उपस्थित थे। और वहाँ उपस्थित सभी ने इस बात को निर्विवाद रूप में स्वीकार किया कि सयुक्त आवास प्रतिष्ठान के ढंग पर किया गया सहकारी गृह निर्माण अमरीका के नगर जीवन के लिए, बड़े महत्त्व का रचनात्मक कार्य है।

इसका प्रमुख कारण तो यही था कि इस प्रकार को गृह-निर्माण योजनाओं में सम-स्वामीत्व का क्रमिक अधिकार प्रदान करते जाने वाले अंश (साम्या-स्वामीत्व) समेत जो मासिक धन-राशि ली जा रही थी वह इसी कोटि के व्यावसायिक मकानों के सादे किराये की अपेक्षा २० से ३० प्रतिशत कम थी और अब भी है। और इस कमी या बचत का बुनियादी कारण यही है कि सहकारी गृह-निर्माण मकानों का उपभोक्ता-निर्देशित उत्पादन होता है—एक ऐसा उत्पादन जो वास्तविक आवश्यकताओं के ही आधार पर ठीक-ठीक तुष्टि के लिए आवश्यकताप्रस्त लोगों के द्वारा ही किया जाता है।

यह सच है कि न्यूयार्क में दूसरे किसी भी लाभार्जन-विहीन मकान की ही तरह सहकारी मकान को भी कर में कुछ छूट दी जा सकती है। इस तरह का कानून दूसरे किसी भी राज्य में नहीं है। और सहकारी मकान के लिए विशेष प्रकार का कर-प्रावधान तो निश्चित रूप से कहीं भी नहीं है। दूसरे किसी भी प्रकार के मकान को जितने कर देने पड़ते हैं ठीक उतने ही सहकारी मकान

भी चुकाता है। लेकिन न्यूयार्क में किसी भी प्रकार का लाभार्जन विहीन मकान, जिसमें सहकारी मकान भी सम्मिलित है, पच्चीस वर्षों के लिए कर में छूट पाने की अर्हता प्राप्त कर सकता है। यह कर से मुक्ति तो किसी भी प्रकार नहीं है। न्यूयार्क के कानून के अन्तर्गत लाभार्जन-विहीन मकानों की इतनी छूट अवश्य दी गई है कि वे पच्चीस वर्षों तक उतना ही कर दे सकते हैं जितना कि नया निर्माण होने से पहले उस सम्पत्ति से लिया जा रहा है। इससे सदस्य-स्वामियों में लो जाने वाली मासिक धनराशि को न्यून करने में कुछ सहायता अवश्य मिल जाती है, लेकिन इसे सहकारी मकानों को दी गई 'विशेष सुविधा' तो कदापि नहीं कहा जा सकता। यह केवल विशेष प्रावधान है, जो न्यूयार्क के कानून में लाभार्जन-विहीन मकानों के लिए किया गया है।

युद्धोत्तर काल में इस क्षेत्र में संयुक्त आवास प्रतिष्ठान अकेला ही काम नहीं कर रहा था। मध्यवित्त आवास निगम (Middle Income Housing Corporation) ने भी कई धार्मिक एवं शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रायोजित मॉनिंग साइड हाइट्स हाउसिंग कोऑपरेटिव के निर्माण, विकास और अधिभोग (दखल किये जाने के कार्यों) के निर्देशन द्वारा कार्यारम्भ किया। इसके बाद नगर और राज्य के साख-सर्वों द्वारा प्रायोजित चैथम ग्रीन हाउसिंग कोऑपरेटिव ने कार्य शुरू किया। राष्ट्रीय साख सघ के नेता विलीयम रीड, जो आगे चल कर न्यूयार्क सिटी आवास आयोग के अध्यक्ष हुए, मध्यवित्त आवास निगम के सभापति बनाये गए।

संयुक्त आवास प्रतिष्ठान की कमियों को काफी हद तक सहकारी आवास प्रतिष्ठान (The Foundation for Co-operative Housing) ने एक दूसरी दिशा में पूरा किया। सहकारी आवास प्रतिष्ठान की स्थापना विनस्जो कार्लटन ने की, जो जन-सेवी नागरिक नेता और एक उपभोक्ता-अभिप्रेरित स्वास्थ्य बीमा कम्पनी के अध्यक्ष हैं, इस प्रतिष्ठान को चलाने के लिए पूंजी का अधिकांश प्रबन्ध भी उन्होंने किया। सहकारी आवास प्रतिष्ठान ने सारे राष्ट्र में अपनी नजर दौड़ाई और सामान्यतः राष्ट्रीय आवास समस्या पर विचार किया और तब सारे देश में कहीं पर भी सहकारी गृह निर्माण के संचालन में सलाह और सहायता देने के लिए लैस हुआ। इसका काम संयुक्त

आवास प्रतिष्ठान की अपेक्षा कम गहन और अधिक व्यापक है, जिन निर्माण योजनाओं को यह कार्यान्वित करता है उनमें सहकारिता के सभी सिद्धान्तों को लागू किये जाने का इसका विशेष आग्रह भी नहीं रहता। इसका उद्देश्य अपने कार्य और प्रभाव को अधिकाधिक व्यापक और विस्तारित करते जाना है। इसने कनेक्टिकट के ब्रिजपोर्ट में, मेरीलैण्ड के ग्रीन वेल्ट में, मिसौरी के कनसास सिटी में और दर्जनों दूसरे स्थानों में मकानों के स्वामीत्व को सहकारी स्वामीत्व में परिवर्तित किया। ब्रिजपोर्ट में हस्तान्तरण का यह कार्य मकानों को खरीदने के बाद नेशनवाइड इन्श्युरेन्स कम्पनी के द्वारा किराये दारों के हाथ उन्हें पुनः बेच कर सम्पन्न किया गया।

१९५० में वाशिंगटन में एक ऐसी घटना घटी जो आगे चल कर ऊपर वर्णित तीनों सगठनों, संयुक्त राज्य की सहकारी लीग (Cooperative League of the United States) और सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित हर व्यक्ति के लिए अच्छी-खासी मुसीबत, कहना चाहिए कि एक चुनौती ही बन गई। इसी वर्ष संयुक्त राज्य की कांग्रेस ने सघीय आवास अधिनियम (Federal Housing Act) की धारा २१३ को कानून का रूप दे दिया। इस नये कानून ने सहकारी गृह निर्माण योजनाओं को दिये जाने वाले कर्जों का सघीय आवास अधिनियम के द्वारा बीमा करवाना आवश्यक कर दिया। और निर्माण योजनाओं के स्वरूप में भी कुछ सशोधन कर दिये गए। अब इन सशोधित निर्माण योजनाओं को उपभोक्ता, निर्माता अथवा पूँजी निवेश करनेवालों में से कोई भी प्रायोजित कर सकता था। ऋण की अदायगी और ब्याज की शर्तों में भी काफी सुविधाएँ दे दी गईं।

इसका परिणाम यह हुआ कि सारे देश में विभिन्न रूप-रंगों और आकार-प्रकारों की सहकारी गृह निर्माण योजनाओं की बाढ़-सी आ गई। उनमें से कुछ योजनाएँ, और विशेषकर वे सब जिनका संचालन और निर्देशन ऊपर बताये हुए सगठन कर रहे थे, अवश्य अपने बहुलांश में शुद्ध सहकारी ही थी; लेकिन दूसरी बहुत-सी तो रिहायशी कमरों के नाम पर निरे विलास-कक्ष बनाने वाली ऐसी योजनाएँ थी, जिनके लिए अधिनियम की 'सहकारिता' वाली धारा ने वित्तीय प्रबन्ध का बड़ा ही सुविधाजनक ढंग प्रस्तुत कर दिया था।

अधिकांश निर्माण योजनाओं ने जो कार्य-प्रणाली अपनाई वह बहुत-कुछ इस प्रकार की थी : मकान बनाना और अपने लिए बहुत ही लाभकारी शर्तों पर उन्हें धड़ाधड़ बेचते चले जाना; क्योंकि निर्माताओं अथवा निवेश-कर्ताओं के लिए अब धारा २१३ ने इस व्यवसाय में लाभ कमाने के बढ़िया अवसर प्रस्तुत कर दिये थे। और मकानों की आवश्यकता तो इतने अधिक लोगों की थी कि अनगिनत परिवारों ने इस प्रकार की गृह-निर्माण योजनाओं के हिस्से तुरत-फुरत खरीद लिये—बहुत-कुछ तो इसलिए भी कि आरम्भ में पहली नकद राशि ज्यादा नहीं देनी पड़ती थी। इनमें से शायद ही किसी को यह पता था कि वह क्या कर रहा है और कितनी बड़ी मुसीबत अपने गले बांध रहा है। यद्यपि फेडरल हाउसिंग एसोसिएशन ने इस सम्बन्ध की जानकारी देने वाला पर्चा तैयार करवा कर लोगों में बाँटवा भी दिया था, फिर भी किसी ने यह जानने-समझने की परवाह नहीं की कि सहकारिता कहते किसे है और सहकारी के स्वामी बन जाने पर उनके कर्तव्य और दायित्व क्या हो जाते हैं। और न किसी ने स्पष्टता से यही अनुभव किया कि अपने मकान के स्वामी बन जाने के अतिरिक्त पड़ोस का विकास और उन्नयन करने तथा आवश्यक वस्तुएँ, सेवाएँ एवं मनोविनोद के साधन उपलब्ध करने में सहकारिता का कितना महत्त्व और कितनी उपादेयता होती है।

१९५९ तक सारे संयुक्त राज्य में कुल मिला कर तीनों के सौ के लगभग सहकारी गृह-निर्माण योजनाएँ हो गई, जिनमें से १५० तो न्यूयार्क राज्य में ही थी और सब में मिला कर अनुमानतः ४० लाख लोग बसे हुए थे। इनमें से कुछ तो आर्थिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से पूर्णतः सहकारी समुदाय थे। कुछ में सहकारिता का नाम भी नहीं था। जो किसी भी दृष्टि से सहकारी नहीं कही जा सकती उनमें लोगों की रहने के लिए नये मकान मिल गए थे; और यह जरूर एक अच्छी बात थी। ऐसे लोगों को यह समझाने का काम कि सहकारी स्वामित्व क्या होता है, अभी पुरो तरह शेष था।

इस काम को कौन करेगा ?

सहकारी लोग ने १९५८ में, वाशिंगटन डी०सी० में, सहकारी गृह-निर्माण पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर इस कार्य को आरम्भ किया।

प्रतिनिधियों ने इसमें इतना अधिक उत्साह दिखाया कि लोग को इस तरह के सम्मेलन प्रति वर्ष बुलाने की तत्काल घोषणा करनी पड़ी।

लेकिन वर्ष में एक बार केवल दो दिनों के लिए सहकारी गृह-निर्माण के कुछ नेताओं का आपस में विचार-विनिमय और अनुभवों का आदान-प्रदान उन लाखों लोगों को, जो घरों में रहने के साथ-साथ उनके स्वामी भी हैं, सहकारिता का अर्थ और महत्त्व समझाने के लिए काफी नहीं हो सकता।

इस दिशा में सहकारी लोग द्वारा प्रायोजित एवं संचालित सहकारी गृह-निर्माण के व्यवस्थापकों के एक त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर की खूब सराहना की गई और साथ ही इस आशय की माँग भी कि इस तरह के प्रयत्न अधिक मात्रा में किये जाने चाहिए।

शोघ्र ही यह विदित हो गया कि सहकारी गृह-निर्माण संघों और संस्थाओं का एक राष्ट्रीय संगठन ही इस सारी समस्या का हल हो सकता है। ऐसा संगठन ही अपने सदस्यों के लिए यथोचित सहकारी कार्यविधि के मानदण्ड निर्धारित कर सकता है। ऐसा ही संगठन समस्याओं को सुलझाने में सहायता और परामर्श दे सकता है। ऐसा ही संगठन देश के अन्यान्य भागों में अधिकाधिक सख्या में 'संयुक्त आवास प्रतिष्ठानों' और 'सहकारी आवास प्रतिष्ठानों' को विकसित कर सकता है। ऐसा ही संगठन प्रशिक्षण शिविरों एवं सम्मेलनों का संचालन कर सकता है। और ऐसा ही संगठन सहकारी गृह-निर्माण योजनाओं के स्वामी-निवासी-सदस्यों की पर्याप्त शिक्षा के कार्यक्रमों पर आवश्यक जोर दे सकता है।

सहकारी गृह-निर्माण का राष्ट्रीय संगठन इन सारे कामों को तभी कर सकता है यदि इस क्षेत्र में काम कर रहे विविध तत्त्वों का समाधान कर उन्हें एक साथ लाया जा सके, विभिन्न दृष्टिकोणों में उचित सामंजस्य स्थापित किया जा सके और राष्ट्रीय संगठन में सम्मिलित होने एवं चन्दा देकर उसका व्यय भार उठाने के लिए सहकारी गृह स्वामित्व वाले समूहों को बहुत बड़ी संख्या में राजी किया जा सके। १९५९ का त्रायः पूरा वर्ष और १९६० के आरम्भ के कुछ दिन सहकारी लोग, संयुक्त गृह-निर्माण प्रतिष्ठान और सहकारी गृह-निर्माण प्रतिष्ठान की प्रेरणा से इन्हीं दिशाओं में कार्य होता रहा।

हुई हैं। सहकारी प्रणालियाँ एवं सहकारी स्वामित्व को कुछ नये ढंग से लागू कर दिया जाए तो इनमें की कुछ समस्याएँ तो अवश्य ही सुलझ सकती हैं। कम-से-कम नगरपालिका को ही पॉंचेक करोड़ डालर करों के रूप में मिल जाएँगे, जो अन्यथा वह कभी वसूल ही नहीं पायेगी। शुरू में ही साम्या-स्वामित्व समाविष्ट पहली नकद अदायगी के रूप में कोई २ करोड़ डालर मिल जाएँगे, जो १३ करोड़ ८० लाख डालर की अनुमानित लागत के बोझ को इस अर्थ में थोड़ा हलका कर देंगे कि २ करोड़ डालर की रकम दूसरी जगह उपयोग करने के लिए तुरत निकल आयेगी। आर्थिक उपदान की आवश्यकता नहीं होगी। उलट नगर की ऋण-धारण की शक्ति के कारण सस्ती दरों पर वित्तीय प्रबन्ध सम्भव हो सकेगा; इससे नये सहकारी-स्वामियों से लो जाने-वाले मासिक किस्ते इतनी घटाई जा सकेंगी कि निम्न-मध्य परिवार उसे आसानी से दे सकेंगे। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है; क्योंकि व्याज की दरों में १ प्रतिशत को कमी मासिक किस्त को २ २५ डालर प्रति कमरे तक घटा सकती है।

न्यूयार्क सिटी आवास आयोग के निर्णय ने सहकारी निवास व्यवस्था की दिशा में एक बिलकुल नया ही मार्ग खोल दिया है। यदि नगर-अधिकारी आशिक उपदान प्राप्त सरकारी भवनों के लालायित, लोगों की मकान-सम्बन्धी माँगों को पूरा करने के लिए सहकारित को अपनाने लगे तो इस सर्वाधिक सकट-ग्रस्त क्षेत्र में भी सहकारी गृह-व्यवस्था को काफी बढ़ाया जा सकता है।

जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ में कहा गया था, जितनी सामर्थ्य है उतने मूल्य पर अच्छा मकान पाना ही सम्भवतः आज अमरीकनो की एक ऐसी आर्थिक माँग है जिसे सबसे कम पूरा किया जा सका है। यह परिस्थिति ही सहकारियों के अस्तित्व का सबल कारण है और उन्हें समाज के लाभ के लिए कुछ कर दिखाने का एवं जन समुदाय का व्यापक समर्थन अर्जित करने का श्रेष्ठतम अवसर प्रदान करती है।

हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सहकारी गृह-निर्माण उत्तरोत्तर महत्व प्राप्त करता जाएगा, इसमें तो किसी को सन्देह है ही नहीं। प्रश्न केवल इतना ही है कि शुद्ध, श्रेष्ठ और सम्पूर्ण सहकारिता के पूरे-पूरे सार्थक लाभ किस सीमा तक प्राप्त किये जा सकेंगे ?

५ | अमरीका के गाँवों में बिजली कैसे पहुँची

‘देहाती विद्युत् सहकारियों को बिजली कम्पनियों का व्यवसाय क्यों छीनने दिया जाता है?’

‘क्या ये सहकारी समाजवादी नहीं हैं?’

‘सरकार स्वयं जिस दर पर कर्ज लेती है उससे भी कम ब्याज पर इन्हें सरकार से कर्ज क्यों दिया जाता है?’

‘किमान बिजली के कार-वार में टाँग क्यों अड़ाते हैं? हैं उनके पास इसका कोई जवाब?’

‘यदि विद्युत् सहकारियों ने देश के सारे बिजली व्यवसाय को हथिया लिया तो क्या होगा? ओर हथिया लेने से इन्हें रोक भो कौन सकता है?’

‘और ये कम्बख्त कर क्यों नहीं देते?’

ये कुछ प्रश्न हैं जो लोगों के मन में, और विशेष रूप से महानगरी के अखबार पढ़ने वालों के मन में, घुमड़ते रहते हैं।

यह अध्याय इसी तरह के प्रश्नों के बारे में है।

१९३५ में संयुक्तराज्य अमरीका के १० में से एक भी किसान के घर में न तो बिजली की रोशनी थी और न खलिहान में विद्युत् शक्ति थी। इसका मुख्य कारण यह था कि बिजली कम्पनियाँ देहातों में बिजली पहुँचाने के काम को लाभ-होन व्यवसाय समझती थी। वे बड़े विश्वास के साथ कहती थी कि किसान कभी बिजली के दाम चुका नहीं सकते। व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से जितनी भी जाँच-पड़ताल की गई उनसे पता चला कि यदि कम्पनियाँ बिजली देने का अपना निर्धारित लाभ उपाजित करना चाहें तो किसानों को उसके लिए प्रति किलोवाट-घण्टा ७५ सेट देने पड़ेंगे। किसानों से कहा जाता था कि उन्हें अपने फार्मों तक बिजली की लाइन ले जाने के ही दो सौ, पाँच सौ और कभी-कभी तो दो हजार डालर तक बिजली कम्पनियों को देने पड़ेंगे।

असल बात यह थी कि १९३५ में व्यावसायिक बिजली कम्पनियाँ इस धन्धे में हर एक ग्राहक से लाभ, जितना ज्यादा-से-ज्यादा हो सके, उतना लाभ कमाने के लिए थी और यही स्थिति आज भी है।

यदि लाभार्जन के अतिरिक्त दूसरा कोई आर्थिक हेतु न होता तो अमरीका के देहात आज भी मोमबत्तियाँ और लालटेन का ही प्रयोग कर रहे होते। अमरीकी किसानों ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान और बाद में उत्पादन के क्षेत्र में जो चमत्कार कर दिखाये वे कदापि न होते। अमरीका कृषि एक पिछड़ा हुआ उद्योग हो होता, आज की तरह का राष्ट्र का सर्वाधिक प्रगतिशील व्यवसाय तो कदापि नहीं। विद्युत् उपकरणों को करोड़ों-अरबों डालरों की खपत वाला एक देहाती बाजार भी न होता। नगर के रहन-सहन को तुलना में देहात का रहन-सहन अपेक्षाकृत आदिकालीन और कष्टकर ही होता। आज शहरों तथा उप-नगरी में बिजली की जोदरे हैं, देहातों में उसका दुगुनी ही होती।

और सबसे विकट समस्या तो होता विद्युत्-शक्ति और विद्युन्-साधनों के व्यवसाय में औद्योगिकीय बेकारी को।

लेकिन एक दूसरा हेतु प्रयुक्त हुआ, जिसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा और विद्युत्-शक्ति-व्यवसाय में एक भिन्न प्रकार का आर्थिक संगठन अस्तित्व में आया।

लाभार्जन के हेतु से जी न हो सका या उसने जी नहीं किया उसे सेवा और पारस्परिक सहायता के हेतु ने कर दिखाया। जो काम वाणिज्यिक कारोबार से न हो सका उसे सहकारी कारोबार ने बहुत अच्छी तरह पूरा किया। जो ग्रामीण अमरीका विद्युत्-शक्ति की बनावटों कमो वाला क्षेत्र था वही सहकारी ढंग पर विद्युत्-उत्पादन और वितरण को एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई जिसने फार्मों (कृषिवरों) और गाँवों को विद्युत्-शक्ति और साधनों की खपत का बड़ी तेजी से निरन्तर विकासमान बाजार बना दिया। मन्दी के जमाने में लाखों लोगों को काम-काज दिया गया; और तभी से विद्युत्-उद्योग में नई-नई नियुक्तियाँ होती रही हैं और आगे भी प्रतिवर्ष होती रहेंगी।

उदाहरण के लिए, किसानों ने १९५७ की अपेक्षा १९५८ में १४ प्रतिशत बिजली अधिक खर्च को और औसत मासिक उपभोग तो ४१५ किलोवाट-घंटा मासिक से बढ़कर ४७२ किलोवाट-घंटा हो गया।

गाँवों में बिजली पहुँचने के पहले पच्चीस वर्षों में ग्रामीण जनता ने विद्युत्-साधनों पर १५ अरब डालर खर्च किये ।

१९५८ तक ९५ प्रतिशत से अधिक अमरीकी कृषिधरों में बिजली पहुँच चुकी थी ।

और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ग्रामीण विद्युत् सहकारियों की प्रतिस्पर्धा ने समूचे व्यवसाय के स्वरूप को ही, जो बनावटी कमों और महँगे दरों वाला था, बदलकर पर्याप्त प्रदाय और उचित दरों वाला व्यवसाय बना दिया । चूँकि हमारी अमरीकी अर्थ प्रणाली में इस बात को गुंजाइश है कि लोगों के समूह अपनी विशिष्ट आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवसाय आरम्भ कर सकते हैं, इसलिए आधुनिक आर्थिक जीवन के एक बुनियादी उद्योग में व्याप्त गड़बड़ों को कम-से-कम नष्ट ना क्षेत्र में तो ठीक कर दिया गया ।

यह सब है कि मरूभ क्षेत्र की 'टा एव' जैसी विद्युत् विकास योजनाओं का भी विद्युत् व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा को पुनः प्रारम्भ करने में काफी बड़ा हाथ है, लेकिन यदि ग्रामीण विद्युत् सहकारी मस्थाएँ न होती तो गाँवों में इस प्रतिस्पर्धा का कुछ भी असर न हो पाता ।

इन प्रकार १९३५ में आरम्भ होनेवाली ग्रामीण बिजली की कहानी इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि उपभोग मुख्यतः उपभोक्ता-निर्देशित उत्पादन और वितरण से समूचा राष्ट्र किस प्रकार और कितनी अधिक मात्रा में लाभान्वित होता है । इस कहानी से, और सहकारा गृह-निर्माण से भी, हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि औद्योगिकों के कारा को कैसे भिटाया जा सकता है । क्योंकि जहाँ उद्योग पर स्वाम्याधिकारों व्यवसाय का एकाधिकार नियन्त्रण होता है वहाँ तो बनावटी ऊँचों कीमतों को बनाये रखने के लिए प्रायः उत्पादन को रोक़ा जाता है और इस प्रकार रोज़गार को कम करके बेकारा बढ़ाई जाती है; लेकिन इसके विपरीत सहकारी अथवा उपभोक्ता निर्देशित व्यवसाय का स्वरूप ही इस प्रकार का होता है कि वहाँ उत्पादन और वितरण उसी का नियंत्रित होता है जिसकी जनता की आवश्यकता होती है, और फिर इस सारे उत्पादन और वितरण का एकमात्र उद्देश्य होता है शुद्ध लागत पर, जो उचित और व्यापक रहेगा भी हो, जनता की आवश्यकताओं को पूर्णरूपेण सन्तुष्ट करना ।

१९३५ में देशव्यापी मन्दी का दौर बड़ा गहरा था। कोई १ करोड़ ४० लाख मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था। किसान और छोटे व्यापारी या तो दिवालिया हो चुके थे या होने ही वाले थे। कांग्रेस और देश का प्रशासन लोगों को रोजगार सुलभ करने के लिए आर्थिक गति-विधियों को बढ़ाने के उपाय खोज रहे थे। कुछ तो यह कारण हुआ और कुछ कृषि की सहायता देने के उद्देश्य से १९३५ में सरकारी आदेश से ग्रामीण विद्युतन प्रशासन (Rural Electrification Administration) की स्थापना की गई। १९३६ में कांग्रेस में नॉरिस-रेवर्न अधिनियम स्वीकृत किया गया, जो ग्रामीण विद्युतन अधिनियम (Rural Electrification Act) के नाम से प्रसिद्ध है। सरकार में ग्रामीण विद्युत् प्रशासन के रूप में एक नये अभिकरण, नये विभाग का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया और यह प्रावधान भी कि नया अभिकरण किसानों, ग्रामीणजनों एवं ग्राम्य सस्थाओं को दी जानेवाली विद्युत्-सेवाओं को बढ़ाने के लिए कर्ज दे सकेगा। शर्तें यह थी कि ग्रामीण विद्युत् प्रशासन से कर्ज पाने वाले एक तो १५०० जनसंख्या से अधिक बड़े समुदाय की सेवा नहीं करेंगे और दूसरे, अपने क्षेत्र में जो भी किसान या अन्य उपभोक्ता सेवा चाहेंगे उन्हें लाभ-हानि की परवाह किये बिना सेवा देंगे। अधिनियम बनानेवालों ने आशा तो यही की थी कि अधिकांश कर्ज जानी-मानी बिजली कम्पनियाँ ही लेगी, जो ग्रामीण विद्युत् प्रशासन से कर्ज पाने के योग्य थी, हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन यह कुछ नहीं हुआ। असल में तो अधिनियम बन जाने के बाद के महीनों में भी कुछ नहीं हो पाया।

तब किसान सोचने लगे कि यदि बिजली कम्पनियाँ गाँवों में बिजली पहुँचाने की दिशा में कुछ भी नहीं करती तो हम किसान स्वयं ही कुछ क्यों न करें।

ग्रामीण विद्युत् प्रशासन के प्रचारकों ने इस विचार की जड़ जमाने और इसे परिपुष्ट करने की दिशा में काफी काम किया। उन्होंने किसानों को यह भी समझाया कि अपना सहकारी मगठन बना लेने के बाद सारे समूह की साख पर किसान बिजली आवश्यक लाइन बनाने के लिए ग्रामीण विद्युत् प्रशासन से कर्ज पा सकते हैं।

इस दिशा में कुछ पुरोगामी प्रयत्न भी अवश्य हो चुके थे। जिस पहले ग्रामीण विद्युत् सहकारी का विवरण मिलता है, वह १९१४ में मिस्से सोटा के

ग्रेनाइट फाल्स में सगठित किया गया था।

१९१९ में क्लाइड ग्रीजर नामक एक व्यक्ति के पास विसकोनसिन में बाँयला के निकट एक छोटा-सा पनविद्युत सयंत्र था। इस कारखाने में जितनी बिजली बनती थी उसकी खपत के लिए पर्याप्त बाजार नहीं था। उस व्यक्ति ने किसानों से प्रस्ताव किया कि वे अपना सहकारी सगठन बना लें। बड़ी-बड़ी लाभकारी कम्पनियों के ठाक विपरीत मिस्टर ग्रीजर ने किसानों से कहा कि मेरा अपना विश्वास तो यह है कि आप लोग बिजली के दाम दे सकते हैं; और उन्होंने यह भी कहा कि मैं आपको ऐसी दरें पर थोक बिजली दे सकता हूँ जो आपके ओर मेरे दोनों के ही लाभ को होंगे। तैतालीस किसानों ने सहकारी में सम्मिलित होना स्वाकार कर लिया। चार आदमियों के एक कर्मि दल ने छ महीने लगा कर उन तैतालीस किसानों के फार्मों तक १८ मील लम्बी लाइन बना दी। १९३५ और १९३६ की जिन घटनाओं का ऊपर वर्णन किया जा चुका है उस समय भी यह सहकारी मस्था विद्यमान थी।

बाद के वर्षों में सहकारी ढग पर बिजली पहुँचाने के कई सफल प्रयत्न यहाँ, वहाँ और सर्वत्र किये गए। उत्तर-पूर्वी मिसिसिपी में अलकान्न काउण्टी इलेक्ट्रिक पावर एमोसिएशन ने, जिसकी अधिकांश कारोबारी पूँजी 'टी बी ए' से प्राप्त कर्ज पर आधारित थी, अपने पहले ही वर्ष के कार्यकाल में बिजली की लागत घटा कर आधी कर दी। और १९३५ में जब ग्रामीण विद्युत् प्रशासन अस्तित्व में आया तो यह एक बड़ा ही सुस्थापित कारवार था।

और इस प्रकार १९३५ और १९३६ में हमारे देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सगठन अभियान आरम्भ हुए। उन दिनों जिन नर-नारियों ने अभियान किये थे आज भी सैकड़ों ग्रामीण समुदायों में उनका सम्मान किया जाता है। सैकड़ों देहातों कस्बों में उनके नाम पत्थर और ईंट की छोटी सुन्दर इमारतों के कोनिया अथवा नीव के पत्थरों पर खुदे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि जिन लोगों ने खेतों और फार्मों पर मोनवत्ती और लालटेन की रोशनी देख रखी है वे इन सगठनकर्ता पुरोगामियों का सयुक्त राज्य अमरीका में आधुनिक कृषि और आधुनिक फार्म जीवन के संस्थापकों के रूप में आदर करते हैं। मुझे एक ऐसी ही घटना याद आ रही है। मैं विसकोनसिन;

के ओकोण्टो फाल्स में एक सभा में सम्मिलित हुआ था। वह सभा वहाँ के आम-पास के क्षेत्र को विद्युत् प्रदाय करने वाले विद्युत् सहकारी का तेईसवाँ वार्षिक स्थापना दिवस मनाने के लिए आयोजित की गई थी। उत्सव के लिए जो बड़ा तम्बू लगाया गया था वह खचाखच भरा हुआ था, कहीं तिल धरने को भी जगह नहीं थी। उत्सव के मुख्य सम्माननीय अतिथि दो व्यक्ति थे— एक पद-निवृत्त मंत्री और दूसरे सहकारी के अध्यक्ष। स्त्री और पुरुष वक्ताओं ने कितनी श्रद्धा से विगलित होकर स्नेहाश्रु पूरित लोचनों एवं गद्गद् कण्ठों से उन्हें सम्मानाजली समर्पित की थी। क्योंकि यही दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने १९३५-१९३६ के हडकम्पो जाड़ों के बर्फ और वदन गलाते पालों में प्रायः लम्बो दुर्गम यात्राएँ करके फारम-फारम में सहकारी ढग पर गाँवों में बिजली देने का आशा भरा सन्देश पहुँचाया था। फिर अत्यन्त सरलता से लेकिन साथ ही प्रभावोत्पादक शैली में ९ दिसम्बर १९३५ की उस बैठक का वर्णन किया गया, जिसमें बारह व्यक्तियों ने ओकोण्टो विद्युत् सहकारी सघ के निगमन पत्रों पर अपने हस्ताक्षर किये थे और ग्रामीण विद्युत् प्रशासन से कर्ज पाने के लिए एक प्रार्थना पत्र वाशिंगटन भेजा था। ओकोण्टो फाल्स में विद्युत् सहकारी का प्रधान कार्यालय ही वहाँ का सबसे सुन्दर इमारत है। और होना भी चाहिए। क्योंकि दूसरे सहकारियों के साथ-साथ यह भी एक ऐसा व्यवसाय है जिसे वहाँ की स्थानीय जनता आने वाले वर्षों में भी एतद्महत्त्वपूर्ण स्थानीय-स्वामित्व वाले एक उद्योग के रूप में अपना बनाये रखना और चलाते रहना चाहेंगी—यदि उसे ऐसा करने दिया गया।

बोसर्वा शताब्दी के मध्यकाल के इन पथप्रदर्शकों ने किसका सगठन किया ? सगठन तो उन्होंने निस्तन्त्रदेह एक सहकारी व्यवसाय सघ का ही किया। आगे यह भी पूछा जा सकता है कि उस सगठन में आखिर था क्या ? यही कहा जाएगा कि अधिक कुछ भी नहीं। सदस्यों का एक अपेक्षाकृत छोटा-सा समुदाय था, जिनमें से प्रत्येक ने पाँच डालर सदस्यता शुल्क दिया था। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विद्युत् सघ से कर्ज पा जाने की आशा भी अवश्य थी। लेकिन यदि इन सहकारियों में दो अत्यन्त मूल्यवान और सशक्त वस्तुओं—भावनाओं को भी संगठित न कर लिया जाता तो बाकी सब का कुछ भी मूल्य

नहीं था। इनमें से पहली वस्तु भी पड़ोसियों के एक समूह की एक-जैसी, सामान्य आवश्यकता। पहली चीज यही थी जिसका संगठन किया जाना था। वास्तव में इन विद्युत् सहकारियों में, और इन्हीं में क्यों किसी भी प्रकार के सुविचारित सहकारी में, संगठन का मूल तत्त्व ही होता है किसी भी जन-समूह को सर्वनिष्ठ आवश्यकता, सबसे पहले इसी का संगठन किया जाना चाहिए। और, हाँ, इसके साथ यह दृढ़ विश्वास भी कि उस आवश्यकता को सहकारिता के द्वारा पूरा किया जा सकता है।

और जब किसानों ने लालटेन की रोशनी में निगमन पत्रों पर अपने हस्ताक्षर किये तो जो दूसरा तत्त्व संगठित किया गया वह था सदस्यों की साख—उनकी यह प्रतीक्षा कि जिस रूप के कर्ज मिलने की आशा है उसे वे नियत समय पर चुकाएँगे। उनमें से बहुत से किसान उस समय दिवालिया होने की स्थिति में थे। लेकिन वे ईमानदार थे। उनका बचनबद्ध होना उनकी सम्पत्ति को बन्धक किये जाने से ज्यादा अच्छी जमानत समझी गई—लेकिन तभी जब कि वे एक संगठित समूह के रूप में सम्मिलित होकर बचनबद्ध हुए।

अकेला एक तो कोई भी किसान अपनी बिजली-सम्बन्धी आवश्यकता पर विद्युत् प्रदाय को पूरा प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन किसानों के समूह, अपने बिजली-सम्बन्धी आवश्यकता को सहकारी ढंग से संगठित करके इस काम को कर सकते हैं। अकेला कोई भी किसान अकेले अपने नाम का साख को रुपया नहीं बना सकता, लेकिन किसानों के समूह सम्मिलित रूप से ऐसा कर सकते हैं। तो, इस प्रकार अमरीकी गाँवों में बिजली पहुँचाना जीवन के इस मौलिक तथ्य का जीता-जागता दिग्दर्शन है कि जिस काम को हम अकेले नहीं कर सकते उसे बहुत से लोग सहकारिता के आधार पर मिल-जुल कर प्रायः कर डालते हैं।

पारस्परिक सहायता समस्याओं को मुलज्ञाने का एक बहुत ही अच्छा ढंग है।

इस ढंग ने कोई ४५ लाख किसानों और ग्रामीण जनता को आधुनिक अर्थ-व्यवस्था के बुनियादी उद्योग-विद्युत् व्यवसाय—के एक अंश का स्वामी बनाने की दिशा में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

यहाँ उस कहानी के विस्तार में जाना आवश्यक नहीं। १९३५ अभी समाप्त

भी नही हुआ था कि ग्रामीण विद्युत् सहकारी संगठित हो गए और इंडियाना, ओहियो, टेक्सास, विसकोन्सिन और मिसिसिपी में उन्हें कर्ज भी मिल गया। उनके बाद तो जैसे-जैसे समय बीतता गया विद्युत् सहकारियों का देशव्यापी जाल-सा बिछता चला गया। ये ही थे जिन्होंने आवश्यकता को संगठित रूप देने और अपना कर्ज चुकाने की ईमानदार लोगों की बचन बढ़ता की सरल प्रणाली को अपना कर उस समस्त कार्य के बहुत बड़े अंश को पूरा किया जिस पर आगे चल कर अमरीका का भविष्य ही निर्भर करने जा रहा था। लाभार्जन करने वाले सम्पन्न और शक्तिशाली व्यावसायिक अधिष्ठानों ने इस कार्य को नहीं किया। वे तो इस ओर तब तक नहीं आये जब तक कि सहकारियों ने यह सिद्ध करके नहीं दिखा दिया कि किसान भी बिजली का पैसा दे सकता है और अच्छी दरे दे सकता है; वे तो तब तक नहीं आये जब तक कि सहकारियों ने यह नहीं दिखा दिया कि गाँवों में विद्युत्-साधनों की खपत की अनन्त सम्भावनाएँ भरी पड़ी हैं; वे तब तक नहीं आये जब तक कि सहकारियों ने अपना कर्ज चुकाने का (९९ ९९८७ प्रतिशत) रिकार्ड कायम नहीं कर दिया; वे तब तक नहीं आये जब तक कि सहकारियों ने प्रतिस्पर्द्धा करके बिजली की दरे ४० प्रतिशत और ५० प्रतिशत और कहीं-कहीं तो इस से भी अधिक नहीं घटा दी। जब तक इतना सब नहीं हो गया लाभार्जन करने वाले व्यावसायिक अधिष्ठानों ने अमरीकी देहातों को बिजली देने की दिशा में वास्तविक प्रयत्न भी आरम्भ नहीं किये। उन्होंने जो कुछ किया इतना सब ही जाने के बाद ही किया।

वे आरम्भ से ही ग्रामीण विद्युत् प्रशासन के कार्यक्रम और विशेष रूप से सहकारियों के विरुद्ध सघर्ष करते रहे। सहकारी, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए वाशिंगटन में उनका जो प्रमुख व्यक्ति रहता है उसे राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युत् सहकारी सघ (National Rural Electric Cooperation Association) के मुख्य व्यवस्थापक से कई गुना अधिक वेतन दिया जाता है। यह स्थिति आज ही नहीं, १९५९ में भी थी, जब कि राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युत् सहकारी सघ की गाँवों के विद्युत् उपभोक्ताओं में सदस्य-संख्या ४५ लाख से भी अधिक थी और वह

देश के बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सगठनों में गिना जाता था। लेकिन जब सहकारियों ने यह दिखा दिया कि देहाती क्षेत्रों में विद्युत् प्रदाय एक 'अच्छा व्यवसाय' हो सकता है तो लाभार्जन करनेवाले सारे-के-सारे व्यावसायिक अधिष्ठान इस नव विकसित व्यापार को हड़पने के लिए दौड़ पड़े। इसके लिए उन्होंने कई तरह के हथकण्डे अपनाये। विद्युत् सहकारी के रूप में 'समाजवादी खतरों' से सचेत करने वाले खर्चीले राष्ट्रव्यापी विज्ञापन कार्यक्रम शुरू किये गए। सहकारियों के कार्य क्षेत्र को सबसे सघन वस्तियों को अपनी ओर करने के लिए भेद नीति-स्वरूप नई विद्युत् प्रदाय लाइनें बनाई गई, जो कालान्तर में 'विद्वेष लाइनों' के नाम से प्रख्यात हो गई। सहकारियों के स्वामियों को फुसलाने के लिए, जिससे वे अपना कारबार उस क्षेत्र को प्रमुख व्यावसायिक विद्युत् कम्पनी के हाथ बेच दे, मुनियोजित अभियान बड़े कुशल ढंग से आरम्भ किये गए।

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया इन सारे हथकण्डों को उतने ही अधिक जोर-शोर से आजमाया गया और उधर कॉंग्रेस पर ज्यादा-से-ज्यादा दबाव डालने के प्रयत्न तो बराबर होते ही रहे।

उन्हे इक्की-दुक्की जगहों में सफलता भी मिली।

अधिकांश विद्युत् सहकारी परम निष्ठावान् सदस्यों वाले सुदृढ़ संगठन हैं, जिनकी वार्षिक सभाओं में सैकड़ों और कभी-कभी तो हजारों की संख्या में सदस्य उपस्थित होते हैं और उन सगठनों को अपने सदस्यों पर अभिमान भी कम नहीं है। इओवा के विद्युत् सहकारी को इस बात का उचित गर्व है कि उसकी वार्षिक सभा में प्रतिवर्ष १० हजार सदस्य बराबर भाग लेते हैं। वहाँ की ये वार्षिक सभाएँ उस जिले का 'वर्ष का अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन' बन गई हैं।

लेकिन कुछ सहकारी सगठन की दृष्टि से काफी कमजोर हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके व्यवस्थापक तानाशाह बन बैठे हैं, मजाल है कि उनके बगैर पत्ता भी हिल जाए। जो जी में आता है करते हैं, न किसी की सुनते हैं न मानते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके सदस्यों में अब किसानों की संख्या कम और बहुमत ऐसे उपनगरवासियों का है जो जन्म से ही विद्युत् का सुखोपभोग कर रहे हैं।

वास्तव में ऐसे सदस्यों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है जिन्हें अपनी सहकारी संस्था द्वारा फारम पर पहले-पहल बिजली पहुँचाने की बात अच्छी तरह याद हो। उनके स्थान पर ऐसे लोगो की संख्या बराबर बढ़ रही है जो बिजली को सदा से चली आती साधारण बात समझते हैं, जिन्हें बिजली पाने के लिए कोई संघर्ष, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसलिए जहाँ सदस्यों की शिक्षा का कोई कार्यक्रम नहीं है, जहाँ सदस्यों को सही और पूरी जानकारी देने वाले संवाद पत्र नहीं भेजे जाते और जहाँ सदस्यों के मन में स्वामीत्व के प्रति गर्व और गौरव की भावना को जगाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता वही विद्युत् सहकारियों को 'बेचने' के लिए की जानेवाली व्यावसायिक बिजली कम्पनियों की चिकनो-चुपड़ी बातों और फुसलावों के सफल होने का अधिक सम्भावना है।

विद्युत् सहकारियों को अपने क्षेत्र में जो भी लोग माँग करे उन सब को विद्युत्-सेवा प्रदान करनी होती है। अक्सर इस तरह की सेवा बड़ी महँगी पड़ती है। सहकारियों के ग्राहकों की औसत संख्या बिजली लाइन के प्रति मील पर उनके प्रबल प्रतिस्पर्द्धियों की औसत संख्या २५ की तुलना में केवल ३ है। कुल आय से संयंत्र और साधन में पूँजी निवेश का उनका अनुपात लाभार्जन वाली व्यावसायिक कम्पनियों की तुलना में तिगुना है। इसीलिए सहकारियों को अत्यन्त कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करते हुए काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त १९५० के बाद के वर्षों में तो उनपर राजनैतिक प्रहारों में भी खूब वृद्धि हुई है। इन राजनैतिक प्रहारों का मुख्य लक्ष्य यह रहा है कि ग्रामीण विद्युत् सहकारियों को ग्रामीण विद्युत् प्रशासन से कर्ज प्राप्त करने की सुविधा से वंचित कर दिया जाए और व्यापारिक पूँजी बाजार में कर्ज लेने को विवश किया जाए। इस आशय की माँगों और प्रस्तावों को बार-बार दुहराया गया।

विद्युत् सहकारियों पर राजनैतिक प्रहार की एक दूसरी दिशा भी है; वह है कांग्रेस को उन कर्जों पर रोक लगाने के लिए राजी करने का प्रयत्न जो ग्रामीण विद्युत् प्रशासन द्वारा सहकारी आधार पर विद्युत् उत्पादन और पारेषण साधनों के वित्तीय प्रबन्ध के लिए दिये जाते हैं।

यह बात समझ में तो आती है, लेकिन साथ ही सहकारियों के लिए

अत्यन्त भयावह भी है। समझ में तो इसलिए आती है कि यदि ग्रामीण विद्युत् सहकारियों पर यह रोक लगा दी जाए कि जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर भी वे विद्युत् उत्पादन का अपना प्रवन्ध नहीं कर सकते तो उन्हें विवश होकर अपनी प्रतिद्वन्दो व्यावसायिक विद्युत् कम्पनियों की कृपा पर ही निर्भर करना पड़ेगा।

वितरण सहकारियों के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि वे अपने द्वारा वितरित की जाने वाली विद्युत् की पूरी मात्रा या उसका अधिकांश स्वयं ही उत्पादित करें। सचाई तो यह है कि वे १९५९ में अपने द्वारा दी जाने वाली बिजली के केवल १५ प्रतिशत का ही उत्पादन कर रहे थे। लेकिन आरम्भ से ही उन्हें यह दुःख अनुभव हो गया था कि विद्युत् का कुछ-न-कुछ उत्पादन तो उन्हें स्वयं करना ही होगा।

बिजली लाइनों का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने के बाद सहकारी वितरण संस्थाओं के सम्मुख जो सबसे बड़ी समस्या मँह बाये आ खड़ी हुई वह थी उचित दरो पर थोक बिजली का उपलब्ध न होना। सब जगह यही स्थिति रही हो सो बात नहीं; कुछ अपवाद भी अवश्य थे, विशेष कर उन क्षेत्रों में जहाँ विद्युत् प्राप्ति के सरकारी साधन सुलभ थे। लेकिन वैसे आम तौर पर व्यापारिक कम्पनियों ने विद्युत् प्रदाय के अनाप-शनाप दाम माँगे और केवल इसीलिए कि किसानों ने अपनी आवश्यकताओं को संगठित कर उसे पूरा करने के लिए नई चमचमाती बिजली लाइनें बना ली थी।

इसलिए जो मार्ग पेट्रोलियम सहकारियों को अपनाना पड़ा था और हर प्रकार के सहकारी को अपनाना ही होगा जब वह इतना शक्तिशाली हो जायेगा सार्थक ढंग से प्रतिस्पर्द्धा कर सके तो वही मार्ग विद्युत् वितरण सहकारियों को अपनाना पड़ा और कुछ क्षेत्रों में उन्होंने विद्युत्-उत्पादन के अपने स्वतन्त्र साधनों को विकसित करना प्रारम्भ कर दिया। केवल यही दिखा देना काफी नहीं था कि बहुत सारे सामान्य जन इकट्ठा होकर विद्युत्-वितरण प्रणाली का संगठन, उसके स्वामित्व का भार वहन और सफल संचालन कर सकते हैं; लेकिन यह प्रमाणित कर देना भी निव्वान्त आवश्यक हो गया था कि जहाँ तक विद्युत् के उत्पादन का प्रश्न है उसे भी सहकारिता की पद्धति को अपना कर लोग 'अपने लिए' अवश्यमेव कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध मे डेरीलैण्ड पावर कोआपरेटिव की कहानी आदर्श कहानी है। १९३७ मे दस विद्युत् वितरण सहकारो सस्थाओ के प्रतिनिधियो की एक बैठक मे इसका जन्म हुआ। वह बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि विसकोन्सिन की व्यापारी बिजली कम्पनियो ने उन्हे थोक मे प्रति किलोवाट-घटा ढाई सेट की दर से कम पर बिजली देना अस्वांकार कर दिया था और ये दरे अत्यधिक महंगे थी। तब उन्होने सोचा कि थोक बिजली के अपने ही साधन का निर्माण कर लेना सबसे बढिया बात हांगी। और अन्त मे उन्होने विसकोन्सिन पावर कोआपरेटिव की स्थापना की।

ग्रामीण विद्युत् प्रशासन से साढ़े छ लाख डालर का कर्ज प्राप्त किया गया और एक वर्ष के बाद उत्तरी विसकोन्सिन की सात सहकारी सस्थाएँ किसानो को अपनी बिजली लाइनो से जो विद्युत् प्रदान कर रही थी उसका जनित्रण चिप्पे वा फाल्स के उन्ही के डिजल जनित्रा ने किया था।

जो कठिनाई उत्तरी विसकोन्सिन के वितरण सहकारियो को अनुभव करनी पडी ठीक वही इओवा, मिन्नेसोटा और दक्षिणी विसकोन्सिन के वितरण सहकारियो के सामने भी आई। उचित दरो पर थोक बिजली इनमे से किसी को कही से भी प्राप्त न हो सकी। तब इन सबने मिल कर त्रि-राज्यीय विद्युत-शक्ति सहकारी (Tri-Stated Power Cooperative) संगठित की और विसकोन्सिन के जेनोआ नामक स्थान मे एक वाष्प नयत्र का निर्माण किया, जो १९४१ मे बन कर पूरा हो गया।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस सयत्र का निर्माण-कार्य पूरा होने से कुछ ही समय पहले उस क्षेत्र की तीन व्यापारी कम्पनियो ने एक नया निवेद किया। वे विद्युत् सहकारियो को पहले मांगी गई दरो से बहुत कम पर थोक बिजली देने को तैयार हो गई। जिस तरह पेन्सिले एकदम नुकीली हो जाती है उसी तरह वे एक दम सचेष्ट हो गए थे और उनकी वणिक् बुद्धि जाग पड़ी थी। पर क्यों ?

केवल इसलिए कि किसान अब यह प्रमाणित करने जा ही रहे थे कि वे अपने लिए बिजली का उत्पादन स्वयं कर सकते है—और व्यावहारिक अनुभव से उन्हे यह भी मालूम हो ही जाता कि उत्पादन को वास्तविक लागत कितनी होती है।

१९४१ के अक्टूबर महीने में विसकोन्सिन विद्युत्-शक्ति सहकारी और त्रि-राज्याय-विद्युत्-शक्ति सहकारी का विलयन कर डेरालैण्ड बना दी गई। उसके बाद तो बहुत-से नये सयत्र निर्मित हुए, नई-नई बिजली लाइनें बनाई गई, कारवार की नई आर्थिक पद्धतियाँ प्रयोग में लाई गई। अधिकांश सयत्र वाष्प-सयत्र हैं, जो कोयले से चलते हैं और वह कोयला इलिनोइस और केण्टुकी की खानों से मिसिसिपी की राह भारवाही डोंगों से लाया जाता है। लेकिन एक पन-विद्युत् सयत्र भी है जो पलाक्व्यू नदी पर साठ लाख डालर से भी अधिक की लागत से बनाया गया है। इस सयत्र के निर्माण में इतना अधिक पैसा केवल इसलिए लग गया कि कुछ लोगों ने इसका घोर विरोध किया जिससे देर-पर-देर होनी गई और लागत खर्च बढ़ता चला गया। विरोधी शक्तियाँ शायद यह कहना ओर कर दिखाना भी चाहती थी कि विद्युत् सयत्र के निर्माण का कार्य किसानों की भोड़ के उपयुक्त नहीं है; बड़े नगरों में बड़े दफ्तरों वाली बड़ी कम्पनियाँ को ही ऐसे कार्य करने का एकमात्र अधिकार है।

लेकिन फिर भी किसानों ने इस काम को कर ही डाला। फारमों और देहाती क्षेत्रों में जैसे-जैसे विद्युत्-शक्ति की माँग बढ़ती गई डेरालैण्ड भी अपनी क्षमता को बढ़ाता चला गई—पहले दुगुना किया और फिर तिगुना। विरोधियों ने हर बार शोर मचाया कि डेरालैण्ड के बढ़े हुए सारे उत्पादन की खपत उसके सदस्यों में ही नहीं हो सकती। लेकिन सत्य तो यही है कि हर बार क्षमता के विस्तार के बावजूद सदस्यों की विद्युत्-शक्ति-सम्बन्धी माँग को पूरा नहीं किया जा सका।

अकेले १९५० में ही डेरालैण्ड के सदस्यों को २० लाख डालर की बचत हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापारी कम्पनियाँ ने जो कम-से-कम दरे बताई थीं उनपर थोड़ा खरोदने से जितना मूल्य देना पड़ता उसकी अपेक्षा अपनी ही प्रणाली से लेने पर २० लाख डालर कम देना पड़ा।

पड़ोसियों के साथ मिलकर स्वयं काम किया जाए तो अवश्य सस्ता पड़ता है और लाभ भी होता है।

१९५८ में जब डेरालैण्ड के किसान और दूसरे ग्रामीण ग्राहक-स्वामियों की संख्या एक लाख से भी अधिक हो गई तो उसने एक दूसरा चमत्कार

कर दिखाया। वह चमत्कार यह था कि पिछले दस वर्षों पर जीवन-निर्वाह-सूचकांक जहाँ ३० प्रतिशत बढ़ता जा रहा था वहीं डेरीलैण्ड की बिजली का लागत मूल्य ३५ प्रतिशत कम कर दिया गया। और १९५९ मे तो थोक बिजली प्रति किलोवाट-घटा एक सेंट से भी कुछ कम पर ही दी जा रही थी।

स्वावलम्बन ने बड़ा काम किया। इसका शुभ परिणाम केवल विसकोन्सिन मे ही नहीं मध्य इओवा मे, केण्टुकी मे, मिसौरी मे और जहाँ-जहाँ भी वितरण सहकारियों ने मिलकर अपने निजी विद्युत् जनित्र सहकारियों की स्थापना की थी वहाँ सभी जगह हुआ।

व्यापारी कम्पनियों के गोष्ठी कक्ष (लॉबी) ने कांग्रेस के आगे बहुत चिल्ल-पौ मचाई। उसने ऐसा कानून बनाने पर बहुत अधिक जोर दिया जिससे ग्रामीण विद्युत् प्रशासन विद्युत् शक्ति के जनित्रण और पारेषण के लिए किसी भी प्रकार का कर्ज दे ही न सके। उनका गोष्ठी कक्ष तो यही चाहता था कि विद्युत् सहकारी अपनी आवश्यकता की हर किलोवाट विद्युत् शक्ति के लिए अपने प्रतिद्वन्द्वियों के मुहताज हो जाएँ—उन्हीं प्रतिद्वन्द्वियों के जो प्रारम्भ से ही उनसे युद्ध ठाने हुए थे और घृणा करते थे।

लेकिन कांग्रेस ने उनकी एक न सुनी।

स्वावलम्बन ने और दिशाओ मे भी कुछ काम किये। विसकोन्सिन विद्युत् सहकारी ने बड़े साहस से एक दूरदर्शिता पूर्ण कदम उठाया। इस सहकारी ने एक स्वतन्त्र एल्यूमिनियम कम्पनी से युद्धोत्तर काल मे सरजाम-सामग्री और केबल की जो घोर कमी थी उसे दूर करने और गाँवों मे विद्युत् विस्तार के लिए अत्यन्त आवश्यक इन वस्तुओं के एकाधिकारियों द्वारा निर्धारित मूल्यों को घटाने के सम्बन्ध मे सविदा किया। इस कदम मे जोखिम तो बहुत था, परन्तु फिर भी बात बन गई। दो तरह से लाभ हुआ। विद्युत् सहकारियों के विकास और विस्तार को ही नहीं एल्यूमिनियम के खपत बाजार को भी एकाधिकारी पूँजी के कुछ बहुत ही अनिष्टकारी प्रभावों से मुक्त किया जा सका।

१९५० के बाद की पूरी दशाब्दी मे ग्रामीण विद्युत् सहकारियों तथा अन्य पारस्परिक एव सहकारी उद्यमों पर प्रहार का वेग निरन्तर बढ़ता ही गया। सहकारियों के प्रतिद्वन्द्वियों द्वारा समाचार पत्रों मे बड़े-बड़े, पूरे पृष्ठों के विज्ञापन

प्रकाशित करवाये जाते थे और उनमें यह दिखाया जाता था कि विद्युत् सहकारियों को सरकार से काफी मोटी आर्थिक सहायताएँ मिलती हैं, ये सहकारी करदाता पर भोषण आर्थिक बोझ बने हुए हैं; सहकारी अनुचित होड़ करते हैं; सहकारी का 'अमरीकी जीवन-पद्धति' से जरा भी मेल नहीं; आदि-आदि। ऊँचा वेतन फटकारने वाले लाबीबाज बार-बार इन माँगों को दुहराने लगे कि जनित्रण और पारेषण के लिए दिये जाने वाले कर्जों में एकदम कमी कर दी जाए, ग्रामीण विद्युत् प्रशासन सहकारियों को जिन दरों पर व्याज देता है उनमें तत्काल वृद्धि की जाए, और अधिक अच्छा तो यही होगा कि ग्रामीण विद्युत् प्रशासन को ही भग कर दिया जाए; और देश के उस समय के प्रशासकीय अधिकारी इन माँगों का समर्थन करते थे ! इस बात पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया कि विद्युत् सहकारियों को अपने वित्तीय प्रबन्ध के लिए नियमित साधनों का ही आश्रय लेना चाहिए, अर्थात् बैंको, बीमा कम्पनियों और साहूकार पेढियों के दरवाजे खटखटाना चाहिए। निजो व्यापारी कम्पनियों के समस्त कर्मचारियों ने इस बात के लिए अपना सारा जोर लगा दिया कि किसी तरह विद्युत् सहकारियों के सदस्यों की निष्ठा को ढिगाया और उन्हें अपने कारवार को व्यापारी गुटों के हाथ बेचने के पक्ष में मत देने के लिए फुसलाया जा सके। यह जाना-माना तथ्य होते हुए भी कि बहुत से जिलों में विद्युत् सहकारी बड़े करदाताओं में गिने जाते हैं, उन पर 'कर-मुक्त' होने का आरोप गला फाड़-फाड़ कर लगाया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युत् सहकारी सघ (National Rural Electric Cooperative Associations) जो १९४२ से विद्युत् सहकारियों की सेवा और सहायता का, उनकी ओर से जन-सम्पर्क का और उनके वैधानिक संरक्षण के रूप में कार्य करने वाला राष्ट्रीय स्तर का केन्द्रीय संगठन रहा है और जिसको इतना सक्रिय नेतृत्व प्रदान करने का श्रेय भूतपूर्व कांग्रेसमैन क्लाइड टी० इलिस को है, उसे कड़ी अग्नि परीक्षाओं और जबर्दस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

और यह सब हुआ अमरीकी कृषि के लिए परिवर्तन, दबाव, तंगी और कठिनाइयों के ऐसे समय जब कि फारमों की सख्या निरन्तर घटती जा रही थी, जब कि फारमों, कस्बों और शहरों तक के बीच की बिजली लाइनें ठण्डी

पड़ती जा रही थी और जब विद्युत् सहकारियों द्वारा लगाये हुए चार लाख मीटर (मापक यन्त्र) सुन्न पड़े थे, क्योंकि उन फारमों पर एक भी आदमी नहीं था।

ऐसे समय सहकारियों के खिलाफ इतनी कटु आलोचना का कारण समझ में नहीं आता। दोमे से एक ही बात हो सकती है; या तो लोगों को आमतौर पर तथ्यों की जानकारी नहीं होती, या वे उनके बारे में कुछ सोचते ही नहीं।

सच्चाई यही है, कि संयुक्त राज्य अमरीका ने ग्राम्य विद्युतन कार्यक्रम से काफी पैसा कमाया है। सहकारियों ने अपना कर्ज हमेशा निर्धारित समय से पहले ही चुकता किया है। ब्याज का २ प्रतिशत दर भी इस कार्यक्रम के समस्त प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए काफी है।

सहकारी अपने प्रतिस्पर्द्धियों द्वारा चुकाये जाने वाले सभी कर चुकाते हैं, और जैसा कि कहा जा चुका है, कुछ मामलों में तो राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कर चुकाने वालों में वे ही सबसे बड़े और प्रमुख करदाता होते हैं। यह सच है कि विद्युत् सहकारियों को सघीय आयकरो से छूट मिली हुई है, जो किसी भी तरह के दूसरे सहकारियों को नहीं दी गई है। इस छूट का प्रावधान इसलिए किया गया कि विद्युत् सहकारी किसी भी उपभोक्ता की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वह उस सहकारी का सदस्य नहीं बन जाता। इस तरह की छूट देने का उद्देश्य यह है कि सहकारियों का संगठन लाभार्जन विहीन ऐसे व्यवसायों के रूप में ही किया जाना चाहिए, जिनकी सारी कमाई उनके सदस्यों को सम्पत्ति होती है, न कि सहकारियों की। इसलिए आयकर चुकाने की पूरी जिम्मेवारी उन सदस्यों की है, सहकारियों की नहीं। अपनी सहकारी संस्थाओं से प्राप्त सरक्षण धन वापसियों के कारण उनकी आय में जितनी भी वृद्धि हो अथवा व्यवसाय करने की उनकी लागत जितनी भी कम हो उसी अनुपात में उन सदस्यों से आयकर लिया जाना चाहिए। कभी-कभी सरक्षण धन वापसी की अदायगी नकद रूपों में की जाती है; लेकिन अधिकतर वह 'पूँजी गत जमा पत्र' के रूप में होती है, जो सहकारी विद्युत्-शक्ति व्यवसायों के स्वामीत्व के सम्बन्ध में इस आशय के प्रमाण पत्र हैं कि उन व्यवसायों पर साम्या (न्यायतः समान अधिकार) उस व्यवसाय के सदस्यों का ही है। १९५९ तक देश के विद्युत् सहकारी व्यव-

साय पर इन-सदस्यों का औसत साम्या स्वामीत्व १७ प्रतिशत तक हो चुका था; लेकिन बहुत तेजी से विकसित हो रहे इन सहकारी व्यवसायों की पूँजी की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए ५० प्रतिशत साम्या स्वामीत्व की जो शर्त बहुत से ऋणदाता लगाते हैं, उससे अभी यह बहुत कम है। तात्पर्य यह कि 'प्रचलित' दरों पर कर्ज मिलने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती।

ग्रामोण विद्युत् प्रशासन द्वारा विद्युत् सहकारियों को इतने न्यून व्याज पर ऋण दिया जाना उनके साथ किये गए सविदा करार का ही एक भाग है। ऋण को इन न्यूनतर दरों का दूसरा पहलू यह है कि विद्युत् सहकारियों को लागत को चिन्ता किये बिना अपने क्षेत्र के सभी इच्छुको उपभोक्ताओं को सेवा अनिवार्यतः करना होती है, प्रचुर खपत वाले सघन उपभोक्ता क्षेत्र उन्हें मुलुम नहीं होते, वस्तुतः उन पर यह प्रतिबन्ध होता है कि वे पन्द्रह सौ में अधिक जनसंख्या वाले समुदाय की सेवा नहीं करेंगे।

ये विद्युत् सहकारी अमरीका की एक नये प्रकार की व्यापारी संस्था हैं। इनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, वस्तुतः ये बहुत अच्छे व्यवहार के अधिकारी हैं। जहाँ पहले न बिजली की रोज़नी थी और न विद्युत् शक्ति। उन फार्मों और गाँवों के घरों और पाठशालाओं और गिरजा-घरों में इन्हीं ने बिजली की रोज़नी और विद्युत् शक्ति को पहुँचाया। हमारे उद्योग का ग्रामोण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण इन्हीं की कृपा से सम्भव हो सका। सभी प्रकार के विद्युत् उपकरणों और सेवाओं की खपत का इन्होंने कितना विशाल और नया बाजार खोल दिया है।

इन्होंने और भी महान कार्य किया, क्योंकि विद्युत् शक्ति आधुनिक अर्थ व्यवस्था और सामाजिक जीवन का प्राण है। इसके बिना न तो कोई उद्योग चल सकता है और न कोई व्यापार, न कोई नगर और न कोई कस्बा—इसके अभाव में सभी ठप्प हो जाते हैं। आज विद्युत् प्रदाय जिसकी मुट्ठी में है राष्ट्र भी उसी की मुट्ठी में है।

इसीलिए विद्युत् शक्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए—निजी व्यापारी-सम्राटों का तो कदापि नहीं।

बड़ी-बड़ी व्यापारी कंपनियों के हाथ में हमारे विद्युत्-शक्ति व्यवसाय

का ८५ प्रतिशत केन्द्रित है। इनकी तुलना में विद्युत् सहकारियों का कुल राष्ट्रीय व्यवसाय वास्तव में बहुत ही थोड़ा है। फिर इन बड़ी-बड़ी व्यापारी कम्पनियों को इन सहकारियों के विरुद्ध इतना विष-वमन और इन पर इतनी चतुराई और इतने अस्त्र-शस्त्रों से आक्रमण क्यों करना चाहिए ?

क्या यह प्रत्येक विचारवान अमरीकी के लिए महान गर्व की बात नहीं है कि हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ दिवालिया होने जा रहे किसानों के समूह अपने अच्छे-भले नामों और अच्छी-भली साख पर और सहकारिता तथा पारस्परिक सहायता की पद्धति को अपना कर बड़ी मन्दी के दौर से बच कर निकल आये और अपने लिए बिजली कम्पनियाँ बना सके ? क्या हमें इस तथ्य से प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि एकाधिकार से समस्त जर्जर उद्योग में स्वस्थ प्रतियोगिता के प्राण पूरित किये गए ? क्या यह सच नहीं है कि समूची अर्थ-व्यवस्था और वाणिज्य के लिए जिस पर आवश्यक नीति का समर्थन किया जा सकता है वह बगैर घाटे की, न्यूनतम लागत पर उत्पादन और वितरण की ही नीति हो सकती है ? यदि हाँ, तब तो विद्युत् सहकारी सारे अमरीकावासियों के धन्यवाद और समर्थन के अधिकारी हैं।

और यह भी क्या कम उल्लेखनीय है कि विद्युत् सहकारियों का—और दूसरे सहकारियों का भी विरोध प्रायः उनके क्षेत्र से बाहर और दूर के ही लोग करते हैं। जिन क्षेत्रों में सहकारी बनाये जाते और काम तथा सेवा करते हैं वहाँ के लोग कभी इनका विरोध नहीं करते—यहाँ तक कि घोर अनुदार और कट्टर पुराणपन्थी व्यापारी भी नहीं।

क्योंकि उन्होंने परिवर्तन और रूपान्तर के आधुनिक चमत्कार को घटित होते देखा और अनुभव किया है; और उनका जीवन उससे पूर्णतः प्रभावित हुआ है, बल्कि आमूल बदल ही गया है, जैसा कि जार्जिया के एक देहाती डाकिये का कहना है : “जो प्रदेश पहले अत्यन्त पिछड़ा हुआ, आदिम ढंग से खेती करने वाला, मलेरिया ग्रस्त घोर जंगल था वही अब आधुनिक कृषि का उन्नत क्षेत्र हो गया, जहाँ के लोग दैनिक पत्र मँगवाते हैं, अपने बच्चों को कालेज भेजते हैं, रात में बिजली की रोशनी में पढ़ते हैं और जहाँ की माँ के पास माँ बनने का समय है।”

अमरीकी प्रणाली के गर्व और गौरव की एक बात यह है कि ४५ लाख किसान और ग्रामवासो इस महान औद्योगिक राष्ट्र के मूल उद्योग के एक अंश के स्वामी हैं। ग्रामीण विद्युत् सहकारी की कहानी इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारी प्रणाली का प्रत्येक को लाभ पहुँचाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे यह भी प्रमाणित होता है कि जनता अपने स्वयं के प्रयत्नों से इस प्रणाली का ऐसा उपयोग कर सकती है। और इससे यह भी प्रमाणित होता है कि सहकारिता हमारे देश के लिए—सहकारियों के प्रतिस्पर्द्धियों सहित हमारे समूचे देश के लिए बहुत अच्छी चीज है।

क्योंकि सहकारियों ने यह दिखा दिया कि किसान बिजली का खर्च भुगत सकते हैं, यदि वह उन्हें उचित दरों पर दी जाये। यह काम करके सहकारियों ने केवल अपने व्यवसाय के लिए ही नहीं अपने प्रतिस्पर्द्धियों के व्यवसाय के लिए भी खपत का कितना विशाल बाजार खड़ा कर दिया।

जिन बाधा-बन्धनों और सीमाओं के अन्तर्गत विद्युत् सहकारियों को अपना काम करना पड़ता है उसे देखते हुए उनसे लिये जाने वाले व्याज की दरे और उनकी कराधान स्थिति सर्वथा उचित ही है। यहाँ इस बात का उल्लेख किये बिना नहीं रहा जा सकता कि इतनी बाधा-बन्धनों और मर्यादाओं के रहते हुए भी विद्युत् सहकारियों ने उस उद्योग में, जिसकी गति बहुत कुछ अशोभे में अवरोध हो गई थी, एक नये प्रकार की सक्रियता प्रवर्तित की। उन्होंने एकाधिकार को उस उद्योग में औद्योगिकीय बिकारी बढ़ाने से रोका। प्रतिस्पर्द्धियों की ओर से उन पर जो प्रबल प्रहार किये जा रहे हैं वे ग्रामीण अमरीका की अर्थ व्यवस्था में उनकी सफलता, महत्त्व और स्थायित्व के ही उत्कृष्ट प्रमाण हैं।

१९६१ में जब (स्वर्गीय) जान एफ० केनेडी ने राष्ट्रपति-पद संभाला तो विद्युत् और दूसरे सभी सहकारियों के भावी विकास को सम्भावनाएँ बहुत उज्ज्वल हो गईं। क्योंकि निर्गामी प्रशासन के प्रतिकूल मिस्टर केनेडी और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी देश के विद्युत् सहकारियों की आवश्यकताओं, समस्याओं और उपयोगिता को ज्यादा अच्छी तरह समझते थे।

६ | एकाधिकारी शक्ति और स्वतन्त्रता की आशा

युद्धोत्तर कालीन अमरीका में रहन-सहन के स्तर में निरन्तर उन्नति, वर्ग-भेदों के अस्पष्ट होते जाने और सम्पत्ति, स्वामीत्व एवं आय के अधिक व्यापक वितरण के सम्बन्ध में काफी बढ़ा-चढ़ा कर बातें कही जाती रही हैं। युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों में इन तीनों प्रवृत्तियों के सबल होने के ठोस प्रमाण भी उपलब्ध हुए। कारखानों के आगे उनमें काम करने वाले मजदूरों की मोटरों की कतारें तो अब भी विदेशी पर्यटकों के लिए अमरीका की भव्य दर्शनोपयोगिताओं में से हैं। दूसरे देशों में मजदूरों के पास मोटरों की जगह अधिक-से-अधिक बाइसिकलें होंगी, या कुछ भी न होगा।

रहन-सहन का स्तर बराबर उन्नत होता रहा और वर्गभेद इस सीमा तक तो अस्पष्ट रहे ही कि वेशभूषा और वस्त्राभूषणों से अब भी यह नहीं पहचाना जा सकता कि कौन स्टैनोग्राफर है और कौन सम्पन्न महिला, लेकिन सम्पत्ति आदि के व्यापक वितरण की बात तथ्यों से जरा भी मेल नहीं खाती—वह निरी डींग ही बनी रही। उलटे, आर्थिक शक्ति थोड़े से और भी थोड़े हाथों में सिमटती चली गई। उद्योग-धन्धे अधिकाधिक मात्रा में 'तीन बड़ों' या 'चार बड़ों' के प्रभुत्व में आते जा रहे हैं। जन संख्या का बहुत ही छोटा-सा भाग उद्योगों के साम्यवादी स्वामीत्व को पूरी सार्थकता से अपने अधिकार में किये हुए है। और औद्योगिक दानवों से सही अर्थों में स्वतन्त्र छोटे व्यवसाय के लिए तो टिके रहना भी अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है।

१९५२ में संयुक्त राज्य अमरीका में साठे सैंतीस लाख परिवारों के एक या एकाधिक सदस्य निगम पूँजी के एक या एकाधिक हिस्सों के स्वामी थे। उसके बाद चार वर्षों तक स्वामीत्व को विस्तारित करने और 'जनता के पूँजीवाद' को आंशिक सत्य का रूप देने के लिए घोर अभियान किया गया तो १९५६ में निगम पूँजी के स्टाकधारियों की संख्या ३५ लाख परिवारों के सदस्यों तक

विस्तारित की जा सकी। लेकिन चार करोड़ परिवार फिर भी ऐसे रहे जिनमें से किसी के पास निगम पूँजी का एक भी हिस्सा नहीं था।

संयुक्त राज्य अमरीका के निगमों में दस में केवल एक ही परिवार एक हिस्से तक का स्वामी होगा। इसके विपरीत चार में से एक परिवार के पास एक या एक से अधिक सहकारियों के एक या एकाधिक हिस्से हैं। सहकारी व्यवसायों के हाथ में कुल राष्ट्रीय व्यापार का केवल २ प्रतिशत है और देश के सारे पजीकृत निगमों के पास ८५ प्रतिशत, फिर भी उनकी अपेक्षा ढाई गुना परिवारों को सहकारियों ने व्यापार के स्वामीत्व का अवसर प्रदान किया है।

यह बात विचारणीय है, और यदि हम 'जनता के पूँजीवाद' को लाने के लिए वास्तव में उत्सुक हों तब तो हमें इस तथ्य पर और भी अधिक विचार करना चाहिए।

विक्टर पलों ने 'अमरीकन इकानामिक रिव्यू' में हाल ही में प्रकाशित अपने एक लेख में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि निगमों के चार अरब डालर मूल्य के हिस्से (स्टॉक) डुपाण्ट परिवार के पास हैं और राकफेलर एवं मेलन परिवारों में से प्रत्येक के पास तीन-तीन अरब डालर के; लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका के सभी मजदूरों के पास कुल मिलाकर इस तरह के हिस्से ७५ करोड़ डालर से भी कम के ही होंगे।

१९२९ की बड़ी मन्दी से लेकर १९४७ तक झुकाव धन और सम्पत्ति के स्वामीत्व को ज्यादा-से-ज्यादा लोगों तक फैलाने की ओर था। उसके बाद प्रवाह की दिशा पलट गई और १९५३ में २ प्रतिशत से भी कम लोग राष्ट्र की वैयक्तिक सम्पत्ति के ३० प्रतिशत के स्वामी थे। निगम पूँजी के कुल हिस्से का ८० प्रतिशत और राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासनों के सारे-के-सारे ऋण पत्र (बाण्ड) भी वस्तुतः इन्हीं लोगों के पास थे। ये तथ्य हमें नेशनल व्यूरो ऑफ इकानामिक रिसर्च से प्राप्त हुए हैं।

लघु व्यवसायों की समस्याओं पर संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि सदन (United States House of Representatives) की विशेष समिति ने यह जानकारी प्राप्त की कि देश की साढ़े इक्यावन प्रतिशत विनिर्माण आस्तियों पर १९५२ में सबसे बड़े ५०० निगमों का स्वामीत्व था, जो केवल तीन साल

बाद १९५५ में बढ़कर ५७ प्रतिशत हो गया। समिति ने थोड़ा हिसाब लगाकर यह चिन्तनीय भविष्यवाणी की कि यदि यही गति रही तो १९७८ तक देश के सारे कारखानों पर इन ५०० निगमों का स्वामीत्व हो जाएगा।

स्वामीत्व के संकेन्द्रण के साथ-ही-साथ नियन्त्रण और निर्णय का संकेन्द्रण भी होता ही है। १९५९ के मार्च महीने में 'वालस्ट्रीट जरनल' ने क्रिस्लर कार-पोरेशन के अध्यक्ष के इस कथन का उल्लेख किया था कि थोड़ी जगह में खड़ी रखी जानेवाली छोटी मोटर बनाने का क्रिस्लर का निर्णय जनरल मोटर्स और फोर्ड के इस प्रकरण से सम्बन्धित निर्णय पर निर्भर करता है। अध्यक्ष महोदय ने यह तो अवश्य नहीं कहा था, लेकिन सचाई यही है कि ऐसी छोटी मोटर का बिक्री मूल्य भी पूर्णतः जनरल मोटर्स द्वारा निर्धारित कीमत पर ही निर्भर करता है।

कई बार तो छोटे व्यवसायों को समझ में ही नहीं आ पाता कि इस नई व्यवस्था में अमरीकी व्यवसाय को चलाया किस तरह जाए।

१९५७ में लघु व्यवसाय प्रशासन (Small Business Administration) से कर्ज पानेवाले एक छोटे नानबाई ने एक बड़े सैनिक रसद विभाग का रोटियों को आपूर्ति का ठेका लेने का निश्चय किया। उस समय तक चार बहुत बड़ी-बड़ी नानबाइयों को ही वहाँ का ठेका मिलता रहा था। केवल राई की रोटियों को छोड़ कर वे चारों हमेशा बाकी रोटियों के लिए एक ही दर भरा करते थे। सफेद रोटियों के लिए उन सबकी दरें हमेशा साढ़े सत्रह सेंट होतीं और दूसरे प्रकार की रोटियों के लिए इससे मिलती-जुलती। राई की रोटियों की दरों के लिए वे पर्ची डाल कर पहले तय कर लेते थे कि जिसका नाम खुले वही दूसरों से एक सेर कम भर दे। इस तरह जो एक सेर कम भरता उसी को ठेका मिल जाया करता था।

इस बार छोटे नानबाई ने १२ ७० सेंट की दरें भरीं जो अभी तक सेना द्वारा दी जाती रहीं दरों से बहुत न्यून थीं। लेकिन यह बात मालूम होते ही उन चार बड़ी नानबाइयों में से एक ने तत्काल अपनी दरें साढ़े दस सेंट कर दी, जो उनकी सदा की दरों से जो लगभग ४० प्रतिशत कम थी। और वह ठेका उस बड़ी नानबाई को मिल गया।

आज संयुक्त राज्य में अनुसन्धान और उन्नयन-सम्बन्धी सारे कार्यों का लगभग ८५ प्रतिशत केवल ३७५ बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा किया जाता है।

प्रतिरक्षा-सम्बन्धी सारे ठोकों का ९४ प्रतिशत हर बार बहुत बड़ी-बड़ी व्यापारी-संस्थाओं का वही-का-वही समूह मार ले जाता है।

सिर्फ निर्माण में ही नहीं दूसरे व्यापारों में भी एकाधिकार का प्रवेश बढ़ता जा रहा है।

१९३९ में देश में फुटकर खाद्यान्न भंडारों की संख्या ३,८७,००० थी, जो १९५४ में २, ७९,००० हो गई, यानी ३९ प्रतिशत कमी हुई। इतना ही नहीं, १९५४ में इन २,७९,००० भंडारों में से ६००० भंडार कुल बिक्री की एक तिहाई बिक्री कर रहे थे।

सहकारी लीग के जन सम्पर्क सम्मेलन को १९५८ में सघीय संचार आयोग (Federal Communication Commission) के एक सदस्य ने यह बताया कि ९० प्रतिशत दर्शक केवल दो टेलीविजन कंपनियों के पास हैं और न्यूयार्क सिटी को सिर्फ १८ कंपनियाँ कुल रेडियो टेलीविजन विज्ञापन का ८० प्रतिशत काम संभाले हुए हैं।

समाचार पत्रों को प्रतिद्वन्द्विता तो अब बीते जमाने की कहानी हो गई है। देश के कोई चौदह सौ नगरों में दैनिक पत्र हैं।

लेकिन समाचार पत्रों को चलाने वाले अलग और उनके स्वामी अलग ऐसे अधिक नहीं केवल दो भिन्न व्यक्ति अथवा भिन्न मस्थाएँ तो तीन सौ से भी कम नगरों में ही होंगी। बाकी स्थानों में तो जहाँ तक समाचार पत्रों का प्रश्न है, संवाद, सूचना और समाचारों पर एकाधिकार का पूर्णछत्र साम्राज्य है। आज तो समाचार पत्र की स्वतन्त्रता का अर्थ ही हो गया है जो जी में आये कहने के लिए अपने पैसों के बल पर समाचारपत्र के स्वामी बनने की मुट्ठी-भर लोगों की स्वतन्त्रता। संयुक्त राज्य की सीनेट के एक बड़े विशिष्ट और सर्वसम्माननीय सदस्य १९६० में तीसरी बार चुनाव के लिए खड़े हुए तो उन्हें यह आशा थी कि राज्य के नौकड़ी समाचार पत्रों में से अधिक नहीं तब भी एक या दो तो उनका अवश्य समर्थन करेंगे। वे जिस पार्टी से सम्बद्ध हैं वह देश के 'शक्ति-श्रेष्ठियों' को फूटी आँखों नहीं सुहाती। ये सीनेटर महोदय जिस राज्य के हैं वहाँ के सबसे बड़े नगर में डेमोक्रेटों का २ : १ या ३ : १ के अनुपात में बहुमत है। लेकिन नगर के चारों समाचार पत्र कट्टर रिपब्लिकन हैं, सिर्फ इसलिए कि

उनके मालिक रिपब्लिकन हैं। समाचारपत्र पक्षपात नहीं करता उसे करना भी नहीं चाहिए। वह तो सम्पत्ति है—अपने पूरे रूप में—उन लोगों की जिनका एक तरह का दृष्टिकोण है। और भिन्न विचारों एवं दृष्टिकोणों को प्रतिस्पर्द्धा तो कभी से भूत काल का बात ही गई है। समाचार पत्र हमारी है समनुरूपता का और दूसरों की भी इसी तरह के आचरण के लिए उद्बोधित करता है।

आर्थिक शक्ति के इस अत्यधिक केन्द्रीकरण के कुछ परिणाम तो बिल्कुल सामने ही हैं। 'फार्च्युन' नामक पत्र ने सबसे बड़े ५०० निगमों का जो वार्षिक सर्वेक्षण किया उससे पता चलता है कि उनके लाभ को वार्षिक औसत दर १० और १२ प्रतिशत के बीच में है। १९५९ की पहली छहमाही में युनाइटेड स्टेट्स स्टील ने बिक्री पर १० प्रतिशत और निवेशित पूँजी पर १७ प्रतिशत लाभ कमाया।

मुनाफा कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन विशाल व्यवसायी दानवों के मुकाबले छोटे व्यवसायों का औसत मुनाफा पचमाश और दशमाश भी मुश्किल से हो होगा।

इसका कारण यह है कि बड़ी कम्पनियाँ अपने उत्पादनों और सेवाओं की कोमते अपनी इच्छानुसार—व्यवस्थापित ढंग से—निश्चित करने की स्थिति में होती हैं १९५८ का गोष्ठी में इन्टरनेशनल मिनरल्स एण्ड केमिकल कारपोरेशन के उपाध्यक्ष नेल्सन सी० वाईट ने इसी बात को यों कहा है: “उद्योग की मूल्य-निर्धारण की पद्धति के सम्बन्ध में जितनी गलत फहमी है उतनी उसके काम करने के और किसी भी ढंग के बारे में नहीं है। इसके लिए अक्सर हमारी आलोचना की जाती है। हमारी ओर से अपना बचाव करने की तो इतनी जरूरत नहीं है, परन्तु स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक है। अपने निगमित उद्देश्यों को सम्पादित करने के लिए हर एक कम्पनी के पास मूल्य-निर्धारण साधन-स्वरूप है। इसलिए तो मूल्य-निर्धारण एक निश्चित नीति के अनुसार, एक निर्धारित योजना के अनुसार किया जाता है, अटकल पच्चू ढंग पर नहीं।” और जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है संयुक्त राज्य इस्पात कारपोरेशन द्वारा प्रकाशित 'इस्पात और मुद्रास्फिति से सम्बन्धित तथ्य एवं कपील कल्पनाएँ' नामक पत्रिका में पड़ा जा सकता है कि वर्तमान अमरीका में प्रचलित ८८ प्रति-

शत कोमते बनावटों तरोके से बढ़ाई हुई व्यवस्थापित ढग की कीमते हैं।

इस तरह की बनावटों कीमते की 'व्यवस्थापित कोमते' या व्यवस्थापित मूल्य' कहा जाता है, क्योंकि कम्पनियों का व्यवस्थामण्डल प्रशासनीय निर्णयों से उन्हें तय करता है। यह पद्धति उद्योग कर्मियों में लागू की जा सकती है जहाँ किसी उद्योग पर अपने ही जैसी तीन या चार विशाल कम्पनियों के साथ एकाधिकारी नियन्त्रण हो। व्यवस्थापित मूल्यों का साधारणतः आर्थिक परिस्थितियों से अथवा माँग और पूर्ति के नियम से कोई भी सम्बन्ध नहीं होता। फेडरल रिजर्व बोर्ड के अनुमन्थान निदेशक राल्फ ए० यंग ने इस्पात और मोटरो की मूल्य वृद्धि पर १९५९ के आरम्भ में टिप्पणी करते हुए अत्यन्त सक्षेप में कहा था 'अर्थशास्त्र की दृष्टि से वे बोग गम्य नहीं हैं।'

वास्तव में ही बोगगम्य नहीं हैं।

इस्पात और मोटरो की कीमते १९५९ में उस समय बढ़ाई गई जब माँग की अपेक्षा माल कहीं ज्यादा था। उस समय इस्पात उद्योग अपनी क्षमता का केवल ५० प्रतिशत के लगभग उत्पादन कर रहा था। मोटरो की विक्री अपेक्षा से बहुत कम हो रही थी, फिर भी कीमते बढ़ा दी गई, घटाई नहीं गई।

१९५० के बाद की दशान्दी में मुद्रास्फीति और डालर की ऋय-शक्ति पर सकट को लेकर काफी चिल्ल-पो मची रही। लेकिन गुहार मचाने वाली में से किसी ने स्फीति के मूल कारणों को खोलकर दिखाने का साहस नहीं किया।

एकाधिकारी औद्योगिक शक्ति ही उस मुद्रास्फीति का मूल कारण थी। १९५० के बाद की दशान्दी में यदि हमारे सारे उद्योग प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योगों की ही तरह चलाये जाते तो स्फीति और मूल्य वृद्धि की नौबत ही न आने पाती। इस सम्बन्ध में प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योगों से दो उदाहरण देना काफी होगा : १९५३ से १९५८ तक के बीच कृषि उपजों के मूल्य ५ प्रतिशत गिर गये और यही हाल कपडे के मूल्यों का भी रहा। लेकिन इसी बीच इस्पात की कीमते ३७ प्रतिशत, मोटर गाड़ियाँ और मशीनों की कीमते २२ प्रतिशत और तम्बाकू की कीमते १५ प्रतिशत बढ़ा दी गईं; और यही स्थिति आमतौर पर उन सारे उद्योगों में हुई जहाँ एकाधिकारी नियन्त्रण के कारण व्यवस्थापित कीमते सम्भव थी।

नतीजा यह हुआ कि कृषि-उपजों और कुछ अन्य कीमतों मे काफो गिरावट होने के बावजूद उन पाँच वर्षों मे थोक कीमतों के सूचकांक मे ८ प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

एकाधिकार ने अपना कर वसूल कर ही लिया।

और एकाधिकार जो दूसरा कर वसूल करता है वह तो और भी खतरनाक है। एकाधिकारी पद्धति पर चलाये जाने वाले उद्योग अपने अधिकांश विकास के लिए आजकल हिस्से बेचकर वित्तीय प्रबन्ध नहीं करते, वे इस कार्य के लिए 'आन्तरिक वित्तीय प्रबन्ध' की प्रलाणी को अपनाते हैं, अर्थात् लाभांश का उपयोग नये सयत्रों का मूल्य चुकाने अथवा प्रतिस्पर्द्धी व्यवसायों को खरीदने मे किया जाता है।

इसका सही अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थ व्यवस्था के एकाधिकारी टुकड़े में फेंसी पूंजी और मजूरी का निरन्तर बढ़ती जाती औद्योगिकीय दक्षता से सारे राष्ट्र को लाभान्वित करने मे कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। यदि हो रहा होता तो या तो उन्हें कीमतें घटानी पड़ती या उन्हीं कीमतों पर ज्यादा अच्छा माल देना पड़ता। और बिना नये हिस्से बेचे नये सयत्रों का निर्माण करने अथवा पूरे व्यवसायों को ही खरीद लेने लायक अनाप-शनाप मुनाफे तो वे कभी भी नहीं कर सकते थे। और नये उपभोक्ताओं से उत्पादित वस्तुओं के मूल्य मे नये सिरे से बनाये जाने वाले कारखानों का मूल्य जोड़ कर अत्यधिक महँगी कीमतें वसूल कर रहे होते।

जब तक यह चलता रहेगा औद्योगिकीय बेकारी बढ़ती ही जाएगी, कृषि—जैसे प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योगों को हानि होती रहेगी और अमरीकी अर्थव्यवस्था के विकास की गति पिछड़ती चली जाएगी।

इस सम्बन्ध मे कुछ तो करना ही होगा। क्योंकि जैसा यूनिनन आयल कम्पनी ने अपने सम्पागत उद्देश्य-सम्बन्धी विज्ञापनों मे कहा है . “थोड़े से लोगों के हाथों मे, चाहे वे व्यवसाय हों, चाहे रुपया लगाने वाले साहूकार, चाहे उद्योगपति हों, सरकारी अधिकारी हो अथवा मजदूर नेता, शक्ति का किसी भी तरह का केन्द्रीकरण बहुसंख्यक जनता को अनिवार्यतः हानि पहुँचाने वाला ही होता है।”

इस सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो संयुक्त राज्य में आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक महोद्यम और आर्थिक विकास का उत्पादन पर लगे प्रतिबन्धों के हाथों, जो व्यवस्थापित मूल्य निर्धारण का अवश्यम्भावी परिणाम है, गला हो घुँट जाएगा।

लेकिन क्या, आखिर क्या किया जा सकता है ?

एक उपाय जिस पर कम-से-कम विचार तो किया ही जाना चाहिए, यह है कि जब तक हमारी समूची अर्थ व्यवस्था पर मुट्ठी-भर निगमों का एकाधिकारी नियन्त्रण पूरी तरह स्थापित नहीं हो जाता, जब तक मूल्यों की होड़ पूरी तरह लुप्त नहीं हो जाती, और जब तक किसी भी उद्योग में नई कम्पनियों का प्रवेश आज मोटर, इस्पात, कृषि-यन्त्र या रसायन उद्योग की ही तरह असम्भव नहीं हो जाता, इस ढर्रे को जैसा यह चल रहा है चलता रहने देना चाहिए। लेकिन यह जरा अविश्वसनीय लगता है कि जिस देश के आदि निर्माताओं ने स्वतन्त्रता की खोज में तूफानी समुद्रों को पार किया था उसी देश की जनता स्वतन्त्रता का यों अन्त हो जाने देगी। परन्तु यदि जनता की निष्क्रियता शीघ्रातिशीघ्र रोषावेश में परिणत नहीं हुई तो ठीक यही परिणाम होकर रहेगा।

दूसरा उपाय है न्यास-विरोधी कानूनों को सचमुच ही लागू कर देना। शरमन कानून बन जाने के बाद भी यह काम अभी तक हो नहीं पाया है। प्रभावशाली होने के लिए इन कानूनों में इतना सशोधन करना पड़ेगा कि किसी भी उद्योग में एकाधिकारी शक्ति का, फिर वह शक्ति कैसे ही क्यों न प्राप्त की गई हो, विद्यमान होना ही उसके खिलाफ प्रतीकारात्मक कारवाई करने का पर्याप्त कारण समझा जाना चाहिए।

लेकिन यह प्रश्न बड़ा टेढ़ा है कि प्रतीकारात्मक कारवाई किस प्रकार की हो ? क्या जनरल मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल फूड या दूसरे किसी भी 'जनरल' निगम को जोर-जबर्दस्ती तोड़ा जा सकता है ? और यदि तोड़ भी दिया जाए तो क्या वे टूटे हुए रहेंगे ? और उनके तोड़े जाने के परिणाम-स्वरूप जो छोटी कम्पनियाँ बनेंगी वे प्रतियोगिता और खास तौर पर मूल्य-निर्धारण की प्रतियोगिता कर सकेंगी ?

ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाना वास्तव में बड़ा मुश्किल है।

कांग्रेस के जिन सदस्यों ने हमारी अर्थ व्यवस्था में एकाधिकार के प्रसार का तथ्यात्मक अनुशीलन किया है उनकी ओर से कई तरह के सुझाव पेश हुए हैं। एक सुझाव तो यह है कि मूल उद्योगों में मूल्य वृद्धि की घोषणा पहले से की जानी चाहिए; इससे उन लोगों के मन पर, जो मनमाने तरीके पर मूल्य-वृद्धि को व्यवस्थापित कर देते हैं, आगा पीछा सोचने की कुछ तो रोक लग ही सकती है। दूसरा प्रस्ताव काफी पुराना है, जिसे सबसे पहले व्योमिंग के सीनेटर ओ माहोनी ने पेश किया था; वह यह कि अन्तर्राज्यीय व्यवसाय करने वाले सभी निगमों को सघीय सरकार द्वारा लाइसेन्स दिया जाना चाहिए, इससे तथ्य-सम्बन्धी जानकारी देने में अधिक तत्परता बरती जा सकेगी। लेकिन इससे इस बात का जवाब तो नहीं मिलता कि उन तथ्यों के आधार पर क्या कारवाई की जाएगी और कैसे की जाएगी।

उपभोक्ताओं की क्रयशक्ति को सगठित करना ही एकाधिकार के खतरों के खिलाफ सबसे पक्का और प्रभावशाली प्रतिकारात्मक कदम है। स्वीडन—जैसे देशों में इस तरह के कदम काफी हद तक उठाने जा चुके हैं और जहाँ भी उठाने जायेंगे वहाँ न्यास-विरोधी कानूनों की आवश्यकता नहीं होगी। उपभोक्ताओं के स्वामीत्व वाले सहकारी व्यवसाय आर्थिक मूल्य-निर्धारण, श्रेष्ठता और, सबसे अधिक, पूरे उत्पादन के द्वारा राष्ट्रीय हित की रक्षा करते हैं। इस तरह के उपभोक्ता स्वामीत्व वाले व्यवसाय सुसंगठित उत्पादकों से बराबरी के स्तर पर मौल-भाव ही नहीं कर सकते, अपने सहकारी भंडारों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए स्वयं उत्पादन भी आरम्भ कर सकते हैं और इस प्रकार प्रभावी प्रतिस्पर्द्धा के पुनरावर्धन की सही पद्धति के द्वारा एकाधिकार की पकड़ को तोड़ सकते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में आगे किसी अध्याय में विचार किया जाएगा।

लेकिन एक कदम है जिसे लघु व्यवसाय तत्काल और स्वयं उठा सकता है।

वह कदम क्या है, यह कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा।।

थोड़ा समय हुआ एक गम्भीर विचारवान व्यक्ति, जो बचपन पार कर चुके थे, सहकारी लीग के दफ्तर में आये। उन्होंने यह कह कर अपनी बात

शुरू की : “छोटे स्वतन्त्र स्वामीत्व वाले व्यवसायों के दिन अब आ लगे हैं। मैं स्वयं नहीं जानता कि कितने दिन टिक पाऊंगा। वह समय दूर नहीं है जब हमारे छोटे कस्बों की मैन स्ट्रीट की सब दुकानें और सारा कारोबार बड़ी राष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में चला जाएगा और हम सब छोटे व्यापारियों को घर में बैठना पड़ेगा।”

सहकारी लीग के दफ्तर में जिन सज्जन ने मुझसे यह बात कही वे कोई उग्र सुधारवादी नहीं थे वे पक्के प्रौढ़ व्यापारी और इलिनोइस के एक देहाती कस्बे में किराना माल की बड़ी दुकान के सफल स्वामी थे। उनका कारबार, जैसा कि उन्होंने बताया, अब भी अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन भविष्य उन्हें दिखाई दे गया था। और जो भविष्य दिखाई दिया वह उन्हें जरा भी पसन्द नहीं आया। वे इसमें विश्वास करते थे कि स्थानीय व्यवसाय स्थानीय लोगों के ही हाथ में रहना चाहिए। वे स्वस्थ प्रतियोगिता में विश्वास करते थे। यह उन्हें स्वीकार नहीं था कि देश व्यापी दुकान-शृंखलाओं वाला कोई विशाल कारबार उनके छोटे कामकाज को लील जाए; अपनी शक्ति-भर वे इसे रोकना चाहते थे।

इसे रोकने का एक उपाय उन्होंने सोच भी निकाला था। और उनका खयाल था कि यह उपाय केवल काम चलाऊ नहीं स्थायी है।

यही कारण था कि वे अपने कस्बे से चल कर सहकारी लीग के दफ्तर में हम लोगों से मिलने के लिए आये थे और उससे पहले दक्षिणी विसकोन्सिन के सहकारियों से मिल लिये थे और उत्तरी इलिनोइस के एक क्षेत्रीय थोक सहकारी से भी बात कर चुके थे।

वे अपने निजी कारबार को सहकारी रूप देना चाहते थे। उनका कहना था कि सहकारी बना देने पर जहाँ कारबार है उसी कस्बे के स्थानीय लोगों के स्थानीय स्वामीत्व का ही वह हमेशा-हमेशा बना रहेगा। यह बात उनकी समझ में आ गई थी और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भी कि एकाधिकारी आर्थिक शक्ति के लिए जो धक्कामेल मची हुई है उसमें एकमात्र सहकारी व्यवसाय ही टिके रह सकते हैं, सामना कर सकते हैं और अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रख सकते हैं।

इन सज्जन ने अपने कस्बे के कुछ प्रभावशाली नागरिकों की बैठक बुला कर उनसे इस बारे में थोड़ी-बहुत चर्चा भी कर ली थी, और उन्होंने बताया कि उन लोगों की भी इसमें दिलचस्पी थी।

हमने उन्हें आश्वासन दिया कि आप जब भी बुलाएँगे हम सहाय्यताथ्र हाजिर हो जाएँगे। अपना कुछ साहित्य भी दे दिया जो उनके काम आ सकता था। वे लोट गये यह कह कर कि घर जाकर अपने कस्बे वालों से इस सम्बन्ध में और चर्चा करेंगे और इस बात की थाह लेंगे कि उनके व्यवसाय को सहकारी का रूप देने और गाँव की ही मिल्कियत बनाये रखने के लिए उसे खरीद लेने में उन लोगों की कितनी-क्या दिलचस्पी है। यदि वे अपने इस अनुष्ठान में सफल हुए तो वह उनके कस्बे के हित में अच्छा ही होगा।

बहुत से उदाहरणों में से अब एक और उदाहरण लीजिए। एक दिन इहोवा से एक लघु निर्माता सहकारी सेवा व्यवसायी के संगठन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास आये।

कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस माल का वे विनिर्माण कर रहे हैं उसमें माल तैयार करने की दक्षता का जहाँ तक प्रश्न है छोटी और बड़ी कम्पनी में कोई अन्तर नहीं पड़ता। छोटी कम्पनी भी उतना ही श्रेष्ठ माल बना लेती है जितना कि बड़ी कम्पनी। प्रतियोगिता की समस्या माल के विनिर्माण को लेकर नहीं थी।

लेकिन देशव्यापी विज्ञापन के इस युग में ('और इस कम्बख्त देश व्यापी विज्ञापन को भी तो अपना विज्ञापन करना पड़ता है।'—यही उन सज्जन ने कहा था।) छोटी कम्पनियों के लिए बड़ी कम्पनियों के मुकाबले अपना माल बेचना असम्भव हो गया है। छोटी कम्पनियों के लिए देशव्यापी पैमाने पर विज्ञापन कर पाना या बड़ी-सी विक्रेता पलटन रखना भी असम्भव ही है। इसलिए आज की व्यापारी दुनिया में न तो अपने नाम और ट्रेडमार्क की साख बन पाती है और न माल को खपत के सन्तोषजनक जरिए ही निकल पाते हैं।

इसलिए उनके मन में एक ऐसी सहकारी बिक्री और प्रचार संस्था बनाने का विचार उदित हुआ, जो उन्हीं की तरह का माल बनाने वाले कई विनिर्माताओं की साझी संस्था होगी। कई छोटे विनिर्माताओं के संयुक्त साधनों

के बल पर ऐसी सस्या बड़े प्रतिस्पर्द्धियों के विक्री और प्रचार विभाग का मुकाबला कर सकती है। माल तो सभी लोग अलग-अलग ही बनाते रहेगें, परन्तु सब के माल के लिए आपस में मिल कर कोई एक नाम और छाप तय की जा सकती है और बाजार में उसकी साख और चलन को बढ़ाया जा सकता है।

सहकारिता बहुत-सी छोटी इकाइयों को अपनी स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाये रखकर स्वेच्छा से साथ मिल कर काम करने का ऐसा अवसर प्रदान करती है जिससे आर्थिक जगत् में अपनी सम्मिलित हैसियत के बल पर वे बड़ी-बड़ी कम्पनियों से होड़ बंद सके। असल में सहकारिता बड़ेपन की दुनिया में 'छोटों' का एकमात्र आसरा है।

वास्तव में कई हजार 'छोटे लोगों' ने इस आसरे को अपनाया भी है। स्वतन्त्र किराना भण्डार इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

राष्ट्रव्यापी दुकान-श्रृंखलाओं को प्रतिस्पर्द्धा से जो जवर्दस्ती लाभ है उन्हें देखते हुए यह सोच कर आश्चर्य होता है कि इन्के-दुक्के स्वतन्त्र किराना भंडार जिन्दा कैसे रह सकते हैं।

लेकिन अभी तक तो एक-दो या तीन-चार नहीं हजारों जिन्दा हैं।

यह कैसे हुआ ?

साल्टलेक सिटी की एशोसिएटेड फूड स्टोर्स इन कारपोरेशन नामक फुटकर विक्रेताओं के स्वामित्व की सहकारी थोक कम्पनी के मैनेजर डोनाल्ड पी० लायड ने १९५९ के जून महीने में कांग्रेस की एक समिति को इस सम्बन्ध में जो कुछ बतलाया था उसका एक अंश इस प्रकार है :

“अमरीका का सहकारी खाद्य वितरक (Co-operative Food Distributors of America) जनता को सीधा माल बेचने वाले लगभग २७ हजार छोटे फुटकर भण्डारों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यापार सघ है। ये फुटकर विक्रेता ही उन सौ के करीब थोक भंडारों या इकाइयों के एकमात्र स्वामो हैं, जिन्हें लोग-बाग फुटकर विक्रेताओं की मलिकियत वाली थोक किराना कम्पनियों के नाम से जानते हैं। सूखे किराने की हमारी वार्षिक विक्री सात अरब डालर से भी अधिक की है, फिर भी हम लघु व्यवसाय ही हैं अर्थात् २७ हजार छोटे व्यावसायिक संगठन हैं। अपने १०० थोक भंडारों से हम ठीक

वही काम करते हैं जो कोई भी थोक किराना व्यापारी कर सकता है। लेकिन उसमें और हममें केवल एक फर्क है। थोक काम से लाभ कमाने के लिए हम इस व्यापार में नहीं आये हैं। हम इस व्यापार में हैं अपने एक-एक फुटकर सदस्य और उपभोक्ता-जनता को थोक खरीद शक्ति का लाभ पहुँचाने के लिए।

“खाद्य और किराना के फुटकर भंडार हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग पचास अरब डालर का काम करते हैं। करीब दो-तिहाई काम एकल भंडारों (एक-एक दुकान या छोटी शृंखलाओं) के द्वारा किया जाता है; बाकी एक तिहाई (सही-सही ३७ प्रतिशत) बड़ी दुकान-शृंखलाओं (ग्यारह या उससे अधिक दुकानोंवाली) के द्वारा। हम इसको सामान्यतः एक मानी हुई बात समझते हैं कि हमारे व्यवसाय में एकल व्यापारी अधिकांश में इसीलिए टिके हुए हैं कि हमारे संगठन की तरह के संगठनों की बदौलत अपेक्षाकृत छोटे भंडार भी खरीदी और बिक्री में बराबर की हौड़ कर सकते हैं।”

मिस्टर लायड ने वस्तु स्थिति की बहुत ही ठीक निरूपण किया है। यदि आर्थिक संगठन की सहकारी पद्धति को अपनाया जाए तो आर्थिक स्वतन्त्रता, प्रभावी प्रतिस्पर्धा और ‘छोटे आदमी’ के लिए अवसर अब भी हो सकता है। बहुत-सी छोटी दुकानों की आवश्यकता-पूर्ति का यदि सम्मिलित स्वामीत्व वाला एक सहकारी स्रोत हो तो वे बाजार में अपने बड़े-से-बड़े और ताकतवर प्रतिस्पर्द्धी का सचमुच ही मुकाबला कर सकती है।

१९५४ में संयुक्त राज्य अमरीका के वाणिज्य विभाग ने यह विवरण दिया कि फुटकर विक्रेताओं के स्वामीत्व वाले सहकारी थोक खाद्य भंडारों ने कुल १ अरब ३० करोड़ डालर की बिक्री की, जो सभी तरह के किराना माल की कुल थोक बिक्री का १७.७ प्रतिशत है।

‘प्रोग्रेसिव ग्रासर’ (प्रगतिशील किराना-विक्रेता) नामक व्यावसायिक पत्र का अनुमान है कि १९४८ से १९५७ के बीच स्वतन्त्र फुटकर विक्रेताओं के स्वामीत्व वाले सहकारी थोक किराना भंडारों ने अपनी बिक्री २०० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा ली।

उपभोक्ताओं के स्वामीत्व वाले बहुत से सहकारी खाद्य भंडार केवल अपने सहकारी थोक संगठनों के ही नहीं अपने क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं के स्वामीत्व

वॉल सहकारी थोक सगठनों के भी सदस्य हैं।

पारस्परिक सहायता एकल व्यक्तियों के लिए ही नहीं छोटे व्यापारी अधिष्ठानों के लिए भी उपयोगी सिद्धान्त है।

जहाँ तक हम पता लगा सके हैं अमरीका में इस तरह की सहकारिता पहले-पहले १८०४ में दिखाई दी थी, जब कोनेक्टिकट के दूध उत्पादकों ने अपना एक सहकारी विक्री सघ बनाया था।

दूसरे छोटे व्यापारियों का एक ऐसा ही पहला तुलनीय काम १८८७ में न्यूयार्क में हुआ जब वहाँ के औषध विक्रेताओं ने किसी दुकान के पीछे वाले कमरे में बैठक करके एक पोपाएप्सम लवण के अपने आदेशों का निकाय बनाने का निश्चय किया था। उनसे भी पहले शिकागो मुद्रक सहकारी सघ अपने सदस्यों के लिए पुस्तक और जाब प्रिंटिंग व्यवसाय लेने और वितरित करने का कार्य कर रहा था।

आज से सैंकड़ों वर्ष पहले मध्ययुग में कारीगरों के जो शिल्पीसघ थे उनकी बहुत-सी बातें आधुनिक सहकारी से मिलती-जुलती थी। पारस्परिक सहायता के सिद्धान्त में ही दोनों की जड़ें निहित हैं।

आज एक लाख से भी अधिक स्वतन्त्र किराना विक्रेता सहकारी थोक-भंडारी के सदस्य और स्वामी हैं। और ८० हजार से ज्यादा औषध विक्रेता अपने-अपने क्षेत्रिय थोक भंडारी से सहकारिता के आधार पर अपनी-अपनी दुकानों के लिए औषधियाँ खरीदते हैं। लौह खड के व्यापारी भी पीछे नहीं हैं, यद्यपि उनका थोक सेवा सस्थाओं के नाम के साथ 'सहकारी' शब्द शायद ही कभी दिखाई देता है, वैसे वे थोक सेवा सस्थाएँ सभी अर्थों में पूरी-पूरी सहकारी हैं।

देश के अधिकांश समाचार पत्र एशोसिएटेड प्रेस के सदस्य और स्वामी हैं। यह सस्था शुद्ध सहकारी ढंग से लाभार्जन विहीन आधार पर चलाई जाती है और 'लाभो' पर किसी भी प्रकार का कर नहीं दिया जाता।

लेकिन समाचार पत्र है कि स्वयं तो अपने एशोसिएटेड प्रेस सहकारी से लाभान्वित होते हैं और जब दूसरे लोग, उदाहरणार्थ किसान या उपभोक्ता, अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान के लिए उन्हीं सिद्धान्तों को

अपनाना और आचरण में लाना चाहते हैं तो उन्हें बुरा-भला कहते हैं, उनके खिलाफ विष-वमन करते हैं।

लोह खड और औषधि विक्रेताओं की सहकारी थोक सस्थाओं के कतिपय सदस्य भी उपभोक्ताओं और किसानों की सहकारी सस्थाओं पर प्रचंड प्रहार करते नहीं चूकते।

लेकिन इतना सब होते हुए भी किसी को यह आपत्ति नहीं हो सकती कि वे स्वयं सहकारी पद्धतियों को क्यों अपनाये हुए हैं और कोई भी यह नहीं कहता कि वे सहकारी तरीके छोड़ दे या इन थोक सस्थाओं की सदा से चली आती औचित्यपूर्ण कराधान स्थिति में परिवर्तन किया जाए।

सुरक्षण वन वापसी जो सहकारी व्यवसायों को अपने ग्राहकों को लौटानी होती है उन व्यवसायों की आस्तियों अथवा आय नहीं देयताएँ हैं। वे ग्राहक-स्वामियों की सम्पत्ति हैं और उनकी कर योग्य आय के अनुसार उन्हीं से उनका कर लिया जाना चाहिए। और यह सिद्धान्त सभी प्रकार की सहकारी सस्था पर लागू होता है फिर चाहे वह उपभोक्ताओं की, किसानों की, समाचार पत्रों की, किराना-विक्रेताओं की, औषध विक्रेताओं की अथवा लोह खड के व्यापारियों की ही क्यों न हो।

संयुक्त राज्य अमरीका में 'बडपन' की बेतहाशा बाढ के बावजूद जो-कुछ आर्थिक स्वतन्त्रता और स्वस्थ प्रतियोगिता अब भी दिखाई देती है वह अधिकांश उन सहकारी व्यवसायों की आभारी है जिन्हे छोटे-छोटे उद्यमों ने अपनी रक्षा के लिए संगठित किया है। यह हमारी आज की अमरीकी अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत ही कम ज्ञात पर निस्सन्देह उतना ही अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य है।

हमारी अर्थ व्यवस्था में एकाधिकारी नियन्त्रण के कारण जिन छोटे व्यवसायियों को कष्ट उठाना पडता है उनमें सबसे बड़ा, सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे हानि में रहने वाला समूह किसानों का है। जनता के किसी भी समूह की अपेक्षा किसानों में सहकारी व्यवसायों की जडे इतनी गहरी, इतनी व्यापक और इतनी परिपुष्ट होने का यही कारण है। किसान की सहकारी सस्थाओं ने ही उसे आर्थिक दृष्टि से मोल-भाव करने की आशिक सामर्थ्य दे रखी है। सम्बद्ध व्यवसायों के सहकारी स्वामित्व के बिना केवल छोटे एकल उत्पादकों

के रूप में किसानों में वह शक्ति ही नहीं होती कि आर्थिक भौलभाव कर सके। सहकारी संस्थाएँ यदि काफी बड़ी और शक्तिशाली हों तो किसान की स्थिति को कुछ तो आर्थिक दृढ़ता दे ही सकता है।

अगले अध्याय में इस सम्बन्ध में और भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।

लेकिन यहाँ एक मामूली-सी सच बात बताना बहुत जरूरी है। महानगरों के अखबार किसानों को दी जानेवाली 'आर्थिक सहायता'—उपदान की शिकायत करते जरा भी नहीं चूकते। और अधिकांश नगर निवासी सम्भवतः यही मानने लगे हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था के दूसरे अंग देश के किसानों की 'आर्थिक सहायता' कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में सचार्इ इसके ठीक विपरीत है। असल में देखा जाए तो किसान ही बहुत बड़ा उपदान सारे राष्ट्र को दे रहे हैं। यदि एक परिवार भोजन और कपड़ा, जितना उनका वास्तव में मूल्य होना चाहिए उससे कम पर खरीदता है तभी वह मोटर और बिजली पर जितना उनका मूल्य होना चाहिए उससे अधिक दे सकता है। इस प्रकार किसान शेष सारी अर्थ व्यवस्था को जो उपदान दे रहा है वह उससे कहीं बड़ा है जो उसे कीमतों के सहारे के लिए यानी कीमतों की गिरावट की रोकने के लिए या गिर जाने पर आर्थिक क्षति पूर्ति के रूप में मिलता है। यदि किसानों के सारे लागत खर्च जोड़े जाएँ, जैसे निवेश पर प्रति लाभ, मजदूरी, वेतन, मूल्य-ह्रास आदि तो यह पाया जाता है कि उन्हें आम तौर पर लागत से कम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। और चूंकि कृषि एवं कुछ अन्य उद्योगों को, जिनमें प्रतिस्पर्द्धा अब भी विद्यमान है, लागत से कम पर या बहुत थोड़े मुनाफे पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता है इसीलिए तो 'व्यवस्थापित मूल्य' वाले उद्योग अपने उत्पादनों को इतनी बेहद बढ़ो-चढ़ो कीमतें वसूल कर पाते हैं। यदि कृषि—जैसे प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यवसायों को अपने माल के लिए उपभोक्ताओं के इतने थोड़े-से डालर भी न मिले तो धातु के बने सामान, रसायन, तम्बाकू आदि की इतनी ऊँची कीमतें चुकाने के लिए डालर कहाँ से आएँगे। फिर तो बहुत बड़े पैमाने पर मुद्रास्फोति ही एकमात्र उपाय रह जाएगा।

जनरल मोर्टर्स और उसके—जैसे अन्य निगमों को उपदान देने के लिए किसान जो ऊँची कीमतें चुकाते हैं और किसानों ने अपनी रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं उस सब का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है।

७ | आधुनिक अमरीका की सबसे बड़ी कमजोरी

मानव-इतिहास के अधिकतर भाग में मूल उत्पादकों का शोषण बहुत-कुछ तो इसलिए होता रहा है कि मूल उपजों का सारा क्रय-विक्रय, विनिर्माण और उन्हें पण्योपयोगी बनाने का काम दूसरे ही लोगों ने किया है।

इस तरह के शोषण के अन्त का अपेक्षाकृत एक सुगम मार्ग तो यही है कि मूल उत्पादक अपना क्रय-विक्रय और अपनी पैदावार के थोड़े-से अंश का विनिर्माण और उन्हें पण्योपयोगी बनाने का काम स्वयं करने के लिए अपनी निजी संस्थाएँ बनाएँ।

किसानों के सहकारी संगठन ठीक इसी प्रकार की संस्थाएँ हैं।

अब्राहम लिंकन का एक ऐतिहासिक वाक्य है : “कोई जाति आधी गुलाम और आधी स्वतन्त्र जीवित नहीं रह सकती।”

इस शती की तीसरी दशान्दी से हमें यह सबक सीखना चाहिए था कि अमरीकी अर्थ व्यवस्था आधी सम्पन्न और समृद्ध एवं आधी विपन्न और अवनत दशा में जीवित नहीं रह सकती।

लेकिन हमने यह सबक नहीं सीखा।

दूसरे महायुद्ध के बाद हमने बाकी जनसंख्या को सम्पन्न बनाने का प्रयत्न किया, जब कि हमारी कृषि और उसमें काम करने वाले मन्दी, अवनति और विपन्नता में छटपटाते रहे।

यह कभी चला नहीं।

यह कभी चलेगा नहीं।

यह कभी चल ही नहीं सकता।

जिस किसी भी जाति अथवा [राष्ट्र ने इस अन्यायपूर्ण असन्तुलन को चलाने का प्रयत्न किया उसे दारुण दुःख ही भोगने पड़े हैं।

इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि कोई महान जाति अपनी कृषि-व्यवस्था को अवनत और अपने कृषकों की स्वतन्त्रता का अपहरण

बचने की उनके लिए कुछ आशा ही सकती है।

इसलिए किसानों ने अपने सहकारी संगठन बनाये हैं। इन्हें आरम्भ हुए काफी समय हुआ। किसानों की जिस पहली सहकारी बिक्री संस्था का उल्लेख हमें मिलता है वह कोनेक्टिकट रीवर वैली के दूध उत्पादकों ने १८०४ में बनाई थी।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ग्रैंगरों का हरावल में वृक्षहीन मैदानों और अन्य स्थानों के सकट ग्रस्त किसानों में विक्रय और उपभोक्ता दोनों ही तरह की सहकारी संस्थाएँ गठित की गईं। उनमें से कम-से-कम एक तो अभी भी कन्सास के कैडमूस नामक स्थान में काम कर रही है।

लेकिन कृषि-उपजों की बिक्री के लिए सहकारियों का बड़े पैमाने पर विकास तो इस शताब्दी के साथ ही आरम्भ होता है। और फारम एव घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाले सहकारी संस्थाओं की ठोक-ठोक उन्नति तो इसके पच्चीस वर्ष के बाद ही गुरु होती है।

विक्रय सहकारियों का निर्माण किसानों को सट्टा बाजार के अनिष्टकारी प्रभावों से बचाने के लिए किया गया। इन सहकारियों का निर्माण होने से पहले किसानों को अपने फसल जो भी इक्का-दुक्का खरीदार मिल जाता उसी के हाथों, उसी की शर्तों पर और जो भी कीमत वह दे देता उतनी ही कीमत पर बेच देना पड़ता था। फसल जितनी ही ज्यादा होती लाभ उतना ही कम होता था। माल को रोकने, रखने और भरने का उनके पास कोई साधन नहीं था। बाजार में माल की आवश्यकता बहुत अधिक हो जाने पर निवारण का कोई उपाय भी वे नहीं जानते थे। विचौलिये सारा माल खरीद कर प्रायः कीमते बढ़ा दिया करते थे, लेकिन उस मूल्य-वृद्धि से किसानों को कोई लाभ नहीं होता था। किसानों को माल रोकने-भरने के अपने साधनों और अपनी ही विक्रय संस्थाओं की आवश्यकता थी। विक्रय सहकारी संस्थाएँ उसी का परिणाम हैं।

विक्रय सहकारी संस्थाएँ बन जाने से किसानों को अपने माल की ज्यादा अच्छी और ज्यादा स्थिर कीमते मिलने लगी। लेकिन यह कहना कि इससे उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ा और उन्हें ऊँची कीमतों पर खाद्य आदि खरीदना पड़ता है, सही नहीं है। उल्टे हुआ यह है कि उपभोक्ताओं का पैसा

अधिकाधिक मात्रा में किसानों और ग्रामीण समुदायों में जाने लगा है जो पहले नहीं होता था। इसके अतिरिक्त विक्रय सहकारियों ने उपभोक्ता को बेचे जाने वाले खाद्यों की किस्म को सुधारने में भी काफी सहायता की। उन्होंने स्तरीकरण, श्रेणीकरण और समूहीकरण पर काफी जोर दिया और इस प्रकार समूचे व्यवसाय में खाद्य-वितरण की प्रणाली के स्तरों को काफी उन्नत कर दिया। सहकारी ढंग से बेची जानेवाली खाद्य-वस्तुओं—जैसे सन्तरे, दूध, किशमिश, आलू, अण्डे, मुर्गियाँ, मक्खन, पनीर आदि के सौ व्यवसाय-नाम माल को श्रेष्ठता और उत्कृष्टता के सम्बन्ध में इतने निर्भरना योग्य हो चुके हैं कि कोई भी अमरीकी उन्हें कहीं भी आँख मूँद कर ले लेता है।

विक्रय सहकारियों और उपभोक्ता सहकारियों के दृष्टिकोण में स्वाभाविक अन्तर है। इन पुस्तक में जितने भी सहकारियों पर विचार किया गया प्रायः वे सभी उपभोक्ता सहकारी हैं। किसानों के विक्रय सहकारी और छोटे व्यापारियों के सहकारी ये दो मुख्य अपवाद हैं। उपभोक्ता सहकारी सदस्यों द्वारा माल अथवा सेवाओं-सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं की जितनी ही मकदद उतनी प्रचुरता से पूर्ति के लिए गठित किये जाते हैं। उत्पादन और वितरण जितना ज्यादा होगा और सरसकट को मख्या भी जितनी अधिक होगी उपभोक्ता सहकारियों के लिए यह उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसके विपरीत विक्रय सहकारियों अपने सदस्यों का उत्पादन दूसरे लोगों को बेचने के लिए होते हैं। उनके दृष्टिकोण से एक माल के बहुत से उत्पादक हो सकते हैं और व्यवस्थित ढंग से तत्काल बेचे जा सकने की अपेक्षा माल का उत्पादन भी अधिक हो सकता है।

सम्भवतः यही कारण है कि भूतकाल में—आज तो बहुत ही कम—कुछ विक्रय सहकारी इसके लिए राजी नहीं होते थे कि उन्हें दूसरे सहकारियों के साथ रखा जाए और उनका समक्ष बताया जाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि विक्रय सहकारी 'एकाधिकारी' व्यवसाय हैं अथवा सहकारी से भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं। वास्तव में वे श्रमिक वर्गों की ही तरह के संगठन हैं जो उत्पादकों के बड़े समूहों की आय, जीवन-स्तर और क्रय-शक्ति की कुछ अंशों में रक्षा करते हैं, क्योंकि अकेला उत्पादक तो आर्थिक दृष्टि से बड़ा निहाय होता है और कुछ भी नहीं कर सकता।

संयुक्त राज्य अमेरिका में सात हजार के लगभग विक्रय सहकारी संस्थाएँ हैं। ये प्रति वर्ष अपने कृषक सदस्यों की द्वारावृत्ति की गुँजाइश सहित कुल नौ-दस अरब डालर तक के मूल्य की चौदह प्रकार की प्रमुख पैदावारे बेचती हैं। अमरोका की समस्त कृषि-उपजों का चतुर्थांश खेत से उपभोक्ता की मेज तक पहुँचने के पहले एक या अधिक अवस्थाओं में इन विक्रय सहकारियों के खर्चों से गुजरता है।

मुर्गी खाने और दूध के कुछ उत्पादन, कुछ प्रकार के ताजे फल और उनके उद्योत्पाद उपभोक्ता के लिए तैयार होकर सहकारी से निकलते हैं। लेकिन अज्ञातिअल्प मात्रा में ये पदार्थ भी किसानों की सहकारी बिक्री संस्थाओं द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं।

क्षेत्र-विशेष के अपने सदस्यों के उत्पादनों को इकट्ठा करके उन्हें व्यवस्थित ढंग से, लेकिन बगैर तैयार किये हुए अर्थात् कच्ची हालत में बेचना ही बिक्री सहकारियों का ऐतिहासिक कार्य रहा है। लेकिन जब से इस मूल कार्य में संवेष्टन और पण्योपयोगी बनाने की क्रियाएँ जुड़ गई हैं और जब से विक्रय सहकारी संस्थाएँ क्षेत्रिय अथवा देशव्यापी बिक्री के लिए संघ बद्ध हो गई हैं किसानों को प्राप्त होने और उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाली कीमतों के बीच की 'खाई' बहुत कम हो गई है, और किसानों को उपभोक्ताओं का पैसा भी अधिक अनुपात में मिलने लगा है।

दुग्धशाला के उत्पादन कुल सहकारी बिक्री का लगभग तृतीयांश है। १९५८-५९ के एक साल में कोई २००० विक्रेता सहकारियों के द्वारा करीब तीन अरब डालर के दुग्धशाला उत्पादन बेचे गए। कुछ अंशों में तो ये उत्पादन उपभोक्ताओं या अधिक हुआ तो फुटकर बिक्री भंडारों को सीधे ही बेच दिये जाते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में ये वस्तुएँ बिक्री सहकारियों द्वारा बड़े व्यापारियों और पण्योपयोगी बनाने वाली के ही हाथ बेची जाती हैं। दूध उत्पादक और विक्रय सहकारियों का राष्ट्रीय दूध उत्पादक महासंघ (National Milk Producers Federation) नाम का एक राष्ट्रीय संगठन भी है। इधर के वर्षों में दुग्धशाला के उत्पादनों की राष्ट्रव्यापी सहकारी बिक्री के सम्बन्ध में काफी चर्चाएँ होती रही हैं।

सहकारिता के आधार पर बेची जानेवाली उपजों में दूसरे नम्बर पर अनाज और सोयाबीन हैं, ये दोनों मिल कर प्रति वर्ष दो अरब डालर मूल्य की बेची जाती हैं। कुछ सोयाबीन कृषि-आपूर्ति सहकारियों को बेच दिया जाता है; और अधिकांश अनाज क्षेत्रीय सहकारियों सार्वजनिक अन्नागारों द्वारा बेचा जाता है; २७०० स्थानीय सहकारी अन्नागारों में से अधिकांश इनसे सम्बद्ध हैं। अनाज सहकारी माल को पशुपयोगी बनाने का काम अभी भी अपेक्षाकृत कम ही करते हैं। अधिकांश अनाज विक्रय सहकारी गल्ला सहकारियों के राष्ट्रीय महासंघ (National Federation of Grain Co-operatives) से सम्बद्ध हैं; इसका प्रमुख कार्यालय वाशिंगटन डी० सी० में है।

सहकारी अपने किसान सदस्यों के लगभग १ अरब और ६० करोड़ डालर वार्षिक मूल्य के पशुधन और पशुधनों के उत्पादन बेचते हैं; फल और सब्जियाँ प्रति वर्ष लगभग १ अरब डालर को बेची जाती हैं; कपास और उसके उत्पादन ४० करोड़ डालर से भी अधिक के और मुर्गियाँ एवं मुर्गी खानों के उत्पादन ३५ करोड़ डालर के बेचे जाते हैं। सहकारियों के द्वारा अच्छी किस्म और और अच्छे दामों के लिए माल का बिल्कुल सही और उचित श्रेणीकरण किया जाता है, इस पर किसानों को पूरा-पूरा विश्वास है। फल और सब्जियों की विक्री करने वाले कुछ सहकारियों को तो अपने बाजार में माल की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में बड़ी धाक और ऊँची साख है और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय बाजारों में उनका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया है।

व्यापार की कूट डालरों में की जाए तब तो कृषि उपज विक्रेता सहकारी संयुक्त राज्य अमरीका के अपने ढंग के सबसे बड़े सहकारी व्यवसाय हैं। लेकिन किसानों की बुनियादी समस्याएँ तो फिर भी बिन सुलझी ही रह जाती हैं। यदि किसानों के स्वामित्व वाले सहकारी व्यवसाय माल को पशुपयोगी बनाने का काम, संवेष्टन, विज्ञापन और विक्री राष्ट्र व्यापी विक्री संगठनों के द्वारा करने लगे तो जो कुछ होगा उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। निश्चय ही हालत एकदम बदल जायेगी—बहुत अधिक लाभ होगा और किसानों के हितों की बहुत अधिक रक्षा होगी।

और यदि किसानों के स्वामित्व वाले व्यापारी संगठन से खेती की पैदावार

को काफी बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं के स्वामीत्व वाले उद्यमों को सीधे बेच सके तो किसानों के पाने और उपभोक्ताओं द्वारा ही की 'खाई' काफी पट जाएगी और अन्तर केवल माल को पण्योपयोगी बनाने, उसकी ढुलाई और बिक्री की लागत भर करह जाएगा।

संकल्प और पूँजी का उचित सम्मिश्रण और संयोजन अब भी, सहकारिता के माध्यम से, अमरीकी किसान की हालत को आमूल बदल सकता है।

फसलों के बेचे जाने पर किसानों को उचित मूल्य दिलाने में तो सहकारी बिक्री पूरी तरह प्रभावोत्पादक नहीं हो पाई; परन्तु कृषि और किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सहकारियों ने किसानों की पैदावार की लागत को घटाने में और फार्मों एवं घर-गिरस्ती के माल की खरीद में उन्हें मोल-भाव की सार्थक शक्ति से सम्पन्न करने में अवश्य उल्लेखनीय कार्य कर दिखाया है।

अमरीकी सहकारी आन्दोलन के विकास का मुख्य आधार व ४३०० सहमध्य पश्चिमी (मिडवेस्टर्न) कस्बों में और देश के दूसरे बहुत से भागों में अब-स्थित हैं।

१९५९ में इनके ३५ लाख से भी अधिक सदस्य थे और इन्होंने लगभग २ अरब ४० करोड़ डालर का व्यापार किया। ये सहकारी अमरीकी ग्राम्य जनता की फार्म और घर गिरस्ती की प्रमुख बड़ी आवश्यकताओं का २० से ३५ प्रतिशत तक पूरा करते हैं। ये किसानों को उत्पादन की लागत को नियन्त्रण में रखने और उसे कम करने की सक्षमता प्रदान करते हैं।

इस तरह का कोई भी सहकारी अपने पूरे जिले (काउंटी) में या जिले के काफी बड़े हिस्से में व्यापार करता है। वह एक किराना दुकान, चारे, बीज और उर्वरक का भंडार, पेट्रोल की बड़ी टकी और पम्प, आमतौर पर कृषि यन्त्रों का प्रदर्शन कक्ष और कोयले की टाल चलाता है। साधारणतः वह जिले के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र में अवस्थित होता है इसलिए दूर-दराज की कुछ छोटी बस्तियों में इसकी शाखाएँ भी हो सकती हैं। काफी संख्या में ये भंडार अपने इलाके की गैर-किसान आबादी की जरूरतें भी पूरी करते हैं।

राज्य अथवा अपने क्षेत्र के शक्तिशाली सहकारियों से सम्बद्ध होने के

कारण इन चार हजार देहाती सहकारियों में से अधिकांश पर किसान बढ़िया किस्म के और भरोसे लायक उच्च विश्लेषण युक्त उर्वरक, उच्च कोटि के बीज और चारा, लौह खड का सामान, कृषि के यान्त्रिक उपकरण, इमारती सामान और रंग-रोगन बिजली का सामान पेट्रोल और उसके विविध उत्पादन, ईंधन, कोटाणु नाशक और पोथी पर छिड़कने के घोल, किराना माल, कपड़े और दूसरे बहुत से सामान के लिए पूरी तरह निर्भर कर सकता है। फारमों द्वारा उपयोग किये जाने वाले मिश्रित चारे के चतुर्थांश उर्वरकों के पचमाश और पेट्रोल के २० प्रतिशत की आपूर्ति इन्हीं सहकारियों के द्वारा की जाती है।

इनमें से अधिकांश वस्तुएँ 'ज्यादा मुनाफे वाला' माल है, इसलिए ये सहकारी अपने सदस्यों को सरक्षण धन वापसी की नियमित अदायगियाँ करते रहते हैं और किसानों के हित में कीमतों को तेजी नहीं पकड़ने देते, नरमी पर ही बनाये रहते हैं। १९२५ के बाद काम और विस्तार शुरू होने के कारण इन ग्रामीण आपूर्ति सहकारियों ने थोक और फुटकर बिक्री का काफी अच्छा काम-काज जमा लिया है। महत्व की बात तो यह है कि इनका कारबार खास तौर पर 'मन्दी के बुरे दिनों' में ही तेजी से बढ़ा है।

देश के प्रत्येक भाग में इन फुटकर कृषि आपूर्ति और कृषि उपभोक्ता सहकारियों के या तो अपने क्षेत्रीय थोक और उत्पादक सहकारी हैं या ये इस तरह के किसी क्षेत्रीय सहकारी से सत्त्वद्ध हैं।

इस तरह के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों में से कुछ इस प्रकार हैं : कोआपरेटिव ग्रैंग लीग फंडेशन, इथाका, न्यूयार्क, सदर्न स्टेट्स कोआपरेटिव, रिचमंड, विरजीनिया; ईस्टर्न स्टेट्स फार्मर्स एक्सचेंज, वेस्ट स्ट्रिंग फोल्ड, मे मेस चुसेट्स; मिडलैण्ड कोआपरेटिव, इन कारपॉरेशन मिनीपोलिस, मिन्नेसोटा कंजूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन, कनसास सिटी, मिसौरी, इलिनोइस फार्म सप्लाय कम्पनी, ब्लूमिंगटन, इलिनोइस; इंडियन फार्म ब्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन, इंडियाना पोलिस, इंडियाना; फार्मर्स यूनियन सेट्रल एक्सचेंज, सेटपाल, मिन्नेसोटा; फार्म ब्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन कोलम्बस, ओहियो, फार्मर्स कोआपरेटिव एक्सचेंज, रैले, नार्थ कैरोलिना; मिसौरी फार्मर्स एसोसिएशन; वॉशिंगटन कोआपरेटिव फार्मर्स एसोसिएशन; पेन्सिलवानिया फार्म ब्यूरो कोआप-

रेटिव एसोसिएशन; सेट्रल कोआपरेटिव्स, इनकारपोरेशन, सुपीरियर, विसको-निप्स; पैसफिक सप्लाई कोआपरेटिव, बल्ला बल्ला, वॉशिंगटन, फ्रुट ग्रीअर्स सप्लाई कम्पनी, लासएजिल्स, कैलीफोर्निया; फार्म ब्यूरो सर्विसेज, लार्निसग, मिचिगन; टेनेसी फार्मर्स कोआपरेटिव, फार्मर्स यूनियन स्टेट एक्सचेंज, ओमाहा, नेबास्का; और उटाह कोआपरेटिव एसोसिएशन।

ये क्षेत्रीय थोक सहकारी अपने सदस्य फुटकर बिक्री सहकारियों की उर्वरकों, पशुखादों, बीज, मोटर के सामान, लौहखड की चीजे, पेट्रोल उत्पादनों और कोटाणुनाशकों सम्बन्धी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। समय को देखते जितनी माँग है उतनी तो नहीं परन्तु फिर भी काफी मात्रा में ये सब वस्तुएँ इन क्षेत्रीय सहकारियों द्वारा या तो अपने निजी कारखानों में या कई क्षेत्रीय सहकारियों के सम्मिलित स्वामीत्व वाले कारखानों में ही बनाई और तैयार की जाती हैं। उदाहरणार्थ इन क्षेत्रीय सहकारियों द्वारा एक सौ से भी ज्यादा उर्वरक कारखाने चलाये जा रहे हैं। सहकारी स्वामीत्व वाले दो हजार से अधिक तो तेल के कुएँ ही हैं और दस सहकारी तेल परिष्करण शालाएँ।

स्वयं उत्पादन आरम्भ कर देने से ये सहकारी अपने सरक्षकों को वे सब वस्तुएँ जो प्रायः बड़ी कठिनाई से मिल पाती हैं या मिलती ही नहीं, पूरी-पूरी तादाद में दे सकते हैं। स्वयं उत्पादन करने का दूसरा लाभ यह है कि इसमें थोक और फुटकर बिक्री की अपेक्षा सहकारी सरक्षकों के लिए लागत और मूल्यों में कहीं अधिक बचत की जा सकती है। जो सहकारी उत्पादन करते हैं वे अपने सदस्यों को दूसरी जगह निर्मित माल की केवल बिक्री करके सरक्षण धन वापसी की जितनी अदायगी और सम्पत्ति पर जितना साम्प्रदायिक स्वामीत्व दे पाते उससे कहीं अधिक देते हैं। क्षेत्रीय थोक आपूर्ति सहकारियों में सबसे बड़े कञ्जूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन के स्थापक और अध्यक्ष हावर्ड ए० फाउडेन का कहना है कि हमारी संस्था ने थोक का काम करके अपने सदस्यों के लिए जहाँ एक डालर की बचत की वहीं अपने कारखानों में माल का उत्पादन करके उस एक डालर के मुकाबले उन्नीस डालरों की बज्जत की।

देश के दो सबसे बड़े राष्ट्रीय थोक आपूर्ति सहकारी संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा के कुछ क्षेत्रीय सहकारियों के स्वामीत्व वाली संस्थाएँ हैं।

इनमें से एक ओहियो राज्य के अलायन्स नगर में है और दूसरा मिन्नेसोटा के अल्वर्ट ली में। पहले का नाम है युनाइटेड कोआपरेटिव्स और दूसरे का नेशनल कोआपरेटिव्स। नेशनल कोआपरेटिव्स दूध दुहने और पानी गरम करने की मशीनें बनाता है और उनकी अधिप्राप्ति और वितरण भी करता है।

अधिकांश कृषि-आपूर्ति क्षेत्रीय सहकारी अमरीकन इस्टीमेट आफ कोआ, परेशन और नेशनल कौन्सिल आफ फारमर्स कोआपरेटिव के सदस्य हैं। बहुत से संयुक्त राज्य अमरीका की सहकारी लीग और अपने राज्य के सहकारी सघों और कौन्सिलों के सदस्य हैं।

फुटकर और क्षेत्रीय दोनों ही प्रकार के कृषि-आपूर्ति सहकारियों की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ १९५० के बाद के वर्षों में सामने आई वे इस प्रकार हैं :

- १—सेवाओं और व्यापार के परिमाण में विस्तार एवं उनका और भी आधुनिकीकरण; विस्तार के लिए गैर-किसानों या आशिक किसानों या उपनगर की जनता में से संरक्षकों की वृद्धि,
- २—अधिकाधिक सदस्यों को सक्रिय करने के लिए सदस्यों की शिक्षा, क्योंकि सहकारी उद्यम की यही सबसे बड़ी कारोवारी पूँजी होती है;
- ३—उत्पादन की ओर भी वृद्धि और विकास, मूल कच्चे माल का अधिकाधिक उत्पादन और प्रबन्ध;
- ४—अधिकाधिक निपुणता और आर्थिक क्षमता प्राप्त करने के लिए कार्य विधियों और कारवारी का एकीकरण और कुछ मामलों में विलयन तथा किसानों के लिए आवश्यक नई सेवाओं का प्रारम्भ;
- ५—इन उद्देश्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुकूल शर्तों पर वित्तीय प्रबन्ध के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था। सहकारी संस्थाओं की बैंक और सहकारी बीमा कम्पनियाँ धन-सम्बन्धी आवश्यकता की कुछ पूर्ति कर सकती हैं। लेकिन नई, एकीकृत और बढ़ती जाती सेवाओं के वित्तीय प्रबन्ध के लिए पूँजी के अतिरिक्त स्रोतों की जुटान की आवश्यकता भी स्पष्ट ही है।

१९६१ के आरम्भ होते ही इस दिशा में उठाये जानेवाले कदमों के सम्बन्ध में चर्चा और विचार विनिमय का सूत्रपात हो गया है।

जिन समस्याओं और अन्यायों से जूझने के लिए किसानों ने पचहत्तर वर्ष पूर्व सहकारियों का संगठन किया था, १९५१ से आरम्भ होनेवाली दशाब्दी में वे और भी उग्र रूप से सामने आयीं।

किसानों की उपज के खरीदारों की सख्या बहुत ही तेजी से गिर गई। १९६० तक हालत यह हो गई कि न्यूयार्क के बाजार में किराने और मांस की जितनी खरोद होती थी उसका ८० प्रतिशत बहुत बड़े-बड़े १७ खरीदारों के हाथों में सिमट आया था। सीटल का बाजार १० खरीदारों के कब्जे में था, पोर्ट-लैण्ड में ८ खरीदार छाए हुए थे और ओमाहा में तो और भी कम। १९४८ में स्वतन्त्र किराना विक्रेता देश के ५० प्रतिशत खाद्य का क्रय-विक्रय करते थे और दुकान श्रृंखलाएँ २९ प्रतिशत का। दस वर्ष बाद दुकान श्रृंखलाओं का काम बढ़ कर ३८ प्रतिशत हो गया और स्वतन्त्र किराना विक्रेताओं का गिरते-गिरते ३० प्रतिशत ही रह गया। १९६० में देश के बड़े सपेष्टक (पैकर्स) स्विफ्ट, आरमर और कुडाही ने सर्वोच्च न्यायालय से इस बात की अनुमति माँगी कि उन्हें फुटकर खाद्य भंडार खोलने और चलाने की अनुमति दी जाए।

एकाधिकारों नियन्त्रण जितनी व्यापकता से फैलते और जितने अधिक उद्योगों में प्रविष्ट होते गए अर्थ व्यवस्था के प्रतिस्पर्द्धात्मक अंगों की स्थिति उतनी ही अधिक शोचनीय होती गई।

लघु व्यवसाय के साथ यही मूसीबत थी।

और कृषि के साथ भी यही मूसीबत थी।

संक्षेप में यह कि संयुक्त राज्य अमरीका का अधिकांश और जिससे किसानों का सीधा सम्बन्ध है वहतो सारे का सारा उद्योग एकाधिकारों में हो गया। कोमर्तों को हीड पुराने जमाने की बात रह गई; जो औद्योगिक माल किसानों को खरो-दना पडता है उसको कोमर्तों हमेशा तेजी को ओर व्यवस्थापित होती है और उनका निर्धारण करते समय आर्थिक स्थितियों का, यहाँ तक कि माँग और आपूर्ति के सम्बन्धों का भी कोई विचार नहीं किया जाता। कोमर्तों की गिरावट को रोकने के लिए उत्पादन को गिराया जाता है, नियन्त्रित किया जाता है।

इसके विपरीत कृषि अब भी प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यवसाय है। देश के ४० लाख किसानों में अकेला एक तो कोई भी ऐसा नहीं है जो समग्र सम्भरण को

किसी भी हद तक प्रभावित कर सके। और इस बात को सभी किसान जानते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे लोगों की भाँति किसान को भी अपनी आजीविका कमाना होती है। किसान की आजीविका का सीधा सम्बन्ध उसकी उपज की बिक्री से जुड़ा हुआ है, अर्थात् कितनी इकाइयों की बिक्री मूल्य की पूर्ति कर पाती है। इकाई का मूल्य जितना ही न्यून होगा किसान उतनी ही अधिक इकाइयों के उत्पादन का जीतोड़ प्रयत्न करेगा। कृषि उपज का न्यून मूल्य तथा-कथित 'अधिशेषों' को कम नहीं करता उल्टे और बढ़ा देता है। फिर किसानों को फसल आने से बहुत पहले बोना और उसकी योजना बनानी पड़ती है। कीमतों को एक ही स्तर पर बनाये रखने के लिए वे उत्पादन पर नियन्त्रण नहीं कर सकते और मान लिया जाए कि कर ही लेते तो भी शायद ही करते।

इसलिए किसान जो कीमतें पाते हैं वे हमेशा निम्नगामी यानी गिरावट की ओर जानेवाली होती हैं और जो कीमतें किसानों को देना पड़ती हैं वे ऊर्ध्व-गामी यानी तेजी की ओर जानेवाली होती हैं। किसानों को मिलनेवाली कीमतें बाजार में जो भी भाव हो उसपर बिके पूरे उत्पादन की कीमतें होती हैं। किसानों को जो कीमतें देनी पड़ती हैं वे अधिकांश में निश्चित—और प्रायः व्यवस्थापित ढंग से निश्चित की हुई कीमतें होती हैं।

यही कारण है कि तुल्याक ८० के आसपास घूमता रहता है; जिसका अर्थ हुआ कि कृषि को राष्ट्रीय आय के उसके अधिकृत भाग के लगभग २० प्रतिशत से काफी समय से अन्यायपूर्वक वंचित किया जा रहा है। और यही कारण है कि १९४७ से १९५७ के बीच जहाँ औद्योगिक उत्पादनों की कीमतें २६ प्रतिशत बढ़ी कृषि उपजों की कीमतों में ५ प्रतिशत गिरावट हुई। और यह उस समय जब कि कृषि में उत्पादन प्रति व्यक्ति-घटा ९० प्रतिशत अधिक होता जा रहा था पर सारे कृषि-इतर उद्योगों में केवल २४ प्रतिशत। कृषि ने औद्योगिक दक्षता के लाभ खरीदारों को हस्तान्तरित कर दिये। जिन उद्योगों से किसानों का सीधा सम्बन्ध है उन समेत दूसरे उद्योगों में भी यदि यही किया जाता तो तुल्याक १०० या उसके आस-पास होता और तब किसानों को शिकायत का कोई अवसर न्यायतः नहीं रह जाता। लेकिन उल्टे हुआ यह कि नवम्बर १९५९ में किसानों को अपनी फसलों के लिए जो कीमतें मिली और सम्भरणों एवं सेवाओं

के लिए उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी उनका अनुपात ७७ तक गिर गया, जो १९४० के बाद निम्नतम बिन्दु है।

तो इस तरह संयुक्त राज्य अमरीका में कृषिकार्य का सामान्यतः आधार है: पूर्ण-उत्पादन और बाजार-निर्धारित-मूल्य। जहाँ मूल्य-सहायता-कार्यक्रम आ जाते हैं उन्हें छोड़ कर किसानों को अपनी पूरी फसलों के लिए जितना बाजार दे दे वह ले लेना पड़ता है। इसलिए यह पूर्ण-उत्पादन ही, जिसका मूल्य उप-भोक्ताओं के लिए बिना किसी बाधा-बन्धन के निश्चित किया जाता है, मुक्त अर्थ व्यवस्था में ऐसा आधार-बल्कि एकमात्र ऐसा आधार प्रस्तुत करता जिसके सहारे हम पूरे रोजगार, पर्याप्त विकास और मूल्यों को स्थिर करने की आशा कर सकते हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था इतनी अधिक एकाधिकारी हो गई है कि उसमें किसानों को सिर्फ इसीलिए आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि वे राष्ट्र के दीर्घकालीन हितों की संवर्धना के विचार से काम करते हैं।

औद्योगिकीय प्रगति तो निरन्तर होती ही जा रही है, इसलिए उससे होने वाले लाभ जब तक उपभोक्ताओं के रूप में सारे राष्ट्र में वितरित नहीं किये जाएंगे न तो खपत बढ़ेगी और न व्यापक औद्योगिकीय बेकारी को उग्र रूप धारण करने से रोकने के लिए उत्पादन की पर्याप्त वृद्धि ही की जा सकेगी।

अमरीका के अधिकांश उद्योगों में आज यही नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ा दुःख तो इस बात का है कि कृषि उत्पादनों के जो अन्तिम उपभोक्ता हैं, उनका हित भी नहीं हो रहा है। किसानों को दिये जाने वाले न्यून मूल्यों से कृषि उत्पादनों को जो पण्योपयोगी बनाते और बेचते हैं ऐसे बिचौलिये ही माला माल हो रहे हैं। न्यून मूल्य लेकर किसान अपनी बिक्री नहीं बढ़ाता; हाँ बिचौलियों की जबे जरूर भर देता है, और उधर उपभोक्ताओं के भोजन की कीमत बढ़ जाती है। १९५० और १९५८ के बीच औसत परिवार के भोजन का मूल्य बढ़ कर १२२ डालर हो गया; लेकिन किसानों को १९५० की अपेक्षा १९५८ में १२ डालर कम मिले, उधर पण्योपयोगी बनानेवाले और दूसरे बिचौलियों को १३४ डालर अधिक मिले। १९५९ में उपभोक्ताने अपने भोजन पर जो डालर खर्च किया उसमें किसान का हिस्सा सिर्फ ३८ सेंट था, बाकी ६२ सेंट बिचौलिये मार ले गए। और आगे हालत इससे भी बिगड़ती दिखाई देती है।

संयुक्त राज्य कृषि सांख्यिकी विभाग (United States Department of Agriculture Statistics) के अनुसार असल उपभोक्ताओं के बचे गए कृषि उत्पादनों का फुटकर बाजार मूल्य १९५१ में ४२ अरब ६० करोड़ डालर था, जो १९५९ में ५१ अरब डालर हो गया। लेकिन किसानों को फिर भी १९५९ में १९५१ की अपेक्षा २० करोड़ डालर कम मिले। लेकिन फारम और फुटकर बिक्री भंडार के बीच 'विक्रय खर्च' १९५१ में २२ अरब ८० करोड़ डालर से बढ़कर १९५९ में ३१ अरब २० करोड़ डालर हो गया।

इसलिए यदि १९५० की अपेक्षा १९५९ में फारमों पर ३९ लाख लोग ही रह गए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

अमरीकी कृषि की दशा को ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए एक राज्य का उदाहरण लेकर थोड़े विवरण में जाना ज्यादा उचित होगा।

मिन्नेसोटा की खेती की जमीन दुनिया में सबसे उपजाऊ है। जो समतल मैदान दक्षिणी मिन्नेसोटा, उत्तरी इओवा, उत्तरी डकोटा में रेड दीवर की घाटी और उत्तरी-पश्चिमी मिन्नेसोटा तक फैला हुआ है वैसे श्रेष्ठ कृषि-योग्य भूमि कहीं पर भी नहीं है।

मिन्नेसोटा की कृषि-स्थिति की तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ के गवर्नर, आरविले एल० फ्रीमैन ने जो बाद में केनेडी प्रशासन में कृषि-सचिव (Secretary of Agriculture) हो गए, एक विशेष आयोग नियुक्त किया था।

उस आयोग ने जो चौकानेवाली जानकारी दी वह किसी भी विवेकशील पुरुष के खून को खोलाने के लिए पर्याप्त है। जानकारी इस प्रकार है:

मिन्नेसोटा में समग्र कृषि-उत्पादन १९३२ से प्रति वर्ष ९ प्रतिशत की दर से बढ़ता जा रहा है; यह देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की दर के दून से भी अधिक है। इसका कारण निगमित कृषि की वृद्धि नहीं था। बल्कि बात बिल्कुल उलटी थी। पारिवारिक ढग के वैयक्तिक फारमों का प्रतिशत १९३९ में जहाँ ६१ था वहीं १९५६ में बढ़कर ६७ हो गया था। प्रति फारम औसत समग्र निवेश १९३९ में १० हजार डालर के मुकाबले १९५६ में ३० हजार डालर हो गया था।

१९५५ में मिन्नेसोटा के ६३ प्रतिशत फारम-किसानों की आय दो हजार डालर से भी कम थी। मिन्नेसोटा में कृषि की औसत प्रति व्यक्ति आय नागरिकों की औसत प्रति व्यक्ति आय की केवल ४३ प्रतिशत है।

सरल भाषा में इसका अर्थ यह हुआ कि अपने व्यवसाय में निवेश को तीन-गुना और उत्पादन की वृद्धि-दरों को अविश्वसनीय सीमा तक बढ़ा कर भी अमरीका के सबसे सम्पन्न कृषि राज्य के किसान परिवारों को नागरिक परिवारों की तुलना में आधे से भी कम आय हो रही थी। इसका कारण क्या है ?

इसका बुनियादी कारण,, जो अब तक साफ हो जाना चाहिए, यह है कि अलग-अलग एक-एक किसान में खरीदते अथवा बेचते समय आर्थिक मौल-भाव को पर्याप्त शक्ति नहीं होती। और इस तरह को आर्थिक मौल-भाव करने को शक्ति प्राप्त करने का जो एकमात्र निर्भरता योग्य उपाय अभी तक समझ में आया है, वह है सहकारियों का संगठन।

लेकिन सहकारी अभी न तो इतने बड़े हो पाये हैं और न इतने सशक्त कि समस्या का पूरी तरह सामना कर सके।

इतना तो मानना ही होगा कि किसानों के सहकारियों ने काफी बड़ा काम कर दिखाया है। उर्वरक व्यवसाय का केवल २० प्रतिशत इन सहकारियों के हाथ में है फिर भी इन्होंने दिखा दिया है कि ये विशाल रासायनिक कम्पनियों से सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सकते हैं। उस प्रतियोगिता का परिणाम क्या हुआ ? १९५३ से १९५८ के बीच रासायनिक पदार्थों की कीमतों में आमतौर पर ४ प्रतिशत वृद्धि हुई, लेकिन उर्वरकों के मूल्य में मुख्य रूप से सहकारियों की प्रतियोगिता के कारण ढाई प्रतिशत का ह्रास हुआ। और कृषि (ग्रामीण) विद्युत्, साख, पेट्रोल, बीमा आदि कई प्रकार के सहकारी व्यवसायों से उदाहरण देकर यह सिद्ध किया जा सकता है कि सहकारी प्रतियोगिता ने सार्थक ढंग से कृषि-उत्पादनों की लागत को कम किया और सम्बद्ध व्यवसायों के अर्जित लाभों से किसानों की आय में अभिवृद्धि की।

काफी बड़ी मात्रा में अपनी उन्नति और विकास करके ये सहकारी अमरीकी कृषि के लिए कितना-कुछ कर सकते हैं यह निम्न तथ्यों और आँकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा।

१९५५ को हम युद्धोत्तर-काल का एक औसत वर्ष मान लेते हैं। स्थान के रूप में कोई भी एक मध्य पश्चिमी ((Middle Western) राज्य ले लेते हैं जहाँ कई प्रकार के सहकारो संगठन हैं। किसानों के स्वामीत्व युक्त जिला सहकारो राज्य व्यापार योद्धा और उत्पादन सहकारी के स्वामी थे। इस प्रकार किसानों ने अपनी आवश्यकता के पेट्रोल और पेट्रोल निर्मित वस्तुओं के एक भाग का स्वयं उत्पादन और परिष्करण किया, जिस चारे और उर्वरक का वे उपयोग करते थे उसके भी एक भाग का उत्पादन, सम्मिश्रण और वितरण स्वयं ही किया, जितना गल्ला और मुर्गी खाने के उत्पादन वे बेचते थे उनके भी काफी अंश को पण्योपयोगी बनाने और उसकी बिक्री व्यवस्था का काम स्वयं किया। १९५५ में इन सहकारी पद्धति से जितना सम्भरण प्राप्त किया गया उस पर किसानों को ६ प्रतिशत सरक्षण धन वापसी दी गई। और उत्पादित वस्तुओं को सहकारो ढग से बिक्री-व्यवस्था करने से अन्यथा होने वाली आय में २७ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अब यदि १९५५ में सारे किसान इसी तरह सहकारी व्यवसायों के स्वामी होने और उनकी सेवाओं का पूरा-पूरा उपयोग करते—जो कि वास्तविक नहीं है—लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ऐसा होता तो सहकारी बिक्री-व्यवस्था को आमदनी से किसानों की आय में ८० करोड़ डालर और जुड़ जाते, और सहकारो फारम आपूर्ति व्यवसाय के परिणाम स्वरूप उनकी लागत में से १ अरब और ८० करोड़ डालर कम हो जाते। उस वर्ष किसानों की असली आय, १ अरब और १० खरब डालर जो हुई थी, उससे १७८ प्रतिशत अधिक होती।

यदि कोई व्यक्ति ईमानदारो से अमरीकी कृषि-व्यवस्था में लगे बोमारी को सरकार पर निर्भर किये बिना दूर करने का उपाय खोजना चाहता है जो उसको उसे सहकारिता में खोजना चाहिए। लेकिन साथ ही उस व्यक्ति को किसानों के स्वामीत्व युक्त सहकारियों को वह हर सम्भव प्रोत्साहन देने के लिए तैयार रहना होगा, जिससे वे शोघ्राशोघ्रा वृद्धि और सार्थक एकीकरण कर सकें। और उस व्यक्ति को प्रचुर उत्पादन के इस युग में उपभोग के मानदण्डों के सम्बन्ध में भी नये ढग से काफी-कुछ सोचना-विचारना होगा।

१९५५ के बाद के वर्षों में फारम-आपूर्ति सहकारियों ने अपने व्यवसाय

को जो एक नई दिशा मे विस्तारित किया वह उस समय अमरीकी प्रजा मे हो रहे आर्थिक और समाज शास्त्रीय परिवर्तनों मे से ही उद्भूत हुआ था। सभझ-दार व्यवस्थापक और सचालक मण्डल उपनगर वासियों और आशिक किसानों को अपना सरक्षक और सदस्य बनाने लगे थे। उनके लिए यह आवश्यक भी हो गया था। मिलवाडकी के समीपस्थ एक 'फारम-आपूर्ति' सहकारी का उदाहरण इस सम्बन्ध मे काफी दिलचस्प रहेगा। कुछ ही वर्ष पहले यह सहकारी एक महत्वपूर्ण कृषि-क्षेत्र से घिरा हुआ था। शहर बढ़ते गए और फारमों को निगलते गए। लेकिन उन्होंने ऐसे परिवार भी पैदा किये जिनकी तेल-ईधन, मोटर के सामान, लौह खड, औजार, यहाँ तक की बीज और उर्वरकों की माँग किसानों से कुछ ही कम थी। सहकारियों ने इस नये व्यवसाय को छोड़ा नहीं। वे इसे पाने मे लगे रहे और अन्त मे पा ही लिया। और सहकारी का कारबार दिन-दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा, जो यदि वह अपने आप को पूरे-पक्के किसानों का सदस्यता-सक्षकता तक ही सीमित रखता तो कदापि न हो पाता। लेकिन इसके लिए सहकारी के एक के उस सुविधा का परित्याग करना पडा जो उसे हिस्से पर लाभार्थ वितरण किये जाने वाले रुपयों पर कर से छूट पाने के सम्बन्ध मे विशेष रूप से मिली हुई थी और जो कुछ विशुद्ध फारम सहकारियों के अब भी मिली हुई है। दूसरे, सहकारियों के बैंक (Bank of Co-operatives) से कर्ज पाने की, जैसा कि दसवें अध्याय मे बताया गया है, सुविधा से भी हाथ धोना पडा; यह बैंक अभी केवल उन्ही सहकारियों का कर्ज दे सकती है जिनका काफी अधिक कारबार पक्के-पूरे किसानों के साथ ही हो। लेकिन व्यापार मे बने रहने और निरन्तर ठोस उन्नति करने के लिए ये त्याग आवश्यक थे।

भोजन के उत्पादन, उसे पण्योपयोगी बनाने, उसके सवैष्टन और उप-भोक्ता तक उसे पहुँचाने का सारा व्यवसाय बड़ा ही लाभकारी है। खेत में उत्पादन को छोड़ कर इस व्यवसाय के बाकी सारे कामों मे लाभ-ही-ला है। आवश्यकता इस बात की है कि किसान भी खाद्य-व्यवसाय के इन अन्य लाभदायी कार्यों मे हाथ डाले। इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि खाद्य-व्यवसाय के लाभदायी कार्य किसानों के स्वामीत्व युक्त हों। जैसा कि हम देख

आये हैं, इसे करने का एक तरीका है। अब हम यह देखेंगे कि सहकारिता का वह तरीका किसानों की बुनियादी समस्याओं को कैसे हल कर सकता है।

अमरीकी कृषि की वर्तमान दुरवस्था के तीन बुनियादी कारण हैं। पहला कारण तो हमारी कृषि के तरीके से यानी जिस तरह वह की जाती है, या अधिक सही यह कि जिस तरह की जानी चाहिए पर की नहीं जाती, उनसे सम्बन्धित है। शेष दोनों कारण कृषि-उपजों की विक्री से सम्बन्धित हैं।

सबसे पहली बात तो यह कि अमरीकी कृषि के सारे अवयवों का ऊपर से नीचे तक जैसा चाहिए वैसा एकीकृत सघटन नहीं है। और जो कुछ है भी वह एकदम अपर्याप्त है।

इस्पात कम्पनियाँ काफी लोहा इस्तेमाल करती हैं, इसलिए वे कोयले को खाने खरीद कर उनकी मालिक बन जाती हैं और स्वयं ही कोयला निकालती हैं। मोटर कम्पनियाँ काफी इस्पात इस्तेमाल करती हैं इसलिए वे इस्पात मिले और लोहा मिले खरीद कर उनकी मालिक बन जाती हैं। किसानों को दूसरी बहुत-सी चीजों के साथ-साथ चारे की और बीज की, बिजली की और उधार रुपए की जरूरत होती है। जिस तर्क से इस्पात कम्पनियाँ कोयला खानों की मालिक बन सकती हैं उसी तर्क से किसान तेल के कुओं, उर्वरक सयंत्रों, बिजली कम्पनियों और बैंकों के मालिक क्यों नहीं बन सकते; वे अवश्य बन सकते हैं। लेकिन वे ऐसा सिर्फ सहकारिता के द्वारा ही कर सकते हैं। अब यदि हम उद्योग के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अवयवों के एकीकृत सघटन के पक्ष में हैं और इसकी अनुमति देते हैं, जो कि स्पष्ट ही हम दे रहे हैं तो कृषि की समस्या को वास्तव में सुलझाने के लिए, यदि हम उसे वास्तव में सुलझाने के लिए उत्सुक हैं तो हमें कृषि के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अवयवों का कारगर ढंग से एकीकृत सघटन शीघ्रातिशीघ्र कर देना चाहिए।

थोड़ा-बहुत एकीकृत सघटन तो हो भी चुका है। कृषि के बाहर एक विशिष्ट प्रकार की संस्थाओं ने अपने कारबार में किसान का समावेश करके इस काम को किया है। पशु-वाद्य बनाने वाली कम्पनियाँ ही अभी तक इसका उल्लेखनीय उदाहरण हैं; लेकिन शीघ्र ही पण्योपयोगी बनाने वाले निगम और भंडार-श्रृंखलाएँ भी इसको अपना सकती हैं। इस तरह के एकीकरण का

सम्बद्ध कृषि-उपजों के अत्यधिक न्यून मूल्यों के रूप में उदाहरणार्थ ब्रायलर (Broilers) — काफ़ी घातक परिणाम हुआ है, और वहाँ किसान की हैसियत गिर कर सिर्फ़ एक मजदूर की रह गयी है जिसको आय का रोजमर्रा के बँधे काम की बँधी मजदूरी के अतिरिक्त और कोई भी साधन नहीं है।

इसके अतिरिक्त एक दूसरी प्रकार का एकीकृत संघटन भी है जिससे कृषि को पुनः सम्पन्नता की ओर ले जाने, कृषकों की आय में अभिवृद्धि करने और अमरीकी ढंग के ग्राम्य जीवन को अस्तित्व-रक्षा की काफ़ी आशाएँ बँधती हैं। यह दूसरी प्रकार की एकीकरण किसानों द्वारा ऐसे सहकारी व्यवसायों के संगठन से कार्यान्वित होता है जिनमें किसान कृषि-उपजों से सम्बद्ध व्यापारों के, आंशिक सम्भरण कर्ता अथवा पण्योपयोगी बनाने और बिक्री व्यवस्था करने वाले के रूप में, स्वयं स्वामी होते हैं। इसमें सहकारिता का सिद्धान्त आर्थिक मोल-भाव करने वाली बहुत-सी कमजोर इकाइयों पर इस तरह लागू किया जाता है कि वे पारस्परिक सहायताार्थ सम्मिलित हो कर शक्तिशाली बनें। इस प्रकार जो व्यवसाय किसानों को पेट्रोल-निर्मित वस्तुएँ बेचते हैं उनमें से कुछेक के स्वामी बन कर अत्यधिक समृद्ध पेट्रोल उद्योग को कमाई का कुछ अंश अपनी आय में समाविष्ट करना किसानों के लिए सम्भव हो जाता है। इसी प्रकार उर्वरक व्यवसाय के कुछेक भाग के स्वामी बनना और उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए बिना घाटे की न्यूनतम लागत पर उस उद्योग को अपने ही हित में चलाना भी किसानों के लिए सम्भव हो जाता है। जब से किसान उर्वरक उद्योग के कुछ भाग को स्वयं चलाने लगे हैं, परिणाम यह हुआ है कि १९५३ से १९५८ के बीच के वर्षों में जहाँ कृषि के लिए आवश्यक अन्य सारी वस्तुओं के मूल्यों में ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं उर्वरक के मूल्य ढाई प्रतिशत कम हुए। इसका कारण यह है कि उर्वरकों का उपयोग करने वाले लोग ही उर्वरक उद्योग के चतुर्थांश के स्वामी हैं।

जो उद्योग कृषि में लगने वाली वस्तुओं का सम्भरण करते हैं, सहकारिता के आधार पर, उनमें से कुछेक के स्वामी बन कर किसानों में अपने कारबार की लागतों का आंशिक नियन्त्रण करने की क्षमता तो अवश्य ही आ जाती है। इस तरह के सहकारी कृत्यों से किसान कुछ अंशों तक आर्थिक मोल-भाव करने

में भी समर्थ हो जाते हैं, जिसके अभाव में आज की अर्थ व्यवस्था में नितान्त निस्सहाय वे कुछ भी नहीं कर सकते।

लेकिन यह एकीकृत संघटन तभी कारगर हो सकता है जब हममें सम्भरण के मूल स्रोतों का, जैसे कि मूल उर्वरक तत्वों, विद्युत्-शक्ति-जनित्रण और कच्चे पेट्रोल आदि सभी आवश्यक अवयवों का समावेश किया जाए।

इन उपायों का अवलम्बन करके जो भी सहकारी संघटन अमरीकी कृषि को आर्थिक दृष्टि से अधिक शक्ति-सम्पन्न बनाने का प्रयत्न कर रहा हो उसे जितना भी हो सके कम-से-कम ब्याज पर कर्ज दिया जाना चाहिए।

सहकारियों के इस ढंग के विस्तार से जिनमें किसान अपने कृषि-कार्य में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का स्वयं क्रय और उत्पादन कर सकें कृषि उत्पादन की लागत ही नहीं घटेगी इन सम्बद्ध उद्योगों की कुछ कमाई से कृषि की आय में वृद्धि भी होगी।

कृषि की लागत कम करने और आय बढ़ाने का दूसरा उपाय यह है कि मूल उत्पादकों को ही कृषि उपजों को पण्योपयोगी बनाने, संवेष्टन, प्रसार, प्रचार, विज्ञापन, वितरण और उपभोक्ताओं को सीधे माल बेचने के काम करने दिये जाएँ और इन कामों पर स्वामीत्व भी उन्हीं का (किसानों का) हो। यही कृषि की दूसरी बड़ी समस्या सामने उपस्थित होती है। वह समस्या यह है कि जब किसानों को मिलनेवाली कीमतें गिरती हैं, तो उन्हीं वस्तुओं के लिए उपभोक्ता जो कीमतें देते हैं वे नहीं गिरती, उल्टे बढ़ जाती हैं।

फारमों की लगभग एक चौथाई फसले सहकारी विक्री संघटनों के द्वारा बेची जाती हैं। लेकिन तथाकथित कृषि-समस्या का सच्चा हल तो तभी निकल सकता है जब खाद्य-सम्बन्धी उपजों को पण्योपयोगी बनाने, संवेष्टन और वितरण का नियन्त्रण ही नहीं इनमें से होने वाली आय पर भी किसानों का उपभोक्ताओं के साथ अधिकार हो। यदि कृषि उपजों के खेत से उपभोक्ताओं की मेज तक पहुँचने के बीच की सारी प्रक्रियाओं-तैयारी, संवेष्टन, वितरण आदि-पर किसानों या उपभोक्ताओं या दोनों का सहकारी स्वामीत्व हो तो कृषि-उपजों का मूल्य गिरने पर उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जानेवाली कीमतों में जो कमी नहीं होने पाती वह गड़बड़ कदापि न होगी। इस तरह के सहकारी व्यवसायों की

अतियोगिता के परिणामस्वरूप या तो किसानों को अपनी पैदावार के अच्छे दाम मिलेंगे या उपभोक्ताओं को अपने भोजन पर कम पैसा खर्च करना पड़ेगा या दोनों ही बातें होने लगेंगी। यदि कृषि-उपजों को खेत से उपभोक्ता की मेज तक पहुँचाने वाली समस्त प्रक्रियाओं पर किसानों अथवा उपभोक्ताओं का सहकारी स्वामित्व रहे तो उससे किसानों और उपभोक्ताओं में सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाएगा। इस सीधे सम्पर्क का परिणाम यह होगा कि जब उपभोक्ता ऊँची कीमतें चुकाएँगे तो कृषि की आय बढ़ जाएगी और जब किसानों के मूल की कीमतें गिरेंगी तो उपभोक्ता कम पैसा खर्च करके ज्यादा माल खरीद सकेंगे और यों किसानों की बिक्री बढ़ जाएगी। इसके साथ ही, दोनों ही स्थितियों में, कृषि पर निर्भर और उससे सम्बन्ध उद्योगों की कमाई के कुछ अंश से ग्रामीण अमरीका की आय में वृद्धि होगी और यों आर्थिक सन्तुलन पुनः स्थापित हो जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था को लगा रोग दूर हो सकेगा।

कृषि-समस्या के व्यावहारिक हल के रूप में प्रायः हर आदमी यह कहता सुना जाता है कि हमें उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए, देहातों में ज्यादा-से ज्यादा छोटे उद्योग शुरू करना चाहिए। लेकिन वह बात कोई नहीं बताता जिससे इस तरह का विकेन्द्रीकरण स्थायी हल बन सकता है।

और वह बात है इन उद्योगों पर वही के लोगों का—किसानों और ग्राम्य जनता का स्वामित्व। इसका अर्थ हुआ सहकारी स्वामित्व। और यह स्वामित्व उर्वरकों, पेट्रोल, विद्युत-उत्पादन और विक्रय-संस्थाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे पण्योपयोगी बनाने वाले और सवेष्टित के सयत्रों पर भी लागू किया जाना चाहिए। यदि उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जानेवाली और किसानों को मिलनेवाली कीमतों में पायी जानेवाली चौड़ी खाई का एकमात्र कारण माल को पण्योपयोगी बनाने और सवेष्टित करने की लागत है तो उस खाई को पटने का एक मात्र उपाय पण्योपयोगी बनाने और सवेष्टित करने के साधनों और व्यवसायों पर किसानों या उपभोक्ताओं या दोनों का सहकारी स्वामित्व स्थापित कर देना है।

यदि इस तरह कृषि से सम्बन्धित उद्योगों का किसानों के सहकारी स्वामित्व में विकेन्द्रीकरण हो जाए तो कृषि समस्या के दूसरे कारण का हल भी

निकल आता है।

लेकिन 'कृषि-समस्या' को यदि केवल कृषि से सम्बन्धित समस्या के ही रूप में देखा-परखा जाएगा तो उसे कभी भी हल नहीं किया जा सकेगा। और यह समस्या तब तो और भी हल नहीं हो सकती यदि किसानों से कृषि में 'स्वतन्त्र बाजार' को नोति पर चलने के लिए कहा जाए, क्योंकि दूसरे तो किसी भी उद्योग में 'स्वतन्त्र बाजार' है ही नहीं। वास्तव में कृषि की समस्या समूचे ग्रामीण अमरीका की समस्या है। और इसका एक ही मौलिक समाधान है और वह यह कि जिन उद्योगों का कृषि से घनिष्ठ सम्बन्ध है, उन पर सहकारी पद्धति से ग्रामीणों का, स्थानिकों का स्वामीत्व स्थापित किया जाए और उनको कमाई से होने वाली आय को कृषि से होनेवाली आपमें जोड़ दिया जाए।

समस्या के इस तरह के समाधान में न तो सरकार का मुँह ताकने की बात है, न छोटे किसानों को जमीन से बेदखल करने की जरूरत है और न उत्पादन को बनावटी ढंग पर गिराते जाने की तरकीब है।

हमारी खेती की बर्बादी का तीसरा बुनियादी कारण यह है कि हम प्रचुर उत्पादन और प्रचुर उपभोग की बात ही नहीं जानते और न इस दिशा में सोचने की ही तैयार हैं।

हम तो १९६० को दुनिया में भी १८९० के ढंग से सोचने-विचारने के अभ्यस्त हैं और उसी विचार-पद्धति पर बराबर जोर देते जा रहे हैं।

लेकिन वह विचार-पद्धति आज काम नहीं आ सकती।

अमरीकी किसान औद्योगिकीय और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से प्रचुर उत्पादन के लिए सन्नद्ध हो चुके हैं; दुनिया की कोई शक्ति अब इसे सम्भवतः बदल नहीं सकती।

असल में जरूरत विचार-पद्धति को ही बदलने की है। कुछ लोगों की—लेकिन सच तो यह है कि बहुत ही ज्यादा लोगों की—अभी तक भी यह मान्यता है कि कभी-कभी भूखा रहना लोगों के चरित्र-निर्माण के लिए अच्छी बात है।

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि जब आवश्यक हो जाए तब अभाव, कष्ट और त्याग से चरित्र का विकास और निर्माण होता है। जब किसी वस्तु की कमी या अभाव होता है तो हम भले लोग उन्हीं को कहते हैं जो अपना हिस्सा दूसरों

के लिए छोड़ देते हैं।

लेकिन जब सबके लिए काफी है या हो सकता है उस समय भी लोगों के अभावग्रस्त रहने पर जोर देने में भला क्या तुक है !

२२ मई १९६० को न्यूयार्क 'टाइम्स' के अन्दर के पृष्ठों में, दूसरे लेखों के घटाटोप में छिपा, किसी कोने में एक लेख प्रकाशित हुआ था जो इस अभाव-समर्थन की विचारधारा का खण्डन करनेवाला था। उस लेख का शीर्षक था. 'गेहूँ का बाहुल्य. शुभांशा का संकेत'। इतनी दक्षता से गेहूँ की इतनी प्रचुर फसल के लिए इस लेख में किसानों के भारी अपराध और दुराचरण का, अन्य लेखकों की भांति, रोना नहीं रोया गया था, न किसानों को 'इतनी भयंकर समस्या' खड़ी कर देने के लिए कोसा ही गया था। 'टाइम्स' पत्र के उस विशेष लेखक जे० एच० कारमाईकेल ने कुछ और ही बात कही थी। उनके लेख का कुछ अंश इस प्रकार है :

संयुक्त राज्य में गेहूँ की दूसरी प्रचुर फसल अब आने ही वाली है। ऐसे समय जबकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आसन्न संकट के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं, यह फसल स्वतन्त्र विश्व के लिए वरदान हो सकती है।

१ जुलाई से शुरू होनेवाली संयुक्त राज्य की नई मौसम में पिछली फसलों की बचत जोड़कर गेहूँ की कुल आमद ढाई अरब बुशल (१ बुशल=२९ सेर) से भी अधिक होने की आशा की जाती है। गेहूँ की इतनी अधिक पैदावार न तो कभी हमारे यहाँ हुई और न किसी दूसरे देश में। १९६१ की नई फसल आने तक हमें घरेलू उपयोग के लिए इस बार की पैदावार के सिर्फ चतुर्थांश की आवश्यकता होगी। तो इस चौगुनी फसल से स्वतन्त्र विश्व की भोजन-सम्बन्धी आपत्कालीन आवश्यकता को बड़े मजे से पूरा किया जा सकता है।

इसके साथ ही ये अधिशेष स्वतन्त्र विश्व के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का मनसूबा करनेवाले किसी भी समूह के लिए अवरोधक का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि परमाणु अस्त्रों के कारण यद्यपि युद्ध का स्वरूप बदल गया है, फिर भी जिस राष्ट्र के पास कई बरसों के भोजन का प्रबन्ध हो उसके खिलाफ कोई एक देश या राष्ट्रों का समूह सहसा युद्ध छेड़ने की बात नहीं सोच सकता—उसे काफी आगा-पीछा सोचना होगा।

लेकिन हमारे देश ने तो कभी चाहा भी नहीं था कि गेहूँ की इतनी प्रचुर फसल हो। सरकार ने वर्षों से गेहूँ का चेम्पल सीमाबद्ध कर रखा है। लेकिन अनुसंधान और औद्योगिकीय विकासों के कारण गेहूँ की प्रति एकड़ पैदावार लगातार बढ़ायी ही जाती है। यही कारण है कि इस वर्ष की फसल जो लगभग १ अरब २२ करोड़ ५० लाख बुशल के लगभग कूती गई है लगभग सवा छः लाख एकड़ भूमि में बोई गई थी। १९३६ में, जब यूरोप में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ तो अमरीकी किसानों ने ठीक इतनी ही भूमि में केवल ७४ करोड़ बुशल गेहूँ पैदा किया था।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित की दृष्टि से दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कम्युनिस्ट संसार को गेहूँ के उत्पादन में इतनी सफलता नहीं मिल पायी है। उत्पादन बढ़ाने की जो तोड़ कोशिशों के बाद भी इधर की खदरो से पता चलता है कि सोवियत संघ, पोलैण्ड और दो-एक दूसरे आश्रित राष्ट्रों में इस वर्ष भी गेहूँ की फसल कम ही हुई है। कुछ ही वर्ष पहले रूस को घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए निजी उत्पादन के अतिरिक्त बाहर से गेहूँ आयात करना पड़ा था। व्यावसायिक पर्यवेक्षकों की ऐसी निश्चित धारणा है कि सोवियत संघ को ३-४ वर्ष भी विदेशों से गेहूँ खरीदना पड़ेगा।

इस प्रचुर पैदावार के कारण संयुक्त राज्य स्वतन्त्र विश्व के दूसरे देशों के साथ गेहूँ की विक्री को बढ़ावा दे रहा है। अभी हाल में संयुक्त राज्य की सरकार ने भारत के साथ एक करार किया है जिसके अनुसार ५८ करोड़ ८० लाख बुशल गेहूँ चार वर्ष की अवधि में भारत को दिया जाएगा। प्रतिवर्ष १४ करोड़ ७० लाख बुशल गेहूँ भारत भेजा जाएगा और रूसका मूल्य भारतीय मुद्रा में ही ग्रहण किया जाएगा।

पता चला है कि इसी तरह के करार कुछ अन्य देशों के साथ भी किये जाने वाले हैं जिनमें से एक पाकिस्तान भी है। बहुत-से देशों के पास, जो इस गेहूँ का अतिरिक्त संचय के रूप में उपयोग करेंगे, मूल्य चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है। अपनी ही मुद्रा में मूल्य चुका कर वे देश अपनी अर्ध-व्यवस्था की इस अर्ध-सहायता करेंगे की संयुक्त राज्य की सरकार को इस तरह जो पैसा मिलेगा वह वापिस गेहूँ खरीदने वाले देशों को ही विभिन्न निर्माण-योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज दे दिया जाएगा।

क्या हम यह अनुभव करने लगे हैं कि जब तक एक भी मनुष्य की आवश्यकता पूरी नहीं होती कोई भी चीज 'अधिशेष' नहीं है और मानव जाति का मुख्य भोजन तो कदापि नहीं? केनेडी प्रशासन ने आते ही जो कदम उठाये हैं वे तो यही इंगित करते हैं।

प्रचुर अन्न और वस्त्र के वितरण और उपभोग-उपयोग की शब्दावली में कैसे सोचे यह हमें सीखना है। वेल्लेस-होमस्टैंड द्वारा संचालित किसानों के एक

जनमत-संग्रह ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसान तो इस दिशा में सोचने भी लगे हैं। इस जनमत-संग्रह में किसानों से पूछा गया था कि छ. तथाकथित कृषि-कार्यक्रमों में वे सबसे अधिक समर्थन किसका करते हैं। ५३ प्रतिशत किसानों ने अपनी सूची के सबसे ऊपर यह लिखा . “स्कूल में दुपहर के भोजन का कार्यक्रम वर्तमान की अपेक्षा दुगुने बच्चों के लिए कर दिया जाए।” ४१ प्रतिशत ने स्कूलों में दिये जाने वाले दूध के विशेष कार्यक्रम को दुगुने बच्चों के लिए कर देने की बात कही। ३८ प्रतिशत ने खाद्य-टिकट योजना (Food-Stamp Plan) शुरू करने का सुझाव दिया, जिससे अधिशेष भोजन अभावग्रस्तों को सुलभ हो सके। इन तीन सुझावों को ही सबसे अधिक मत मिले। बाकी किसी भी प्रस्ताव को जनमत-संग्रह में भाग लेने वाले किसानों के २९ प्रतिशत से अधिक मत नहीं मिले।

सचार्थ तो यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका के उन सभी ८० लाख परिवारों को, जिनका वार्षिक आय २००० डालर से कम है यदि पर्याप्त भोजन मिलता तो उनका अतिरिक्त उपभोग १९५७ से १९५९ तक पूरे तीन वर्षों के तथाकथित खाद्य ‘अधिशेषों’ के बराबर हो जाता।

और शेष दुनिया के उन १ अरब लोगों का क्या हो जो रोज बिलकुल भूखे रहते हैं ? संयुक्त राज्य निश्चय ही अपने कृषि अधिशेषों को पिण्ड छुड़ाने के लिए दूसरे देशों में बिखेर नहीं सकता। लोगों को भोजन बाँटना भी सीधी-सी बात नहीं है—और न हमेशा समझदारी की ही बात होती है। लेकिन चिरकालिक भूख और चिरकालिक अधिशेषों को एक दूसरे के समीप लाने और कम करने की कोई विश्व खाद्य योजना सोची ही न जा सके यह बात तो किसी भी तरह मानी नहीं जा सकती।

लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम बनावटी अभाव और विरलता का स्थिति को श्रेयस्कर समझने के बदले प्रचुर उत्पादन और प्रचुर उपभोग को श्रेष्ठ और श्रेयस्कर समझे और उनके अभ्यस्त होते जाएँ। प्रचुरता को श्रेष्ठ समझना और उसका अभ्यस्त होते जाना इसलिए और भी आवश्यक है, क्योंकि अमरीकी कृषि पर लादी गई बनावटी कमी कभी सफल नहीं हुई और न आगे कभी हो पाएगी।

यदि हमारी कृषि-समस्याओं को सुलझाने के लिए सहकारी पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए तो उसपर बनावटी कमी लाने के प्रयत्नों की कभी आवश्यकता ही न हो। लेकिन शर्त यही है कि हम सहकारिता को उसके व्यापकतम अर्थों में अपनाये और उसका उपयोग करे, अर्थात् मानवी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सारी दुनिया के लोगों के साथ मिल कर काम करे।

किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सहकारी पद्धति के उपयोग का नैतिक और समाज शास्त्रीय पक्ष इतना परिपुष्ट है कि हमारे देश के गिरजाघरों ने भी १९५१ से इस पद्धति का खुले रूप से समर्थन करना आरम्भ कर दिया है। ४ जून १९५८ को संयुक्त राज्य के गिरजाघरों की राष्ट्रीय कौन्सिल के जनरल बोर्ड ने (General Board of the National Council of Churches of Christ in the United States) 'कृषि-नीति के नैतिक लक्ष्य' नामक एक वक्तव्य प्रकाशित किया था। इस वक्तव्य में एक जगह यह अनुच्छेद आता है -

किसानों में स्वेच्छिक संगठन, सहकारिता और पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहना। प्रभु और पड़ोसी को प्यार करने के ईश्वरीय आदेश की व्यावहारिक अभिव्यक्तियों के रूप में पारस्परिक सहायता और सहकारिता पर ईसाई परम्परा ने सदैव जोर दिया है। पारस्परिक सहायता और सहकारिता के लिए अपने आपको स्वेच्छिक संगठनों में संघबद्ध करके कृषकों ने बड़ा ही उत्तम कार्य किया है। स्वतन्त्र विवेचन निर्णय क्षमता, उत्तरदायित्व का वहन आदि गुणों के द्वारा चरित्र-निर्माण का अवसर प्रदान करनेवाली ऐसी इस संघबद्धता को उत्साहित करना चाहिए। गिरजा घरों को चाहिए कि वह पारस्परिक सहायता और सहकारिता के ऐसे संगठनों में सदस्यों की पूरी सक्रियता को, समाज के लिए ईसाई और जनवादी आदर्शों के सच्चे योगदान के रूप में, बढ़ावा दे।

१९६० में राष्ट्रीय कैथोलिक ग्राम्य जीवन सम्मेलन (National Catholic Rural life Conference) ने अक्तूबर महीने में अपने मुख-पत्र "कैथोलिक रूरल लाइफ" का सहकारी मस्याओं तथा किसानों और ग्राम्य जीवन में उनके मूल्य एवं महत्व पर एक पूरा विशेषांक ही प्रकाशित किया। इस विशेषांक के मुख्य लेख में फोर्ट वेईन-साउथ वेण्ड के विंगन परम आदरणीय लियो ए० पर्सली के एक अनुच्छेद इस प्रकार था -

सामाजिक न्याय का सिद्धान्त, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सर्व सामान्य हित की संवर्द्धना के लिए अपना योगदान करना चाहिए, मानव जाति की एकता और समाज की अन्तरवर्ती रचना से आविर्भूत होता है। सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्बाध और अन्यायपूर्ण प्रतियोगिता से एक दूसरे को वंचित करना रोका जा सकता है। इन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से हम अपने नियन्ता द्वारा अभिप्रेत जीवन प्रणाली पर आचरण कर सकते हैं। सहकारी आन्दोलन इस धारणा से उद्भूत होता है कि सभी वर्ग आपस में जुड़े हुए हैं और एक वर्ग का हित सभी का हित है और सबकी समृद्धि के बिना एक वर्ग कभी समृद्ध नहीं हो सकता। सहकारी संस्थाएँ वस्तुओं के स्वामीत्व को अधिकांशक लोगों में प्रसारित करने में सहायक हैं। स्वामीत्व उत्तरदायित्व और स्थिरता प्रदान करता है। इस प्रकार सहकारी संस्थाएँ मानव-जाति की एकता और व्यक्ति की गौरव-गरिमा को परिपुष्ट करनेवाले सधान और ईसाइयत तथा जनतन्त्र के शक्तिशाली आधार हैं।

८ | तेल के व्यापार में जनता

एक जमाना था जब तेल व्यापार में उत्पादन, समन्वेषण और कच्चे तेल के अधिकार पर जोर दिया जाता था। लेकिन आज, कच्चे तेल के ज्ञात संचय-स्रोतों का लगभग ८५ प्रतिशत बड़ी कम्पनियों के हाथों में चले जाने और विश्व-उत्पादन माँग से कहीं अधिक हो जाने के कारण सारा प्रयत्न बिक्री-निकासों के अधिकार पर केन्द्रित हो गया है। लेकिन इस तरह के निकासों के बिना स्वतन्त्र उत्पादक ओर परिष्करण कर्ता। अपने व्यापार से हाथ धोते जा रहे हैं।

१९५७ में चोदह छोटी तेल विक्रेता कम्पनियाँ विशाल एकीकृत कम्पनियों में या तो विलीन हो गई या उनका अधिग्रहण कर लिया गया। १९५८ में आठ और कम्पनियों का यह हाल हुआ। और १९५९ में न कम न ज्यादा पूरी छत्तीस छोटी कम्पनियाँ इस रास्ते गायब हो गईं।

१९६० का आरम्भ होते ही तेल-व्यवसाय के गुरु को समझने और अन्दर-रूनी बातों को जानने वाले लोग यह भविष्यवाणी करते सुनाई देने लगे कि स्वतन्त्र विक्रेताओं के ही नहीं स्वतन्त्र उत्पादकों और स्वतन्त्र परिष्करण कर्ताओं के दिन भी अब आ लगे हैं। सुस्थापित विक्रेता अधिष्ठानों की सम्पत्ति और नाम के लिए बड़ी कम्पनियाँ खुले हाथों मुँह माँगी कीमते देने लगी, बल्कि कहना चाहिए कि लुटाने लगी। नाम तो शायद ही कभी बदले जाते हैं। उपभोक्ता यही समझता है कि वह एक स्वतन्त्र व्यापारी से तेल खरीद रहा है, लेकिन हर महीने हालते कुछ ऐसी होती जा रही है कि वह वास्तव में किसी बड़ी कम्पनी के अनुषंगी निकास का प्रतिपोषण कर रहा होता है। तेल-व्यापार में केन्द्रीकरण बढ़ता जाता है।

‘पेट्रोलियम बोर्ड’ (६ नवम्बर १९५९) ने टेक्सास के एक प्रमुख तेल महा-जन (बैंकर) का निम्न अन्तरण उद्धृत किया था:

उस समय स्वतन्त्र कारबार करने वाले बहुत से लोगों ने इस बात को नहीं समझा और आज भी कई ऐसे हैं जो इसे नहीं समझते कि प्रोडेशन

(Proration) लागू कर दिये जाने से कच्चे तेल का सारा बाजार एकदम बड़ी कम्पनियों के हाथ मे चला गया है। तेल-उत्पादकों की आज गैस-उत्पादकों से तुलना कीजिए। गैस-उत्पादक के पास करारनामा होता है; ज्यादातर करारनामो मे माल की न्यूनतम लेवाली और स्थिर मूल्यों का स्पष्ट उल्लेख रहता है और आमतौर पर उनकी अवधि बीस वर्ष की होती है। तेल-उत्पादक के पास ऐसा कोई करारनामा नहीं होता। वह अपनी बिक्री किसी बड़ी तेल कम्पनी के मार्फत ही कर सकता है। और वह बड़ी कम्पनी जब चाहे कीमतों मे अदला-बदली कर सकती है, और चाहे तो कल से उसका तेल लेना भी बन्द कर दे। आज तेल का सम्भार इतना अधिक है कि बड़ी कम्पनी को संयोजन (कनेक्शन) बदलने के लिए विज्ञापित मूल्यों पर दिये जाने वाले कुछ अधिशुल्क के बाहर प्रायः उत्पादक को और कोई अभिप्रेरण नहीं देना पड़ता।

तेल के स्वतन्त्र व्यापारी शायद इस बात को सचमुच ही भूल चुके हैं कि सहकारी बिक्री व्यवस्था भी हो सकती है। कोई भी ऐसी वैधानिक या नैतिक बाधा नहीं है जिसके कारण स्वतन्त्र व्यापारी अपना सहकारी विक्रय सध नहीं बना सकते।

अब जो बची रह गई है वे स्वतन्त्र तेल कम्पनियाँ व्यापार मे ठिके रहने के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाती हैं या नहीं यह तो अभी देखने की बात है; लेकिन पेट्रोल-उत्पादनों के कई लाख उपभोक्ताओं ने इस काम को काफी सफलता के साथ कर दिखाया है और अपने-आप को तथा सभी तेल उपभोक्ताओं को जितना लाभ पहुँचाया है उसका सही-सही अनुमान लगा पाना कठिन ही है।

कुछ साल पहले यह कहा जाता था कि रोमन कैथोलिक चर्च, स्टैंडर्ड आयल कम्पनी और फ्रान्सिसी सेना—ये दुनिया के तीन सबसे शक्तिशाली सगठन हैं।

द्वितीय महायुद्ध ने फ्रान्सिसी सेना का नाम तो इस सूची से खारिज कर दिया। कैथोलिक चर्च अवश्य अपने लाखों-करोड़ों भक्तों पर अब भी वैसा ही शक्तिशाली प्रभुत्व रखता है।

और स्टैंडर्ड आयल कम्पनी का भी उससे भिन्न प्रकार का अधिकार लगभग अपने ही लोगों की जेबों पर है। बहुत-सी बड़ी तेल कम्पनियों के अभ्युदय के

बाद भी 'स्टैंडर्ड' को विज्ञापित कीमते' आज भी संयुक्त राज्य अमरीका और अधिकांश विश्व के पेट्रोल व्यवसाय के लिए निर्देशात्मक और अन्तिम रूप से निर्णयात्मक होती हैं।

प्रायः एक आध शहर के पेट्रोल के फुटकर बिक्री पम्पों पर कीमतों की लागू-डॉट हो जाया करती है और हॉड़ा-होड़ी मच जाती है, लेकिन यह ज्यादा समय तक चल नहीं पाता। कच्चे और परिष्कृत दोनों ही तरह के माल की कीमतें बड़ी कम्पनियों का 'भाई चारा' अपने अच्छे-खासे नियन्त्रण में रखता है। इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं कि पचास बरस पहले न्याय-विरोधी काररवाइयों के जो परिणाम हुए थे उनका भी घोर परावर्तन कर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड आयल कम्पनियों में की कुछ कम्पनियाँ जो उस अकेले न्याय की उत्तराधिकारी हैं आज अपने विलय की चर्चा करने लगी हैं। और उस जमाने से भिन्न आज की उग्र मन स्थिति में उनका यह कृत्य किसी उल्लेखनीय जन-विरोध के बिना सम्भवतः स्वीकार भी कर लिया जाएगा।

यह तो एक दस्तावेजों हकीकत है कि संयुक्त राज्य अमरीका और कम्प्यूनिस्ट गुट के बाहर शेष सारी दुनिया का पेट्रोल उत्पादन सात कम्पनियों के कब्जे में है। लेकिन न्याय विभाग (Department of Justice) ने इस समूह की अमरीकी कम्पनियों के विरुद्ध अपने न्याय-विरोधी वाद को समाप्त कर दिया। ऐसा करने का कोई भी कारण आज तक नहीं बताया गया; लेकिन इसका उत्तर तो इस बात से मिल जाता है कि जहाँ अमरीकी जीवन का कोई कोना-अंतरा और कोई छेड़-दरार कांग्रेस स्तरीय खोज-बीन से बच नहीं पाई वहाँ तीस वर्षों से भी अधिक समय होने आया तेल-व्यापार को किसी भी जाँच-पड़ताल के द्वारा छेड़ा नहीं गया। तेल की आवाज ऊँची नहीं है, लेकिन वह बोलता है एकछत्र अधिकार के दर्प से।

अकेले इसी उद्योग में शास्ता शासितों के अधिकार में देखे जाते हैं। संयुक्त राज्य में उपलब्ध पेट्रोल के परिमाण के प्राक्कलन के लिए खनि विभाग (Bureau of Mines) बड़ी तेल कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों का ही उपयोग करता है। और इस विभाग ने तेल उद्योग को अप्रसन्न करने वाली कोई बात कही या को हँसी; कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय या कम-से-कम प्रकाशन ही किया था

उसका समर्थन किया ही ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं।

यह भविष्यवाणी तो अब आम होती जा रही है कि निकट भविष्य में ही पेट्रोल व्यवसाय के समस्त स्वतन्त्र व्यापारी खत्म हो जाएँगे और बड़ी कम्पनियों से प्रतियोगिता करने के लिए केवल सहकारी सस्थाएँ ही रह जाएँगी। स्वतन्त्र तेल परिष्कर्ता सघ (Independent Oil Refiners Association) के अध्यक्ष ने सहकारी स्वामीत्व को किसी परिष्करण-शाला की एक नई इकाई का उद्घाटन करते हुए यह कहा था कि सहकारियों के इस व्यवसाय में आने के लिए बड़ी कम्पनियों को उनका कृतज्ञ होता चाहिए। क्योंकि, अध्यक्ष महोदय की राय में, इस व्यवसाय में सहकारियों की विद्यमानता ही वह बड़ा कारण थी जो सरकार को एकाधिकारी स्थिति को सुधारने के लिए कोई कड़ा कदम उठाने से रोके रही। उन अध्यक्ष महोदय के इस तरह की बात कहने का कारण भी था। जिस शहर में (कुशिंग, ओक्लाहामा) उन्होंने यह बात कही वहाँ कुछ समय पहले चौदह परिष्करण शालाएँ थी, जिनमें से अधिकांश स्वतन्त्र थी; लेकिन जिस समय उन्होंने उद्घाटन किया वहाँ केवल दो परिष्करण-शालाएँ थी—एक तो किसी बड़ी कम्पनी की और दूसरी सहकारी सस्था की। इसीलिए ऐसी टिप्पणी करने का यह काफी उचित कारण था।

सहकारी संस्थाओं द्वारा की जानेवाली प्रतिस्पर्धा निराले प्रकार की है। यह प्रतिस्पर्द्धा व्यापार में पिट कर बिक जाने वाली प्रतिस्पर्द्धा नहीं है। सबसे पहली बात तो यह कि सहकारी सस्थाएँ 'पैसा कमाने के लिए' नहीं, बल्कि अधिमूल्यन के भार में बुरी तरह दबे किसानों के लिए पैसा बचाने की उद्देश्य में ही तेल व्यवसाय में आई हैं। जैसे-जैसे सहकारी संस्थाओं की वृद्धि होती गई और वे अपने कार्य-व्यापारों का एकीकरण करती गई उनका उद्देश्य भी व्यापक रूप धारण करता चला गया। अब इस उद्देश्य में अपने सदस्यों को एक बड़े उद्योग के कुछ अंश का स्वामी बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने की बात और जुड़ गई। मुँह माँगा दाम पाकर बड़ी कम्पनियों के हाथ अपने को बेच देने से तो इन दोनों ही उद्देश्यों की उपलब्धि नहीं हो सकती।

जनता द्वारा तेल-व्यापार की जोखिम उठाने का आरम्भ किसी नाटकीय घटना से कम नहीं है। १९२० के बाद के वर्षों में ट्रैक्टर के आगमन से भी इसका

अनिष्ट सम्बन्ध है। ट्रैक्टर के ईंधन के लिए काफी पैसा चाहिए। और खेती की तो रौढ़ वैसे ही टूटी जा रही थी, इतने महँगे ईंधन के लिए ढेर सारा पैसा आये कहाँ से ! मिन्नेसोटा में किसानों का एक समूह अँगोठी के आगे बैठ आपस में सलाह-मशविरा करने लगा कि क्यों न अपनी गाड़ी कमाई के कुछ पैसे को लगाकर अपने लिए पेट्रोल का एक पम्प और बड़ी टकी बना ली जाए। इस कारबार को सहकारी ढंग से स्वयं करके एक तो वे पेट्रोल-उत्पादन सम्बन्धी अपनी और अपने पड़ोसियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे और दूसरे उन्हें यह भी मालूम हो जाता कि पेट्रोल की लागत और कीमत क्या बैठती है। यह मिन्नेसोटा के काटन वुड कस्बे की १९२१ की बात है। तेल के व्यापार में जनता का यह पहला कदम था। और पहले ही दिन से यह कदम काफी सफल रहा।

लेकिन काटन वुड के लोगों को शीघ्र ही यह पता चल गया कि खाली फुटकर विक्री का कारबार तो खतरे से खाली नहीं होता और बाज वक्त उसे चलाना ही मुश्किल हो जाता है। राज्य की दूसरी बस्तियों में जो पेट्रोल सहकारी सस्थाएँ काम कर रही थी उनका भी यही अनुभव था। प्रायः तेल पाना ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए अन्त में १९२६ के एक दिन, अपने क्षेत्र के सभी सहकारियों को पेट्रोल उत्पादन का सम्भरण करने के लिए, शुभ मुहूर्त देखकर, प्रार्थना और शुभाकांक्षा ओर बड़ो-बड़ो सद्भावनाओं के साथ मिडलैण्ड सहकारी थोरो सस्था (Midland Cooperative wholesale) की स्थापना की गई।

आरम्भ के वर्षों में तेल सहकारी सस्थाओं ने अपने सदस्यों को औसत १६ प्रतिशत के आस पास सरक्षण धन वापसियाँ की।

उपर ओहियो, इंडियाना और इलिनोइस के किसानों की भी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि कस्बे की टकी से सिर्फ फारम तक लाकर देने में ट्रैक्टर के द्रव-ईंधन की कीमत सात सेट प्रति गैलन कैसे हो जाती है ! और शोध हो उन्होंने मालूम कर लिया कि यह कीमत तो आधी भी नहीं होनी चाहिए। यह भेद उन्होंने जाना मिन्नेसोटा के किसानों की तरह अपनी निजी तेल-वितरण सहकारी सस्थाओं की स्थापना करके। लेकिन इनके सामने भी वही समस्या

आई और इन्हे भी सम्भरण के लिए थोक सहकारी सस्था की आवश्यकता महसूस हुई। और तीनों ही राज्यों में फारम ब्यूरो ने जिला सहकारियों की माँग का निकाय कर आपूर्ति प्रयत्नों के लिए राज्य व्यापी सहकारी थोक सस्थाएँ प्रायोजित की।

लेकिन इन थोक सहकारी सस्थाओं के सामने भी ठीक वही कठिनाई आई। अपने सम्भरण कर्ताओं से, जो इनके एकीकृत प्रतिस्पर्द्धी भी थे, इन्हे बड़े विचित्र ढंग से और सहसा ही माल मिलना बन्द हो जाता था।

अक्सर ऐसे अवसर आ जाते थे जब कुछ कच्ची हिम्मत वाले यह सलाह देने लगते कि इस खटराग को बेच-बाचकर छुट्टी की जाए। लेकिन उनको बात चल नहीं पाती थी।

इसके विपरीत उधर कन्सास के मैदानों में १९२५ के बाद के वर्षों में अमरीकी इतिहास में पहली सहकारी तेल परिष्करण-शाला का अभ्युदय हुआ। उसके बाद देश के विभिन्न भागों में इस तरह की और कई परिष्करण-शालाएँ बनीं, जिन्हे विभिन्न सहकारी सस्थाओं ने या तो स्वयं निर्मित किया या किसानों से खरीद लिया। कन्सास की परिष्करण शाला को उचित मात्रा में कच्चा तेल किसी भी तरह मिलना सम्भव न हो सका तो मामले को जाँच-पड़ताल के लिए न्याय विभाग को सौंपने की धमकी देनी पड़ी और तभी आवश्यक मात्रा में और ठीक समय पर तेल मिलना शुरू हुआ और तभी वह परिष्करणशाला ठीक ढंग से चलने लगी।

लेकिन जनता का तेल-व्यापार अभी तक एकीकृत नहीं हो पाया था, जो उसके जीवित रहने के लिए नितान्त आवश्यक था, और न वह स्वतन्त्र ही हो पाया था, जो केवल सम्पूर्ण एकीकरण के बाद ही सम्भव था।

जनता को यह सिद्ध कर के दिखा देना था कि वह कच्चे तेल के उत्पादन से लेकर परिष्करण, थोक वितरण और फुटकर बिक्री तक सारे काम स्वयं कर सकती है।

और लोगों ने यह करके दिखा भी दिया।

१९३९ की सर्दियों में फिर कन्सास के मैदानों में एक अलाव के चारों ओर उपभोक्ता सघ (Consumers Cooperative Association) के

लोगों का एक छोटा-सा समूह आग ताप रहा था। वे लोग सारी रात इसी तरह बैठे प्रतीक्षा करते रहे थे। अन्त में जैसे ही सवेरा हुआ उनकी चिन्ता मिटी और लम्बी प्रतीक्षा का फल मिला। पहली बार जमीन के अन्दर से वह तेल निकला जिसके स्वामी वही लोग थे जिन्हें उस तेल के परिष्कृत उत्पादनों की स्वयं अपने लिए आवश्यकता थी। पहली बार, सब लोगों के लाभ के लिए भगवान् की कृपा से प्रकृति की प्रक्रियाओं द्वारा पेट्रोल में सन्निहित ऊर्जा का वह महत् मन्त्र कुएँ से पाईप लाइन द्वारा सीधे उन साधनों में पहुँचाया गया जो इन लोगों की आवश्यकताओं को सीधे-सीधे पूरा करने के लिए बनाये गए थे।

१९४३ में मिडलैण्ड कोआपरेटिव्स ने कुशिंग, ओक्ला होमा में एक परिष्करणशाला खरीदा जिसकी पूरी कीमत उसी की तीन माल की वचतों से निकल आई।

इस कहानी का अधिक विस्तार अनावश्यक ही है। आज संयुक्त राज्य के किसानों द्वारा जितना पेट्रोल खर्च किया जाता है उसका १८ से २२ प्रतिशत सहकारी संस्थाएँ अपने कुओं से थोक टकियों और फुटकर पम्पों तक पहुँचाती हैं। मध्य पश्चिम (middle west) के ऊपरी हिस्से के राज्यों में तो यह अनुपात और भी अधिक है। कुछ जिलों में ४० से ५० प्रतिशत पेट्रोल का पूरा व्यवसाय सहकारी संस्थाओं के हाथ में है।

उन्नति का यह क्रम बड़ा ही उत्साहवर्द्धक है। उदाहरण के लिए १९५० में सहकारी संस्थाओं ने संयुक्त राज्य के फारमों पर खर्च किये जानेवाले पेट्रोल उत्पादनों के १६ प्रतिशत का सम्भरण किया। १९५७ में यह बढ़कर २०.४ प्रतिशत हो गया। इन सात वर्षों में सहकारी संस्थाओं के पेट्रोल उत्पादन के कुल कारबार के असल मूल्य में ३३ ७ प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि उसी अवधि में किसानों के तेल-उत्पादनों के कुल व्ययों में केवल १४.४ प्रतिशत बढ़ती हुई।

सहकारी संस्थाएँ अपने सदस्यों और ग्राहकों को जितना तेल बेचती हैं उसका अधिकांश स्वयं उन्हीं की परिष्करण-शालाओं से प्राप्त होता है। १९५७ में सहकारी संस्थाओं ने १,९५,७००,००० गैलन द्रव ईंधन के रूप में पेट्रोल बेचा, इसमें से सहकारी परिष्करण-शालाओं ने १,८३,३०,००,०० गैलन तैयार किया था। दो हजार सहकारी तेल कुओं की पैदावार परिष्करण आदि के बाद २७००

बड़ो टकियों और २००० पम्पों को चलाने वाली कोई २७०० स्थानीय पेट्रोल सहकारी संस्थाओं के मार्फत उपभोक्ताओं को बेची जाती है।

सहकारी संस्थाओं का लगभग २००० तेल कुओं पर स्वामीत्व है। वे १० परिष्करण शालाएँ चलाते हैं, जो पहले से सख्या में अवश्य आधी हैं, लेकिन उनको कुल क्षमता पहले से काफी ज्यादा है। देश के कुल पेट्रोल उत्पादन के लगभग २२ प्रतिशत का सहकारी संस्थाओं द्वारा अपनी पाईप लाइनों, ट्रकों, थॉक और फुटकर निकासों के द्वारा वितरण किया जाता है। १.६ प्रतिशत का वे परिष्करण करती हैं। उनको सबसे बड़ी कमी यह है कि अपनी परिष्करण-शालाओं के लिए जितना कच्चा तेल चाहिए उससे उन्हें अपने कुओं से १५ प्रतिशत कम मिल पाता है। परिष्करणशालाओं के सन्तुलित और निश्चित संचलन के लिए उन्हें कोई ५० प्रतिशत की आवश्यकता है।

एक महान उद्योग के इतने छोटे-से कारवार से भी सहकारी संस्थाओं ने काफी-कुछ कर दिखाया है। वे सरक्षण धन वापसी के रूप में किसानों को, फारम को आय को, देहाती कस्बों और उनकी आय को लाखों-करोड़ों डालर लौटा चुकी हैं। ये वापसियाँ वह बचत हैं जो थोक और फुटकर बिक्री के अन्तर के कारण हुई हैं, अर्थात् वह बचत जो वास्तविक लागत और बाजार में चालू कीमतों के अन्तर के कारण हुई हैं। इस बचत में उत्पादन और परिष्करण का अन्तर भी समाविष्ट है। यह मुनाफे की वह भलाई है जो किसानों और ग्राम्य जनता से बसूली जाती, परन्तु धूम-फिर कर उन्हीं के पास उनके सहकारी स्वामीत्वकृत तेल कुओं और परिष्करणशालाओं के माध्यम से लौट आई।

ये सब तो प्रत्यक्ष लाभ हुए, लेकिन इसके अप्रत्यक्ष और अप्रकट लाभ भी कई हैं। यदि १९१०-१९१४ को आधार अवधि मानकर मूल्यों का सूचकांक १०० स्थिर किया जाए तो १९५९ में किसानों को आवश्यक सम्भरणों और यन्त्रादि के लिए जो कोमते देनी पड़ी उसका सूचकांक २७५ ही गया। लेकिन सहकारियों के दो सत्रसे तगड़े बारबार पेट्रोल और उर्वरक में मूल्यों का सूचकांक क्रमशः १७५ और १५२ ही रहा। •

मिन्नेसोटा, विसकोन्सिन और दूसरे कुछ राज्यों में १९३४ के मुकाबले १९५९ में जिनमें को कोमती में आमतौर पर जो बढ़ती हुई उसकी तुलना में

गैसोलिन (पेट्रोल) के मूल्य में केवल दो-तिहाई वृद्धि हुई। यह किस हद तक उस क्षेत्र की शक्तिशाली सहकारी संस्थाओं की प्रतियोगिता का परिणाम है इसका ठीक-ठीक निश्चय कर पाना तो असम्भव ही है। लेकिन इस बात को तो मानना ही होगा कि सहकारियों की प्रतियोगिता का हममें काफी बड़ा हाथ है।

सहकारियों के आर्थिक प्रयोजन बहुत सीधे और साफ हैं। उनका हेतु है अपने ग्राहकों को, जो उनके स्वामी भी होते हैं, उत्कृष्ट कोटि का माल, बिना घाटे की न्यूनतम असली कीमत पर प्रदान करना है। अपने-आप से मुनाफा कमाने में कोई तुक नहीं है। इसलिए पेट्रोल उद्योग की सहकारी संस्थाओं का अपने संरक्षक-स्वामियों के लाभ के लिए उत्पादन की विस्म को निरन्तर सुधारते रहने का प्रयत्न समूचे उद्योगों पर एक ऐसा प्रभाव है, जिसे नापना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसने उन अनगिनत लोगों को गौण रूप से लाभान्वित किया है, जो इन तेल सहकारियों के अस्तित्व तक से अनभिज्ञ हैं।

काफी विले (कन्सास) की सीसीए की, कुशिंग (ओक्लाहामा) की मिडलैण्ड की, या मेक्फरसन (कन्सास) की राष्ट्रीय सहकारी परिष्करण संघ (National Cooperative Refining Association) द्वारा संचालित सहकारी परिष्करण शालाओं से अधिक दक्ष और श्रेष्ठ क्या कोई दूसरी भी है, यह प्रश्न सम्भवतः अनुत्तरित ही रहा। राष्ट्रीय सहकारी परिष्करण मक्ख वाली परिष्करणशाला तो सात क्षेत्रीय पेट्रोल सहकारी संस्थाओं के संयुक्त स्वामित्व और संचालन में एक केन्द्रीय प्रतिष्ठान है। इसकी दैनिक क्षमता २६ हजार पीपे है।

सहकारियों के कार्य संचालन के इस नियम को कि उनकी प्रवृत्ति मुनाफों को, जिसका मजा उनके सदस्यों को केवल एक ही बार मिलता है, आम जनता में वितरित करने की है, अभी तक भी बहुत कम समझा गया है। और आज तो यह बात शायद ही किसी को याद होगी कि तीस बरस पहले शहर से फारम तक ईंधन (पेट्रोल) पहुँचाने में उसका दाम सात सेट प्रति गैलन होता था। सहकारियों ने यह अनुभव किया कि इन दरों को ढाई या तीन सेट प्रति गैलन तक घटाया जा सकता है और जब घटा दिया तो सारे पेट्रोल उद्योग को भी ऐसा करना पड़ा।

अमरीकी अर्थ व्यवस्था में तेल का व्यापार कुल मिला कर सबसे अधिक लाभ का व्यवसाय है। यद्यपि बीस लाख सहकारी सदस्यों का इस उद्योग के बहुत ही छोटे हिस्से पर स्वामीत्व है, फिर भी उन्हें जो लाभ होता है वह बिलकुल उजागर ही है।

उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम मध्यम दर्जे के मिडिल वेस्टर्न कस्बे के एक चौराहे को ले सकते हैं। चौराहे के तीन कोनों पर तीन पेट्रोल पम्प हैं। एक पम्प तो किसी बड़ी तेल कम्पनी का है, दूसरा किसी स्वतन्त्र ठेकेदार का है और तीसरा सहकारी सस्था का है।

प्रकट ही है कि दूसरे और तीसरे क्रम के पम्प तो स्थानीय स्वामीत्व कृत उद्यम हैं, लेकिन पहला अन्यत्रवासी अनुपस्थित स्वामी का है। बड़ी तेल कम्पनी के पम्प पर लाभदायी फुटकर बिक्री, माल को भराई-डुलाई, थोक-बिक्री, परिष्करण या उत्पादन से जो कमाई होती है उसमें से उस बस्ती में कुछ भी रहता नहीं। केवल वही है जो तनखाह और मजदूरी के रूप में उस पम्प पर काम करने वालों को दिया जाता है। दूसरा पम्प जिसका मालिक स्थानीय आदमी है और जिसने अपने सम्भरण के लिए एक तेल कम्पनी से मविदा किया है उसकी स्थिति कुछ भिन्न है। यहाँ काम करनेवाले का पारिश्रमिक ही नहीं फुटकर बिक्री का मुनाफा भी बस्ती में ही रहता है। लेकिन सम्भरणकर्ता तेल कम्पनी को कमाई में से इस पम्प के स्वामी को भी कुछ नहीं मिलता।

सहकारी इन दोनों से ही भिन्न प्रकार का व्यवसाय है। जो लोग इसकी सेवाओं का प्रयोग करते और इसके उत्पादन खरीदते हैं यह उन्हीं की सम्पत्ति है और सदैव रहेगा। वे स्थानीय लोग हैं—उसी कस्बे के किसान और दूसरे लोग। फिर उनके स्थानीय सहकारी के क्षेत्रीय थोक और उत्पादन सहकारियों में हिस्से भी हैं। इस तरह कस्बे का पम्प चलाने वाले लोगों की तनखाह और मजदूरी ही बस्ती के घर-की-घर में नहीं रहती, फुटकर बिक्री, थोक के काम, परिष्करण, परिवहन और उत्पादन की कमाई (इसे सहकारी शब्दावली में बचत कहते हैं) के सारे सीमान्तों का उचित सानुपातिक अंश बस्ती में ही रहता है। क्योंकि थोक और उत्पादन सहकारी द्वारा ये उपार्जन संरक्षणधन वापसियों के रूप में प्रति वर्ष अपने स्थानीय सहकारी सदस्यों को लौटा दिए जाते हैं। और वह

रकम पेट्रोल पम्प में उनके संरक्षण के अनुपात से पुनः बस्ती वालों की जेब में लौट आती है क्योंकि वे ही तो उस पम्प के ग्राहक और मालिक भी हैं।

एक जमाना था जब पेट्रोल पम्प के ग्राहकों की और मालिकों की संख्या बहुत ही सीमित हुआ करती थी, क्योंकि सहकारी पेट्रोल पम्प न तो इतने आकर्षक, न इतने व्यवस्थित, न इतने साफ-सुथरे और न इतने रंगे-बूंगे ही होते थे जितने कि प्रतिस्पर्द्धियों के हुआ करते थे। कुछ वस्तियों में आज भी यही हाल है। एक स्थानीय सहकारी पेट्रोल पम्प के व्यवस्थापक का वह किस्सा तो सभी को मालूम है जिसने यह कहकर नये साइनबोर्ड का विरोध किया था : “नया साइनबोर्ड क्यों लगाने हो ? सदस्य तो सभी जानते हैं और दूसरा कोई फटकता नहीं।”

सच है, दूसरे शायद ही फटकते होंगे।

लेकिन अब समय बदल गया है। १९५१ के आरम्भ से ही पेट्रोल सहकारियों का काया पलट होने लगा; चमक-दमक वाली कार्यकुशल परिष्करण-शालाओं का रंग-रोगन और चेहरा-मुहरा हो नहीं स्थानीय पेट्रोल पम्पों और बड़ी टंकियों की शकल-मूरत भी एकदम बदल गई। पेशे से सम्बन्धित कार्यों के विकास और साधन-सामग्रियों की एकरूपता के कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय थोक सहकारियों ने पैसा दिया। गन्दे, बुरी जगहों में बने हुए अनाकर्षक सहकारी पेट्रोल पम्पों के स्थान पर चमक-दमक वाले, अच्छी तरह सजे-सँवारे, साफ-सुथरे और आकर्षक सेवा-साधन-केन्द्र दिखाई पड़ने लगे, और जिन्हें अपने सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे लोगों से भी व्यवसाय मिलने लगा। देश का सर्वोत्कृष्ट पेट्रोल पम्प और सेवा-केन्द्र मित्रिया पोलिस की महानगरी में मिडलैण्ड कोआपरेटिव्स इन कारपोरेशन का है जिसे वह स्वयं चलाती है और जो इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि सहकारी सेवा कितना बढ़िया-से-बढ़िया काम कर सकती है।

तेल के व्यापार में जनता १९२० के बाद के वर्षों में, मुख्य रूप से किसानों और कृषि पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने के लिए, आई थी। आज भी तेल-उत्पादनों के अधिकांश सहकारी व्यापार पर किसानों का स्वामीत्व है और वे मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीण वस्तियों की ही सेवा करते हैं। लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद से देश का शहरातीकरण तेजी से बढ़ता जा रहा है और नगर ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गए हैं और पूरे-पूरे किसानों की संख्या कम हो गई है।

तेल सहकारियों ने समय के इस संकेत को देखा और सम्झा। उन्होंने अपने व्यापार को और खासतौर पर वाष्पीय तेलों और मोटर के ईंधन एवं तेल के कामकाज को शहरों में फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उपनगरीय वस्तियों में पेट्रोल पम्पों का अधिग्रहण किया और इक्के-दुक्के पेट्रोल पम्प शहर के ठीक मध्य में भी प्राप्त कर लिये। इसी बीच नागरिक आधार वाले उपभोक्ता सहकारियों ने बाजार के रख को परख कर पेट्रोल पम्प और मोटर सम्बन्धी सेवाओं का सारा काम अपने यहाँ और बढ़ा लिया; ये सहकारी अपना पेट्रोल और तेल क्षेत्रीय सहकारियों से लेने लगे, जो कभी एकमात्र किसानों को ही माल दिया करते थे।

इन नये खेतालों का दिलचस्प उदाहरण ओहियो राज्य की कुया होगी काउटी में देखने को मिलता है।

१९३४ में जब जिला (काउटी) फारम ब्यूरो को आपरेटिव बनाया गया तो कुया होगी काउटी में १२३० फारम थे। १९५९ में पचास एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले मुश्किल से सौ फारम रहे होंगे। लेकिन पाँच और दस एकड़ के बगीचे और छोटे खेतों की संख्या काफी बढ़ गई और ये सब नगर का काम करने वाले लोगों के पास थे। पक्के-पूरे किसान परिवार बलीबलैण्ड नगर सहित पूरे जिले की आबादी के १ प्रतिशत के पचमाश से भी कम ही होंगे।

ऐसी स्थिति में फारम ब्यूरो को आपरेटिव का कारबार बड़ी आसानी से बन्द हो जाता अगर वह पुराने ढर्रे पर ही काम करता रहता। लेकिन इसका संचालक-मण्डल और व्यवस्थापक दूरदर्शी थे। कृषि-योग्य उर्वरकों की बिक्री कम होने लगी तो उन्होंने वाटिकाओं में बोये जानेवाले बीज और उद्यानोपयोगी उर्वरक की बिक्री शुरू कर दी। खेती के उपकरणों की बिक्री गिरी तो उद्यानोपयोगी औजारों और घर-गिरस्ती के साधन-साधनों की बिक्री शुरू कर दी और ये चीजें बिकने भी तेजी से लगी। लेकिन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई शहर और कस्बे के ग्राहकों में गैसोलिन, द्रव ईंधन आदि पेट्रोल निर्मित वस्तुओं की बिक्री की। यह व्यापार काफी बढ़ा। १९३६ में पेट्रोल निर्मित वस्तुओं की बिक्री २६,८०० डालर की हुई थी, १९५८ में वही ५,०२,२०० डालर तक पहुँच गई। १९५३ में मोटरों के द्रव ईंधन की बिक्री शुरू की गई थी और यह वृद्धि उसी का परिणाम थी।

सहकारी की समग्र बिक्री में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई। १९३४ में जहाँ समग्र बिक्री मुश्किल से सत्रह हजार डालर थी वहाँ १९५८ में दस लाख डालर के आसपास पहुँच गई।

किसान अब भी अधिकार से चिपटे हुए हैं। नगरवासियों वैसे तो सरक्षण-धन वापसी का अपना पूरा हिस्सा पा रहे हैं, परन्तु उनकी हैसियत बिना मत-धिकार के केवल 'सहायक' सदस्यों की है। लेकिन समय इस स्थिति को भी शीघ्र ही बदलेगा। क्योंकि इस सहकारी ने बड़े ही व्यावहारिक ढंग से आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ताओं के रूप में फारम और नगरवासियों के सामान्य हितों को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है और मान भी लिया है।

जनता तेल व्यवसाय में स्थायी रूप से रहेगी। इस उद्योग में जनता के सहकारी उतने ही कार्यक्षम और सुसंचालित हैं जितने कि उद्योग को चलाने वाले अन्य घटक। और इस उद्योग की समृद्धि इस बात की मूचक है कि व्यापारिक कम्पनियाँ काफी मुनाफा करती हैं, इसलिए उद्योग के सहकारी अग के स्वामी-ग्राहकों को काफी सरक्षण-धन वापसियों की जा सकती हैं। इन सहकारियों का अभी और भी एकीकरण करना आवश्यक है। कच्चे तेल के आवश्यक सम्भारों पर और अधिक अनुपात में इनका स्वामीत्व होना भी उतना ही आवश्यक है।

जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है बड़ी कम्पनियाँ 'स्वतन्त्र' व्यवसायियों की सारी प्रतियोगिता का अधिग्रहण कर उसे समाप्त करके ही रहेगीं। लेकिन कुछ भी हो जाए सहकारी, अर्थात् तेल के व्यापार में आई हुई जनता, अपने कार-वार को उनके हाथों कभी नहीं बेचेगी, क्योंकि बेचने का अर्थ है उस उद्देश्य और प्रयोजन से ही पराङ्मुख होना जो उन्हें इस व्यापार में ले आया है। और बेचने का अर्थ होगा अमरीकी जनवादी परम्परा के ओज की सबल अभिव्यक्ति को, उसके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रमाण को नष्ट कर देना।

संयुक्त राज्य अमरीका के अत्यधिक एकीकृत उद्योग के काफी अच्छे अंश पर बीस लाख औसत अमरीकी परिवारों का स्वामीत्व और विश्व के कतिपय सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थ (आर्थिक) दानवों से उनकी सफल प्रतियोगिता—यह वास्तव में कितना महान दृश्य है। और यह सब उनके इन निर्णयों की बदौलत कि ऐसा करना समझदारी का काम है, और वह निर्णय सम्भव हुआ। व्यापार को चलाने की सहकारी पद्धति के अस्तित्व की बदौलत।

६ | जनता का पैसा

यह जनता का पैसा है।

सारा पैसा जनता का है—या एक समय था।

जितना भी पैसा और साख है वह सब या तो जनता की बचतों का फल है, या बैंकों, बोमा कम्पनियों और अन्य महाजनी (वित्तीय) संस्थाओं द्वारा उन बचतों का उपयोग है, या बैंको अथवा सरकार द्वारा जनता की साख का मुद्रोकरण है, या सरकार अथवा निजी संस्थाओं द्वारा जनता की साख का उपयोग है।

एक बोमा कम्पनी, न इससे कम और न इससे ज्यादा, सिर्फ यही तो है कि लोगों का एक समूह मिलकर जीवन को एक समान आपत्तियों-विपत्तियों में साझा बनने को तैयार हो जाता है, और जब भी वे विपत्तियाँ आये उनका सामना करने के लिए अपनी बचतों का निकाय करता है। जनता की इन्हीं बचतों पर तो बोमा-व्यवसाय का सारा साम्राज्य टिका हुआ है।

बैंक किसानों, मकान मालिकों और व्यापारियों को कर्ज देते हैं और जमानत में उनके खेत, मकान या व्यापारी सम्पत्ति को बन्धक रखते हैं। लेकिन क्या बैंक ने इन्हें अपना रुपया या अपनी साख उधार दी है? नहीं, कदापि नहीं। वास्तव में बैंक ने किसानों, या मकान मालिकों या व्यापारियों की उस साख का मुद्रोकरण कर दिया है जो पहले से उन लोगों के पास है, लेकिन जिसे मुद्रा में परिवर्तित करने का उनके पास कोई साधन नहीं है।

जब ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाएँ सरकार से रुपया उधार लेती हैं तो वे किसी दूसरे को साख उधार नहीं ले रही होती हैं। वास्तव में वे अपनी ही साख पर उधार लेती हैं। क्योंकि ४५ लाख ग्रामवासियों और किसानों ने निश्चय ही सारी जनता की साख में अपने सानुपातिक हिस्से से अधिक कर्ज नहीं लिया होता है, इसलिए कि सारी जनता की उस साख का निर्माण में अपनी उत्पादन-शक्ति से उन्होंने भी सहायता की है।

इस प्रकार हमारी अर्थ-व्यवस्था के अन्दर की प्रक्रिया में सारी पूंजी, सारा रुपया और सारी साख कभी-न-कभी सीधे-सादे, सामान्य नागरिकों के हाथ में रहो है, जिनमें से कुछ धनो हैं, बहुत से मध्य वित्त श्रेणों के हैं और अधिकांश गरीब हैं।

थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो ये सारी बातें विस्मयकारी तो जरा भी नहीं हैं। आश्चर्य की बात केवल इतनी ही है कि लोग इनके बारे में सोचते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अवश्य हैं जो सोचते हैं, और कुछ लोग सोचकर उनपर आचरण भी करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं और क्यों करते हैं, यही इस अध्याय का विषय है।

यह अध्याय लोगों के पैसे, साख और बचतों के बारे में है। यह बैंकों, बोमा कम्पनियों और साख संस्थाओं के बारे में है। इसमें जनता की बचत संस्थाओं, जनता की बोमा कम्पनियों और जनता की साख संस्थाओं का वर्णन भी है।

इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जनता की साख का उपयोग—और दुरुपयोग भी—कैसे किया जाता है, उस साख को कैसे आधुनिक जीवन का शक्तिशाली उभारण बनाया जाता है, और जिनकी वह साख है उन्हीं लोगों के जीवन को नियन्त्रित करने वाला हथियार भी। और संक्षेप में हम कर्ज के उस भयंकर अभिशाप का भी उल्लेख करेंगे जो जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता और बहुत से तथाकथित 'कम विकसित' देश के निवासियों की प्रगति को अवरोध करने वाला गले का पत्थर बना हुआ है।

ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सामान्य जन से बार-बार कहा जाता है, बल्कि उसे विश्वास दिलाया जाता है कि वह इन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता। अज्ञान को असाध्य समझ लेने की यह गलत धारणा ही तो हमारी अधिकांश गम्भीर आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है।

राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने, जो उग्र सुधारवादी तो कदापि नहीं थे एक जगह लिखा है:

“अमरीका की सारी परेशानियाँ गडबडों और तकलीफों का कारण हमारे विधान या सच में खामियों का हीना अथवा हम लोगों में सद्गुण

या सम्मान की कमी नहीं, उनका असली कारण है सिक्के, साख और चलन के बारे में हमारा घोर अज्ञान।”

राष्ट्रपति एडम्स का यह कथन आज भी सच है। इसलिए हम बचत से शुरू करेंगे, क्योंकि सारी आर्थिक प्रगति की कुञ्जी यहीं है।

परिवारों, जन-समुदायों और राष्ट्रों की सारी आर्थिक प्रगति का राज-मार्ग बचत के सिद्धांत से होकर ही जाता है। आर्थिक प्रगति के लिए पहले से बचत किये बिना उस दिशा में मनुष्य कोई कदम उठा नहीं सका है।

आदि मानव अपनी तात्कालिक आवश्यकता से कुछ अधिक भोजन यदि अपनी कन्दरा में एकत्रित न कर लेता तो वह कभी प्रगति कर ही नहीं सकता था। लेकिन जब उसके पास कम-से-कम एक ही दिन का भोजन जमा हो गया तभी वह उस दिन का उपयोग अपक्षेपी^१ बनाने में कर सका, जिससे कम श्रम में अधिक वन्य पशुओं का आखेट कर सके, या वह उस दिन का उपयोग जंगली बीजों को बोने में कर सका जिससे अनाज की फसल प्राप्त कर सके।

संगृहीत भोजन बचत का पहला ढग था।

कन्दरा में संगृहीत भोजन रहने पर आदि मानव पत्थर के अनगढ़ औजार बनाने के लिए अथवा अपने और अपनी जाति के दूसरे लोगों के लिए आश्रय स्थान बनाने को समय निकाल सका।

अब बचत ने पत्थर के औजारों, आश्रय स्थलों और भोजन का रूप ले लिया।

आगे चलकर धातु के औजारों के रूप में बचत की जाने लगी, या हो सकता है कि धातु के ही रूप में, जिससे बहुत-सी चीजे बनाई जा सकती थी, बचत का जाने लगे ही।

ये बचतें सही अर्थों में धन की, जीवन को टिकाये रखने और उसकी रक्षा करने वाली वस्तुओं की बचतें होती थी। इन बचतों का अर्थ होता था तात्कालिक आवश्यकताओं से मुक्ति। इनका अर्थ होता था नये काम करने की, आगे बढ़ने और प्रगति की स्वतन्त्रता।

१. पात्राण युगीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर फेंकने का पहला यन्त्र, जो बहुत ही भद्दा और आदिम ढग का था।

बचत के बिना मनुष्य या तो उन लोगों का दास है जिनके पास बचत है या फिर वह दास है जीवन को टिकाये रखने के लिए भोजन उपलब्ध करने की अपनी ही मौलिक आवश्यकता का।

स्वतन्त्र केवल वे ही लोग ही सकते हैं जिनके पास बचत है।

और इस प्रकार बचतों पर अधिकार और नियन्त्रण स्वतन्त्रता का प्रवेश-द्वार है, ठोक जिस प्रकार बचत आर्थिक प्रगति का प्रवेश द्वार है।

सभी युगों और सभी समाजों में लोग कुछ-न-कुछ बचत करते ही आये हैं। सभी युगों और सभी समाजों में जो तेज-तर्रार और चतुर लोग होते हैं वे शेष सब की बचतों पर यदि नहीं तो उन बचतों के सार्थक नियन्त्रण पर तो अपना अधिकार अवश्य स्थापित कर लिया करते हैं।

निरकुश सत्ताधिकारी राजाओं, सम्राटों या अधिनायकों द्वारा शासित समाजों में शासकों को निरकुश सत्ता जनता की बचतों पर उनके अधिकार और मन का भोजन पर उन बचतों के अपहरण के रूप में अभिव्यक्त होती रही है।

हमारे युग में भी ठोक यही सिद्धान्त लागू होता है। केवल ढग बदल गए हैं। हम मुख्यतः मुद्रा की शकल में बचत करते हैं। इस तरह की कुछ बचतों के उपयोग के बिना परिवारों, समुदायों अथवा राष्ट्रों की हैसियत से हम कोई भी आर्थिक प्रगति नहीं कर सकते। हम अपने परिवार की कल की आवश्यकताओं का प्रबन्ध भी नहीं कर सकते यदि हमारे पास उसके लिए बचत उपलब्ध न हो। यदि हमारे पास अपनी निज को बचत नहीं है तो हम दूसरे लोगों से उनकी बचत उधार लेने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन तब हम सही अर्थों में स्वतन्त्र नहीं रह जाते, क्योंकि इसके लिए हमें मुँह माँगी कोमत, कर्ज के रूप में, देनी पड़ती है और प्रायः अपनी कुछ सम्पत्ति को भी जोखिम में डालना पड़ता है।

पुराने समाजों की ही तरह हमारे अपने समाज में भी अधिकांश लोग समय-समय पर बचन करते हैं। और पुराने समाजों की ही तरह आज भी अधिकांश लोग अपनी बचतों पर अधिकार नहीं रख पाते—जिन्हें अपनी बचतों का अधिकार सौंपते हैं उन्हीं के आश्रित हो जाते हैं।

इसे बदला जा सकता है। ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा लोगों के समूह—चाहे वे बहुत थोड़ी ही बचत करते हों—अपनी बचतों को अपने अधिकार में रख

सकते हैं और अपने लिए स्वतन्त्रता और आर्थिक सुरक्षा का दृढ़ आधार निर्मित कर सकते हैं ।

लेकिन अकेले तो इस काम को कोई कर नहीं सकता । केवल लोगों के समूह पारस्परिक सहायता के लिए सम्मिलित हो कर और उस पारस्परिक सहायता को प्रभावी बनाने के लिए सही ढंग का साधन अपना कर ही इस काम को कर सकते हैं ।

इस तरह के साधनों में हैं साख सघ (क्रेडिट यूनियन्स), सहकारी ढंग की पारस्परिक बोमा कम्पनियाँ, सहकारी कृषि-साख संस्थाएँ, पारस्परिक बचत बैंके, बचत और ऋण सघ, पारस्परिक निवेश निधियाँ और इसी प्रकार की अन्य पारस्परिक सहायता संस्थाएँ ।

बचत के ठीक विपरीत है उधार लेना । यदि लोग साथ मिल कर बचाएँ—अपनी बचतों और अप... साख का निकाय करे—तो वे साथ मिल कर उधार ले सकते हैं और साथ मिल कर निवेश कर सकते हैं । यही है वित्त में प्रयुक्त सहकारी सिद्धान्त ।

जब घर का कमाने वाला मर जाता है, या बच्चा कालेज जाने लगता है, या कपड़ा धोने की मशीन टूट जाती है, या सहसा कोई बीमारी आ धमकती है तो औसत परिवार को इन कठिनाइयों से पार पाने के लिए उधार लेने की जरूरत पड़ जाती है और वह साख का ऐसा स्रोत ढूँढ़ता है जहाँ से उधार मिल सके । साख-सघ का आविर्भाव इसी आवश्यकता में से हुआ है । साख-संघों के पहले भी औसत परिवारों को उधार मिल जाया करता था । लेकिन वैध बैंके तो उन लोगों को रुक्यों पर छोटे कर्ज देती नहीं, जिनके पास कोई जमानत न हो, क्योंकि उनकी साख नहीं होती, जब कि साख की ऐसे ही लोगों को सबसे अधिक आवश्यकता है । तो दूसरा उपाय होता था किसी महाजनी पीढ़ी के आगे हाथ फैलाना, जो कस कर ब्याज लेती थी; या फिर निरूपाय होकर किसी सुदखोर की शरण जाना, जिसका पट्टानी ब्याज आँते ही निकाल लेता था ।

इस स्थिति को सुधारने वाली साख-संघ की परिकल्पना सरलता का प्रत्यक्ष

उदाहरण और सहकारिता का सार ही है। अकेला एक परिवार न तो महाजन पेढी के ऊँचे व्याज की दरों को कम करवा सकता है और न बैंकों को बगैर जमानती छोटे उधारों का प्रावधान करने के ही लिए राजी कर सकता है। लेकिन ऐसे परिवारों का काफी बड़ा समूह—चाहे वे परिवार गरीब ही क्यों न हों—यदि काम करने के लिए सयुक्त हो जाए तो इस समस्या के समाधान का साधन सुलभ कर सकता है। उधार के लिए साख की आवश्यकता को नियमित बचत के आचरण से सयुक्त करके इस काम को किया गया। एकल सदस्यों को जब भी उधार लेने की आवश्यकता हो पूरे समूह द्वारा लोगों की अपनी ही बचतों का उपयोग करके उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यदि एक समूह के काफी लोग किसी साख-संघ में पाँच डालर वाले हिस्से खरीद ले तो जब भी किसी को कर्ज लेने की आवश्यकता पड़े वह अपने ही समूह से उचित दरों पर उधार ले सकता है, अपने ही समूह को कर्ज चुका सकता है और उपार्जन का अपना अंश भी प्राप्त कर सकता है।

साख-संघ की सदस्यता समान हित वाले लोक-समुदाय में ही होती है, जैसे कि एक ही मालिक के यहाँ नौकरी, एक ही गिरजाघर के सदस्य, एक ही श्रमिक संघ, या ऐसा ही कोई दूसरा संगठन या अडोस-पडोस में रहने वाले लोग आदि। संघ अथवा राज्य के अधिकारी समय-समय पर सभी साख-संघों के काम काज की जाँच-पड़ताल करते रहते हैं, खास तौर पर यह देखा जाता है कि धन में कुल कितनी पूँजी लगी हुई है और वह जमानतों से बढ़ तो नहीं रही है—साख-संघों के कारबार की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए पूँजी निवेशों को, सरकारी हस्तक्षेप से, जमानतों की सीमा में बाँधे रखना बहुत जरूरी है।

१९२१ में सयुक्त राज्य अमरीका में केवल १९९ साख-संघ थे। १९६० तक इनकी संख्या कोई बीस हजार हो गई, इनके सदस्यों की संख्या १ करोड़ १० लाख से भी ज्यादा और कुल आस्तियाँ ५ अरब डालर के लगभग। इस देश में प्रति वर्ष एक हजार से भी अधिक नये साख-संघ बनाये जाते हैं। सयुक्त राज्य में कुल अंशों उधार (वह उधार जो किस्तों में लौटाये जाते हैं) का ८ प्रतिशत साख-संघों द्वारा दिया जाता है।

सहकारी संस्थाओं की ही तरह साख-संघों का जन्म सूत्र भी पुरातन युगों

में कहीं दबा पड़ा है, ये सस्थाएँ उतनी ही पुरानी हैं जितनी लोगों में पारस्परिक सहायता। और वूँकि पारस्परिक सहायता मानवी सभ्यता का मूलाधार है इसलिए साख-सस्थाएँ अवश्य ही बहुत-बहुत पुरातन होनी चाहिए।

साख-सघों से मिलती जुलती सस्थाएँ भारत में और दूसरे देशों में भी पिछले कई शताब्दियों से चली आ रही हैं। लेकिन आधुनिक ढंग के साख-सघों का जन्म स्थान जर्मनी है। १८वीं शताब्दी के मध्यकाल में प्रायः एक ही साथ हरमन शुल्ज-डेलित्ख नगर में और फ्रेडरिक राईफी सेन देहात में दरिद्रता, ऋण और व्याज को जित जबर्दस्त दरों के मारे ऋण चुकाये नहीं चुकता, उन युगों पुरानी समस्या के बारे में कुछ करने की सोच रहे थे। राईफी सेन फ्लेक्सकेन्ड नामक छोटे से जर्मन कस्बे के मेयर थे। लोगों की दुरवस्था के बारे में सोचते-सोचते जब वे लगभग निराश हो गये तो सहसा एक विचार उनके मस्तिष्क में कौंध गया, जो हमारे युग का सबसे ओजस्वी विचार है। वह विचार था सहकारी उधार पद्धति का। उन्होंने सोचा कि ऋण ग्रस्त किसानों में से अकेला एक तो वर्तमान दरों से अधिक सुविधाजनक शर्तों पर उधार पा नहीं सकता, लेकिन यदि किसानों का एक समूह आपसी ऋण चुकाने की असीमित देयता के लिए सम्मिलित रूप से वचन बद्ध हो जाए तो कुछ किया जा सकता है। उन्होंने इस दिशा में प्रयत्न किये। उन्होंने लोगों को समझाया। अन्त में उन्होंने एक मध बनाया, जिसमें अधिकतर किसान थे और जो सम्मिलित रूप से अर्थात् सहकारिता के आधार पर वचनबद्ध होने और उधार के लिए अपनी-अपनी साख का निकाय करने के लिए तैयार थे। इसके बाद राईफी सेन ने छोटी-सी निधि एकत्रित की, जो उस पहले साख-सघ का बीजाकुर बनी। वह प्रयोग काफी सफल रहा। उसके द्वारा व्याज की उचित दरों पर उधार दिया गया, पुराने कर्ज बेबाक किये गए, और उस समय पर उधार चुकाया गया। आज हजारों राईफीसेन समितियाँ देहाती बैंकों, एंव बचत तथा उधार सभाओं के रूप में जर्मन-भाषी ग्रामीणों की सेवाएँ कर रही हैं।

शुल्ज-डेलित्ख ने ठीक इसी तरह का जो काम जर्मन नगरों के श्रमिकों के लिए किया उसका सम्मान जर्मन फेडरल रिपब्लिक ने १९५८ में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट निकाल कर किया।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य काल के बाद के वर्षों में जर्मनी के आदर्श पर ही इटली में भी काम हुआ। वहाँ कैथोलिक चर्च ने इसका समर्थन किया। आज इन चर्च के प्रमुख सामाजिक उद्देश्यों में से एक है दुनिया के सभी देशों में साख-सर्घों को बढ़ावा देना।

कई वर्षों तक असीमित देयता की प्रथा का पालन किया गया। इटली के कई भागों में यह प्रथा आज भी है। लेकिन अनुभव से इसकी अनावश्यकता सिद्ध होती गई और क्रमशः इसका परित्याग किया जाता रहा। इसका स्थान नाथो सदस्य के अनुमोदन में ले लिया। इस आन्दोलन के इतालवी प्रवर्तक लुजाती ने इसे 'ईमानदारी का पूँजीकरण,' कहा है।

जैना कि हम आगे चल कर देखेंगे, संयुक्त राज्य के साख-सर्घों पर भारत का साख समितियों का अमिन ऋण है। लेकिन अमरीकी साख-सर्घों का जो रूप हमें अजिद दिखाई देना है वह हमारे यहाँ कनाडा होता हुआ यूरोप से ही आया है—जर्मनी और इटली के आरम्भिक प्रयत्नों की प्रति छाया के रूप में। क्यूबाई पत्रकार अलफोंस डेस जार्डिन्स कनाडा के साख-सर्घों के पिता और महान नेता थे। १९०९ में न्यू हैम्पशायर के मंचेस्टर नगर के सेंट मेरी नामक मुहल्ले में संयुक्त राज्य अमरीका का पहला साख-सर्घ भी उन्हीं ने स्थापित किया था।

अमरीका का साख-सर्घ सम्बन्धी पहला विधान मेनाचुसेट्स में राज्य के ग्रैक-ग्रानार के आयुक्त पीर जय की जॉच-पडताल के बाद पारित हुआ था। इस जॉच-पडताल से न केवल यही बात सामने आई कि नूदखोरो से लड़ने के लिए एक सशस्त्र को आवश्यकता है बल्कि यह भी पता चल गया कि वह उत्कृष्ट आयुध कौन-सा है। डेस जार्डिन्स इस पडताल में अभि साक्ष्य के लिए कनाडा से आये थे।

बीस्टन के करोडपति व्यापारी एडवर्ड ए० फिलेन ने भी गवाही दी थी। उन्होंने बताया कि अपनी भारत यात्रा में मैं डबल्यू० आर० गौरले से मिला था जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के गाँवों में साख समितियाँ बनाने के लिए सेवा-नियुक्त किया था। फिलेन ने गौरले के साथ गाँवों का दौरा भी किया और भारत की अत्यधिक गरीब ग्रामीण जनता की ये समितियाँ जो ठोस सेवा कर रही थी उससे और इस कार्य के पूरे विचार से वे बहुत ही अधिक प्रभावित

हुए थे। उन्होंने ये सब बातें मेसाचुसेट्स के विधायकों को बताई और अपने अत्यधिक उत्साह से सभी को अभिप्रेरित कर दिया। साख-संघों के कानून को पारित कराने में फिलेन के उत्साह का भी कुछ कम हाथ नहीं था।

उस दिन से लेकर १९३७ में अपनी मृत्यु तक फिलेन की सारी सम्पत्ति, लगन और उत्साह सम्युक्त राज्य में साख संघों की उन्नति और विकास में लगे रहे। हमारे यहाँ इस कार्य की वृद्धि का अधिकांश श्रेय उन्हीं के प्रयत्नों को है। १९२१ में उन्होंने पूरे जी-जान से यह कार्य शुरू किया। उसी वर्ष उन्होंने राय एफ० वरगेन ग्रेन को सहायता से साख संघ राष्ट्रीय विस्तार कार्यालय (क्रेडिट यूनियन नेशनल एक्सटेन्शन ब्यूरो) की स्थापना की और वरगेन ग्रेन को उसका मंत्री नियुक्त किया। इसी बीच साख-संघों को कार्यान्वित करनेवाले तीन राज्य कानून और पारित हो गए और १९९ साख-संघों की स्थापना हो गई।

फिलेन के ब्यूरो का उद्देश्य था साख-संघों के कार्यान्वितपन के लिए आवश्यक कानून बनवाना, कानूनों के रूप में साख-संघों की स्थापना करना; साख-संघों की संख्या में इतना वृद्धि करना कि उनकी प्रत्येक राज्य में आत्म निर्भर प्रादेशिक समस्याएँ और ऐसी सब प्रादेशिक समस्याओं का एक अखिल देशीय संघ स्थापित किया जा सके। १९३४ में जब क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन का विधान बनकर उस पर दस्तखत हो गए तो ये चारों उद्देश्य भी पूरे हुए।

राय एफ० वरगेन ग्रेन १९३४ में क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन के स्थापना काल से १९४५ तक इसके प्रबन्ध निर्देशक रहे। १९४५ में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। १९४६ में उन्हें सेवायुक्त प्रबन्ध निर्देशक का सम्मान प्रदान किया गया। उनके बाद साख-संघों के प्रवर्तक नेता और संगठन कर्ता टामस डब्ल्यू० डोहग १९५५ तक इस पद पर काम करते रहे, फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वे अलग हो गए। जब तक १९५७ में प्रबन्ध-निर्देशक के पद पर एच० बान्स आस्टिन का चुनाव नहीं हो गया तब तक की अन्तरिम अवधि में टेक्सास के साख-संघों के नेता और क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष एच० बी० येट्स् इस पद पर कार्य करते रहे।

१९३४ से ही साख-संघ के मूल उद्देश्यों की प्रगति की दिशा में भी बराबर कार्य होता रहा : कांग्रेस और प्रायः सभी राज्य के विधान मण्डलों ने और कनाडा

की प्रादेशिक सरकारों ने साख-संघों के उपयुक्त और समर्थकारी कानून बनाये । राज्य की सभाएँ और राष्ट्रीय संघ (National Association) साख संघों के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने और उनकी कार्य विधियों को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाने में सतत सहायता करते हैं । कनाडा और वाशिंगटन के कार्यालय राष्ट्रीय मध के मैडीसन (विसकोन्सिन) स्थित प्रधान कार्यालय की हर तरह से सहायता करते हैं । १९३४ में संयुक्त राज्य में साख संघों की संख्या १०,४५६ थी, जो फेडरल क्रेडिट यूनियन्स के कार्यालय के प्रयत्नों के फल-स्वरूप दूसरे महायुद्ध के आरम्भ काल तक दुगुनी हो गई । जब दूसरा महायुद्ध आरम्भ हुआ तो सदस्यों की संख्या ३५,३२,००६ तक पहुँच चुकी थी और समग्र पूँजी ३२,२५,१५,००० डालर थी ।

लेकिन सही अर्थों में व्यापक विस्तार तो दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद ही हुआ । १९५८ तक सारे विश्व में साख संघों की संख्या २५,०००, उनके सदस्यों की संख्या लगभग १,३०,००,००० और कुल आस्तियाँ ४,७०,००,००,००० डालर तक पहुँच चुकी थी ।

इनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा में थे । १९५९ की समाप्ति तक केवल अमरीका में ही साख-संघों की संख्या १९,८००. उनके सदस्यों की संख्या १,१३,००,००० और आस्तियाँ ४,३८,२०,००,००० डालर (मुख्यतः सदस्यों की हिस्सा पूँजी) एवं सदस्यों को दिया हुआ कर्ज ३,७०,००,००,००० डालर था । लेकिन साख-संघों में सारे ही पश्चिमी गोलार्ध और विश्व के दूसरे भी अनेक देशों के लोगों की अभिरुचि बराबर बढ़ती जा रही थी । साख संघों से लाभान्वित होने की इस विश्व व्यापी प्रवृत्ति की संवर्द्धना और सन्तुष्टि के लिए १९५४ में क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन ने अपना एक नया विभाग विश्व विस्तार विभाग (World Extension Division) के नाम से खोला ।

साख-संघ का सरलतम सिद्धान्त यह है कि एक समान सम्बन्धों और एक समान हितों वाले लोगों का समूह अपनी बचतों और उधार के लिए अपनी साख को अपने ही नियन्त्रण में रखता और इन दोनों का समूह के पारस्परिक लाभ के लिए उपयोग करता है ।

जिते साख-सघो का 'मूल मन्त्र' कहा जा सके वह कुछ इस प्रकार होगा। किसी स्त्री अथवा पुरुष का आदर-मान इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास क्या है, बल्कि इसलिए किया जाना चाहिए कि वह क्या है। इसीलिए साख-सघ के सदस्यों को उधार देते समय यह कभी नहीं देखना चाहिए कि उनके पास जमानत कितनी है, क्योंकि तब तो सच में उन्हें उधार लेने की जरूरत ही नहीं है बल्कि देखना यही चाहिए कि उन्हें सचमुच उधार लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ अपना अच्छा भला नाम है और उनके साथी सदस्य उस अच्छे-भले नाम का आदर करते हैं। इस सिद्धान्त और इस मूल-मन्त्र ने अनेक स्थानों में अनेक बार चमत्कारिक काम किया है। और ये आगे अभी और भी चमत्कार करेंगे।

नौवा स्कोटिया में मन्दी के घनघोर दिनों में सन्त फ्रान्सिस जेवियर विश्व-विद्यालय के कुछ स्कॉटिश कैथोलिक पादरियों ने मछुओं को यह सुझाया कि पहले अपना साख-सघ बनाकर उसके बाद वे अपनी निजी विक्रय सहकारी सस्था, 'काव्स्टर कारखाने' और अपनी मछलियों के उचित मूल्यार्जन के अन्य साधन कैसे सुलभ कर सकते हैं। नया और सरल तरीका यह था कि मछुओं ने अपनी मछलियाँ विचौलियों के हाथ रखाने वाली कोमर्तों के बदले वोस्टन और न्यूयार्क के बाजारों में उचित मूल्यों पर स्वयं सीधे बेचना शुरू कर दिया। उनके साख पत्रों ने उनके लिए अपने ही भंडार और अपने ही पण्योपयोगी सयत्रों की सुविधा कर दी जहाँ वे अपनी मछलियों को उचित कीमत के आने तक रोके रख सकते थे।

भारत में आज सहकारी साख समितियों ने किसानों को मुदखोर महाजनों के चंगुल से अपने-आप को छुड़ाने और उसके कर्ज की नाग फास से अपने गले को मुक्त करने की सामर्थ्य प्रदान की है। जिस देश के लोग सदियों से कर्ज के भँगे भीषण बोझ तले पिसते रहे हों और जहाँ बाप के बाप का कर्ज बेटे का बेटा भी न चुका सकता हो वहाँ के लिए यह कितनी बड़ी बात है।

फिजी द्वीप के निवासी यह सोखते जा रहे हैं कि मुद्रा क्या है, इसका मतलब क्या होता है और यह किस काम आती है। साख-समितियों के निर्माण के लिए उनके यहाँ काफ़ी बड़ा आन्दोलन है। वे मिल-जुलकर अपना-अपना पैसा बचा रहे हैं। अपने और अपने पड़ोसियों के रुपए के निकाय से कर्ज के लिए आवेदन

करने का अर्थ वे सीख रहे हैं। यथोचित ब्याज पर ऐसे कर्जों को चुकाना और अपने ही चुकाये ब्याज से स्वयं अपनी निधि के निकाय का निर्माण करना भी वे सीख रहे हैं। प्रायः आदिम अवस्था से सभ्य जीवन की ओर अपनी प्रगति की प्रारम्भिक स्थितियों में वे सीख रहे हैं कि लोगों के एक समुदाय के बीच पारस्परिक सहायता उस समुदाय को अपनी वचतों पर अधिकार बनाये रखने की ही नहीं अपने आर्थिक कल्याण की भी क्षमता प्रदान करती है। इन द्वाप वासियों को, और दूसरे भी बहुत-से लोगों को इस काम की प्रेरणा दी है और नेतृत्व भी कर रहे हैं। बीसवीं सदी के आधुनिक ढंग के रोमन कैथोलिक ईसाई मिशनरी जमैका से ठेठ मदरास तक ऐसे अनेक पादरी मिल जाएंगे जो सूदखोरी के खिलाफ और अपने पड़ोसी भाई का संरक्षक बनने के बाइबिल के उपदेशों को अक्षरशः लोगों के आचरण में उतार रहे हैं।

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि साख-सघों ने केवल अभाव ग्रस्तों और विपत्तिग्रस्तों को ही स्वावलम्बन और सामूहिक सहायता का साधन उपलब्ध किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा साख-सघ डेट्रोइट के शिक्षकों का है। इस साख सघ ने २ करोड़ डालर, जो इसकी कुल आस्तियों का बहुत ही छोटा-सा भाग है, अपने सदस्यों को सहकारिता के आधार पर रिहायशी कमरों वाली कई सुन्दर इमारतें बनाने के लिए कर्ज दिया है, इमारतें बन जाने पर ये सदस्य स्वयं ही उनमें रहेंगे।

मिचिगन के साख-सघ के नेताओं ने एक गृहनिर्माण-आर-ऋण सघ की स्थापना की है और उसमें राज्य-अधिकृत कुछ साख-सघों ने भी अपनी अतिरिक्त पूँजी का कुछ अंश लगाया है। इस गृह निर्माण और ऋण सघ का उद्देश्य निम्नवित्त परिवारों के लिए ऐसे मकानों के निर्माण में वित्तीय प्रवन्ध करना है जिनका मूल्य इन परिवारों की सामर्थ्य से अधिक न हो।

न्यूयार्क सिटी के साख-सघों ने अपने सदस्यों के लिए नगर के मध्य भाग में महद्वन में एक सहकारी रिहायशी कमरों वाले मकान की निर्माण योजना ही नहीं प्रायोजित की, उसकी पहली तकद किस्त चुकाने के लिए उन्हें कर्ज भी दिया। इन प्रकार सामान्य आय वाले परिवारों को विन्ड के सबसे बड़े नगर के मध्य भाग में अपने निर्जी मकान रहने के लिए मिल सके। लेकिन यह इतना

बड़ा काम केवल इसीलिए सम्भव हो सका कि पहले लोगों ने साख-सघ के पाँच डालर के हिस्से खरीदे और उसके बाद अपनी बचतों का स्वयं नियन्त्रण करने को कला सीखी।

न्यूयार्क के इस चमत्कार के प्रणेता का नाम है मिस्टर विलियम रीड, जिन्हें १९५९ में न्यूयार्क सिटी हार्डिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

कोलो रेडो के एक मुहल्ले के कैथोलिक साख सघ को जब यह पता चला कि मेक्सिकोई वशानुक्रम के उनके ६४ सदस्य परिवारों को किराये के झोंपड़ों से बंदखल किया हो जाने वाला है तो उसने उस जमीन के अधिकार-त्याग का पट्टा (दाखिल खारिज) प्राप्त कर लिया और तब स्वयं कर्ज देकर उन परिवारों को उसी जमीन के अलग-अलग टुकड़े खरीदवा दिये। उसके बाद उसी जमीन पर अपने छोटे-छोटे आरामदेह मकान बनाने के लिए उन्हें कर्ज भी दे दिया। इस प्रकार जिस जमीन पर पहले सताये हुए किरायेदार अस्त-व्यस्त दशा में पड़े हुए थे वही मकान मालिकों को एक अच्छी-खासी बस्ती बन गई।

सोटल में जब परिवारों को पुगेट साउण्ड की सामूहिक स्वास्थ्य योजना (Group Health Cooperative of Puget Sound) में सम्मिलित होने का आवश्यकता पड़ती है तो सामूहिक स्वास्थ्य साख सघ (Group Health Credit Union) उन्हें सदस्यता शुल्क के सौ डालर चुकाने के लिए कर्ज देता है। इस सहकारी स्वास्थ्य योजना के चार चिकित्सा केन्द्रों और एक अस्पताल से लाभग्राहक साठ हजार लोगों को सभी आवश्यक स्वास्थ्य परिचर्या और सधारण कामों से आधे दाम पर दवाईयें भी मिलती हैं। यहाँ स्वास्थ्य परिचर्या और चिकित्सा सेवा पर प्रति व्यक्ति जितना खर्च आता है वह औसत व्यक्ति द्वारा आकस्मिक, आपाती और कभी-कभी जरूरत पड़ने वाली महँगी चिकित्सा से कहीं कम होता है।

इंडियाना, कनसास और दूसरे बहुत से राज्यों के किसानों ने भी अपने कृषि आपूर्ति सहकारियों के सदस्यों में साख-सघों के संगठन की आवश्यकता को अनुभव किया। इसका कारण यह था कि किसानों के पास साल के कुछ खास मौकों पर जरूरत पड़ने वाले महँगे कृषि यन्त्रों या प्रचुर मात्रा में लिये

जाने वाले कृषि-सम्भरणों के लिए काफी नकद पैसा नहीं रहता। सहकारियों द्वारा लेन-देन का काम शुरू करना काफी खर्चीला पड़ जाता है और फिर उसमें सदस्यता-सम्बन्धी कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। लेकिन साख-संघ तो कारबार ही हमारे के लेन-देन का करते हैं और इस तरह को खरोदियाँ के लिए तुरत पैसा दे सकते हैं। फारम-आपूर्ति सहकारियों वाला हिसाब-किताब की बारीकियों और सदस्यता-सम्बन्धी झमेला भी यहाँ नहीं है। सहकारी में लेन-देन का नया खाता खोलने की समस्या को सहकारी काम-काज को एक नये क्षेत्र में निजी लेन-देन में विकसित करके आसानी से हल कर लिया गया।

जो कुछ थोड़े-से कार्य ऊपर बताये जा चुके हैं वैसे चमत्कारपूर्ण कार्यों को पूरा कर दिखाने का बहुत से लोगों ने साख-संघों को काफी उपयोगी साधन पाया है। ऐसे लोग साख-संघों को काफी महत्त्व की सहकारी संस्थाएँ मानते हैं और विश्वास करते हैं कि वे सामाजिक और आर्थिक उन्नति की तीव्र आवश्यकता को पूरा करने में बड़ी हद तक सहायक हो सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका में अधिकांश साख-संघ प्रायः मालिक कम्पनियों द्वारा उदारता से प्रायोजित औद्योगिक और वाणिज्य संस्थाओं के कर्मचारियों के संगठन हैं। सामान्यतः साख-संघों के सदस्य अपनी इन संस्थाओं की वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने वाली, कर्ज चुकाने में सदस्यों की आर्थिक सहायता करने वाली और जरूरत पड़ने पर छोटी रकम उधार देने वाली संस्थाएँ हो समझते हैं—इससे अधिक कुछ भी नहीं। इनमें और सहकारिता के दूसरे रूपों में जरा भी सम्बन्ध नहीं समझा जाता। इन कर्मचारी साख-संघों के बहुत से नेता तो इनके काम-काज को छोटी रकम उधार देने आदि की मामूली सुविधाओं से जरा-सा भी आगे ले जाने के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि ऐसे प्रयत्नों का बड़ी सक्रियता से विरोध करते हैं। फिर मालिक कम्पनियों द्वारा उदारता से प्रायोजित होने के कारण इनके सदस्य प्रायः स्वामीभक्त होते हैं और सामाजिक तथा आर्थिक मामलों एवं मतान्तरों में अधिकतर मालिकों का ही पक्ष ग्रहण करते पाये जाते हैं।

साख-संघ के कार्य क्षेत्र के बारे में बड़े गहरे मतभेद हैं। एक ओर तो ऐसे साख-संघ और उनके सदस्य हैं जो अपने काम के अनुभव को दूरगामी महत्त्व का समझते हैं। वे साख-संघ को लोगों का सर्वाधिक मौलिक ढंग का सहकारी

अथवा पारस्परिक उद्यम मानते हैं। उनकी ऐसी मान्यता कि साख-सघ और, उसकी आर्थिक शक्ति को आधार बना कर दूसरे-ऐसे काम भी अवश्य आरम्भ किये जाने चाहिए जो न केवल सदस्यों अपितु अपने क्षेत्र के पूरे जन-समुदाय को लाभ पहुँचाएँ। साख-संघों को सहकारी लीग आदि व्यापक केन्द्रीय संगठनों से सम्बद्ध किये जाने का वे बड़े उत्साह से समर्थन करते हैं, और अपने अनुभव तथा साधनों से दूसरे प्रकार की सहकारी संस्थाओं के उन्नयन और विकास में सहायता पहुँचाने को सदैव तत्पर रहते हैं।

दूसरी ओर कम्पनी कर्मचारियों के साख सघ हैं। इनका दृष्टिकोण बड़ा ही सकुचित और अनुदार है। ये चाहते हैं कि साख सघ केवल साख संघों का ही और जैसी कि उनकी अपनी समझ है सिर्फ लेन-देन का ही काम करे—उससे अधिक कुछ भी न करे। वे यह कदापि नहीं चाहते कि साख-सघ बैंकों और अन्य महाजनों की संस्थाओं के काम से होड़ करे और न यही चाहते हैं कि ये संस्थाएँ साख सघ के कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे। और इनका यह विश्वास भी है कि यदि साख-संघों का आन्दोलन उनकी नीति पर चले तो बड़े-बड़े आर्थिक हितों की ओर से साख-संघों पर किये जाने वाले प्रहार कभी होंगे ही नहीं।

लेकिन उनकी यह धारणा भ्रान्त है। साख संघों पर जो प्रहार—और ये सर्वथा अनुचित हैं—किये जाते हैं उनका सिर्फ एक ही कारण है।

और वह कारण है साख-संघों का बड़ी तेजी से बढ़ते जाना।

साख संघों के आन्दोलन में जितने भी गुट हैं वे सभी और समस्त विचार-शील अमरीकी भी इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि हमारी अमरीकी अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में साख संघों का तेजी से बढ़ते जाना सभी प्रकार से वाछनीय है।

१९५० में उपभोक्ता ऋण का परिमाण १८,००,००,००,००० डालर था। १९५९ के आरम्भ में वह ४७,९०,००,००,००० डालर हुआ और उसी वर्ष के अन्त तक ५२,००,००,००,००० डालर हो गया। समस्त उपभोक्ता आय का १५ प्रतिशत अशाश ऋण की अदायगी में अधिवद्ध था; और यों निम्न वित्त परिवारों की आय का ३० से ४० प्रतिशत 'बन्धक' हो गया था। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि यदि उपभोक्ता ऋण में वृद्धि न होती चली

गई तो स्वचलित उद्योग माल-असबाब का जो ढेर लगाने जा रहे थे उसकी खपत का प्रभावी बाजार नहीं रह जाएगा।

ऋण का फैलाव किसी जगह पर पहुँच कर खतरा बन जाता है। वह खतरे का बिन्दु ठीक किस जगह पर है यह कुछ तो व्याज की दर पर और कुछ अर्थ-व्यवस्था की कुल मिलाकर जो स्थिति होती है उस पर निर्भर करता है। व्याज की दरें जितनी ही तेज होंगी हम खतरे के बिन्दु के निकट ऐसी जगह पहुँच जाएँगे जहाँ लोगों के लिए एक साथ दोनों काम—अपना कर्ज चुकाना और माल तथा सेवाओं की सामान्य माँग का निर्वाह करते जाना असम्भव हो जाएगा। और ऋण का परिमाण जितना ही अधिक होगा आर्थिक क्रियाशीलता में जरा-सी भी मन्दी, बेकारी में थोड़ी-सी भी वृद्धि और इन दोनों के परिणाम स्वरूप परिवारों की कर्ज चुकाने की क्षमता में जरा-सी भी कमी बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेगी।

आज के उपभोक्ता ऋण का इतना अधिक परिमाण बैंकों या अन्य मद्राजनी संस्थाओं द्वारा उधार की निर्मित का ही कुपरिणाम है। जनता को उधार के जितने अधिक 'अवसर' या 'मुविधाएँ' दी जाती हैं वे सभी व्याज की भारी-भरकम दरों या 'व्यवस्था' खर्चों के अत्यधिक बोझ से लदी हुई होती हैं। १९६० में 'वाल स्ट्रीट जर्नल' ने बिल्कुल ठीक ही बताया था कि मोटर विक्रेताओं ने नई मोटरों की बिक्री में जो औसत ७० डालर मुनाफा कमाया उसमें मोटर की असली बिक्री का मुनाफा तो सिर्फ २७.०० डालर है और शेष ४३.०० डालर व्यवस्था और वित्तीय खर्चों के नाम पर वसूला गया है। उसी समाचार पत्र ने आगे यह भी बताया कि फरनीचर भण्डारों के कुल मुनाफों का ५७ प्रतिशत उधार माल देने के खर्चों की अर्थात् 'उधारी की' कमाई है।

यदि हमारी अर्थ व्यवस्था में उपभोक्ता ऋण का बहुत बड़े परिमाण में रहना आवश्यक ही हो तो उसके लिए दो बातें अवश्य की जानी चाहिए : एक तो यह ऋण फूलने-फैलाने वाला अर्थात् स्फीतिकारी ऋण न हो और दूसरे व्याज की दरें बिल्कुल उचित हों। साख्र संघ ठीक यही काम करते हैं और इसीलिए वे हमारी आज की अर्थ व्यवस्था में इतने महत्त्व के सृजनशील घटक हैं। व्यापारी बैंकों या अधिकांश महाजनी संस्थाओं की तरह साख्र-संघ उधार

देने के लिए न तो नये रुपये का निर्माण करते हैं और न प्रत्यय जमाओं का ही। वे तो सिर्फ उस रुपये को उधार देते हैं जिसकी उनके सदस्य पहले से बचत कर के रख लेते हैं। और अदत्त अवशेष पर साख सघों द्वारा लिया जाने वाला एक प्रतिशत मासिक ब्याज उन दरों से निश्चय ही बहुत कम है जो अकसर उपभोक्ता-ऋणदाताओं से वसूला जाता है।

इसके अतिरिक्त साख सघ आर्थिक परिस्थितियों की विषमता और 'चलन की तगी' के कारण भी कभी अपने ब्याज की दरों में बढोतरी नहीं करते। १९५९ में जब सारे पूँजी बाजार में ब्याज की दरें आसमान छू रही थी तब अकेले साख-सघ ही थे जिन्होंने अपने ब्याज की दरों में कोई वृद्धि नहीं की। क्यों नहीं की ?

केवल इसलिए कि उन्हें जरूरत नहीं थी और वे चाहते भी नहीं थे। साख-सघ **ब्याज देने वाले** लोगों को सस्थाएँ हैं **ब्याज वसूलने वालों** की नहीं। उनका उद्देश्य सदस्यों की पारस्परिक सहायता है, ब्याज वसूल कर मुनाफा कमाना नहीं। साख सघों की सारी कमाई उनके सदस्यों की सम्पत्ति है जो उन्हें उनके हिस्सों के लाभांश के रूप में अथवा उनके द्वारा चुकाये ब्याज के एक अंश की संरक्षण-धनवापसी के रूप में वापिस कर दी जाती है।

सारा अन्तर पारस्परिक सहायता के उद्देश्य के ही कारण है।

१९५९ में मिचिगन राज्य के साख सघों ने अपने उधार लेने वालों को ३०,००,००० डालर संरक्षण-धन वापसी की। और सारे देश के १९,००० साख-सघों में से २,७३७ ने भी ऐसी ही संरक्षण-धनवापसियों की। ऐसा करने वालों को यह सख्या १९५७ से दुगुनी है।

साख-सघ किसी भी समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी और निर्माणकारी गतिविधि है। लेकिन इनके पूरी तरह क्रियाशील और प्रभावशाली होने के मार्ग में कुछ स्वाभाविक और अनिवार्य बाधाएँ भी हैं। एक तो यह स्वभाव सिद्ध बात है कि लोग अपनी सारी या अधिकांश बचतें कभी भी साख-सघों में जमा नहीं कराएँगे। दूसरे आधुनिक उद्योगों को, जिनमें सहकारी उद्योग भी सम्मिलित हैं, आज जिस बड़े पैमाने के वित्तीय प्रबन्ध की आवश्यकता है, वह साख सघों के बूते की बात नहीं।

संयुक्त राज्य अमरीका के समस्त साख-सघों की कुल आस्तियाँ न्यूयार्क या कैलीफोर्निया की किसी भी एक विशालतम बैंक की कुल आस्तियों का आधा भी मुश्किल से हो पाएँगी। और जहाँ तक निजी बचतों का प्रश्न है उनका तो ३ प्रतिशत से भी कम साख सघों में जमा होगा। हाँ, बचतों का यह अनुपात स्थिर नहीं है, निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वित्तीय क्षेत्र में जनता अकेला साख सघों का ही आयुध चलाना नहीं जानती, उसने कुछ और भी सीख रखा है।

कृषि में लम्बी मन्दी का एक कारण यह भी था कि किसानों को ब्याज की बहुत ऊँची दरें, अनचाहे भी, चुकानी पड़ती थी। वह मन्दी १९२० में, फेडरल रिजर्व सिस्टम द्वारा जान बूझकर की गई अवस्फिती के कारण, शुरू हुई थी और दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने तक बनी रही। १९२० के बाद दो दशब्दी में किसानों को १०, १२, १६ और इससे भी अधिक प्रतिशत ब्याज की दरों पर कर्ज देना आम बात थी। कर्ज बैंक देती थी और वे अपने स्टाकधारियों के लाभ के लिए व्यवसाय कर रही थी इसलिए इतनी ऊँची दरों के समर्थन में उनके पास दलीले भी थीं।

उनकी दलीले यों तो बड़ी सीधी-सादी पर वास्तव में बड़ी भयंकर थी।

संक्षेप में उनका तर्क इस प्रकार था : किसान की हालत जितनी ही गिरी हुई और खेती की आर्थिक हालत जितनी ही बिगड़ी हुई होगी किसानों को रुपया उधार देने में उतनी ही अधिक जोखिम होगी; इसलिए ब्याज की दरें जोखिम के हिसाब से तय की जानी चाहिए।

लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई तो यह थी कि ब्याज की ऊँची दरें उनके सारे उद्देश्य को ही चौपट कर देती थी। क्योंकि ब्याज की दरें जितनी ही ऊँची होगी कर्ज को चुका पाना उतना ही कठिन हो जाएगा और खासकर उस समय तो और भी कठिन जब रुपए का मूल्य गिर रहा हो। अवस्फिती के उन दस वर्षों में किसानों की पैदावार के दाम बुरी तरह गिरते चले गए। यदि किसी किसान ने जब गेहूँ के भाव एक डालर प्रति बुशल थे, उस समय एक हजार डालर कर्ज लिये और बाद में गेहूँ का दाम प्रति बुशल पचास सेंट गिर गया तो

उसपर कर्ज का बोझ एकदम दुगुना हो गया। अब उस किसान को दो हजार बुशल गेहूँ पैदा करके हजार डालर का कर्ज चुकाना होगा, जो रकम उधार लेते समय केवल हजार बुशल के बराबर थी।

१९३० के बाद की दशाब्दी में प्रायः ऐसा होता था कि जब ऋणदाता ब्याज न चुका पानेवाले असामी के खेत की कुर्की-निलामी करवाता तो किसान अपनी मगठित काररवाई से उसे विफल कर देते थे। निलामी की जगह पर बहुत बड़ी संख्या में किसान जमा हो जाते और नाम-मात्र की बोली से किसी को भी आगे नहीं बढने दिया जाता था। बिक्री खतम हो जाने पर खेत उसके असली मालिक को उसी समय फिर नाममात्र के डालरों में बेच दिया जाता था।

इस तरह करते-करते किसानों को एक विचार सूझा। यह ठीक वैसा ही विचार था जिसने ग्रामीण विद्युत सहकारियों, आवास सहकारियों और पारम्परिक सहायता के दूसरे सभी प्रकार के उद्यमों को जन्म दिया था, जिनके बारे में यह पुस्तक है।

विचार यह था कि लाभ के लिए उधार का उपाय कई स्थितियों में चल नहीं पाता। वास्तव में तो यह उलटा चलता था। ब्याज की दरों के जितना ही कम होने की जरूरत होती लाभ के लिए उधार पद्धति से वे और भी ऊँची चढ़ जाती थीं। ऐसे में किसानों को उधार की आवश्यकता के लिए साख संस्थाओं की जरूरत थी। उन्हें जरूरत किसी ऐसे तरीके की थी जिससे कर्ज के और सो भी कम-से-कम दरों पर—सब्त जरूरतमन्द किसान उधार की अपनी आवश्यकता और अपने अच्छे-भले नामों का (साख) निकाय करके ऐसी शर्तों पर कर्ज पा सके कि फिर उसे आसानी से चुकाया भी जा सके।

परिणाम स्वरूप कृषि साख प्रणाली (Farm Credit System) अस्तित्व में आई। इसने न्यू डील (New Deal)^१ के १९३२ में जन्म लेने की प्रतीक्षा भी नहीं की और शुरू कर दी गई, यद्यपि उसके बाद भी कई आवश्यक उदार संशोधन पारित किये गए। कृषि साख प्रणाली के तीनों कार्य सरकारी

१. संयुक्त राज्य का किसान सहायक कानून, जो उन्हें मन्दी और ऊँचे मूल्यों से राहत देने के लिए बनाया गया था।—अनु०।

पूँजी के साधन से ही आरम्भ किये गए। अब तो सरकार की अधिकांश पूँजी लौटा दी गई है और उसका स्थान किसानों की पूँजी ने ले लिया है; लेकिन उस समय भी सरकारी पूँजी ही वह एकमात्र बुनियाद नहीं थी जिस पर इस प्रणाली के तीनों भागों की तीन इमारतें—भूमि बैंक संस्थाएँ, उत्पादन साख संस्थाएँ और सहकारियों की बैंके (Banks for Cooperatives) निर्मित की जा सकी।

मूल तत्त्व था पारस्परिक सहायता का विचार। जिस काम को अकेला एक आदमी अपने लिए नहीं कर सकता उसे लोगों का एक समूह अपनी-अपनी आवश्यकताओं, अपनी-अपनी जोखिमों और उधार के लिए अपनी-अपनी साख का निकाय करके बखूबी कर सकता था। समाज में सभी की—यहाँ तक कि मन्दी की मार से अर्द्ध मृत किसान की भी थोड़ी-बहुत साख तो होती ही है। वह साख बनती है या तो उसकी सम्पत्ति से, या उसकी योग्यता से, या काम और उत्पादन करने की उसकी तत्परता से या अपने वायदों और अपनी जिम्मे-वारियों को पूरा करने की उसकी ईमानदारी और उसके अच्छे-भले नाम से।

लेकिन अकेला कोई भी आदमी—यदि उसकी अपनी बैंक नहीं है तो अपने नाम के चंक् छाप कर उनसे अपने देयकों की अदायगियाँ नहीं कर सकता। इस तरह की वैयक्तिक मुद्राकृत साख को न तो बाजार में कोई मानता है और न वह चलन ही पा सकती है। लेकिन जब लोगों का एक समूह अपनी साख को संगठित करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह ठीक इसी काम को कर सकता है।

उदाहरण के लिए मेसन सिटी (इओवा) की उत्पादन-साख संस्था (Mas-on City Production Credit Association) की १९३४ में जब उन्तीस किसानों ने स्थापना की तो ठीक यही बात हुई। यह सच है कि उनके पास काम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय साख का उनका अपना हिस्सा था। यह भी सच है कि कुछ सरकारी पूँजी भी उन्हें काम चलाने के लिए मिल गई थी। लेकिन इन दोनों में भी अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है यहाँ और देश के दूसरे हिस्सों में भी कुछ किसानों की ऋण की अपनी आवश्यकताओं को संग-ठित करने, उधार पाने के अपने श्रोतों का निकाय करने और आपस में उधार

देने एव सरकारी पूँजी को लौटाने की जोखिमों में सहभागी बनने की तत्परता। पारस्परिक सहायता अथवा सहकारी साख सस्था की, या जैसा कि हम इसके लिए ऊपर कह आये हैं उधार पाने की आवश्यकता के लिए साख सस्था की सफलता के आवश्यक मूल तत्त्व यही हैं।

इस बात को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि इस सस्था का प्रबन्ध कुशलता से न किया जाता तो किसान १,४५,००० डालर की सरकारी पूँजी कभी न लौटा पाते और न २,००,००० डालर की अधिशेष पूँजी ही बना पाते। सस्था के कृषक संचालक मण्डल ने इस काम के लिए कुशल प्रबन्धकों की सेवा प्राप्त करने की समझदारी अवश्य दिखाई।

और यदि उत्पादन-साख संस्था के सदस्यों ने अपने स्वामीत्व को ठीक-ठीक न समझा होता और संस्था की सेवाओं का ठीक-ठीक उपयोग न किया होता तब भी सफलता नहीं मिल पाती। जहाँ तक किसान सदस्यों के उत्पादन-साख सहकारी संस्था के स्वामीत्व को ठीक से समझने की बात है वह तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने इसके हिस्से (स्टॉक) में अपनी लगभग १,७५,००० डालर पूँजी का निवेश कर दिया। बिना समझे भला कौन कही पूँजी लगाता है। फिर स्वामित्व का अर्थ समझने की बात इससे भी सिद्ध हो जाती है कि सस्था के जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में सस्था के किसानों ने सस्था के ही किसानों को ३,००,००,००० डालर उधार दिये और कर्ज का आखरी सेट तक ब्याज सहित चुका दिया गया। लेकिन वह ब्याज स्वयं उन्हीं को लौटा दिया गया। ऋणदाता महाजन को ब्याज दिया जाता है मृताफे के लिए, यहाँ जो ब्याज दिया गया उससे जमा प्रत्यर्थों और बचतों के तथा पहले से जिन लोगों की साख थी, अर्थात् उधार लेने वालों के, जो इस सस्था के स्वामी भी हैं, साधन-स्रोतों के निकाय में वृद्धि हुई।

इस प्रकार अपने ही कर्ज से लोगों के जमा प्रत्यय और उधार पाने की साख निर्मित होती है; किसी भी महाजनी सस्था के सघटन में जब सहकारिता के सिद्धान्त को और पारस्परिक सहायता को लागू किया जाता है तो बिलकुल यही होता है। इसी सिद्धान्त और इसी विचार पर सारी कृषि साख प्रणाली का निर्माण और प्रचलन हुआ है।

आज कृषि साख प्रशासन (Farm Credit Association) के निरीक्षण में सहकारी कृषि साख प्रणाली किसानों और उनकी सहकारी संस्थाओं को सन्तुलित उधार-सेवा प्रदान कर रही है। इस प्रणाली की संस्थाओं से किसान खेत के स्वामीत्व के लिए, फसलों और पशुधन की पैदावार के लिए, फारम उपयोगी वस्तुओं की खरीद के लिए और अपनी पैदावार की विक्री-व्यवस्था के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रणाली की निम्नलिखित विभिन्न सहकारी संस्थाएँ हैं : लगभग १००० सघीय (केन्द्रीय) भूमि बैंक समितियाँ और १२ सघीय भूमि बैंक, जो किसानों के खेतों को बन्धक रख कर लम्बी अवधि का कर्ज देती हैं; ४७९ उत्पादन साख समितियाँ और १२ सघीय मध्यवर्ती साख बैंक (Federal Intermediate Credit Banks) जो खेती के काम-काज के लिए छोटी और मध्यम अवधि के कर्ज देता है; और १३ सहकारी संस्थाओं की बैंकें (Banks for Cooperatives) जिनसे किसानों की विक्रय और क्रय एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी संस्थाएँ लम्बी और छोटी अवधि के कर्जें प्राप्त कर सकती हैं।

इनमें से कोई भी बैंक जमा रुपये से कारबार करने वाली बैंक नहीं है। लेकिन सहकारी कृषि साख प्रणाली के माध्यम से किसान बड़े पूँजी केन्द्रों के निवेश बाजारों से निगमों द्वारा दिये जाने वाले व्याज की दरों पर ही आवश्यक धन राशि प्राप्त कर सकते हैं।

सघीय भूमि बैंकें फारमों के मूल बन्धकों वाले बांड बेचती हैं, जिनके भुगतान का बारहों बैंकों का सम्मिलित दायित्व रहता है। सघीय मध्यवर्ती साख बैंकें और सहकारी संस्थाओं की बैंकें वाण्ड और डिबेचर दोनों ही बेचती हैं। इनके भुगतान का भी अपने-अपने समूह की समस्त बैंकों का सम्मिलित दायित्व है। लेकिन इन बांडों और डिबेचरों की सरकार की ओर से कोई गारंटी नहीं की जाती।

३० जून १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में कृषि साख प्रणाली की बैंकों और सभा-समितियों ने ४ अरब डालर की रकम उधार दी। उस समय भूमि बैंकों के ३.७६,००० और उत्पादन साख संस्था के २,९२,००० उरवार खातों में और २,७५४ कृषि सहकारी संस्थाओं के नाम प्रणाली का ४ अरब ८० करोड़

डालर का खड़ा ऋण था। उसी तिथि को कृषि साख बँको और सभा-समितियों में किसानों एवं कृषि सहकारों संस्थाओं के ३६ करोड़ ९० लाख डालर के पूँजागत हिस्से थे।

सुविधा का दृष्टि से सारे संयुक्त राज्य को बारह क्षेत्रों में बाँट दिया गया है और हर क्षेत्र में एक भूमि बैंक, एक मध्यवर्ती साख बैंक और एक सहकारी संस्थाओं को बँक है। सहकारों संस्थाओं की तरहवी बैंक सहकारों संस्थाओं की केन्द्रोय बँक है और उसका कार्यालय वाशिंगटन डी० सी० में है।

स्थानीय साख सहकारा समितियाँ, सहाय भूमि बैंक समितियाँ और उत्पादन साख समितियाँ हर एक क्षेत्र में स्थान-स्थान पर इस तरह संगठित की गई हैं कि सारे किसान उनको सेवाओं से लाभ उठा सकें। कहना नहीं होगा कि हर उधार लेने वाला इन सहकारा संस्थाओं का स्वामी होता है।

स्थानीय समितियों के सदस्य अपने में से एक संचालक मण्डल का चुनाव करते हैं। संचालक मण्डल समिति की नीतियाँ निर्धारित करता है और दैनन्दिन काम चलाने के लिए एक वैतनिक सचिव जो कोषाध्यक्ष भी होता है की नियुक्ति करता है।

सहाय भूमि बैंक से किसान को उस सहाय भूमि समिति के मार्फत जिसमें उसने अपने कर्ज के ५ प्रतिशत के बराबर पूँजागत हिस्से खरीदे होते हैं, सीधे हा कर्ज दिया जाता है।

उत्पादन साख समितियाँ अपने सदस्यों को कर्ज देती हैं और सदस्यों के तमस्सुका का सहाय मध्यवर्ती साख बैंक में हुण्डावन करके इसके लिए निधि प्राप्त करता है। उत्पादन साख समिति के सदस्यों का भी उसमें अपने कर्ज के ५ प्रतिशत के बराबर पूँजागत हिस्सा होना चाहिए।

सहाय भूमि बैंकों और उत्पादन साख समितियों से मिलने वाला कर्ज किसी भी प्रकार के कृषि-कार्य में खर्च किया जा सकता है।

सहाय भूमि बैंकों से उधार लेने वाले अपने कर्ज की अदायगी वार्षिक या अर्द्ध वार्षिक ब्याज सहित ऐसी किस्ती में करते हैं कि सारा कर्ज कम-कम पाँच और ज्यादा-से-ज्यादा चालीस वर्षों में बँबाक किया जा सके।

उत्पादक साख समितियों का अधिकांश कर्ज, जो खेती के चालू कामों को

पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है, साल-भर में अदा हो जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई किसान कर्ज को इस रकम का कोई हिस्सा मशीन या पशु आदि खरीदने की पूजोगत मद में खर्च कर देता है तो जाहिर है कि साल-भर में पूरा खाता उठाया नहीं जा सकता; ऐसा हालत में जमाना-नामे का हिसाब करके बाकी खाता नया कर दिया जाता है। इस तरह की खरीदों के लिए उत्पादक साख समितियाँ पाँच वर्ष को लम्बा अवधि का कर्ज भी देती हैं।

उत्पादन साख प्रणाली का कार्य पद्धति का खास विशेषता यह है कि उसका ऋण समिति में दो किसान निदेशक आर सस्था का सचिव-सह-कोषाध्यक्ष भी रहते हैं। निदेशकों का स्थानाय परिस्थितया और अपन क्षेत्र के कृषि कार्यों का व्यावहारिक जानकारी होता है।

कृषि सहकारि सस्थाएँ अपन क्षेत्र के सहकारियों के बैंक से सीधे कर्ज पाती हैं। इस काम के लिए बका के अपन कर्मचारी हँते हैं, जिनसे सम्बद्ध सहकारी सस्थाओं के बारे में सहा और पूरा जानकारी का अपेक्षा की जाती है। ये कर्मचारी व्यापार-व्यवहार के बारे में हा ठाक सलाह देने की योग्यता नहीं रखते। सस्थाओं के नव-निर्माण और आधुनिकीकरण के बारे में भा सुझाव दे सकते हैं।

कई वर्ष तक ऐसा कानूना प्रतिबन्ध रहा जिसके कारण सहकारी संस्थाओं की बैंकों से उधार लेने वाला कृषि सहकारी सस्थाएँ कर्ज बका हो जाने के बाद उन बैंकों में अपना पूजोगत हिस्सा रख नहीं सकती थी। कर्ज का पूरी अदायगी पर बैंकें ऋण चुकाने वाली सस्थाओं के हिस्से का विमोचन कर देती थी। इससे न तो सरकारी पूँजी लौट पा रही थी और न बैंकें उधार लेने वालों के स्वामित्व वाली सच्ची सहकारी सस्थाएँ हो बन पा रही थी।

इसलिए १९५५ में कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया जिससे सहकारी संस्थाओं की बैंकों में सहकारी सस्थाओं का पूँजी निवेश सरकारी पूँजी का स्थान ग्रहण कर सका। इस विधेयक की मुख्य गवाही ७वीं कृषि साख क्षेत्रीय सभा के निदेशक आर्थर जे० स्माबी ने दी थी। स्माबी महोदय सहकारी लीग के भी निदेशक हैं और उक्त गवाही में उन्होंने लीग का प्रतिनिधित्व भी किया था। अपने अभिसाक्ष्य का समाप्त करते हुए स्माबी ने कहा था : “कृषि साख मण्डल (Farm Credit Board) ने विधेयक की जिस रूप में सिफारिश

की है उसी मूल रूप में इसे पारित करना अमरीकी कृषि को आत्म निर्भरता की ओर बढ़ाने वाला बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कदम होगा ।”

१९५५ के अधिनियम के बड़े शुभ परिणाम रहे। उधार लेने वाली सहकारी संस्थाओं के पूँजीगत हिस्से अब बैंकों में बने रहते हैं और बैंक सरकारी पूँजी की इतनी ही रकम लौटा देती है। उधार लेने वाली सहकारी संस्थाओं की संरक्षण धन वापसियाँ भी अब बैंकों में जमा रहती हैं और उनका उपयोग भी सरकारी पूँजी को चुकाने में किया जाता है। इतना ही नहीं, व्याज की अदायगियाँ भी १५ से २० प्रतिशत रकम से सहकारी पूँजी चुकाई जाती है।

१९५५ में उक्त विधेयक पारित होते समय यह परिकल्पना की गई थी कि सारी सरकारी पूँजी चुकाने और सहकारी संस्थाओं की बैंकों को पूरी तरह सहकारी स्वामित्व कृत संगठन बनाने में कोई तेरह वर्ष का समय लग जाएगा। १९६० के आर्थिक वर्ष की समाप्ति तक ३,२०,००,००० डालर सरकारी पूँजी चुका दी गई है और इतनी ही रकम का सहकारी संस्थाओं का पूँजी निवेश हो चुका है। लेकिन उस समय तक भी ११,८०,००,००० डालर के हिस्से सरकार के पास थे। जिस गति से सरकारी पूँजी लौटाई जा रही है उसे देखते हुए आशा की जा सकती है कि सारी सरकारी पूँजी तेरह वर्ष की अवधि से बहुत पहले ही चुका दी जाएगी।

संघीय भूमि बैंकों और उत्पादन साख सभाओं का मामला पहले से ही इसलिए अच्छा था कि उनके विधान में आरम्भ से ही सदस्यों के पूँजी निवेश को अपने यहाँ रोक रखने और सरकार की पूँजी को लौटाने का प्रावधान था। बारहों संघीय भूमि बैंकों में तो १९४७ से ही कोई सरकारी पूँजी नहीं रही, सब-की-सब उसके पहले ही लौटा दी गई। अब तो उनकी सारी पूँजी सदस्यों की पूँजी है। स्थानीय संघीय भूमि बैंक समितियों की तो सारी पूँजी आरम्भ से ही किसान-सदस्यों के हिस्सों की पूँजी रही है।

जून १९५९ तक ४९५ उत्पादन साख समितियों में से ४५४ पर पूरी तरह सदस्यों का स्वामित्व स्थापित हो चुका था। उधार लेने वाले किसानों की पूँजी इन ४५४ उत्पादन साख समितियों की सारी सरकारी पूँजी का स्थान ले चुकी थी इसके अतिरिक्त शेष ४१ समितियों में सदस्यों की १४,५६,००,०००

डालर पूंजी के मुकाबले केवल ३९,००,००० डालर सरकारी पूंजी शेष थी।

अब तो थोड़े ही समय की बात है जब कि कृषि साख प्रणाली का सारा पूंजीगत निवेश उसके सदस्यों और केवल सदस्यों का ही होगा। और इस चमत्कार के चरितार्थ होने की सरलतम प्रक्रिया होगी किसानों का अपनी साख पर अधिकार, किसानों द्वारा अपनी साख का मूद्रीकरण, किसानों का अपनी ही साख को उधार लेना और स्वयं अपने को ब्याज चुकाना। यह सभी कुछ सहकारी साख की सकल्पना में अन्तर्निहित है। वास्तव में सहकारी साख है भी इसी का नाम : अपने ही पैसे और अपनी ही साख का अपनी ही आवश्यकताओं के लिए जनता द्वारा उपयोग।

यहाँ सहकारी संस्थाओं की बैंकों के भविष्य के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना अप्रासंगिक नहीं होगा। अभी ये बैंक ऐसी ही सहकारी संस्थाओं को उधार दे सकती हैं जिनमें मतदान का ९० प्रतिशत अधिकार खेती करने वालों यानी पक्के-पूरे किसानों के हाथ में हो। लेकिन पूरी आबादी के मुकाबले किसानों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है और कुछ समय खेती और बाकी समय दूसरा काम करने वाले आंशिक किसानों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। ग्रामीण और उपनगरीय परिवार एक-दूसरे के समीप और समीपतर आते जा रहे हैं। कृषि-सम्भरण-सहकारी संस्थाओं के व्यापार के लिए ऐसे परिवारों के जो पक्के-पूरे किसान नहीं हैं, अधिकाधिक संरक्षण को प्राप्त करते जाना अपरिहार्य होता जा रहा है। इसलिए जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा सहकारी संस्थाओं की बैंकों के कार्य विधि-सम्बन्धी वर्तमान नियमों को अधिकाधिक उदार करते जाना होगा। १९६१ में कृषि-साख-मण्डल ने एक सुझाव का समर्थन किया था जिसके अनुसार सहकारी संस्थाओं के लिए सहकारी संस्थाओं की बैंकों से कर्ज पाने की शर्त में 'पक्के-पूरे किसानों के ९० प्रतिशत नियन्त्रण' के स्थान पर ७५ प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

प्रत्येक सहकारी व्यवसाय अपनी मूल पूंजी के लिए अपने सदस्यों के पूंजी-निवेश पर निर्भर करता है। यह भी एक ढंग है जिसके द्वारा लोग अपने पैसे पर स्वयं अधिकार रख सकते हैं और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं।

सदस्यों के पूँजी-निवेश के मुख्य तीन ढग हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक सदस्य को सस्था के सादे पूँजीगत हिस्से में से अपनी सदस्यता का कम-से-कम एक हिस्सा अवश्य ही खरीदना चाहिए। कई सदस्य ज्यादा हिस्से भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा हिस्से लेने से मतदान की क्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती, क्योंकि सहकारी सस्थाओं में एक व्यक्ति केवल एक ही मत दे सकता है, हिस्से उसके पास कितने हों क्यो न हों। सहकारी सस्था के सादे हिस्से में कोई भी व्यक्ति तेजी-मन्दो के विचार से पूँजी नहीं लगाता, क्योंकि शहर बाजार में इन हिस्सों का सट्टा नहा होता और हिस्सों की कीमतें कभी बढ़ती नहीं, सदा एक-सो बनो रहती हैं। इसलिए सिवाय उस व्यक्ति के जिसे सहकारी सस्था की सेवाओं या माल की जरूरत है दूसरा कोई भी व्यक्ति सस्था के सादे हिस्से क्यों लेगा और क्यों उसे लेना चाहिए। सहकारी सस्थाओं के हिस्सों का 'बाजार मूल्य' निर्धारित कर पाना जो इतना कठिन है उसका कारण भी यही है कि 'बाजार' सहकारी की परिभाषा के अनुसार, उसके ग्राहकों और संरक्षकों तक ही सीमित रहता है।

सदस्यों द्वारा सहकारी सस्था में पूँजी लगाने का दूसरा ढग है सामान्य हिस्सों के अतिरिक्त दूसरी प्रतिभूतियाँ जैसे कि डिवेन्चर, अधिमानित (प्रिफर्ड) हिस्से या प्रमाणित ऋणपत्र आदि खरीदना। ये सभी सव्याज प्रतिभूतियाँ हैं और सहकारी सस्था के सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे निवेशकर्ताओं, व्यक्ति और सस्थाएँ दोनों—के लिए भाँ इनमें पूँजी रोकना लाभदाई होता है। जब सदस्य इन प्रतिभूतियों में पैसा लगाते हैं तो वे अपने पूँजी का सीधे अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। और सस्था के ग्राहक एवं संरक्षक के रूप में अपने पूँजी निदेश पर अपने लाभार्जन को भी स्वयं ही सुनिश्चित करते हैं।

सदस्यों द्वारा सहकारी सस्थाओं में पूँजी लगाने का तीसरा ढग सहकारी व्यवसायों का अपना ही विशिष्ट ढग है। यह ढग है संरक्षण-धन वापसियों के निदेश का यह ताँ पहले भी बतलाया जा चुका है कि सहकारी सस्थाओं का सारा शुद्ध उपार्जन उनके संरक्षकों और सदस्यों की सम्पत्ति है, सस्थाओं की नहीं। ये उपार्जन सहकारी संस्थाओं की देयताएँ हैं, आस्तियाँ नहीं, और किसी समुचित रूप में अपने वास्तविक स्वामियों को, उनके संरक्षण के अनुपात में, लौटाई जानीं

चाहिए। कभी-कभी संरक्षण-धन वापसियाँ, पूरी-की-पूरी या उनका कुछ अंश, नकद रूप की शकल में, की जाती हैं। लेकिन आमतौर पर उनकी अदायगी साम्या स्वामीत्व के वृद्धि-सूचक प्रमाण पत्रों, हिस्सों अथवा सव्याज प्रतिभितियों के रूप में की जाती है। अधिकांश सहकारी संस्थाओं के उपनियमों में इस आशय का प्रावधान होता है कि सदस्यों को अपनी संरक्षण-धन वापसियाँ नकद रूप में अथवा किसी अन्य रूप में लेना स्वीकार है। यदि सदस्यों ने नकद लेना स्वीकार न किया और उन्हें संरक्षण-धन वापसी सामान्य हिस्सों या स्वामीत्व के प्रमाणपत्रों के रूप में की गई तो स्पष्ट है कि वे अपनी संरक्षण-धन-वापसी सहकारी संस्था में ही निवेशित कर देते हैं। सहकारी संस्थाओं की काफी पूँजी इसी प्रकार उपलब्ध होती है।

यह पद्धति है भी बहुत अच्छी। सहकारियों को अपनी मूल पूँजी के लिए मुख्य रूप में सदस्यों के पूँजी निदेश पर निर्भर करना चाहिए। उनके सदस्यों से से साधन-सम्पन्न तो कोई भी नहीं होता। अपनी संस्थाओं में पूँजी निदेश का उनके लिए सबसे अच्छा समय वही होता है जब उन्हें संरक्षण-धन वापसी की अदायगियाँ की जाती हैं।

जिन लोगों को सहकारी संस्थाओं का ज्ञान नहीं है वे संरक्षण-धन वापसी के निदेश की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते। यह बात उनकी समझ में नहीं आ पाती कि संरक्षण धन वापसी को नकद लेकर फिर उस रूप में सामान्य हिस्से, स्वामीत्व के प्रमाणपत्र आदि खरीदने और उसका सीधे ही निदेश कर देने में कोई भी अन्तर नहीं है; विधियाँ दो हैं, लेकिन अन्तिम परिणाम तो दोनों का एक ही है। दूसरी बात जो उनकी समझ में नहीं आ पाती यह है कि सहकारी संस्था के सदस्य का आर्थिक लाभ किस में है : संरक्षण धन वापसी के निदेश में चारे की बढ़िया मिल, उर्वरक संयंत्र, किराना भण्डार, या विद्युत शक्ति का प्रबन्ध हो जाने में या सदस्य को संरक्षण-धन वापसी नकद मिल जाने में !

लेकिन कुछ लोग हैं जो इन बातों के सूक्ष्म अन्तर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए सहकारियों को अपने सदस्यों की पूँजी के मुख्य स्रोत से वंचित करके अधप कर देना चाहते हैं। ये लोग बहुत दिनों से शोर मचा

रहे हैं कि सहकारी संस्थाओं से सदस्यों द्वारा निदेशित सारी धनवापसियाँ पर एक विशेष दण्ड कर वसूल किया जाना चाहिए। उनके अभियोग का मुख्य मुद्दा यह है कि सहकारी संस्थाएँ 'कर मुक्त पूँजी' पर अपना विकास कर रही हैं। लेकिन इसमें इतनी ही सचाई है जितनी यह बात कहने में कि निगम अपनी जिस कमाई को हिस्से में लगाता है उस पर कर लगाना चाहिए, यद्यपि सभी निगम अपनी कमाई को हिस्से में लगाते हैं और उनसे उस निवेश पर कोई कर नहीं लिया जाता।

यह सच है कि सहकारी संस्थाओं के लिए यह उचित नहीं कि वे संरक्षण-धन वापसी को अदायगी ऐसे निदिष्ट तिथिहीन और बिना ब्याज के कागज में करें, जो वर्षों तक बिना मोचन के पड़ा रहता है। यह भी सच है कि सहकारी संस्था के सदस्यों पर किसी भी रूप में प्राप्त होनेवाली संरक्षण-धन वापसी को आय पर, यदि वह कराधान के योग्य हुई तो कर लगाना चाहिए और उन्हें वह कर हर हालत में चुकाना ही चाहिए। यह भी सच है कि सदस्य अपना कर चुका सके इसलिए सभी सहकारी संस्थाओं को काफी संरक्षण-धन वापसियाँ नकद देनी चाहिए और अधिकांश देनी भी हैं। और यह भी सच है कि कुछ अदालतों ने, अधिकांश सहकारी नेताओं की राय में गलती से, संरक्षकों-सदस्यों को इस आधार पर कि सहकारी संस्थाओं के हिस्सों और अन्य प्रतिभूतियों का 'बाजारमूल्य' निर्धारित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के करों की अदायगी से मुक्त कर दिया है। बाजार मूल्य का निर्धारण क्यों नहीं किया जा सकता यह बात पछे बताई जा चुकी है। लेकिन इन सबसे संरक्षण-धनवापसी के स्वामित्व की मूल स्थिति में कोई अन्तर नहीं होता। वह न तो सहकारी संस्थाओं की मिल्कित है और न उनका उस पर कोई अधिकार ही है; हर सूरत में वह उसकी देयता है जो उसे अपने संरक्षकों को देनी ही होगी। और सहकारी संस्था के किसी पूँजी-निवेश पर यह मानकर कि वह उसका लाभ है कर लगाना अनुचित और अन्याय ही नहीं पक्षपात भी होगा।

सहकारी संस्थाएँ पूँजी के लिए आज की अपेक्षा आरम्भिक वर्षों में अपने सदस्यों द्वारा संरक्षण-धन वापसियों के निवेश पर ज्यादा निर्भर करती थीं। आज सहकारी संस्थाएँ, अपने सदस्यों अथवा बाहरी निवेश कर्तियों को अधिका-

अधिक मात्रा में प्रतिभूतियों की सीधी बिक्री करके पूँजी प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। पूँजी उगाहने के वित्तीय कार्यक्रम अपनाये जाते हैं और कइयों में तो आशातित सफलताएँ मिलती हैं। ओहियो फार्म ब्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन, मिडलैण्ड कोआपरेटिव्स, इनकारपोरेशन, कञ्जूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन और हडियाना फार्म ब्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन-जैसे क्षेत्रीय कृषि-सम्भरण-सहकारी-संगठन अधिमानित हिस्से और अन्य प्रतिभूतियों की सीधी बिक्री करके हमेशा काफी पूँजी इकट्ठी कर लेते हैं। इन पर काफी अच्छा व्याज बड़े नियमित रूप से दिया जाता है और इसलिए इस प्रकार की प्रतिभूतियों की खपत निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के पूँजी-निवेशों में, विशेष रूप से सदस्यों को, आकर्षित करने के लिए ओहियो फार्म ब्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन ने एक बाड निकाला है, जो निवेशकर्ता को स्फीती से रक्षा करता है। इन बाडों को व्याज की दरे जोवन-निर्वाह के सूचकांक से बँधी होते हैं। जीवन-निर्वाह के सूचकांक में श्रमिक सांख्यिकी मंडल (Bureau of Labor Statistics) जितनी वृद्धि की घोषणा करता है उसी अनुपात से इन बाडों के व्याज की दरे बढ़ जाते हैं।

इधर के वर्षों में नगर को कुछ उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं ने भी पूँजी प्राप्त करने के लिए, मुख्य रूप से अपने ही सदस्यों में, कई वित्तीय कार्यक्रम आरम्भ किये और उनमें पुरो सफलता प्राप्त की। सफलता का एक कारण तो यह है कि वे काफी समय से और नियमपूर्वक अपने हिस्सों पर पाँच प्रतिशत लाभांश देती आ रही हैं। दूसरा कारण अपने कारबार में उनकी सफलता है। लेकिन तीसरा कारण निस्सन्देह बस्ती की एक महत्वपूर्ण संस्था के स्वामीत्व का गौरव है जो सहकारी-सदस्यता से स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। प्रमाण-स्वरूप शिकागो के दक्षिणी विभाग (South Side) की हाईडपार्क उपभोक्ता सहकारी समिति (Hyde Park Consumer Cooperative Society) का उदाहरण लिया जा सकता है जिसके हिस्सों की अक्सर बहुत अधिक माँग रहती है और संस्था को यह सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं अतिशय पूँजी-करण न हो जाए। •

लेकिन फिर भी सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को अपनी सहकारी संस्थाओं-

जितनी अधिक पूँजी लगानी चाहिए उतनी उन्होंने अभी तक भी लगाई नहीं है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि किसानों ने अपनी सहकारी संस्थाओं में अपने कुल निवेशों की सिर्फ़ दो से तीन प्रतिशत के ही लगभग पूँजी लगाई होगी। और यह स्थिति है इस वास्तविकता के बाद कि दूसरी जगह पूँजी लगाकर प्रति डालर जितना लाभ होता है सहकारी संस्था में पूँजी लगाने पर उससे कहीं अधिक होता है।

इसलिए सहकारियों का यह भी एक आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि ज्यादा मात्रा में पूँजी लगाने के लिए वे अपने सदस्यों की उचित शिक्षा पर ध्यान दें। सदस्यों की शिक्षा की दिशा में दो कार्य किये जाने चाहिए। एक तो सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों को उच्चकोटि की आर्थिक और सामाजिक सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए। और दूसरे शिक्षा और सचना का अबाध कार्यक्रम, जिससे यह बात साफ-साफ़ उनकी समझ में आ सके कि अपनी सहकारी संस्था में ज्यादा पूँजी लगाना क्यों आवश्यक है।

जहाँ ये दोनों काम किये गए हैं वहाँ हमें कुछ बड़े ही उत्साह वर्द्धक परिणाम देखने को मिलने हैं। १९५९ में प्गोट साउण्ड की सामूहिक स्वास्थ्य सहकारी संस्था ने २५,००,००० डालर उगाहने के लिए अपने पचपन हजार सदस्यों में बाँड बेचने का निश्चय किया। जितने बाँड बेचने के लिए निकाले गए थे वे कुछ ही महीनों में अति-दन हो गए। सहकारी स्वास्थ्य योजना के सदस्य स्वयं अपने को एक-एक करके समष्टिगत रूप से ब्याज देते रहेंगे। बाहरी कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह जनता का पैसा ही जनता के अस्पताल को बना रहा है।

न्यूयार्क सिटी की उमरी परानी अमलगामेटेड हाउसिंग कोओपरेटिव (समा-मेलित आवास सहकारी संस्था Amalgamated Dwellings Housing Cooperative) ने १९६० में अपनी बन्धक पूँजी के अन्तिम ढाई लाख डालर जमा करने के लिए ४ प्रतिशत ब्याज पर पाँच सौ डालर मूल्य के बन्धक बाण्ड अपने ही सदस्य-आवासी-स्वामियों और पास-पड़ोस की सहकारी-गृह-निर्माण-योजनाओं में रहने वाले लोगों को बेचने का काम हाथ में लिया। कुछ ही महीनों में ढाई लाख डालर की अपेक्षित पूँजी इकट्ठी हो गई। कुछ खरीदारों

की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक थी। उनका कहना था : “अपने रुपए को किसी बचत बैंक में जमा करने या कहीं और लगाने के बदले अपने ही मकानों में क्यों न लगाया जाए ? दूसरी जगह जमा करने या लगाने पर अपने मकान में लगाने के लिए अपना ही रुपया उनसे उधार लेकर उनका ऋणी बनना होगा !”

इस प्रकार सहकारी संस्थाओं के वित्त प्रबन्ध में प्रगति होती जा रही है।

लेकिन यदि ऊपर बताये उपायों का ही अवलम्बन किया जाता रहा तो यह प्रगति धन की दृष्टि से बहुत अपर्याप्त और गति की दृष्टि से बहुत शिथिल होगी। कई प्रकार की सहकारी संस्थाएँ इस बात को प्रदर्शित कर चुकी हैं कि उनमें विकास और विस्तार की महान क्षमताएँ हैं और हमारे समाज की वर्तमान आवश्यकताएँ उनके इस विकास और विस्तार का पूरा-पूरा समर्थन करती हैं। यदि पूँजी का प्रबन्ध हो जाए तो सहकारी गृह-निर्माण योजनाएँ, सहकारी समूह स्वास्थ्य योजनाएँ, सहकारी विद्युत् सेवाएँ, नगरों में सहकारी वृहद् भण्डार (सुपर मार्केट), सहकारी तेल कम्पनियाँ आदि सहकारी ढग के कई उद्यम हैं जो बहुत तेजी से उन्नति कर सकते हैं और करेंगे और सारे समाज को लाभ पहुँचाएँगे।

सौभाग्य से और सम्भवतः इसी भविष्य की दृष्टि में रख कर पिछले तीस वर्षों में सहकारी ढग की बहुत-सी पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ स्थापित की गई हैं। क्योंकि इस समय अमरीकी जनता की बचतों की मुख्य धारा बीमा करवाने की ओर ही प्रवाहित हो रही है। किसी जमाने में अमरीकी उद्योग के वित्तीय भविष्य की निर्णायक ‘वाल स्ट्रीट’ हुआ करती थी। अब नहीं। अब वह शक्ति देश की जबर्दस्त बीमा कम्पनियों के हाथ में आ गई है। जनता की बचतों और पूँजी का बहुत बड़ा अंश आज उन्हीं को सौंपा जा रहा है। यहाँ तक कि सरकारी बाण्डों के ब्याज की दर भी उन्हीं के खरीदने या न खरीदने से प्रभावित होती है। उन्हीं की निवेश-नीतियाँ सारे देश की निवेश निधियों का दिशा-निर्देशन करती हैं।

‘वालस्ट्रीट’ के उत्कर्ष काल में फिर भी सच्ची प्रतियोगिता प्रचुर परिमाण में विद्यमान थी। आज हमारे अधिकांश शक्तिशाली उद्योगों में उस प्रतियोगिता

का निरा औपचारिक रूप ही बचा रह गया है। इसलिए थोड़े-से हाथों में औद्योगिक एकाधिकार के साथ वित्तीय एकाधिकार भी यदि सिमट आया तो उन हाथों आर्थिक स्वतन्त्रता का गला घुटने की आशका एक वास्तविकता बन जाएगी।

लेकिन यदि ऐसे उपाय खोजे जा सकें जिनके द्वारा जनता, जिसकी बचते ही पूँजी के महान निकायो का निर्माण करती है, उस पूँजी का सफल और सार्थक निदेशन और निर्देशन कर सके तो हमारी जनवादी और स्वतन्त्र सस्थाओं में ओज और प्राणवत्ता की आशा की जा सकती है।

हमारे युग की आर्थिक समस्या का एकमात्र समाधान है ऐसे उपायो का अवलम्बन जिनके द्वारा महत्तम दक्षता वाले विशालतम उद्योग-व्यवसायो पर बहुत से लोगों का जनवादी स्वामीत्व और बहुत-से लोगों का जनवादी नियन्त्रण तो हो ही, साथ ही वे जनता के साधन-स्रोतों अर्थात् जनता की पूँजी के सच्चे और निष्ठावान न्यासधारी भी हों।

सहकारी बीमा कम्पनियों के इतने अधिक महत्त्वपूर्ण होने का यही कारण है।

जन-समुदायों द्वारा 'अपनी सुरक्षा का भार स्वयं वहन करने, के विचार में से ही सहकारी पारस्परिक बीमा का जन्म हुआ। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बीमा कम्पनी वास्तव में एक समान दुःख-तकलीफों वाले, उन दुःख-तकलीफों को मिल-बाँटने के लिए सम्मिलित होने वाले और उनका सामना करने के लिए अपनी कुछ बचतों का निकाय करनेवाले लोगों का समूह है। इसलिए लोगों का कोई भी समूह यदि सचमुच चाहे तो अपने से और सुरक्षा-सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं से एक बीमा कम्पनी बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह समझदारी से और कुशल प्रबन्ध के अन्तर्गत काम करे।

बेंजामिन फ्रैंकलिन इस विचार को अमरीकी जीवन में लाये। उन्होंने फिलाडेल्फिया के निवासियों में १७५२ में एक पारस्परिक अग्नि-बीमा कम्पनी संगठित की।

इधर-इधर तो पारस्परिक बीमा के विचार को कई जन समूहों ने अपनाया और उसका उपयोग किया है। उन्होंने इस विचार का उपयोग किया अपने-आप को प्रीमियम देने और अपनी बचतों का स्वयं नियन्त्रण करने वाले

माध्यम के रूप में। अधिकांश सहकारी उद्यमों की भाँति इस तरह के सहकारी बीमा का बिल्कुल आरम्भ का रूप, आवश्यकता के कारण ही अस्तित्व में आया। व्यापारिक बीमा कम्पनियाँ किसानों का अग्नि-सुरक्षा बीमा नहीं करती थी, और जैसा कि नियम है आज भी नहीं करती। अग्नि सुरक्षा विभागों से खेतों को यथोचित सहायता और प्रभावी सेवा नहीं प्राप्त होती थी। इसलिए उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में किसानों की पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ—फारमर्स म्यूचुअल्स-बनने लगी। आरम्भ से ही वे एकदम शुद्ध सहकारी उद्यम रही हैं। उनकी कार्य विधि भी बहुत ही सरल होती है। वे आग की जोखिम का निकाय कर लेती हैं और यह समझौता कि यदि उनमें से किसी की भी आग से हानि हुई तो सब मिल कर क्षतिपूर्ति कर देंगे, अर्थात् हानि के मूल्य को आपस में बाँट लेंगे। बहुत-सी फारमर्स म्यूचुअल्स बगैर प्रीमियम के काम करती हैं; आग की हानि का दावा होने पर हानि के कुल मूल्य में अपने सदस्यों (पालिसी धारियों) का हिस्सा निर्धारित कर देती हैं। इस समय दस हजार से भी अधिक फारमर्स म्यूचुअल्स या जैसा कि कभी-कभी उन्हें कहा जाता है टाउन शिप म्यूचुअल्स लाखों किसानों को और ग्रामवासियों को आग, बवंडर और ओला वृष्टि से सुरक्षा प्रदान कर रही हैं।

इन छोटी सहकारी बीमा कम्पनियों ने काफी उपयोगी कार्य किया और आज भी कर रही हैं। उन्होंने एक ऐसी आवश्यकता की पूर्ति की है जो अन्यथा कभी न हो पाती। और उन्होंने उस आवश्यकता की पूर्ति विशुद्धतम सहकारी ढंग से की है।

लेकिन इतना ही काफी नहीं था। १९२५ के आसपास सहकारी विचार वाले लोगों ने अपनी ही बीमा-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी ही बीमा कम्पनियाँ बनाना शुरू किया। इस बार भी नेतृत्व किसानों का ही रहा। ओहियो फार्म ब्यूरो के मरे डी० लिंकन—जैसे कृषक सदस्यता संगठन के नेताओं को सहकारी बीमा कम्पनियाँ अपने सदस्यों के लिए धन बचाने और अपनी बचतों पर अधिकार रखने एवं उनका उपयोग करने के साधन के साथ ही दूसरे प्रकार के सहकारी उद्यमों में लगाने के लिए सुरक्षित ऋण-पूँजी के सबल स्रोत भी दिखाई दीं। इसी अन्तर्दृष्टि के परिणाम स्वरूप नेशन वाइड

इन्श्यूरेन्स कम्पनीज-अस्तित्व में आईं, जो पहले-पहल १९३६ में ओहियो की फारम व्यूरो इन्श्यूरेन्स कम्पनीज आफ ओहियो के रूप में संगठित की गई थी और आज देश के सारे बीमा व्यवसाय में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। म्युचुअल सर्विसे इन्श्यूरेन्स कम्पनीज, जो मिन्नेसोटा और विसकांन्सिन के किसानों द्वारा १९२० के बाद की दशाब्दी में इसी उद्देश्य से गठित पाँच बीमा कम्पनियों के पारस्परिक विलयन से बनी है, आज एफ० एफ० रण्डड्यू की अध्यक्षता में मिडवेस्ट के ऊपरी भाग की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में है। फारमर्स यूनियन कम्पनीज और दूसरी भी बहुत-सी कम्पनियों ने यही मार्ग अपनाया है।

साख संघ के नेताओं को भी ऋणों की अन-अदायगियों के लिए साख सकों का बीमा करवाने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। वे इस मानवतावादी विचार के कायल होते जा रहे थे कि ऋणी की मृत्यु के साथ ही उसका ऋण भी समाप्त हो जाना चाहिए। इसी विचार से प्रेरित होकर और ऋण की सुरक्षा एवं आजीवन-वचत बीमा सुलभ करने के लिए उन्होंने क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन म्युचुअल इन्श्यूरेन्स सोसाइटी (साख संघ राष्ट्रीय सभा पारस्परिक बीमा समिति) (Cuna Mutual Insurance Society) के नाम से एक बीमा कम्पनी स्थापित की।

परिणाम इसके बहुत ही अच्छे और अक्सर चकित कर देने वाले रहे। ये बीमा कम्पनियाँ पालिसी धारियों की थी—और आज भी हैं—इसलिए जितना अधिक-से-अधिक घटा सकती थी प्रीमियम की दरें आसानी से घटा देती। कई बार तो व्यापारी बीमा कम्पनियों से इनके प्रीमियम की दरें ४० प्रतिशत तक कम होती थी। लेकिन यह सहकारी बीमा व्यवसाय के आरम्भिक दिनों का बात है। अब तो दूसरी भी कई व्यापारी कम्पनियों ने सहकारी बीमा कम्पनियों की प्रतियोगिता में प्रीमियम की अपनी दरें कम कर दी हैं।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे सहकारी बीमा कम्पनियों ने अपने आचरण से सिद्ध कर दिखाया यह है कि बीमा कम्पनियों को सौंपा गया सारा पैसा वास्तव में पालिसी धारियों का ही है।

और यह पैसा थोड़ा नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। १९४५ से १९४९ के बीच बीमा कम्पनियों की समग्र पूँजी औसतन ३ अरब ६० लाख डालर प्रति

वर्ष के हिसाब से बढ़ती रही है। जीवन-बीमा कम्पनियों की समग्र पूँजी हर दस बरस में दूनी हो जाती है और इस समय उनकी पूँजी संयुक्त राज्य के समस्त राष्ट्रीय धन के दशमांश से कुछ अधिक ही होगी। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि देश की समस्त जीवन-बीमा कम्पनियों की कुल स्वीकृत आस्तियों का ७० प्रतिशत दस सबसे बड़ी जीवन-बीमा कम्पनियों के अधिकार में है। ऐसी कम्पनियों के अधिकारियों को प्रति वर्ष आठ-दस अरब डालर के निवेश का अधिकार भी है और अवसर भी। 'बाल स्ट्रीट' के उत्कर्ष काल में वहाँ के सब निवेश कर्त्ता बँकर जितनी पूँजी का नियन्त्रण करते थे उससे यह रकम दूनी है। केवल यही नहीं कि अधिकांश बड़े उद्योगों की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना बीमा कम्पनियों के हाथ में है, बल्कि इधर-इधर तो जिन उद्योगों में पूँजी लगाना सभी तरह सुरक्षित है उन उद्योगों के हिस्से भी इन्होंने स्वयं खरीदना शुरू कर दिया है। अभी कुछ ही राज्यों में इसकी अनुमति मिल पाई है। लेकिन इससे बीमा-व्यवसाय के सूत्रधारियों के हाथ में इतनी शक्ति तो आ ही जाती है कि वे जिस कम्पनी को चाहेंगे जिन्दा रखेंगे और उन्नति करने देंगे और जिसे चाहेंगे खत्म कर देंगे।

इस तरह के अधिकार का उपयोग अथवा दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है यह बात विद्युत-शक्ति व्यवसाय की ओर देखने से स्पष्ट हो जाती है। बीमा कम्पनियाँ पैसा लगाने का सबसे अच्छा साधन बिजली कम्पनियों के बांडों को समझती हैं। यही कारण है कि बिजली कम्पनियों को अपेक्षाकृत सस्ती दर पर कर्ज मिल जाता है। अब यदि किसी दिन ग्रामीण विद्युतीकरण के विरोधियों का बस चल ही जाए और वे कांग्रेस पर जोर डाल कर ग्रामीण विद्युतीकरण प्रशासन (Rural Electrification Administration) को, जो ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाओं के कर्ज पाने का एकमात्र स्रोत है खत्म करवाने में सफल हो जाएँ तो क्या होगा ? क्या विद्युत सहकारी संस्थाओं को बीमा कम्पनियों से कर्ज मिल सकेगा ? है कोई सम्भावना ? विसकोन्सिन की विद्युत् सहकारी संस्थाओं की औसत ग्राहक संख्या लाइन के प्रति मील पर सिर्फ एक है, जब कि उनकी प्रतिद्वन्द्वी बिजली कम्पनियों की नौ है। कुछ राज्यों में तो यह अन्तर और भी ज्यादा है। विद्युत् सहकारी संस्थाओं को अपनी

की बैठकों में शायद ही कोई शरीक होता और वोट दे पाता है। इसलिए आमतौर पर निदेशक-मण्डल और अधिकारी काफी लम्बी अवधियों तक अपने पदों पर बने और अनिश्चित काल तक पालिसी धारियों की बचतों का नियन्त्रण करते रहते हैं। कम्पनी जितनी ही बड़ी होती जाएगी और जितने ही अधिक लोगों का पैसा उसके पास जमा होता रहेगा यह स्थिति वहाँ उतनी ही अधिक होगी।

बीमा कम्पनी, जैसा कि हम देख आये हैं, जनता की सर्व सामान्य सुरक्षा के लिए उनकी बचतों के निकाय पर आधारित महान और बहुत ही आदर्श-वादी संस्था है।

लेकिन आज तो बीमा कम्पनियाँ जनता की बड़ी-बड़ी बचतों पर अबोध अधिकार जमाए उस धन से अनाप-शनाप मुनाफा कमा रही हैं। यद्यपि कम्पनी का सारा अस्तित्व पालिसी धारियों के प्रताप से है, लेकिन बहुत-सी बीमा कम्पनियाँ जनता की बचतों पर अपने अधिकार का उपयोग मोटे मुनाफे कमाने में ही करके अपने कर्तव्य का इति श्री मान लेती हैं, पालिसी धारियों के व्यापक हितों का वे कुछ भी विचार नहीं करती।

आशा तो यही की जानी चाहिए कि पारस्परिक बीमा कम्पनियों के बारे में यह बात सच नहीं होगी, क्योंकि वे जनता की बीमा-सम्बन्धी माँग को इस तरह से पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं कि सारे लाभ बीमाधारी जनता को ही प्राप्त हों।

लेकिन दुर्भाग्य से कुछ पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ केवल नाम को ही पारस्परिक हैं। उनके उद्देश्य भुलाये जा चुके हैं। उनका नियन्त्रण पालिसी धारियों के हाथ में नहीं है। उनकी बचतें, जो आर्थिक प्रगति की कुञ्जी हैं, उनके हाथ से निकल चुकी हैं। उन बचतों के निवेश और नियन्त्रण का काम प्रबन्धकारी समूह करते हैं, जो उन बचतों के वास्तविक स्वामी, पालिसी धारियों के प्रति अपनी कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझते।

इस तरह का आचरण अमरीका के लिए भयावह हो सकता है। जब जनता अपनी बचतों पर, और विशेषकर जब वे बचतें बड़े-बड़े निकायों के मकलित रूप में हों, अपना अधिकार गँवा बैठती हैं तो उस देश में जनवाद के लिए

जबदैस्त खतरा उपस्थित हो जाता है।

यहाँ पाठक पूछ सकते हैं कि बीमा में जमा की हुई अपनी बचतों पर अपना अधिकार फिर से पाने के लिए जनता के सामने कोई रास्ता है या नहीं ! रास्ता जरूर है। वह रास्ता है नई 'सहकारी' ढग की बीमा कम्पनियाँ, जिनके उद्देश्य और प्रयोजन और दृष्टिकोण और काम करने का ढग, सभी कुछ सही अर्थों में पारस्परिक होता है और जिस तरह की कम्पनियों के कुछ उदाहरण हम ऊपर दे आये हैं।

ये पारस्परिक कम्पनियाँ इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि जिन लोगों को बीमा की अत्यधिक आवश्यकता है, वे अपनी बचतों का जो निकाय करे, उस पर उन्हीं के नियन्त्रण को बनाये रख उन्हें बीमा की सेवा-सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। और ये कम्पनियाँ इस बात को भी प्रमाणित करने के लिए बनाई गई थी कि यदि जनता जी-जान से चाहे तो अपनी ही कम्पनियों के द्वारा अपने लिए बीमा की सेवा-सुविधा प्राप्त कर सकती है।

ये पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ वित्तीय कारबार करने वाली दूसरी संस्थाओं की ही तरह 'जनता के उपयोग के लिए जनता के नियन्त्रण में जनता का पैसा' वाले सिद्धान्त का अमल करती हैं। इनमें सब तो नहीं लेकिन बहुत-सी कम्पनियाँ ऐसे जन समूहों में गठित हुई हैं जो पहले से किसी-न-किसी सहकारी उद्यम से सम्बद्ध हैं।

कानून की दृष्टि से इन कम्पनियों को भले ही सहकारी न कहा जा सके, परन्तु वास्तव में ये 'सहकारी' बीमा कम्पनियाँ ही हैं, जो दूसरी (पुराने ढग की) बीमा कम्पनियों से कई बातों में भिन्न हैं।

एक तो यही कि कम्पनी के नीति-सम्बन्धी निर्णयों में पालिसी धारी भाग ले सकें इसलिए ये कम्पनियाँ कई तरह के उपाय करती हैं। फिर कम्पनी पर पालिसी धारियों के प्रभावी नियन्त्रण के लिए भी अनेक प्रकार के प्रयत्न किये जाते हैं।

उदाहरण के लिए एक 'सहकारी' कम्पनी है—समूह स्वास्थ्य पारस्परिक बीमा कम्पनी। इसका सारा कार्य क्षेत्र कई हलकों में बँटा हुआ है। हर हलके की नियमित बैठकें होती हैं और सभी पालिसी धारियों को उनमें सम्मिलित होने के

लिए प्रेरित किया जाता है। बैठकों में सम्मिलित होने वाले प्रतिवेदन और विवरण प्राप्त करते हैं, कम्पनी के वार्षिक अधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और प्रचलित विषयों पर मतदान के सम्बन्ध में उन प्रतिनिधियों का मार्ग-दर्शन करते हैं।

जिन पारस्परिक बीमा कम्पनियों का गठन किसी दूसरे सहकारी उद्यम से सम्बद्ध जन-समूह में किया गया है उनमें से कुछ उस सदस्यता-संगठन से निकट सम्बन्ध बनाये रखकर जनवादी नियन्त्रण को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करती हैं। इस तरह की कम्पनियों में नेशनल एण्ड नेवास्का फारमर्स यूनियन इन्श्यूरेन्स कम्पनी, कुछ राज्यों की फार्म ब्यूरो कम्पनियाँ, विसकोन्सिन विद्युत् सहकारी द्वारा हाल में गठित एक कम्पनी और राष्ट्रीय एव राज्य स्तर की सहकारी संस्थाओं द्वारा गठित और भी कई कम्पनियों के नाम गिनाये जा सकते हैं।

नेशन वाइड इन्श्यूरेन्स कम्पनीज ओहियो में फार्म ब्यूरो इन्श्यूरेन्स कम्पनीज कृषि मण्डल बीमा कम्पनियों के रूप में आरम्भ की गई थी। १९६० तक इनके कार्य क्षेत्र का विस्तार देश के आधे राज्यों में हो चुका था। काम के विस्तार के सिलसिले में ये कम्पनियाँ जिस किसी भी राज्य में गई वहाँ इन्होंने किसी एक जनवादी ढंग से नियन्त्रित सदस्यता-संगठन से 'प्रायोजी' करार किया। इस तरह के सदस्यता-संगठनों में से कुछ तो राज्य स्तरीय क्रेडिट यूनियन लीग हैं, पर अधिकांश राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रीय सहकारी संगठन हैं, जैसे कि कैरोलिनास में फारमर्स कोऑपरेटिव एक्सचेंज या ओहियो और पेनसिलवानिया में फार्म ब्यूरो कोऑपरेटिव एसोसिएशन्स या न्यूयार्क में ईस्टर्न कोऑपरेटिव्स आदि। 'प्रायोजक' संस्था का कार्य होता है नेशनवाइड के काम को अपने राज्य में सभी उचित प्रकारों से आगे बढ़ाना; इन सेवाओं के पारिश्रमिक स्वरूप प्रायोजक को नेशनवाइड से नकद धन के अतिरिक्त अपने निर्देशक मण्डल में एक सदस्य नियुक्त करने का अधिकार भी दिया जाता है। इधर कुछ समय से तो 'पालिसी धारियों की सलाहकारी परिषदे' नामक योजना पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। नेशनवाइड बीमा कम्पनियों का एजेंट पालिसी धारियों को स्थानीय बैठकों से आरम्भ करता है। इन बैठकों में कम्पनी की रीति-नीति पर जमकर चर्चा की जाती है और इसी तरह की क्षेत्रीय बैठकों के लिए

प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। क्षेत्रिय सम्मेलन पचास व्यक्तियों को चुनते हैं, जो प्रति वर्ष नेशनवाइड के अतिथि बनकर दो दिन के लिए कोलम्बस जाते हैं और कम्पनी के अधिकारियों को नेशनवाइड के 'राष्ट्र व्यापी' पालिसीधारियों के विचारों और आकांक्षाओं से अवगत करते हैं।

लेकिन अपनी ही बचतों के संचित कोष के निवेश और उपयोग पर पालिसी-धारियों के अभीष्ट सार्थक नियन्त्रण का जो उपाय म्युचुअल सर्विस इन्श्युरेन्स कम्पनी ने, जिसका प्रधान कार्यालय सेट पाल में है, कई वर्षों के प्रयत्नों के बाद खोज निकाला है उसे अनेक अर्थों में अच्छा उपाय कहा जा सकता है। इस कम्पनी ने अलग से एक वैधानिक सस्था म्युचुअल सर्विस कोऑपरेटिव के नाम से बना दी है। इस सस्था में हिस्से खरीदकर मतदान का अधिकार केवल कृषि-सम्भरण, विक्रय, उपभोक्ता, विद्युत् या अन्य प्रकार की सहकारी सस्थाओं को, साख-सर्घों को या किसानों की पारस्परिक कम्पनियों को ही है। इस समय ये मतदायी-हिस्से (वोटिंग शेअर्स) इस तरह के पाँच सौ से भी ज्यादा स्थानीय सहकारी सगठनों के पास हैं, और उन स्थानीय सहकारी सगठनों में से अधिकांश के सदस्य म्युचुअल सर्विस इन्श्युरेन्स कम्पनी के पालिसी धारी हैं। ये पालिसी-धारी बीमा कम्पनियों की वार्षिक बैठकों में अपने मत देने के लिए म्युचुअल सर्विस कोऑपरेटिव के निदेशक मण्डल को अपना प्रतिपत्री नियुक्त कर देते हैं। और जिन स्थानीय सहकारी सस्थाओं के पास मतदायी हिस्से हैं उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इस निदेशक-मण्डल का चुनाव करते हैं। इस तरह, जिन लोगों ने रुपया दिया है उनके सीधे नियन्त्रण से इन कम्पनियों का बच पाना मुश्किल ही है। चाहे तो भी वे बच नहीं सकती, हालाँकि वे कभी चाहती भी नहीं।

दूसरे यह कि 'सहकारी' बीमा कम्पनियाँ अपने पालिसी धारी सदस्यों को वैधानिक दृष्टि से और सरलता से भी जितना हो सके उतने न्यून मूल्य पर बीमा की सेवा-सुविधा प्रदान करती हैं। यह दो तरह से किया जाता है : एक तो प्रीमियम को जितना सम्भव हो सके घटा कर और दूसरे अपने पालिसी धारियों को जितना अधिक-से-अधिक हो सके लाभान्श देकर। पालिसियों के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनमें मूल प्रीमियम का चालीस प्रतिशत तक लाभान्श दिया जाता है।

तीसरे यह कि 'सहकारी' बीमा कम्पनियाँ इस बात को जानती और मानती हैं कि पालिसी धारियों ने अपना रुपया उनके विश्वास पर छोड़ा है, इसलिए उस रुपए का निवेश उन लोगों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए जिनकी वचनों से ही वह निवेश सम्भव हुआ है। इसलिए सहकारी बीमा कम्पनियाँ अपनी आस्तियों का जितना बड़ा भाग दूसरे प्रकार के सहकारी व्यवसायों में लगाना चाहे लगा सकती हैं और उन्हें लगाने दिया जाता है। वे कृषि-आपूर्ति और नगर-उपभोक्ता सहकारी सस्थाओं को, गृह निर्माता सहकारी सस्थाओं और सहकारी स्वास्थ्य योजनाओं को ऋण देती हैं, जहाँ पैसा बिल्कुल सुरक्षित है।

लेकिन जैसा कि हम अन्य सहकारी वित्तीय संगठनों के सम्बन्ध में देख आये हैं, सहकारी बीमा कम्पनियाँ के मार्ग में कुछ ऐसी वास्तविक रुकावटें हैं जिनके कारण वे इस दिशा में जितना करना चाहिए कर नहीं पाती। एक बाधा, जो बहुत अच्छी भी है, यह कि बीमा-कम्पनी के अधिकारी पहले खूब ठोक-बजाकर देख लेते हैं कि सहकारी सस्था में लगाई गई पूँजी के प्रति लाभ का स्तर दूसरे किसी भी पूँजी-निवेश के समकक्ष है या नहीं, यदि न्यून पाया जाता है तो वे सहकारी सस्था में पूँजी लगाने से इनकार कर देते हैं। जिन सहकारी सस्थाओं की हालत अच्छी नहीं होती उनके लिए यह बड़ा माकूल इलाज है। इसके अतिरिक्त कई राज्यों में ऐसे बीमा कानून बने हुए हैं जिनके कारण अच्छी जमानतों के रहते हुए भी बीमा कम्पनियाँ अपनी आस्तियों के ५ प्रतिशत से अधिक रकम किसी सहकारी व्यवसाय में न तो लगाने और न कर्ज ही दे सकती हैं। दूसरे राज्यों में कानून अवश्य इतने कड़े नहीं हैं, लेकिन सहकारी सस्थाओं में निवेश या उन्हें ऋण देने की संरचना वही भी निर्धारित है, जो कुल आस्तियों के बहुत छोटे से अंश से आगे नहीं जा पाती, चाहे बीमा कम्पनी कितनी ही सहकारिता-अभिप्रेरित क्यों न हो।

यह तो सहकारी बीमा कम्पनियों का माना हुआ नियम है कि वे सबसे पहले उत्कृष्ट कोटि की बीमा कम्पनी हैं; क्योंकि इसके बिना दूसरे सहयोगी उद्यमों की उन्नति में सहायक उनका अभीष्ट कभी पूरा नहीं हो सकता।

इन दोनों उद्देश्यों के समन्वय के उपायों पर विचार और उनके कार्यान्वयन के लिए १९४७ में सहकारी लीग न सहकारी पद्धति की अधिकांश बड़ी और महत्वपूर्ण बीमा कम्पनियों का एक अनौपचारिक संघ बनाया जो सहकारी लोग का बीमा सच (The Insurance Conference of the Co-operative League) कहलाता है। इस सच के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किये गए, जिनमें इस पुस्तक के लिखे जाने के समय तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ; और सहकारी बीमा कम्पनियों के दोनों मूल प्रयोजनों का इन उद्देश्यों में पूर्णतः समावेश कर लिया गया है।

- १—बीमा-व्यवसाय में प्रतियोगिता-स्वातन्त्र्य की रक्षा करना और बीमा सेवाओं का उपयोग करने वालों के हितों के अनुरूप बीमा-व्यवसाय में स्वतः प्रेरणा, उपक्रम, उन्नति और विकास को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित करना।
- २—बीमा-व्यवसाय के बारे में जनता की समझ को प्रोत्साहित और अभिवर्द्धित करना।
- ३—सदस्यों की रुचि के विषयों का पता लगा कर सम्बन्धित जानकारी प्रसारित करना।
- ४—सर्व-सामान्य समस्याओं पर चर्चा एवं उनके अध्ययन और निराकरण के लिए विचार-गोष्ठियों का प्रबन्ध करना।
- ५—सदस्यों में पारस्परिक लाभ के व्यापारिक सम्बन्धों को सुगम बनाना।
- ६—सच और बाकी सभी क्षेत्रों में सहकारी उद्यम के आपसी सम्बन्धों पर शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित करना।
- ७—बीमा करवाने वाली जनता और सच के सदस्यों के हितों का सभी उचित उपायों से रक्षण और सबर्द्धन करना।

८—वे सभी कार्य और कार्यवाहियाँ करना जो उपर्युक्त से सम्बन्धित हों।

सहकारी बीमा कम्पनियाँ और अन्य प्रकार की सहकारी संस्थाएँ पारस्परिक लाभ के लिए साथ मिल कर कैसे काम कर सकती हैं इसका मिडलैण्ड सेण्ट्रल म्युचुअल कारपोरेशन काफी अच्छा उदाहरण है। इस तरह साथ मिल कर काम करना सहकारी बीमा कम्पनियों की ऋण देने को सामर्थ्य को विकसित करने और अपनी सहकारी संस्थाओं में जनता की निवेशित पूँजी के सार्थक

उपयोग का अत्यन्त सफल और सुरक्षित साधन है। मिडलैण्ड सेण्ट्रल म्युचुअल कारपोरेशन दो क्षेत्रीय थोक सहकारी संस्थाओं और एक 'सहकारी' बीमा कम्पनी का निगम है। इन तीनों संस्थाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं : मिडलैण्ड कोऑपरेटिव इनकारपोरेशन, सेण्ट्रल कोऑपरेटिव्स इन कारपोरेशन और म्युचुअल सर्विस इन्श्यूरेन्स कम्पनीज। ये तीनों कम्पनियाँ मिडवेस्ट के ऊपर के भाग में काम करती हैं। मिडलैण्ड सेण्ट्रल म्युचुअल कारपोरेशन सही अर्थों में भू-स्वामी और विकास कार्यों को करने वाली संस्था है। यहाँ इस निगम को कार्यविधि सम्बन्धी बारीकियों में जाने की आवश्यकता नहीं है; संक्षेप में बताने से ही काम चल जाएगा। यह निगम स्थानीय सहकारी संस्थाओं की जमीन में पैसा फँसाने की आवश्यकता को अपने ढंग से पूरा कर उस पैसे को कृषि कारबार में लगाने में उनकी सहायता करता है। जिस जमीन की सहकारी संस्थाओं को अपने काम के विकास के लिए आवश्यकता होती है उसे निगम या तो उनसे खरीद लेता है या अधिग्रहण कर लेता है। फिर निगम की ओर से वे जमीनें दोनों में से किसी एक थोक सहकारी संस्था को पट्टे पर दे दी जाती हैं और थोक सहकारी संस्था उन्हें स्थानीय सहकारी संस्थाओं को उठा देती हैं। स्थानीय सहकारी के साथ पट्टेदारी करने से पहले थोक सहकारी की ओर से काफी गहरी जाँच-पड़ताल कर ली जाती है और एक करारनामे के रूप में शर्तों को लिखा-पढ़ी भी कर ली जाती है। इतनी छान-बीन और लिखा-पढ़ी के बाद निगम अपनी सम्पत्ति पर कर्ज पाने के लिए जो जमानत पेश करता है वह साधारण बन्धक की अपेक्षा काफी मूल्यवान होती है; और इसीलिए निगम की तीसरी स्वामी संस्था, म्युचुअल सर्विस इन्श्यूरेन्स कम्पनी सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य से काफी अधिक धन राशि उधार दे पाती है, जो वह अन्यथा नहीं दे सकती थी।

इस प्रकार अपनी बीमा कम्पनियों के विश्वास पर छोड़ा गया जनता का अधिकतर पैसा उन्हीं को स्थानीय सहकारी संस्थाओं के वित्तीय प्रबन्ध में लगाया जा सकता है। फिर जनता का पैसा जमीन-जायदाद में कम-से-कम फँसना चाहिए जिससे ज्यादा पैसा साधित्र-सरंजाम, तनखाह, सेवाओं के विस्तार और दूसरे काराबारी कामों पर खर्च किया जा सके।

देश के दूसरे भागों में भी भूमि-सम्पत्ति के विकास कार्यों में लगी सहकारी संस्थाएँ कुछ इन्हीं से मिलते-जुलते तरीकों पर काम करने लगी हैं।

आज से तोस बरस पहले जब इनका जन्म हुआ था तभी से 'सहकारी' बीमा कम्पनियाँ बहुत तेजी से बढ़ती और उन्नति करती आई हैं। क्योंकि ये कम्पनियाँ बीमा करवाने वाले स्त्री-पुरुषों की आवश्यकताओं से निर्देशित और उन आवश्यकताओं का पूरा करने के ज्यादा अच्छे और नये उपायों के अन्वेषी दूरदर्शी पुरुषों से निर्देशित होती हैं। अधिकांश कम्पनियाँ १९२८-२२९ में या भन्दी के वर्षों में बड़ी अकिंचनता से, मामूली साधनों के सहारे खड़ी हुई थी वहाँ आज तेरह बिसाल सहकारी बीमा कम्पनियाँ हैं और उनका सम्पूर्ण चालू बीमा व्यवसाय ७ अरब डालर से भी अधिक होगा। सहकारी लीग ने इन कम्पनियों के काम-काज के बारे में १९५० से १९५७ तक के जो तथ्य एकत्रित किये हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

सहकारी हताहत और अग्नि बीमा कम्पनियाँ ने इन सात वर्षों में प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष प्रीमियम में ७,६५,००,००० डालर से १८,०१,००,००० डालर की वृद्धि की जबकि १९५७ में वे इस क्षेत्र में हमारे देश के कुल बीमा व्यवसाय का केवल १.५ प्रतिशत प्रीमियम प्राप्त कर रही थी। सहकारी बीमा कम्पनियों की इस १३५ प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले देश के इस क्षेत्र के कुल बीमा व्यवसाय के प्रीमियमों में केवल ७८ प्रतिशत वृद्धि हुई।

जीवन-बीमा का काम करनेवाली सहकारी कम्पनियों की प्रगति के आँकड़े तो और भी प्रभावोत्पादक हैं। १९५० में उनके पास १ अरब ७ करोड़ डालर मूल्य के बीमे थे जो १९५७ में बढ़कर ५ अरब १४ करोड़ डालर के हो गए; यह वृद्धि पाँच गुने के लगभग है। १९५७ में उनके पास देश के समस्त जीवन-बीमा व्यवसाय का केवल १.१ प्रतिशत था, लेकिन उनकी इस ३८२ प्रतिशत वृद्धि की तुलना में देश के इस क्षेत्र के कुल व्यवसाय में केवल ९९ प्रतिशत वृद्धि हुई।

इन कम्पनियों ने बीमा व्यवसाय में पालिसी धारियों को लाभ पहुँचाने वाली कई नई पद्धतियों को प्रचलन किया और अन्ध व्यापारी कम्पनियाँ को भी प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए उन पद्धतियों को अपनाना पड़ा। इस

के वर्षों में सहकारी बीमा नेताओं के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई है; वह है स्फीती के दौरान बीमा-व्यवसाय में निवेशित डालर के निरन्तर अवमूल्यन से अपने पालिसी धारियों की रक्षा की समस्या। १९५२ में नेशनवाइड इन्श्यूरेन्स ने म्युचुअल इनकम फाउण्डेशन को उसकी समस्त आस्तियों सहित खरीद लिया। इस सुस्थित निवेशकर्ता कम्पनी के माध्यम से नेशनवाइड ने अपने पालिसी धारियों के लिए सुव्यवस्थित कम्पनियों की अच्छी आय और सतत वृद्धिशोभ लाभवाली प्रतिभूतियों में अपनी बचतों को लगाने का एक बहुत ही अच्छा अवसर उपस्थित कर दिया। नेशनवाइड के विक्रेता अपने ग्राहकों के बीमा की पालिसियों के साथ-साथ म्युचुअल इनकम फाउण्डेशन के हिस्से भी बेचते हैं। १९५९ के एक ही वित्तीय वर्ष में म्युचुअल के हिस्से के पूँजीगत शुद्ध मूल्य में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। हिस्से धारियों को अपने निवेश पर ३.६ प्रतिशत लाभान्श मिला और ७.२ प्रतिशत पूँजी गत लाभ हुआ। बीमा करवाने-वालों ने इस अवसर से पूरा-पूरा लाभ उठाया; और म्युचुअल की शुद्ध आस्तियों की निधि इस एक ही वर्ष में ४९ लाख डालर से बढ़कर १ करोड़ २७ लाख डालर हो गई; ६३ लाख डालर मूल्य के हिस्से बिके और बीमा के कारबार में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई।

पालिसी धारियों की इस नई वित्तीय सेवा में नेशन वाइड इन्श्यूरेन्स की अत्यधिक सफलताओं से प्रेरित होकर सहकारी लीग ने १९५९ और १९६० में अपने निदेशक-मण्डल की कई बैठकों में काफी विचार-विमर्श के बाद व्यापक आधार वाले वित्त विनियोजन के लिए अमरीकन कोआपरेटिव्स के नाम से एक नया कार-बार शुरू करने का निश्चय किया।

सम्मिलित निवेश निधियाँ छोटे निवेशकर्ताओं के लिए तेजी से बढ़ने वाले पूँजी निवेश का बड़ा ही सुलभ और प्रिय साधन हैं। ये साधन औसत परिवार या छोटी व्यापारी संस्था को अत्यधिक सुरक्षित और एक ही साथ कई तरह की प्रतिभूतियों में अपनी बचतें लगाने का अवसर देते हैं। इसके अतिरिक्त ये निम्मलित निधियाँ सभी दृष्टियों से मूलतः विशुद्ध सहकारी संस्थाएँ हैं।

इसी से सहकारी लीग के निदेशकों के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि देश के कई सहकारी बीमा व्यवसायों की प्रवर्तकता में एक सम्मिलित निधि ही

क्यों न संगठित की जाए और क्यों न उसे सन्तुलित, वैविध्यमुखी (बहु प्रयोजनीय) और खुली निधि रखा जाए ? इसका अर्थ यह हुआ कि उस निधि के अर्द्धांश को तो उन सहकारी व्यापारों की प्रतिभूतियों में निवेशित किया जा सकेगा जिनकी निरन्तर लाभदायी निवेश के रूप में बहुत ही अच्छी ख्याति है। शेष अर्द्धांश को ऐसे वाणिज्यीय (सहकारी नहीं) व्यवसायों के सामान्य हिस्सों में निवेशित किया जायेगा जो केवल उपार्जन की ही नहीं वृद्धि और पूँजीगत लाभ देने की क्षमता भी रखते हैं। इस तरह की निधि, यदि उसका प्रबन्ध अच्छी तरह और कुशलता से किया गया, जो कि करना ही होगा, तो सभी के लिए पूँजी लगाने का सुदृढ़ और आकर्षक साधन होगी। विशेष रूप से अपनी सदस्य संस्थाओं के, जो अभी एक बार में केवल एक ही सहकारी उद्यम में पूँजी लगा सकती है, कुल निवेश के काफी बड़े अंश को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगी। सम्मिलित निधि के माध्यम से वे एक साथ कई सहकारी संस्थाओं की अलग-अलग प्रतिभूतियों में अपनी पूँजी लगा सकेगी। जहाँ अभी सहकारी सदस्य परिवारों का सहकारी व्यापारों के कुल निवेश में दो या तीन प्रतिशत भी नहीं है वहाँ इस तरह की सम्मिलित निधि चालीस या पचास प्रतिशत क्यों नहीं ला सकते ? और सामान्यतः यही तर्क सहकारी व्यवसायों के अपने अधिशेषों के निवेश पर भी जिनका काफी-कुछ अंश सहकारियों के प्रतिस्पर्द्धियों की जेबों में पहुँच गया है, लागू होता है। यदि सम्मिलित निधि सहकारी-निवेश-अभिमुखी होकर सफलता और ख्याति प्राप्त कर सकती है तो जनता की सहकारी संस्थाओं द्वारा नियन्त्रित जनता के धन के अधिशेषों को क्यों बड़े निकायों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता और जनहित में उनका इकहरे के स्थान पर द्विगुणित उपयोग भी क्यों नहीं किया जा सकता ?

इसके अतिरिक्त लीग के सलाहकारी और संचालक मण्डल इतनी अधिक पूँजी की आवश्यकता महसूस करते हैं जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। निम्न और मध्यवित्त परिवारों की आर्थिक-सहायता-प्राप्त मकानों की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में अकेले न्यूयार्क क्षेत्र में जो प्रयत्न किया गया उसकी इतनी सराहना हुई और माँग इतनी अधिक बढ़ी कि अकेले उसी क्षेत्र के लोगों और समुदायों को लाभान्वित करने के लिए करोड़ों डालरों

की आवश्यकता है। कतिपय सहकारी स्वास्थ्य योजनाओं ने चिकित्सा-व्यवस्था के निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या को हल करने और उच्च कोटि की व्यापक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं को सामान्य परिवार के लिए सुलभ करने में काफी प्रशंसनीय कार्य किया है; इसलिए इन योजनाओं की—सुस्थापित और नई दोनों ही—साधन-मुविधाओं की वृद्धि के वित्तीय प्रबन्ध के लिए भी काफी धन की आवश्यकता है। पिछली दशाब्दी में देश के सभी भागों में सौंदा खरीदने के उपभोक्ता सहकारी केन्द्र—सहकारी बाजार—काफी बड़ी संख्या में स्थापित हुए हैं। देश की वितरण-प्रणाली पर उपभोक्ताओं के स्वामीत्व को तेज। से बढ़ाते जाने का समय भी ही चला है, जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में लाखों नये परिवारों का स्वामीत्व विस्तारित किया जा सके और एकाधिकार के प्रसार को रोका जा सके।

लेकिन इन सब कार्यों के लिए इतनी अधिक पूंजी की आवश्यकता है जिसे हमारे वर्तमान सहकारी वित्तीय संगठन मिलकर भी शायद ही पूरा कर सकें।

सबसे बड़ी और तात्कालिक आवश्यकता तो अमरीकी किसानों की है। अमरीकी कृषि की उत्पादन शीलता और औद्योगिकीय दक्षता में विविध प्रकार की क्रान्तिकारी उन्नति के बावजूद उनकी आय निरन्तर गिरती जा रही है—कौन जाने उनकी आय में यह ह्रास इन नये क्रान्तिकारी परिवर्तनों के ही कारण हो! और इस हालत को सुधारने के लिए सिर्फ एक प्रस्ताव सुझाया जा सका, उसके अतिरिक्त कही से किसी ने भी कोई सुझाव नहीं दिया। और वह एक मात्र सुझाव है कृषक-स्वामी त्वकृत सहकारी संस्थाओं के कार-बार में, कार्यक्षेत्र और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से, अधिकाधिक विस्तार करते चले जाना। इसी तरीके से किसानों की आर्थिक मोल-भाव करने की अपहृत शक्ति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरीके से किसान उन उद्योगों की कुछ आय को, जो पहले कृषि से पैसा कमाया करते थे, अपनी आय में जोड़ सकते हैं। सहकारी कृषक-स्वामीत्व के अन्तर्गत एकीकरण कृषकों के उस एकीकरण से बहुत भिन्न है, जो वाणिज्यीय हित अपने पशु-खाद्य व्यवसाय की उन्नति के लिए करना चाहते हैं।

इसलिए १९५९ का अन्त होते-होते सहकारी लीग के निदेशक महन् ने

एक सम्मिलित निधि स्थापित करने के पक्ष में निर्णय कर लिया। अभिसन्धि में यह तय किया गया कि निधि खुली होगी अर्थात् जब भी कोई चाहे हिस्से खरोद सकेगा और जिस समय भी चाहे हिस्से को निधि के तात्कालिक मूल्य पर निधि को ही बेच भी सकेगा। दूसरे यह कि निधि सन्तुलित होगी, अर्द्धांश सहकारी और अन्य प्रकार की निरन्तर लाभदायी प्रतिभूतियों में निवेशित होगी और शेष अर्द्धांश दूसरे प्रकार के व्यवसायों के हिस्सों में। तीसरे यह कि निधि वैविध्य सुखी होगी, अर्थात् एक बार में किसी भी एक कम्पनी में उसकी कुल आस्तियों के पाँच प्रतिशत में अधिक नहीं लगा रहेगा।

सम्मिलित निधि की व्यवस्था और संचालन के लिए जो हामीदार और निवेश-प्रबन्धक कम्पनी बनाई जाने की थी उसके स्वामीत्व में सहभागी बनने के लिए सभी सहकारी व्यवसायों को खुला निमन्त्रण दिया गया। और जो सहकारी लोग के सदस्य नहीं थे उनमें से भी बहुतों ने इस कम्पनी में अपनी पूँजी लगाई।

सहकारी वित्त-विनियोजन—जनता की आवश्यकताओं और जनता के व्यापार में जनता का पैसा—के क्षेत्र में इस नये उद्यम का भविष्य इतनी जल्दी बता पाना तो असम्भव ही है; लेकिन यह निर्विवाद है कि आज अमरीका के सहकारी व्यवसाय के नेताओं में एक नये प्रकार की नीति-मर्मज्ञता दिखाई दे रही है; और उससे यह आशा बँधती है कि जनवाद के इस विश्व व्यापी संकट काल में सहकारिता का सिद्धान्त और आचरण अमरीकी जनता के एक भाग को मानव-इतिहास में प्रथम बार सम्भवतः यह प्रदर्शित करने की योग्यता प्रदान कर सके कि जनता के पैसे, जनता की साख और जनता की बचतों का कम-से-कम कुछ अंश तो जनता के अधिकार में रखा और जनता के लाभ के लिए उपयोग में लाया ही जा सकता है।

आरम्भ में कहा गया था कि इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि “जनता को साख का उपयोग—और दुरुपयोग भी—कैसे किया जाता है; उस साख को कैसे आधुनिक जीवन का शक्तिशाली उपकरण बनाया जाता है, और जिनकी वह साख है उन्हीं के जीवन का नियन्त्रित करने वाला हथियार भी।”

अध्याय को समाप्त करने से पहले इस विषय पर भी कुछ कह देना आवश्यक है।

इसमें जितनी भी सहकारी वित्तीय संस्थाओं की चर्चा की गई है उनमें से कोई भी हमारे देश की मुद्रा-प्रणाली के प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं है। इसलिए इस मुद्रा प्रणाली की कुछ विशिष्टताओं और खतरों का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों विशेषताएँ अपनी बचतों का और अपनी साख के उपयोग का नियन्त्रण करने वाले लोगों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देती हैं। और जहाँ तक नियन्त्रण का प्रश्न है वह तो सहकारी वित्तीय संस्थाओं के इतने महत्वपूर्ण निष्पादन के बाद भी अभी आरम्भिक अवस्था में ही है।

हमारी वर्तमान मुद्रा-प्रणाली ने हमारी आर्थिक सम्पन्नता को ऋण की निरन्तर वृद्धि का वशवर्ती बना दिया है। समुचित विकास और अधिकतम रोजगार के लिए आवश्यक रूपया हम ऋण का निरन्तर बढ़ाते रह कर ही पा सकते हैं। हमारी मुद्रा का निर्माण निजी व्यापारी बैंको के द्वारा उस समय किया जाता है जब वे कर्ज देती हैं और उस समय भी जब वे बचत-प्रत्ययों के बाहर की रकम का निवेश करती हैं। मुद्रा का निर्माण मूलतः राजकीय कार्य-व्यापार है, इसे निजी हितों के हाथ में देना बड़ी विचित्र और करीब-करीब अवैधानिक बात है; लेकिन यह परिणाम है आशिक आरक्षित कोष की उस पद्धति का जिसपर हमारी व्यापारी बैंकदारी प्रणाली चल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंको को इस बात की अनुमति है कि वे जितना रूपया लगाना और कर्ज देना चाहें उसका केवल एक अंश संचित कोष के रूप में अथवा हाजिर रख सकती हैं। बाकी वे जो भी कर्ज देती और निवेश करती हैं वह सब उधार है जिसे उन्होंने अपनी खाता बहियों में आँकड़ों की लिखा-पढ़ी करके 'बना लिया है', या कहना चाहिए कि 'गढ़ लिया है' फेडरल रिजर्व बोर्ड ने बैंकों के लिए आरक्षित कोष २० प्रतिशत से भी कम निर्धारित किया है। इससे बैंकों को यह सुविधा हो गई है कि वे हुकमी-जमा-उधारियाँ (ऐसा उधार जो माँगे जाने पर तुरत जमा किया जाए) मनचाही मात्रा में गढ़ कर ब्याज से कर्ज पर चला सकती हैं। केवल २० प्रतिशत आरक्षित निधि से बैंकों नई दर्शनी मुद्रा तुरत-फुरत गढ़कर पाँच गुने डालर तक उधार पर उठा देती हैं, मानो फेडरल रिजर्व बैंक की बहियों में नकद या उधार उनका इतने डालरों का संचित कोष दर्ज हो। इसी प्रकार जब बैंके सरकारी बाण्ड खरीदती हैं तो वे उनको

खरीदने के लिए सरकार और जनता की साख का, उधारी का, अर्थात् मुद्रा का निर्माण करने की शक्ति का उपयोग करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बैंकों को जो ब्याज मिलता है वह उनको राष्ट्र की ओर से दिया गया उपदान है। और इसका मतलब यह भी हुआ कि सरकार अपनी ही उधार पर स्वयं ब्याज चुकाती है।

१९५१ में राष्ट्रीय ऋण पर लगभग ५३ अरब डालर ब्याज हुआ था। १९५९ में वह ९ अरब डालर हो गया, जिसका एक प्रमुख कारण ब्याज की दरों में वृद्धि भी थी।

राष्ट्र ने मुद्रा-निर्माण का अपना अधिकार यों हस्तान्तरित कर दिया है इसलिए ऐसा माना जाता है कि स्वयं उसे उस अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिए। वह स्वयं तो ऐसा कभी नहीं करता; लेकिन जब फेडरल रिजर्व बैंक बैंक-प्रदत्त उधार का नया सचित्त कोष गढ़ती है तो कुछ-कुछ ऐसा आभास होता है मानो राष्ट्र अपने हस्तान्तरित अधिकार का उपयोग कर रहा हो। इसका कारण यह है कि सभी फेडरल रिजर्व बैंक निजी कम्पनियों के स्वामीत्व की होते हुए भी उन पर कुछ अंशों में तो कांग्रेस और कार्यपालिका के द्वारा राष्ट्र का सार्वजनिक-नियन्त्रण रहता ही है। जब तक फेडरल रिजर्व बोर्ड और बैंक यह स्वीकार करती रहेगी कि वे मुद्रा के निर्माण और नियन्त्रण के मूलतः सार्वजनिक एवं राजकीय कार्य को कर रही हैं तब तक ऋण की निरन्तर वृद्धि वाली चिरकालिक समस्या के अतिरिक्त इस प्रणाली के ठीक-ठाक चलते रहने की सम्भावना है।

लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि आरक्षित कोष वाली पद्धति जनता के हित में काम करे न कि निजी ऋण दाता और महाजनी संस्थाओं के हित में।

फेडरल रिजर्व बोर्ड ने ऐसा इक्की-दुक्की बार किया है लेकिन उतना ही काफी नहीं है, उसे ऐसा अधिक बार करना चाहिए।

यह बात किसी भी तरह समझ में नहीं आती कि ऋण बढ़ा कर मुद्रा प्राप्त करने वाली पद्धति पर निर्भर करके हम यथोचित विकास, अधिकतम रोजगार और मूल्यों का स्थिरीकरण कैसे कर सकते हैं? ऋण की बढ़ती ही वह मूल्य है जिसे चुका कर आवश्यक मुद्रा का निर्माण किया जाए और तब कहीं जाकर

आर्थिक विकास हो। इस तरह जो कृत्रिम मुद्रा अस्तित्व में आती है वह ऋण के कम होते ही सहसा गायब भी हो जाती है। और इस बीच संयुक्त राज्य की सरकार विवश होकर अपनी ही उधार जमा पर स्वयं ब्याज देती रहेगी।

समय का तकाजा है कि इस पद्धति में कुछ परिवर्तन किये जाएँ।

अर्थ व्यवस्था में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और मूल्यों की यथोचित स्थिरता को बनाये रखने के लिए पर्याप्त नई मुद्रा—लेकिन पर्याप्त से जरा भी ज्यादा नहीं—अपने कार्यों से और कर्ज के परिमाण को बढ़ाये बिना समय-समय पर स्वयं निर्माण करने का उत्तरदायित्व संयुक्त राज्य की सरकार को ग्रहण करना चाहिए।

जिस अनुपात में सरकार मुद्रा-निर्माण के अपने उचित कर्त्तव्य को पूरा करे उसी अनुपात में निजी व्यापारों बैंकों की मुद्रा-निर्माण करने की शक्ति कम कर दी जानी चाहिए।

इस तरह की वैज्ञानिक मुद्रा-प्रणाली से ही हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ऋण के पर्वताकार बोझ को क्रमशः घटाया जा सकेगा। इस प्रणाली का अवलम्बन करके ही मुद्रा को स्फोति अथवा अव स्फोति की सार्थक ढग से रोका जा सकेगा। आर्थिक समस्याएँ केवल आर्थिक नहीं राजनीतिक भी होती हैं और राजनीतिक समस्याओं पर विचार करना इस पुस्तक का अभीष्ट नहीं है। परन्तु एक नागरिक के नाते तो वे हमारी चिन्ता और चिन्तन का विषय हैं ही।

१० | उपभोक्ताओं की संगठित क्रय-शक्ति

इस पुस्तक में हमने जितने भी प्रकार के सहकारी उद्यमों की चर्चा की है वे या तो उपभोक्ता सहकारी हैं अथवा 'उपयोक्ता' सहकारी। किसानों की विक्रय सहकारी सस्थाओं के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। किसानों को अपनी फसले सहेज कर रखने की सुविधाओं और उन्हें व्यवस्थित ढंग से बेचने का प्रबन्ध करने वाली संस्था की आवश्यकता होती है। विक्रय सहकारी सस्थाएँ ठीक यही सेवाएँ प्रदान करती हैं और किसान उनका उपभोग या उपयोग करते हैं।

यदि इसे शब्दों की खीचा-तानी समझा जाए तो यह खीचा-तानी केवल विक्रय सहकारी सस्था के ही सम्बन्ध में सच हो सकती है। सहकारी स्वास्थ्य योजनाएँ उन जन-समूहों को स्वास्थ्य-परिचर्या प्रदान करने के लिए संगठित की जाती हैं जिन्हें इस तरह की परिचर्या की आवश्यकता है और जो उसका उपभोग करते हैं। गृह-निर्माता सहकारी सस्थाएँ मकानों के उपभोक्ताओं के द्वारा बनाई जाती हैं और वे ही उनके स्वामी होते हैं। विद्युत् सहकारी सस्थाएँ ग्रामीण जनता के उपभोग के लिए बिजली प्रस्तुत करते हैं; यदि ये विद्युत् सहकारी न होते तो ग्रामीण जनता आज भी बिजली की उपभोक्ता न बन पाती। फ़ारम-आपूर्ति सहकारों तो विशेषतः ऐसे उत्पादनों का सम्भरण करने वाली सहकारी सस्थाएँ हैं जिनका किसानों को अधिकाधिक मात्रा में उपभोग करना चाहिए ताकि वे अपने कृषि-सम्बन्धी कार्यों को दक्षतापूर्वक कर सकें। साख-संच ऐसी उपभोक्ता सहकारी सस्थाएँ हैं जो अपने सदस्यों की ऋण और साख-सम्बन्धी माँगों को पूरा करती हैं। सहकारी बीमा कम्पनियों का उद्देश्य बीमा सेवाओं के उपभोक्ताओं को इस योग्य बनाना है कि वे अपनी बचतों का प्रभावशाली नियन्त्रण स्वयं कर सकें। विभिन्न प्रकार की उधार-सुविधाएँ प्रदान करने वाली फ़ारम उधार प्रणाली के किसान उपभोक्ता हैं। पेट्रोलियम सहकारी

पेट्रोल-विनिर्मित वस्तुओं के उपभोक्ताओं के हितों में चलाई जाने वाली और उन्हीं के स्वामीत्व की स्थापना है, फिर वे उपभोक्ता ट्रेडर के लिए प्रचुर आवश्यकता वाले किसान हों या अकेली मोटर गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहने वाले नगरवासी हों। यहाँ तक कि स्वतन्त्र फुटकर विक्रेताओं के थोक सहकारी भी अपने सदस्यों को थोक माल और थोक की सेवाएँ प्रदान करते हैं और उनके सदस्य उस माल और उन सेवाओं का अपने व्यापार के दौरान में उपयोग करते हैं।

इसलिए यह अध्याय 'उपभोक्ता' सहकारी संस्थाओं के बारे में नहीं है। उनके बारे में पिछले अध्यायों में जितना कहा गया है उतना ही इस अध्याय में भी है।

लेकिन यह अध्याय उन सहकारी संस्थाओं के बारे में अवश्य है जिनका विचार 'उपभोक्ता सहकारी' शब्दों के बोले जाते ही अधिकांश लोगों के मन में घूम जाता है।

वे हैं सहकारी खाद्य स्टोर्स, वृहद् भण्डार (सुपर मार्केट्स) और सौदा खरीदने के केन्द्र यानी सहकारी बाजार।

'उपभोक्ता सहकारी' शब्दों के साथ मन में इनका विचार आना असंगत भी नहीं है। क्योंकि औसत परिवार अपनी आय का ४० प्रतिशत भोजन पर खर्च करता है। उपभोक्ता के नाते जनता की सबसे अधिक और एकमुखी रुचि खाद्य-भण्डार में या उसके इर्द-गिर्द ही होता है। उपभोक्ता के नाते जनता की संगठित क्रयशक्ति का कुछ प्रभाव तो अर्थ व्यवस्था पर पड़ता ही है, चाहे वह क्रयशक्ति तेल, स्वास्थ्य-परिचर्या, वचत और उधार आदि किसी भी व्यापार में क्यों न हो।

लेकिन किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर सहकारी उद्गम का पूरा प्रभाव केवल तभी अनुभव किया जा सकता है जब जनता की बड़ी-बड़ी आवश्यकताओं को सहकारी ढंग से पूरा किया जाए, जब जनता अपने बड़े खर्चों वाली आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यवसायों की स्वामी बने। 'उपभोक्ता अधिमान्यता' का केवल तभी कुछ अर्थ हो सकता है। और केवल तभी अत्यधिक दृढ़ता से संगठित उत्पादकों के उद्दण्ड बल के विरुद्ध श्रेयस्कर प्रतिकूलित शक्ति के रूप में उपभोक्ता के हित का दावा और समर्थन किया जा सकता है।

कुछ देशों में यह हुआ भी है। स्कैण्डिनेविया, स्विट्जरलैण्ड और आस्ट्रिया इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी और हालैंड के नाम भी गिनाये जा सकते हैं। स्वीडन में कुछ विनिर्माण का ४ प्रतिशत और कुल राष्ट्रीय व्यापार का १७ प्रतिशत सहकारी सगठनों द्वारा किया जाता है। वहाँ का राष्ट्र अपना ३० प्रतिशत से भी अधिक भोजन सहकारी भण्डारी से खरीदता है। आरम्भकालीन उपभोक्ता-स्वामीत्व कृत भण्डार केवल किराने माल का काम करते थे। उसके बाद उपभोक्ताओं द्वारा प्रमुख उपभोक्ता हित का सहकारी स्वामित्व में व्यापक सगठन किया गया। इस आधार पर घर-गिरस्ती की आवश्यकताओं, कपड़े-लतों, साधित्र-सरजामों आदि को आपूर्ति का व्यापक उपभोक्ता समर्थन व्यापार खड़ा हुआ। और अन्त में विनिर्माण इसका अत्यन्त स्वाभाविक परिणाम हुआ।

बोतबो गताब्दी के आरम्भ काल में स्वीडन में विद्युत् प्रदाय, जूते, आटा आदि कई व्यवसायों में जबर्दस्त इज्जतदारियाँ थीं। आज वहाँ इस तरह के व्यवसायों में कोई एकाधिकार नहीं है। इसका यह कारण नहीं कि सरकार को 'न्यायविनाशक' कदम उठाने पड़े। नहीं, स्वीडन में न्याय-विरोधी कानून ही नहीं है।

वहाँ उनकी जरूरत ही नहीं हुई। क्योंकि वहाँ सहकारी सगठन राष्ट्र का ४ प्रतिशत विनिर्माण करते हैं और आवश्यकता हुई या उचित समझा गया तो वे ४४ प्रतिशत भी कर सकते हैं।

सहकारिता के आधार पर अधिकांश विनिर्माण को आपरातिवा फोर बुन्देत नाम का राष्ट्रीय सहकारा थोक सगठन करता है। स्वीडन को फुटकर विक्री का उपभोक्ता सहकारा सस्थाएँ इस सगठन का स्वामी हैं। पुकारने को सुविधा के लिए लोगों ने आपरातिवा का 'के' और फोर बुन्देत का 'एफ' लेकर इतका संक्षिप्त नाम बना लिया है 'केएफ या कोफा'। कोफा ने विनिर्माण इसलिए आरम्भ किया क्योंकि स्वीडनी जनता के अर्द्धांश से भी अधिक को क्रयशक्ति उनको अपने सहकारा सस्थाओं में सगठित कर ली गई थी। उपभोक्ताओं के आर्थिक हित को रक्षा करना अब इन सहकारी सस्थाओं का काम था। इसलिए जब यह बात सामने आई कि उपभोक्ताओं को कुछ वस्तुओं के बड़े महँगे दाम देने पड़ते हैं, क्योंकि एकाधिकारियों या अर्द्ध एकाधिकारियों ने उनके

मूल्यों को 'व्यवस्थापित' कर रखा है तो कोफा के नेताओं ने इस दिशा में कुछ करने को ठाना।

वे जो करना चाहते थे उसका नकशा बिल्कुल साफ था। इजारेदारियों से प्रतिस्पर्द्धा करो जिसमें वे एकाधिकारी बनें ही न रह सकें और उन्हें अपने उत्पादनों का कोमते मन चाहे 'व्यवस्थापन' से नहीं, बाजार की प्रतियोगिता से निर्धारित करना पड़े।

इसलिए कोफा ने बिजली के लट्टू बनाने का काम शुरू किया और उनके दाम चालीस प्रतिशत कम हो गए। फिर कोफा ने ऊपरी जूते (ऑवर शू) बनाना शुरू किया, जो स्वाइन की प्राथमिक आवश्यकता है। और ऊपरी जूतों को कामते भी ग्राहकों के लिए लाभकारी स्तर तक घट गई। आटे और कुछ दूसरे वस्तुओं के सम्बन्ध में भी ठोक यही बात हुई।

इस तरह का काम सहकारी ही कर सकते हैं। जहाँ व्यवसाय के दूसरे प्रकार मजबूती से जमे हुए एकाधिकार को चुनौती नहीं दे सकते वहाँ सहकारी, यदि उनके सदस्यों की संख्या काफी बड़ी है तो इस काम को बखूबी कर सकते हैं। क्योंकि सदस्यों की काफी अधिक संख्या रहने पर उन्हें अपने विनिर्मित माल को खपत की चिन्ता नहीं रहती—उनका बाजार सुनिश्चित रहता है।

यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि यदि ऐसी बात है तो स्वीडनी सहकारी सगठन ने अपने विनिर्माण कारखानों को चार प्रतिशत से आगे क्यों नहीं बढ़ाया, वही क्यों रुक गए ? वे इसलिए रुक गए कि उपभोक्ता के रूप में सारे राष्ट्र के आर्थिक हितों का सार्थक सुरक्षा के लिए उन्हें उसने आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने जितना किया उतना ही काफी था।

कोआपरातिवा फोरबुन्देत ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि यदि जनता को करना ही पड़े तो वह अपने कारखानों में विनिर्माण और उत्पादन कर सकती है और पूरी सफलता से अत्यन्त शक्तिशाली एकाधिकारों से प्रतियोगिता भी कर सकती है और मूल्यों में उचित स्तर तक कमी भी।

इतना कर लेने के बाद, बहुत ऊँची कोमते वसूल करने वाले उद्योगपतियों के मन पर सगठित उपभोक्ताओं का आतंक जमाने के लिए कोफा के निदेशक-

मण्डल का किसी नई वस्तु के विनिर्माण को आरम्भ करने के प्रश्न पर केवल विचार करने के लिए अपनी बैठक आयोजित करना और लोगों को उसकी भनक पड़ जाना ही काफी है।

लेकिन ऐसा केवल तभी सम्भव हुआ जब आरम्भ में जनता की बड़ी उपभोग्य क्रय-वस्तु-भोजन-खरीदने की शक्ति का स्वीडन के गाँवों, कस्बों और नगरों में सहकारी स्वामीत्वकृत खाद्य भण्डारों में व्यापक सगठन कर लिया गया।

स्वीडन और इंग्लैण्ड के उपभोक्ता सहकारियों का अन्तर पाठकों के लिए रुचिकर होगा। १९६० आरम्भ हुआ तब भी स्वीडनी सहकारी सगठन काफी अच्छी प्रगति करते जा रहे थे। सहकारिता से जीवन-मानों को उन्नत करने में आर्थिक दृष्टि से अविकसित देशों के निवासियों की सहायतार्थ वहाँ ऐच्छिक चन्दे के रूप में काफी बड़ी-बड़ी रकमें इकट्ठी की जा रही हैं। स्वीडनी जीवन, विचार और नीति पर सहकारी आन्दोलन का प्रभाव भी कम नहीं है। इन पक्तियों के लेखक ने एक बार एक स्वीडनी सहकारी नेता से पूछा था कि क्या आपका सगठन कोआपरातिवा फोरबुन्देत स्वीडनी आम चुनावों में हस्ताक्षेप का प्रयत्न करता है ? उन्होंने तपाक से उत्तर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वीडन में सहकारी आन्दोलन एकदम 'अराजनैतिक' है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब भी जन-नीति-सम्बन्धी कोई प्रश्न उपस्थित होता है हम अपने अनुसन्धान विभाग को काम पर लगा देते हैं और उपभोक्ता के रूप में जनता के हिताहित से उस नीति के सम्बन्धों पर प्रतिवेदन तैयार करवा कर प्रसारित कर दिया जाता है। ऐसे प्रतिवेदनों का हमारी सरकार पर काफी प्रभाव पड़ता है।

इसके विपरीत इंग्लैण्ड का सहकारी आन्दोलन कटु वाद-विवाद और सुस्थापित निर्णयों की खीचातानी में पड़ा हुआ है। वहाँ की सहकारी संस्थाएँ कमजोर होती जा रही हैं। उनका व्यापार निरन्तर घटता जा रहा है। जन-नीति पर उनका प्रभाव कुछ भी नहीं है।

इस अन्तर का कारण क्या है ? स्वीडनी सहकारी आन्दोलन को विनिर्माण क्यों और कैसे शुरू करना पड़ा यह हम देख आये हैं। एकाधिकार द्वारा नियन्त्रित कुछ वस्तुओं के अधिमूल्यन को समाप्त करने के लिए उन्होंने विनिर्माण

आरम्भ किया था। यह बात तो साफ है कि इससे केवल सहकारी सदस्यों का ही नहीं सारी जनता को लाभ हुआ। और यही दृष्टिकोण स्वीडन के सभी उपभोक्ता सहकारियों द्वारा अपनाया गया। वे अपने सदस्यों की संरक्षण-धन वापसियों की बड़ी रकम चुकाने की इतनी चिन्ता नहीं करते जितनी इस बात की कि सदस्यों और सभी स्वीडनासियों को लाभ पहुँचाने के लिए देश के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित किया जाय; और उनका सारा प्रयत्न इसपर केन्द्रित होता है।

यह प्रयत्न सहकारी क्षेत्रों में 'सक्रिय मूल्य नीति' के नाम से जाना जाता है।

इसका अर्थ यह हुआ कि सहकारी संस्थाएँ अपना माल चालू बाजार भाव पर तभी बेचती हैं जब उन मूल्यों का औचित्य अर्थ नीति-संगत हो। लेकिन ठोस आर्थिक संगतियों से यदि वे कीमते ऊँची पाई गईं तो सहकारी संस्थाएँ उन्हें घटा देती हैं। इस प्रकार, संरक्षण-धन-वापसी की मोटी रकम देकर केवल सदस्यों को ही लाभान्वित करने के स्थान पर सहकारी संस्थाओं द्वारा सदस्यों और संरक्षकों को मुख्य लाभ न्यून मूल्यों के रूप में विक्री में दिया जाता है। इसका प्रभाव दूसरे प्रतिस्पर्द्धियों पर भी पड़ता है और उन्हें भी कीमते घटानी पड़ती है। और यों समस्त स्वीडनी उपभोक्ताओं को लाभ होता है।

इंग्लैण्ड में ठीक इसकी विरोधी नीति का अवलम्बन किया जाता है। वह है चालू बाजार भाव पर ही बेचने की परम्परागत 'रोगडेल' नीति और संरक्षण-धन वापसी, या जैसा कि इंग्लैण्ड में इसका नाम है, 'दिवी', की राशि पर, जो सहकारी सदस्यों का प्राप्तव्य है, बहुत अधिक जोर दिया जाता है। वस्तुओं की लागत और बाजार भाव में अन्तर कितना ही क्यों न रहे ब्रिटिश सहकारी संस्थाएँ हमेशा चालू बाजार भाव पर ही माल बेचती हैं और उनी अनुपात में 'दिवी' की राशि बढ़ा देती हैं। इससे सहकारी सदस्यों की सारी रुचि, और सो भी बहुत जोरों से, लाभांश पर केन्द्रित हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि ब्रिटिश सहकारी संस्थाएँ अपने देश की अर्थ-व्यवस्था की मूल्य-संरचना को जरा भी प्रभावित नहीं कर पाती। इसीलिए तो इंग्लैण्ड में स्वीडन की तरह यह नहीं कहा जा सकता कि सहकारी आन्दोलन द्वारा प्रसारित प्रतिवेदनों का 'बहुत अधिक प्रभाव' पड़ता है। स्कैंडिनेविया

का भी शायद यही कारण है। यदि वहाँ के सहकारी सगठन और व्यक्ति गहरी निष्ठा और सक्रिय अभिरुचि को प्रशसनीय गुण समझते हैं और चाहते हैं कि उनके सदस्यों में ये गुण हा तो पारस्परिक सहायता और सहकारिता के व्यापक आदर्शों को उन्हें सही अर्थों में व्यावहारिक रूप देना चाहिए।

औसत अमरोको तो अभी तक भी उपभोक्ता सहकारियों के बारे में कुछ नहीं जानता। इसका स्पष्ट कारण यह है कि बढ़ते हुए नगरों में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अभी सहकारी भण्डार और वृहद् भण्डार (सुपर-मार्केट्स) इतनी अधिक सख्या में नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति इससे भिन्न है। वहाँ तो कई प्रकार की सहकारी सस्थाएँ हैं, जो अमरोकी ग्रामीण जीवन का अविभाज्य अंग बन गई हैं।

जो प्रवृत्तियाँ १९५० के बाद की दशाब्दी में आरम्भ हुई थी वे यदि चलती रही तो बहुत शायद अमरोका का नगरवासो भी अपने देहाती भाई की तरह उपभोक्ता सहकारियों से अभिन्न हो जाएगा।

वास्तव में आज इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज उपभोक्ता के रूप में अमरोकावासियों को अपना एक पक्षपोषक चाहिए। न्यास-विरोधी कानूनों का शायद ही कभी उपयोग किया गया है—खास कर बड़े अपराधियों के खिलाफ तो कभी भी नहीं किया गया। उपभोक्ता-हितों की रक्षा के लिए जो तथाकथित 'नियामक' आयोग बनाये गए थे उनमें, १९५० के बाद वाली दशाब्दी में, उन्हीं उद्योगों के प्रतिनिधियों को भर दिया गया जिनके नियमन की उनसे आशा की जाती है।

टेलीविजन के हर पर्दे से चमक कर, रेडियो के हर बक्से से चीत्कार कर और सभी समाचार पत्रों एवं पत्र-पत्रिकाओं से बहक-फुसला कर आज उपभोक्ताओं को जेब, मनोबल और मानसिक शक्ति पर जो चतुर्दिक आक्रमण हो रहे हैं उनको तुलना में किसी पक्षपोषक या समर्थक का न होना तो बहुत ही मामूली समस्या है।

कोई भी विचारशील व्यक्ति अमरोकन उद्योग की उपलब्धियों की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। बड़े पैमाने पर उत्पादन अपनाकर इस उद्योग ने पारिवारिक बजट को पहुँच में ऐसे साधित्र और साधन सुलभ कर दिये हैं जिनसे

जीवन के दैनन्दिन कार्यों और विशेष रूप से गिरस्ती के कमरनोड धन्धों में समय और शक्ति की काफी वचत हो जाती है।

इससे नारी सार्वजनिक क्षेत्र सहित जीवन के दूसरे नभी क्षेत्रों में सक्रिय भाग लेने के लिए आज जितनी स्वतन्त्र हो गई है उतनी मानव-इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हो पाई थी। इसका परिणाम होना चाहिए था ज्यादा अच्छी सम्यता, ज्यादा ऊँची संस्कृति और भरा-पूरा, आध्यात्मिक जीवन।

लेकिन वास्तविकता यह है कि अति आधुनिक भवन बनाये जाते हैं और उनमें पुस्तकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती।

और दूसरी बात यह कि बड़े पैमाने के उत्पादन को कोई खास बढ़ावा भी नहीं दिया जाता।

फिर सबसे बड़ी बात तो यह कि हमें इन न्यामतों के लिए कर्ज लेना चाहिए। और छोटे कर्ज का इलाज हमें यह बताया जाता है कि बड़ा कर्ज गले लगा लो- बिना यह पूछे कि शर्तें क्या हैं और बिना यह पता लगाये कि व्याज की दर क्या है; बस, आँख मूँद कर ले ही लो।

१९६० के आते-आते इस सवने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया और अंशांश ऋण पर कुछ छिपे खर्च इतने बढ़ा दिये गए, उदाहरण के लिए मोटर को अशाश उधार कि इलिनोइस के मोनेटर डगलस को इस आगय का एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा कि ऐसी सभी भड़कोली उधार व्यवस्थाओं में वार्षिक व्याज को वास्तविक दरों का ईमानदारी से खुलासा करना आवश्यक होना चाहिए। इस विधेयक के प्रबल समर्थक थे श्रमिक सघ, सहकारी सस्थाएँ, साख-सघ और महिलाओं के संगठन। लेकिन ज्यादातर वाणिज्यीय हितों ने इसका विरोध किया, जो स्वाभाविक भी था, क्योंकि अधिकांश वे ही तो थे जो माल की बिक्री को अपेक्षा उस बिक्री के वित्तीय प्रबन्ध में से अनाप-शनाप पैसा पीट रहे थे।

१९५० के बाद के वर्षों में हमसे यह कहा गया कि हमारा देश 'बहुत गरीब' है इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा के लिए यथेष्ट स्कूली इमारतें नहीं बना सकता और न शिक्षकों को ठीक ढग का वेतन ही दे सकता है। हमारा राष्ट्र 'बहुत गरीब' है इसलिए हम अपने जल स्रोतों के प्रदूषण और वायु के संदूषण को नहीं

रोक सकते। हम 'बहुत गरीब' हैं इसलिए गन्दी बस्तियों के उन्मूलन और अपने नगरों के पुनर्वास के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा सकते !

लेकिन हमारा अर्थ व्यवस्था को तेजी को बनाये रखने के लिए उपभोक्ताओं को जितनी ज्यादा हो सके विलास प्रियता को अपनाना और अपने कर्ज के बोझ को बढ़ाते जाना होगा। क्योंकि उपभोक्ताओं के क्रमशः बढ़ते हुए कर्जों और सैनिक खर्चों के बहुत बड़े परिमाण पर ही तो उत्पादक कम्पनियों के उस माल की खपत निर्भर करती है जिसे वे बाजार में अन्धाधुन्ध फेकते रहना चाहते हैं। और किन चीजों का उत्पादन किया जाए इसका निश्चय भी बड़े उत्पादकों के निर्णय से होता है, उपभोक्ताओं की अधिमान्यता, उनकी माँग और आवश्यकता से नहीं। 'वाल स्ट्रीट जनरल' ने विक्रो-व्यवस्था के एक प्रमुख विशेषज्ञ के मन्तव्य को यों उद्धृत किया था : "विक्रो-व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं का यह हल आवश्यक नहीं कि उपभोक्ता जो चाहें वह उन्हें दे दिया जाए, बल्कि सच्चा हल यह है कि जो हम, विक्रो व्यवस्थापक, चाहें, उपभोक्ता भी उसी को चाहें।"

इधर के वर्षों में इस सिद्धान्त का परम आस्था से पालन करने वाला एक बिलकुल नया व्यवसाय ही चल पड़ा है। यह 'अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धान' नाम का नया समाज शास्त्र है। इन अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धाताओं ने स्तम्भित करने वाली एक जवर्दस्त खोज की है। उनकी उस खोज के अनुसार मनुष्य स्वभाव से अवम, पतित और स्वार्थी जीव है। उसे विलास की ओर प्रवृत्त करना होता है और इसी तरह उसको ईर्ष्या, अहंकार, तृष्णा, प्रदर्शन-च्छा, लोभ, लिप्सा, आत्म प्रेम आदि की पुष्टि करके चीजों की खरीदारी की ओर। लोग बापुयान में समय बचाने और अधिक लोगों से सम्पर्क करने के लिए सवार नहीं होते; वे सवार होते हैं न चढ़ पाने वालों की आत्म ग्लानि से अपने अह को सन्बोधित करने के एकान्त उद्देश्य से। अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धाताओं का तो कम-से-कम यही विचार है। और ऐसे ही धुरन्धरों और उनके चले-चपारों को अमरीकी उद्योग प्रति वर्ष बारह अरब डालर की रकम सौंप देता है सिर्फ इसलिए कि वे उनकी अभीष्ट 'अपीलों' को प्रभावकारी बना सकें। लेकिन मानव स्वभाव के बारे में उनकी यह खोज कोई नयी बात नहीं है।

पुरातन धर्म ग्रन्थ (ओल्ड टेस्टामेण्ट) के रचयिताओं ने आज से चार हजार वर्ष पहले ठीक यही बात कही थी। लेकिन उन्होंने इसको भर्त्सना की थी और, इसे इसलिए बदलने पर जोर दिया था कि कही भगवान का कोप सारी मनुष्य जाति पर ही न उतर पड़े।

लेकिन आज हमे एक सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है।

अभी कुछ ही समय हुआ गिकागो को एक वचन सस्थाने अपने रेडियो विज्ञान को बदल कर इन तरह कर दिया है - “वचन का खयाल आप का, ‘पछियों के लिए’ नेक और दुस्त है समाज की निगाह मे। वचन आप की हमारे पास, आपके अपने मोज-शोक को ज्यादा चीजों का बढ़िया खुदगर्ज तरीका है।”

अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धाताओं को इस स्तम्भित करने वाले खोज में कि उच्च अभिप्रेरकों को अपेक्षा मनुष्य को निम्न अभिप्रेरकों के माध्यम से अधिक सरलता से अभ्यर्थित किया जा सकता है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन महान जातियों और महान समाजों ने सदैव अपने नागरिकों को उच्च अभिप्रेरकों को ही बढ़ावा देने का प्रयत्न किया और असूजनशील समाज विरोधी अभिप्रेरकों को नियंत्रण में रखने का। जब अहंकार, मिथ्यादर्प और अहम्यता की हर भावना और स्वार्थपरता के हर आवेग को विकसित करना समाज का स्वीकृत प्रतिमान बन जाता है तो किसी भी उच्च राष्ट्रीय उद्देश्य की ग्राह्यता के लिए उस समाज के लोगों को उद्वुद्ध करना वास्तव में ही कठिन हो जाता है।

हमारी अर्थ व्यवस्था में उपभोक्ताओं के महत्त्व पर किताबें लिखी जा रही हैं; और अनेक ‘उच्च जीवन स्तर’ पर भी लिखी जा रही हैं। लेकिन ‘उपभोक्ता अधिमान्यता’ पर कोई एक शब्द भी नहीं कहता। वह तो लुप्त ही होता जा रहा है। बड़ी कम्पनियाँ जितनी ही बड़ी होती जाती हैं और छोटी की आत्मसात् या विलीनित करती जाती हैं और छोटी मरती जाती हैं, उपभोक्ताओं को उतने ही जोर से यह आदेश सुनाया जाता है कि वे “राष्ट्र व्यापी स्तर पर विज्ञापित छापा और ठप्पा वाली चीजें ही खरीदें।” लेकिन इस तथ्य की ओर तो शायद ही कभी ध्यान दिलाया जाता है कि ऐसा करके उपभोक्ता सभी स्वतन्त्र छोटे व्यापारी की अशामयिक मृत्यु और सभी मूल उद्योगों में छाई हुई

मुट्ठी-भर विशाल कम्पनियों के हाथों में हमारी अर्थ व्यवस्था का अन्तिम नियन्त्रण सुनिश्चित कर देगे।

टेलीवीजन उद्योग में लगे लोग प्रायः इस बात की ओर इशारा करते रहते हैं कि राष्ट्रव्यापी टेलीविजन विज्ञापन का सारा काम सिर्फ बीस कम्पनियाँ बड़ी खूबी से संभाल सकती हैं। तो “राष्ट्रव्यापी स्तर पर विज्ञापित छापो और ठप्पो वाली चीजों” को खरीदने का अर्थ हुआ उन बीस में से कभी इस या कभी उस कम्पनी को प्रश्रय देना।

लेकिन खाद्य भण्डारों के कारोबार में अवश्य ही जबर्दस्त प्रतियोगिता दिखाई देती है। कम-से-कम फुटकर बिक्री के स्तर पर तो हालत यही मालूम पड़ती है। पशुधन, फल और सब्जी बाजारों पर अवश्य बड़ी-बड़ी दुकान श्रृंखलाओं का एक छत्र साम्राज्य है; वहाँ कीमतें वे ही तय करती हैं और प्रायः विशेष सुविधाएँ भी प्राप्त कर लेती हैं। परन्तु खाद्य-व्यापार की फुटकर बिक्री में प्रतियोगिता से अभी तो गृहिणियाँ ही लाभान्वित होती दिखाई दे रही हैं।

जानकारों का ऐसा स्थाल है कि हवा के रुख को देखते तो वे दिन दूर नहीं लगते जब खाद्य-व्यापार की फुटकर बिक्री पर भी मुट्ठी-भर कम्पनियों का नियन्त्रण हो जायगा। और उनमें नियन्त्रण होते ही रोटी और सेम-सब्जी का भी ‘व्यवस्थापित मूल्यन’ शुरू हो जाएगा।

सुपर मार्केट उद्योग के सुप्रसिद्ध अग्रवर्ती राष्ट्रीय नेता मिस्टर आर० जी० जिफरमैन ने १९५६ के बोस्टन वितरण-सम्मेलन में सच ही कहा था:

“वर्तमान प्रवृत्तियों के हमारे अध्ययन का यदि कोई अर्थ हो सकता है तो हमें यही भविष्य दिखाई देता है कि दस या बीस बरसों में खाद्य-पदार्थों की फुटकर बिक्री का व्यवसाय बहुत ही थोड़े हाथों में सिमटकर रह जाएगा। १९६५ तक खाद्य-व्यापार के ७५ प्रतिशत पर गिने-चुने विशालतम सुपर मार्केट संगठनों का नियन्त्रण सर्वथा अकल्पनीय बात नहीं है।”

‘व्यवस्थापित मूल्यन’ का उपभोक्ताओं की समस्या को विषम करने में कितना बड़ा हाथ होता है यह एक इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाए कि यदि तथाकथित ‘स्वाभाविक’ आर्थिक प्रभावों को अपना काम करते रहने का अवसर

दिया जाता तो १९५० के बाद की दशाब्दी में मूल्यों का जो स्फीतीकरण हुआ वह कदापि न होता। हमारी अर्थ-व्यवस्था का प्रतिस्पर्द्धी क्षेत्र १९५३ से १९५८ के बीच हुई मूल्य वृद्धि के केवल एक प्रतिशत का उत्तरदायी है। लेकिन उन वर्षों में उपभोक्ताओं के रूप में उन उद्योगों और सारे ही राष्ट्र पर थोक विक्री के मूल्य के सूचकांक में ८ प्रतिशत समग्र वृद्धि का बोझ लाद दिया गया। इस वृद्धि के ८५ प्रतिशत की जिम्मेवारी कीमतों में 'व्यवस्थापित मूल्यन' से बढ़ोतरी करने वाले एकाधिकारी उद्योगों पर है।

हमारी अर्थप्रणाली में उपभोक्ताओं के हितों के प्रभावी स्वत्वद्योतन का मार्ग भी अवश्य है। और ऐसा उपाय भी है जिसका अवलम्बन करके न केवल वस्तुओं के मूल्य और विस्म के सम्बन्ध में बल्कि इस सम्बन्ध में भी कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, 'उपभोक्ता अधिमान्यता' को फिर से अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है।

वह उपाय है उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को संगठित करना, जिससे वे सम्मिलित रूप से अपना दावा पेश कर सकें और जिससे उस दावे का पूरा-पूरा वजन पड़े। और वह उपाय है स्वयं उपभोक्ताओं को उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले कुछ व्यवसायों के स्वामीत्व के योग्य बनाना और इस प्रकार सार्थक प्रतियोगिता के द्वारा उपभोक्ता-हितों को प्रवर्तित करना।

लेकिन यह काम आसान नहीं है। विशेषकर उपभोक्ता के खर्च के सबसे बड़े क्षेत्र, खाद्य-व्यवसाय में तो बहुत ही कठिन है। क्योंकि आज उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिला पाना मुश्किल ही है कि उन्हें अधिकाधिक खाद्य-भण्डारों और सुपर मार्केटों की आवश्यकता है। कई बार तो ऐसा लगता है मानो उनकी भरमार हो गई है। हालत उन दूसरे बहुत-से क्षेत्रों की तरह तो नहीं ही है जहाँ सहकारी सस्थाएँ सफल हुईं। जब तक आवश्यकता प्रस्तो ने अपनी सहकारी सस्थाएँ नहीं बना डाली ग्रामीण विद्युत् का क्षेत्र करीब-करीब खाली ही पड़ा था। यही बात खुले सूत्रवाले उच्च विश्लेषणयुक्त उर्वरक के बारे में भी है। औसत परिवार जिनका मूल्य आसानी से चुका सके ऐसे अच्छे और सस्ते मकानों की निर्माण योजनाएँ भी तो अभी बहुत ज्यादा नहीं हैं। उच्चकोटि की स्वास्थ्य-परिचर्या या सुविधाओं का भी यही हाल है। इस तरह के और भी

कई नाम गिनाये जा सकते हैं।

लेकिन खाद्य भण्डार ऐसी आवश्यकता नहीं है जिसका अभाव अमरीकी उपभोक्ता को खलता हो। १९७५ के आस पास सम्भवतः यह स्थिति हो जाए, आज तो नहीं है।

अमरीकी सहकारी आन्दोलन द्वारा उपभोक्ता सहकारी भण्डार की स्थापना की कहानी काफी हानि उठाने और अनेक मर्मघात सहने की कहानी है।

हमें इन बात की सही-सही जानकारी नहीं है कि संयुक्त राज्य अमरीका में किराना माल का पहला उपभोक्ता सहकारी भण्डार कब स्थापित हुआ था।

सहकारिता का जो इतिहास उपलब्ध है उसके अनुसार वह १८४४ से पहले तो बन नहीं सकता; क्योंकि उसी वर्ष रोशडेल (इंग्लैण्ड) के उन अट्ठाइस गरीब बुनकारों के अपार कष्ट, आँसू और पसीने और वर्षों की बचत में से पहले सच्चे उपभोक्ता सहकारी का जन्म हुआ था।

पहले अमरीकी उपभोक्ता सहकारी भण्डार का जन्म भी उसके बहुत बाद का नहीं होना चाहिए; यद्यपि कोई विवरण नहीं मिलता, हो सकता है कि खो गया हो, पर अनुमान किया जाता है कि पहला अमरीकी उपभोक्ता सहकारी भण्डार १८४४ के दो-चार वर्षों बाद ही कहीं स्थापित हुआ होगा।

१८७१ में लेकर १८९० तक की दो दशाब्दियों के बारे में हमारा ज्ञान अधिक निश्चयात्मक है। य वर्ष बड़े मैदान के निवासियों के लिए घोर सकट के थे और उनमें मुक्ति पाने के लिए ग्रैंगर आन्दोलन के तत्त्वावधान में वहाँ सहकारी सगठनों की एक लहर-सी चल पड़ी थी। इन सगठनों के बारे में सबसे ज़ातक बात यह है कि उनमें से कई कार्य विधि की दृष्टि से वर्तमान शताब्दी के सहकारी 'जनरल स्टोर' की तरह के सहकारी उपभोक्ता भण्डार और फार्म आपूर्ति सहकारी संस्थाएँ थीं। उनका उद्देश्य बड़े मैदान के किसान परिवारों की कम कीमत पर दैनन्दिन जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। उस समय के ग्रैंगर-संस्थापित सहकारियों में का एक इस समय भी कनसास राज्य के कैडमस में कारवार कर रहा है।

भौगोलिक विस्तार के वर्षों में, जबकि बस्ती पश्चिम की ओर बढ़ती जा रही थी और औद्योगिक उन्नति और विकास के वर्षों में सारी अमरीकी जनता

का ध्यान उत्पादन पर केन्द्रित रहा। बीसवीं शताब्दी के मध्यकाल तक यही स्थिति रही। यह सच है कि कहीं-कहीं किसी इक्के-दुक्के आदर्शवादी गुट ने उपभोक्ताओं की सहकारिता की दिशा में भी अवश्य यत्न किये, लेकिन जनता की विचारधारा का सारा प्रवाह और प्रयत्नों का सारा जोर उत्पादन से अपनी आय में वृद्धि करने की ही ओर रहा। अपने कमाये हुए डालरों से उपभोक्ता के रूप में ज्यादा अच्छा काम लेने की ओर लोगों का ध्यान बहुत ही कम गया।

यही कारण है कि दूसरे प्रकार के उपभोक्ता सहकारियों से एकदम भिन्न उपभोक्ता सहकारी खाद्य भण्डारों का इतिहास ठेठ द्वितीय महायुद्ध के परवर्ती काल तक निरन्तर असफलताओं और भग्न आशाओं का इतिहास रहा है।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में कुछ श्रमिक संघों ने, खासतौर पर खनि श्रमिक संघ (Mine Workers) ने अपने सदस्यों के लिए उपभोक्ता सहकारी भण्डार स्थापित करने का प्रयत्न किया। लेकिन वे भण्डार चल नहीं पाये; क्योंकि हेतु कितना ही उदार और आशय कितना ही उच्च क्यों न हो दूसरी सस्थाओं द्वारा जनता के लिए स्थापित सहकारी सस्थाएँ कभी सफल नहीं होती। जिन सहकारी सस्थाओं को जनसमूह स्वयं अपने उपयोग के लिए स्थापित करते हैं केवल उन्हीं की सफलता को अधिक सम्भावनाएँ होती हैं। खनि श्रमिक संघ ने जब अपने सदस्यों से कहा, “यह तुम्हारा भण्डार है इसका पोषण-संवर्द्धन करो;” तो सब लोग लगे उस दान की वछिया के मुँह फाड़-फाड़कर दाँत गिनने; और खनिकों की पत्नियाँ ने तो थन भी टटोल डाले! और उन्होंने हर बार यही पाया कि सारा कारबार बड़े ही घटिया किस्म का है और जो आदमी प्रबन्धक बना बैठा है उसको एकमात्र योग्यता केवल इतनी है कि वह संगठित श्रमिकों से सहानुभूति रखता है!

१९४० के बाद वाली दशाब्दी में डेट्रोइट में भी ठीक यही प्रयोग दुहराया गया, जिसका बहुत ही खेदजनक परिणाम हुआ। पुराने खेबे के श्रमिक नेता खाद्य-भण्डार के ढग की उपभोक्ता सहकारी सस्था के इतने प्रतिकूल हो गए कि उन भण्डारों को संयुक्त राज्य अमरीका में श्रमिकों का वह समर्थन नहीं मिल पाया जो पश्चिमी यूरोप के श्रमिक संघों से बराबर मिलता आ रहा था।

बड़ी मन्दी के वर्षों में सहकारिता के प्रति, जो कई रूपों में अभिव्यक्त हो

रही थी, लोगो का नये सिरे से षचि लेना अनिवार्य हो गया। सहकारी लीग के प्रमुख सस्थापक जेम्स पीटर बारवेस की पुस्तके अधिकाधिक पढ़ी जाने लगी। उपभोक्ताओं की सहकारिता का विचार लोगो के मन में घर करता चला गया। इस विचार के उत्साही समर्थक 'खरीदार क्लब' के सदस्यों को किराना माल देने के लिए अपने गैराज—बेशक मोटरों से खाली—देने लगे। कैलिफोर्निया में बेकारों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं उत्पादन करने के योग्य बनाने वाली अप्टनसिकल्लर की महाकाव्योचित रम्य, रोचक और भव्य योजना की १९३४ में पराजय के बाद, पहली बार कई समुदायों के लोग अपनी वर्तमान आर्थिक स्थितियों को सुधारने के आशास्पद उपाय के रूप में उपभोक्ता सहकारियों के संगठन की ओर उन्मुख होने लगे। लेकिन पूँजी इन उद्यमियों के पास प्रायः होती नहीं थी। साधारणतः किसी बेकार को व्यवस्थापक बनाकर बिठा दिया जाता था। इसलिए इनमें से कोई भी ज्यादा दिन चल नहीं पाया।

लेकिन असफलताओं के इस दौर में कुछ अपवाद भी अवश्य थे। उत्तरी यूरोप से आकर जो लोग अमरीका में अपने समुदाय बनाकर बस गए थे वे अपने साथ 'पुराने देश' से सहकारी सफलता की परम्परा भी लेते आये थे। विशेषकर स्कैंडिनेवियाई और फिन लोगों में यह परम्परा काफी पुष्ट थी। न्यू इंग्लैण्ड के कुछ समुदायों में, कैलिफोर्निया के खाड़ी वाले प्रदेश में, लेक सुपीरियर के हेड आफ दि लेक्स क्षेत्र में और कुछ दूसरे स्थानों में बीसवीं शताब्दी के शुरू के वर्षों में ठोस आधार वाले सुदृढ़ उपभोक्ता सहकारी भण्डार स्थापित किये गए जो आज भी धीरे-धीरे उन्नति करते जा रहे हैं। न्यू कोआपरेटिव कम्पनी हमारे देश के सबसे पुराने उपभोक्ता-वस्तु सहकारी भण्डारों में से है; यह १९०८ में दक्षिण-पूर्वी ओहियो में चैक किसानों और चैक खनिकों द्वारा स्थापित की गई थी।

१९३९ में यूरोप में युद्ध आरम्भ होने के साथ-साथ कहते दुःखः होता है कि—जो आर्थिक सम्पन्नता आई उस समय देश में उपभोक्ता खाद्य भण्डारों की सहकारिता का एक अस्त-व्यस्त-सा आधार अवश्य था।

दूसरे महायुद्ध के काल को हम खाद्य-भण्डार आन्दोलन में आत्म-प्रवचना का युग कह सकते हैं। इस काल में कई उपभोक्ता सहकारी भण्डार संगठित

किये गए। पहले से स्थापित क्षेत्रीय थोक फारम आपूर्ति सहकारियों में से भी कइयो ने किराना माल का कामकाज शुरू कर दिया। उनका और नेशनल कोआपरेटिव का, जो बहुतसी चीजों का केन्द्रीय सम्भरण कर्ता है, व्यापार फूलता-फलता दिखाई देने लगा। लेकिन किसी ने भी यह समझने की कोशिश नहीं की कि लड़ाई के जमाने में जब उपभोक्ता-वस्तुओं की तंगी हो जाती है; किसी भी प्रकार का व्यापार फलता-फूलता ही दीखता है। और इस तथ्य की ओर तो शायद ही किसी का ध्यान जा पाया कि खाद्य-पदार्थों की बिक्री करने वाला दूसरा बहुत-सी कम्पनियों के मुकाबले सहकारी बहुत-ही कम उन्नति कर पा रहे थे। ओछी पूँजी की जीर्ण बीमारी तो थी ही और प्रबन्ध बिल्कुल काम चलाऊ ढंग का। सारी कतर-ब्योत भण्डारों की साज-सज्जा में ही की जाती थी। इसलिए असफलताओं का दूसरा दौर बस आरम्भ होने को ही था।

इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि इस दौर की सबसे बड़ी असफलता ऊपर बताई गई कमजोरियों को दूर करने के प्रयत्न स्वरूप ही हुई। शिकागो में, सहकारी भण्डारों में रुचि रखने वालों से नगर व्यापी पैमाने पर, पूँजी उगा-हने और प्रबन्ध की समुचित देखरेख एवं केन्द्रीय प्रशासन-व्यवस्था के अन्तर्गत भण्डारों की एक श्रृंखला स्थापित करने की दिशा में अभियान आरम्भ किया गया। इस प्रयत्न में तो कोई खराबी नहीं थी। सच पूछा जाए तो बीमारी का इलाज भी यही था। लेकिन कमजोरी यह रही कि देखरेख की व्यवस्था को ठीक से विकसित नहीं किया जा सका। भण्डार के व्यवस्थापक इसके लिए बनाई गई योजना को पूरा करने में असमर्थ रहे। भण्डारों के लिए स्थान के चुनाव और उनकी साज-सज्जा पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे स्थानों में भण्डार आरम्भ करने की जल्दबाजी की गई जहाँ पास-पड़ोस के परिवारों ने हिस्सों में पूँजी लगा कर भण्डारों में अपनी रुचि और उत्सुकता अभी दिखाई भी नहीं थी। इस सब के परिणामस्वरूप कुछ ही महीनों में सारा प्रयत्न एकदम व्यर्थ हो गया और पूरी योजना भहरा कर गिर पड़ी।

इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के तत्काल बाद के वर्ष उपभोक्ता सहकारी खाद्य भण्डारों की असफलता के दूसरे दौर के वर्ष सिद्ध हुए। मिडिलवेस्ट के कई क्षेत्रीय थोक सहकारी संगठनों ने किराना माल के कारबार को बन्द कर

दिया। और १९५० के लगते-लगते असफलता के महासागर में सफलता के कुछ ही द्वीप डूबते-उतराते बचे रह सके।

१९५१ में सहकारी लोग ने उपभोक्ता सहकारी खाद्य भण्डारी के व्यवस्थापकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। उस सम्मेलन के विचार-विनिमय और चर्चा का मुख्य विषय यह था कि जिन सहकारियों का व्यापार निरन्तर गिरता जा रहा है उन्हें बन्द होने से कैसे बचाया जा सकता है। इस बात का बड़ी बारीकी से पता लगाया गया कि इन पिछले दुःखदाई वर्षों में असफलता किन-किन कारणों से हुई। इस छानबीन में सफलता के कारणों का भी साथ ही माथ पता चल गया और यह भी मालूम हो गया कि सफलता के लिए क्या करना चाहिए।

तब से उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के व्यवस्थापकों का सम्मेलन प्रतिवर्ष होता आ रहा है। १९५९ में व्यवस्थापकों के एक ऐसे ही सम्मेलन में उपभोक्ता सहकारी व्यवस्थापक सघ (Consumer Cooperative Managers Association) की स्थापना की गई। इस सघ में सबसे बड़े और सबसे सफल सुपर मार्केटों और बाजार-केन्द्रों के, जिनकी सख्या आजकल तेजी से बढ़ती जा रही है, व्यवस्थापकों की प्रधानता है। ऐसे व्यवस्थापकों और उनके निदेशक-मण्डलों में यह आत्म विश्वास स्पष्ट हो परिलक्षित होता है कि वे अपने व्यापार में राष्ट्र व्यापी शृंखलाओं सहित किसी भी व्यापारी सगठन से मुकाबला कर सकते हैं।

इन प्रयत्नों का परिणाम क्या हुआ ?

उपभोक्ता सहकारी खाद्य भण्डार और उपभोक्ता बाजार केन्द्रों का आन्दोलन उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। इसने एक नितान्त आवश्यक बुनियादी सबक सीखा। वह सबक है : एक अच्छा विचार ही काफी नहीं होता। यहाँ तक कि मनुष्य को सबसे महान नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं में आरोपित श्रेष्ठ क्रान्तिकारी आदर्श भी अपने-आप में अकेला किसी व्यापारी उद्यम की सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकता। वे विचार और आदर्श किसी भी व्यापारी उद्यम के लिए अनमोल सम्पदा तो अवश्य हैं लेकिन स्वतः उनमें प्रतिफलन की क्षमता नहीं होती। अकेले तो वे पल्लवित और पुष्पित भी नहीं हो सकते। उन्हें आवश्यकता होती है प्रबन्ध कुशलता, समुचित पूँजी, बड़े पैमाने

पर कारबार करते रहने के लिए निवेश के माध्यम से काफी परिवारों की निश्चित सहभागिता और अच्छे स्थानों में आकर्षक साज-सज्जा वाले ऐसे अधिष्ठान जो प्रतियोगियों से घटिया तो कदापि न हों। इतने सब के संयुक्त हो जाने पर भी ही किसी व्यापारी उद्यम की निरन्तर प्रगति और विकास सुनिश्चित हो पाती है।

उदाहरणार्थ :

१९४८-१९४९ के आसपास जीवन-निर्वाह के मूल्यों में तेजी से जो वृद्धि होती जा रही थी उसे रोकने के श्रमिक संघों के प्रयत्न भी पराकाष्ठा पर थे। इन प्रयत्नों में कुछ वैसी ही गलतियाँ दुहराई गईं जो पहले महायुद्ध के समय की गई थी। लेकिन सारे विश्व के रबर उद्योग की राजधानी, ओहियो राज्य के अक्रोन नगर के युनाइटेड रबर वर्क्स आफ अमरीका के सदस्य अपना सबक बहुत अच्छी तरह सीख चुके थे। उन्हें एक उपभोक्ता सहकारी भण्डार की अत्यन्त आवश्यकता थी; लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो चलता रहे, चार दिन चल कर बन्द न हो जाए। वे जानते थे कि यदि उनका भण्डार अक्रोन के बढ़िया-से-बढ़िया भण्डार की टक्कर का न हुआ तो चल नहीं सकेगा। इसके लिए पूँजी की जरूरत थी—दो लाख डालर के आसपास तो होने ही चाहिए। वे यह भी जानते थे कि मूल पूँजी उगाहने का सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है। जो परिवार नये सहकारी भण्डार के सदस्य, स्वामी और ग्राहक बनने वाले थे उन्हें हिस्से बेचकर पूँजी इकट्ठी कर ली जाए। लेकिन डेट्रोइट क्षेत्र के अनुभवों से वे यह सीख चुके थे कि केवल श्रमिक संघ के सदस्यों की आम दिलचस्पी ही काफी नहीं होती। उनकी पत्नियों को भी उदघाटन और शुभारम्भ से पहले सहकारी भण्डार का महत्त्व समझाना आवश्यक था। श्रमिक संघ के नेताओं और सदस्यों की आगेवानी में अक्रोन के निवासियों ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। जब तक वे बस्ती के परिवारों में सवा लाख डालर के हिस्से नहीं बेच लेंगे भण्डार खोलने का नाम न लेंगे। यह साधारण नहीं, बहुत बड़ा काम था, क्योंकि उन्हें दस-दस डालर मूल्य के हिस्से एक-एक कर बेचने थे।

लेकिन उन्होंने इस काम को कर डाला।

स्वयंसेवकों ने इस काम को किया। पूरा साल भर वे स्थापित किये जाने वाले सहकारी भण्डार के बारे में लोगों को समझाते-बुझाते और स्त्री-पुरुषों को

दस, बीस या कभी-कभी पचास डालर के हिस्से लेकर उसका स्वामी बनने के लिए राजी करते रहे।

जब सवा लाख डालर का सकल्प पूरा होने को आया तो उन्होंने स्थानीय श्रमिक सर्वों के हाथ अधिमानित हिस्से बेचना शुरू कर दिया। इस तरह एक लाख डालर और जमा हो गया। लेकिन अब ये सवा दो लाख डालर भी काफी नहीं थे, क्योंकि नये सिरे से प्राक्कलन करके आवश्यक पूँजी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा ली गई थी, इसलिए उन्होंने नेशन वाइड इन्ड्यूस्ट्रियल कम्पनीज से काफी मोटी रकम कर्ज लेना का निश्चय किया।

और जब कर्ज मंजूर हो गया केवल तभी सगठन कर्ताओं ने अपना सुपर मार्केट खोलने की ओर निश्चित कदम उठाये।

आखिर कोआपरेटिव एण्टर प्राइजेज आफ अक्रोन के नाम से उनका भण्डार खुल गया और खुलते ही खूब धड़ल्ले से व्यापार होने लगा। कारबार उस पहले दिन से आज तक बराबर बढ़ता जा रहा है। मूल भण्डार ही इतना अच्छा था कि हर सदस्य को उस पर नाज हो सकता था। व्यवस्थापक जन्म जात प्रोत्सायक था और स्थान के चुनाव एवं साज-सज्जा के बारे में उसे किसी के आगे आँखें झुकाने की जरूरत नहीं थी। इस कम्पनी को अपनी परेशानियाँ न हो सो बात नहीं, दूसरे सफल सहकारी भण्डारों-जैसी दक्षता भी नहीं है, लेकिन बावजूद इस सब के बराबर उन्नति होती जा रही है। अब यह कम्पनी पाँच भण्डार चलाती है; और इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण कि एक नये उपभोक्ता सहकारी भण्डार को शुरू करने का सही तरीका क्या है।

ग्रीन वेल्ड कंज्यूमर्स सर्विसेज सयुक्त राज्य अमरीका का सबसे बड़ा सहकारी सुपर मार्केट है। १९६० मे इस सहकारी ने वाशिंगटन डी० सी० क्षेत्र में अपना दसवाँ केन्द्र खोला है। इसका कुल वार्षिक व्यापार दो करोड़ डालर के आस-पास पहुँच गया है। यों ग्रीनवेल्ड है तो स्थानीय सस्या, परन्तु अखिल देशीय स्तर पर सभी बड़ी ऋखलाओं सहित समस्त फुटकर बिक्री खाद्य भण्डारों मे अपनी सदस्यता वाला यह सबसे बड़ा चौथा सगठन है। ग्रीनवेल्ड के व्यवस्थापक सैम्युअल एफ० ऐंशेलमैन सहकारी व्यवसाय के सबसे बढ़िया और सदैव असन्तुष्ट रहने वाले व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व मे ग्रीन वेल्ड के सुयोग्य प्रबन्धक

इल ने कारबार को नये समुदायों में विस्तारित करने, नये भण्डार खोलने, उन्हें पहले ही दिन से सफल बनाने और सेवा की उत्कृष्टता पर सदस्यता को बढ़ाते जाने के बड़े सफल ढंग विकसित कर लिये हैं। ग्रीनवेल्ट ने सुनियोजित, अडिग, ऊर्जस्व गति से निरन्तर प्रगति और विस्तार करते जाने का अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया है। इसने दिखा दिया कि उपभोक्ता सहकारी व्यापार को भी महानगरी के बाजार का काफी बड़ा और महत्वपूर्ण अंग बनाया जा सकता है। निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर होते हुए, कुछ अंशों में सहकारी लीग के भी प्रयत्नों के फलस्वरूप, रोशडेल कोआपरेटिव्स का इसके साथ विलयन हो गया। आज ग्रीनवेल्ट क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति थोक सहकारी संस्था, सर्दन स्टेड्स कोआपरेटिव्स के पेट्रोल-उत्पादनों की सबसे बड़ी ग्राहक है। इसके सदस्यों की सख्या इतनी अधिक हो गई है कि जनवादी नियन्त्रण के लिए नितान्त आवश्यक सदस्यों की वार्षिक सभा आयोजित की ही नहीं जा सकती; इसलिए सारे सदस्यों का मण्डली में विभाजन कर मण्डल-संगठनों के आधार पर 'काप्रेस' प्रणाली और प्रतिनिधि सरकार का ढंग निकाला गया जो काफी सफल रहा। 'काप्रेस' प्रणाली का मूल विचार स्वीडन की कञ्जूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी आफ स्टॉक होम से लिया गया है। ग्रीन वेल्ट केवल विचार ही लेकर रह गया हो सो बात नहीं, वह आइसलैण्ड के सहकारी संगठनों से मास, डेनमार्क के सहकारियों से फरनीचर और यहाँ तक कि पोलैण्ड से शूकरमांस भी आयात करता है।

यदि यह सब वार्शिगटन में किया जा सकता है तो दूसरी जगह क्यों नहीं किया जा सकता ?

देश के उस पार सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के क्षेत्र में वास्तव में ऐसी प्रगति हो भी रही है।

वहाँ वर्कले की कञ्जूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी इन सब कामों को कर रही है। इसके सुयोग्य व्यवस्थापक युगीन मनीला के पास एक अनमोल निधि है, वह है उनका सदस्य-कार्यशीलता-कार्यक्रम, जो संयुक्त राज्य की किसी भी सहकारी संस्था के इस तरह के कार्यक्रमों में सम्भवतः सर्वश्रेष्ठ है। विशिष्ट वार्षिक सभाओं में नये सदस्यों का स्वागत किया जाता है और उन्हें सदस्यों

के लाभ के लिए सस्था जो बहुत से कार्य करती है उनकी जानकारी दी जाती है। इस कार्यक्रम, सुदक्ष प्रगतिशील सेवाओं और ग्राहको-सदस्यों में अच्छी प्रतिष्ठा के कारण वर्कले ने केवल तीन वर्ष की छोटी-सी अवधि में अपनी क्षमता को एक से चार भण्डारों तक बढ़ा लिया; और कारोबार एवं सदस्य-संख्या तो इससे भी कम समय में दुगुनी हो गई। अपने काम के विस्तार के सम्बन्ध में वर्कले की नीति प्रादेशिक मर्यादाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके निदेशक-मण्डल की नीति यह है कि जहाँ भी निम्नलिखित शर्तें पूरी की जा सकें वही भण्डार खोल देना चाहिए :

- १—समुदाय कारवार को पाँच हजार परिवारों तक बढ़ा ले जाने की क्षमता वाला हो।
 - २—कम-से-कम पच सौ परिवार पचास हजार डालर सहकारी सस्था के हिस्सों में लगाने को तैयार हों।
 - ३—ये पाँच सौ परिवार साल-भर में सदस्यता और पूँजी को हुना करन अर्थात् पाँच सौ नये सदस्य और पचास हजार डालर लगाने का बचन दें और उसे पूरा करें।
 - ४—समुदाय सस्था के सबसे पुराने भण्डार से पच्चीस मील के अन्दर-अन्दर हो। यह उल्लेखनीय है कि पच्चीस मील के घेरे में घनी जन संख्या वाली सैन-फ्रांसिस्को खाड़ी का पूरा क्षेत्रफल आ जाता है।
- यहाँ से कुछ ही मील दक्षिण में पालो आल्टो की कञ्जूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी भी अमरीकी सहकारिता आन्दोलन के इतिहास में ठीक ऐसा ही अध्याय लिख रही है। इसका कार्य क्षेत्र सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग के पश्चिम में अवस्थित वह प्रायद्वीप है जो इन दिनों बहुत तेजी से अपना विकास और उन्नति कर रही है।

१९६० के जुलाई महीने में सहकारी लीग के पत्र 'इकानामिक बुलेटिन' (आर्थिक विवरणिका) ने दस लाख डालर या इससे अधिक का कारवार करने वाले सहकारी सुपर मार्केट्स का वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया था। उस सर्वेक्षण का एक अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है; जिससे उपभोक्ता की सहकारिता के इन प्राथमिक संगठनों की राष्ट्र व्यापी उन्नति और विकास की

पूरी तसवीर सामने आ जाती है।

‘बुलेटिन’ का वह उद्धरण इस प्रकार है

१९५६ के बाद से चार और सहकारी सुपर मार्केटों ने दस लाख डालर की वार्षिक बिक्री सीमा को पार कर लिया है। प्रमुख उपभोक्ता सहकारियों से सम्बन्धित हमारे इस वर्ष के प्रतिवेदन में इन चारों का नाम प्रथम बार समाविष्ट किया जा रहा है। चार ऐसे सहकारियों का नाम भी इसमें और जोड़ लिया गया है जिनकी वार्षिक बिक्री दस लाख डालर के आसपास पहुँच रही है; ये चारों अपने-अपने क्षेत्र के प्रमुख सहकारी संगठन हैं। इस प्रकार अब कुल संख्या ३३ हो जाती है।

इन सहकारियों की उन्नति काफी प्रभावोत्पादक है। १९५३ में ७४,००० सदस्य थे, जो १९५६ में १,३६,००० हो गए; इस प्रकार सदस्यता में ८४ प्रतिशत वृद्धि हुई। सात वर्षों में (१९५३ से १९५६ जोड़कर) ६०,३३,००० डालर संरक्षण धन वापसियाँ अदा की गईं। एक १९५४ के अपसर्पण को छोड़कर हर वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा सदस्यों को अधिक राशि दी गई। आज इस उद्योग में जैसी कड़ी प्रतियोगिता है उसे देखते हुए यह काफी महत्वपूर्ण है।

बिक्री में दुगुने से भी अधिक वृद्धि हुई। १९५३ में बिक्री ४,१७,७६,००० डालर थी, १९५६ में वह ८,६२,०६,००० डालर हो गई; इस प्रकार १०६ प्रतिशत वृद्धि रही। इन छह वर्षों में केवल एक सहकारी की सदस्यता में कमी हुई, जो बहुत मामूली है; यह संस्था फारमों के बीच काम करती है और वहाँ की जनसंख्या निरन्तर कम होती जा रही है। दो संस्थाओं की बिक्री में कमी हुई; ये दोनों भी फारमों के बीच काम करती हैं। इनमें से एक ने नया केन्द्र शुरू किया है, इसलिए इस वर्ष बिक्री बढ़ने की आशा है।

यह प्रगति तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यदि सारे उद्योग से इन सहकारियों के कार्य-चालन की तुलना की जाए तो वह और भी महत्वपूर्ण है। चार को छोड़कर बाकी सभी संस्थाएँ अपने सुपर मार्केट चलाती हैं, और इन सभी की बिक्री का मुख्य साधन सुपर मार्केट ही है। निम्न तालिका में संयुक्त राज्य के सभी सुपर मार्केटों के बिक्री पर शुद्ध लाभ से सहकारियों की बिक्री पर शुद्ध वचत से तुलना की गई है। प्रतिशत शुद्ध वचतें बिक्री की हैं और करो से पहले के शुद्ध अन्तर या चलन अनुपात को मूल इकाई माना गया है।

करोँ से पहले के शुद्ध अन्तर

वर्ष	सुपर मार्केटों सहित		(शुद्ध लाभ बिक्री के प्रतिशत रूप में)
	सभी ३३ सहकारी	२० सहकारी	संयुक्त राज्य के सभी सुपर मार्केट
१९५३	२.१६	२.१५	—
१९५४	१.६८	१.६८	२.४६
१९५५	२.१७	२.१६	२.५६
१९५६	२.२८	२.२७	२.१३
१९५७	२.३२	२.४५	२.२६
१९५८	२.२५	२.३२	२.२०
१९५९	२.३३	२.३९	२.३०

इस सस्थाओं में से कुछ और भी हैं जिनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना आवश्यक है। शिकागो की हाईड पार्क सहकारी समिति शहर का सबसे बड़ा सुपर मार्केट चलाती है। यह शिकागो के मिश्रित जातियों वाले साउथसाइड के हाईडपार्क-केनवुड पुनर्विकास क्षेत्र के मध्य में एक विलकुल नये बाजार के अन्दर है। हाईडपार्क सहकारी समिति के व्यवस्थापक वाकर सैंडबेल्स व्यावहारिक आदर्शवादी, यदि किसी आदर्शवादी के लिए यह विशेषण प्रयुक्त किया जा सके, व्यक्ति हैं और यह सस्था सही अर्थों में सामुदायिक सस्था है। इसने सतत परिश्रम से यह प्रतिष्ठा और मान्यता अर्जित की है। इसकी स्थापना शिकागो विश्वविद्यालय के आसपास रहने वाले परिवार-समूहों ने की थी, जिनमें सीनेटर पाल एफ० डगलस भी थे, जो उन दिनों शिकागो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। आज साउथ साइड के कोई छः हजार परिवार इसके स्वामी हैं। यह केवल नगर के अभिमान की सुदृक्ष व्यापारी सस्था ही नहीं है, परन्तु साउथ साइड के सभी उल्लेखनीय सामुदायिक उपक्रमों और जनकल्याण-कार्यों की प्रबल समर्थक और परिपोषक भी है। इसके वेतन भोगी कर्मचारियों में दुनिया के सभी राष्ट्रों और सभी जातियों के लोग हैं।

हाईडपार्क सहकारी समिति को नये बाजार में सुपर मार्केट के लिए जगह का पट्टा देने का जवर्दस्त विरोध किया गया। लेकिन सामुदायिक आप्रह उससे कही शक्तिशाली सिद्ध हुआ। क्योंकि एक तो अडोम-पडोस के रहने वाले हजारों परिवार पहले से इसके स्वामी थे, दूसरे यह अन्यत्रवार्मी स्वामियों का व्यवसाय नहीं था और न आगे कभी हो सकता था और तीसरे उम क्षेत्र में इसकी जड़े इतनी गहरी थी कि वहाँ से हटने या कारबार समेटने की बात भी नहीं सोची जा सकती थी, फिर इसे पट्टा देने से किस विरते पर इनकार किया जाता।

कुछ इसी तरह की बातें, लेकिन विलकुल ही भिन्न प्रकार के समुदाय में, विसकोन्सिन राज्य में यू क्लेअर की उपभोक्ता सहकारी समिति को अद्भुत सफलता का कारण हुई। इसके सदस्यों में आधे तो आमपाम के देहाती क्षेत्र के किसान परिवार हैं और आधे नगरवासी, जिनमें से अधिकतर यूक्लेअर के प्रमुख उद्योग, टायर फैक्ट्रियों, में काम करते हैं। सस्था के व्यवस्थापक रैथीसेन पन्द्रह मिनट का दैनिक रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। यह सहकारी अपने

सदस्या के चेक ही नहीं भुनाती इस सुविधा के लिए उन्हें कुछ शुल्क भी देती है। और इस सस्था का साख-सघ नगर की सबसे शक्तिशाली और उपयोगी महाजनी सस्था है।

जब लोग अपने जीवन की एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए साथ मिल कर पूँजी लगाना और व्यापार करना सीख लेते हैं तो दूसरी आवश्यक-ताओं को पूरा करने के लिए इसी ढंग को अपनाना उनके लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।

१९५० तक न्यूयार्क सिटी उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की दृष्टि से निरा रेगिस्तान था। उसके बाद एक-एक करके सहकारी गृह निर्माण योजनाएँ गन्दी बस्तियों का उन्मूलन कर वही अच्छे मुहल्लों और आदर्श पास-पड़ोस का निर्माण कर सम्मिलित स्वामियों को अपने निजी घरों में पूरी सफलता के साथ बसाती चली गई। सहकारिता ने इन परिवारों की सबसे बड़ी आर्थिक माँग—मकानों का आवश्यकता को पूरा किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन सहकारी गृह निर्माण योजनाओं में उपभोक्ता सहकारी भण्डार संगठित किये जाने लगे। पहले इस तरह के कई प्रयत्न असफल हो चुके थे, लेकिन इस बार के ये प्रयत्न सफल हुए। और एक समय वह भी आयेगा जब 'सहकारी भण्डारों का रेगिस्तान' न्यूयार्क अमरीका का सहकारी गृह-निर्माण योजनाओं की राजधानी ही नहीं दूसरे अनेक प्रकार के उपभोक्ता सहकारी उद्यमों की राजधानी भी होगा।

कृषि में सहकारिता की शक्ति का केन्द्र है क्षेत्रीय थोक और निर्माता सहकारी सस्थाएँ। इन थोक सस्थाओं पर स्थानीय अथवा जिला फुटकर विक्रता सहकारी सस्थाएँ अनेक प्रकार की सहायता के लिए निर्भर होती हैं। एक अपवाद के अतिरिक्त, उपभोक्ता सहकारी सुपर मार्केट आन्दोलन की शक्ति निहित होती है फुटकर विक्रता सहकारी सस्थाओं में और थोक सहकारी अधिकतर उनके लिए माल खरीदने वाली संस्थाएँ होती हैं।

उस अपवाद का कोई खास महत्त्व नहीं है। लेक सुपीरियर के चारों ओर का इलाका—उत्तरी मिन्नेसोटा, विसकोन्सिन और मिचीगन का ऊपरी प्राय-द्वीप—सेण्ट्रल कोआपरेटिव इनकारपोरेशन का कार्य क्षेत्र है। इसके मुख्य गोदाम और प्रधान कार्यालय विसकोन्सिन के सुपीरियर नगर में है। १९१७ में इसकी

स्थापना मुख्यतः फिन आप्रवासियों ने की थी, तब से इतका इतिहास बड़ा लम्बा और वैविध्यपूर्ण रहा है। यह अपनी सदस्य सहकारी सस्थाओं को, जो इसकी स्वामी भी हैं, कृषि उपयोगी और उपभोक्ता वस्तुएँ दोनों ही प्रकार के माल का सम्भरण करता है। दो सौ से भी अधिक फुटकर विक्रेता सहकारी सस्थाएँ इसकी सदस्य हैं; ये सब छोटे भण्डार हैं और आर्थिक दृष्टि से विभिन्न धुर उत्तरी देहातों के छोटे-छोटे समुदायों की सेवा करते हैं। लेकिन जे० वाल्डेमेर कोस्की के थोक के प्रधान व्यवस्थापक बनाये जाते ही इस क्षेत्र में उपभोक्ता सह-कारिता की भूमिका एक नया रूप ग्रहण करने लगी। वह नया रूप है 'क्षेत्रीय विकास'। पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का अध्ययन और पर्यवेक्षण किया गया। उसके बाद खूब अच्छी तरह सोच-विचार कर यह तय किया गया कि पूरी तरह अधुनातन सुपर मार्केट की स्थापना किस जगह करना उचित रहेगा। निर्णय हो चुकने के बाद थोक संगठन स्थानीय सहकारी के साथ मिल कर उन स्थानों में सुपर मार्केट की स्थापना करता है। सभी सुपर मार्केटों की इमारतें, साज-सज्जा और फर्नीचर भी एक-सा ही रखने पर जोर दिया जाता है। विशेष आग्रह इस बात का रहता है कि सहकारी सेवा-संस्थाएँ सज-धज में भी अपने टक्कर की एक ही हों। व्यवस्था, प्रबन्ध-कौशल और कार्यकर्ताओं की शिक्षा के पाठ्यक्रम होते हैं। कुछ पुराने सहकारी नेताओं को इस सब का महत्त्व समझने में काफी समय लगा। शुरू में वे इन सब कामों को बकवास समझते रहे। लेकिन १९६० के आरम्भ में जब सारे क्षेत्र का सबसे सुन्दर, सबसे चित्ताकर्षक भण्डार मिन्नेसोटा के क्लोकेट नगर में उस क्षेत्र की सबसे पुरानी सहकारी सस्था ने खोला और पहले ही दिन घडल्ले से कारबार चल निकला और बिक्री निरन्तर बढ़ता ही गई तो अनुदार-से-अनुदार पुराने नेताओं की आँखें खुल गई और नये तौर-तरीकों का महत्त्व तुरंत उनकी समझ में आ गया।

सेण्ट्रल काआपरेटिक्स इनकारपोरेशन के सहकारी अपने प्रदेश का लग-भग ५ प्रतिशत खाद्य-भण्डार सम्बन्धी कारबार करने हैं। आगामी वर्षों में इसके १० प्रतिशत—१५ प्रतिशत भी हो सकता है—तक हो जाने की आशा है। उस समय उपभोक्ता के हित का—बाजार पर जनता की संगठित क्रय-शक्ति के प्रभाव का आग्रह अधिक सार्थक हो सकेगा।

उपभोक्ता का हित ही एकमात्र सार्वजनीन हित है; अकेला यही हम सब का साझी हित है। इसीलिए उपभोक्ता-हित राष्ट्रीय आर्थिक हित का समरूप होता है। जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है वह सभी के लिए लाभदायी है। उपभोक्ता के हित का प्रभावशाली आग्रह ही उच्चकोटि के उत्पादन, स्वतन्त्र बाजार में सस्ती कीमतों, आर्थिक उन्नति और प्रचुर उत्पादन की कुजी है।

यह सब स्पष्ट ही राष्ट्र के हित में है, या जैसा कि संयुक्त राज्य के विधान में कहा गया है, 'सर्व साधारण के कल्याण का सर्वर्द्धक' है।

जनता के उपभोक्ता हित की आग्रहशीलता का अभी तक केवल एक ही उपाय सही अर्थों में अपने को प्रभावोत्पादक सिद्ध कर सकता है। वह उपाय है उप-भोक्ता सहकारियों की स्थापना और उनका चतुर्दिक विकास।

उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए बनाये गए कानून कुछ मामलों में आवश्यक होते हैं और सहायक भी। उदाहरण के लिए खाद्य-पदार्थों की विशुद्धता और औषधियों से सम्बन्धित कानून।

लेकिन एक सीमा के आगे कानून और सरकार दोनों के ही लिए कुछ कर पाना सम्भव नहीं रह जाता। उपभोक्ता के हित का निश्चित और रचनात्मक आग्रह अर्थ-नीति-संगत न्यूनतम मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के प्रचुर उत्पादन के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसे न कानून कर सकता है और न सरकार।

न अधिक लम्बे समय तक उत्पादकों की प्रतियोगिता ही जनता के उपभोक्ता-हितों की रक्षा कर सकता है। अर्थ शास्त्र के शास्त्रीय ग्रन्थ कुछ भी कहते रहे, औद्योगिक क्रान्ति के बाद का स्वतन्त्र जातियों का सच्चा आर्थिक इतिहास तो यही बतलाता है कि प्रतियोगिता और विशेष रूप से मूल्यों की प्रतियोगिता धीरे-धीरे कम होती जा रही है और एकाधिकार एवं 'व्यवस्थापित मूल्यन' क्रमशः बढ़ता जा रहा है।

यह सच है कि जब तक अन्धाधुन्ध सैनिक खर्चे, जो धन का निरा अपव्यय है, होते रहेंगे और जब तक परिवारों को उपभोक्ता ऋण के बदले अपना आर्थिक भविष्य बन्धक रखने को अधिकाधिक मात्रा में फुसलाया जाता रहेगा

ऊपरी मतह पर यही दिखाई देता रहेगा मानो हम बड़े सम्पन्न हैं और मानो उपभोक्ता के हित का पूरी तरह पोषण हो रहा है।

लेकिन अर्थ व्यवस्था की ये थूनियाँ तो वास्तव में वह कीमत है जो अपनी अर्थ व्यवस्था पर एकाधिकारी उत्पादकों को प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति देने के लिए हम चुकाते जा रहे हैं। आज अमरीका में जिन्हें 'शक्तिशाली' उद्योग माना जाता है वे सब इजारेदारियाँ हैं—मोटर, इस्पात, रसायन, प्रसारण, समाचार पत्रों का प्रकाशन आदि। जिन उद्योगों को हम 'कमजोर' कहते हैं वे ऐसे उद्योग हैं जिनमें प्रतियोगिता अब भी है, जैसे कि वस्त्र उद्योग, कृषि इत्यादि।

यह क्यों ?

यह इसलिए कि जो भी उद्योग अपने मूल्यों को 'व्यवस्थापित' करने की स्थिति में होता है वह जो उद्योग ऐसा नहीं कर सकते उनके और उपभोक्ता के रूप में सारे राष्ट्र के माथे पर, यानी उनका शोषण करके ही मुटाटा है। ऐसी स्थिति में 'दुर्बल' उद्योगों को जीवित रखने के लिए उपभोक्ता-माँग को सैनिक खर्चों और उपभोक्ता-ऋण की वृद्धि के रूप में आर्थिक उपदान देना आवश्यक हो जाता है, जिससे 'व्यवस्थापित मूल्यों' वाली एकाधिकारी प्रथा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के अधिमूल्यन से उपभोक्ता की क्रय-शक्ति का जो ह्रास होता है उसकी आंशिक पूर्ति की जा सके।

इसलिए उपभोक्ता सहाकारियों के महत्त्व के प्रतिपादन में यह कहना कि अमरीकी अर्थ व्यवस्था के समक्ष निम्नलिखित तीन विकल्प हैं, जरा भी अत्युक्ति नहीं होगी। पहला विकल्प तो यह है कि हम वर्तमान प्रवृत्तियों को इसी प्रकार चलने दें, अपनी अर्थ व्यवस्था पर एकाधिकार और अल्प एकाधिकार की वृद्धि को चुप खड़े देखते रहें और आँखें मूँदे हुए प्रतियोगिता के क्रमशः विलुप्त होते जाने तथा आर्थिक विकास की गति के निरन्तर मन्द होते रहने की स्थिति में पहुँच जाएँ। दूसरा विकल्प यह है कि हम सरकार को एकाधिकार की वृद्धि रोकने, प्रतियोगिता को पुनर्नियोजित करने और आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के पूरे अधिकार दे दें। लेकिन सरकार के द्वारा केवल कानून बना देने से तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि सरकारी कानून पुनर्नियोजन तो कर सकते हैं, निर्माण या सृजन नहीं; गति को मन्द तो कर सकते हैं, उसमें तेजी नहीं ला सकते।

सरकार के सामने स्थिति को सँभालन का सिर्फ यही एक रास्ता है कि वह एकाधिकारियों के मुकाबले स्वयं उत्पादन शुरू कर दे। लेकिन केवल विद्युत-शक्ति—जैसे उद्योगों को छोड़कर, जहाँ जनता के मूल हित बिल्कुल स्पष्ट और एकाधिकार अवश्यम्भावी हो जाता है, हम उत्पादन के क्षेत्र में सरकार की क्रिया शीलता और शक्ति का विस्तार न तो चाहेंगे न उसकी अनुमति ही देंगे।

अब रह जाता है तीसरा विकल्प। यह विकल्प है जनवाद और उद्यम की स्वतन्त्रता के जिन मूल सिद्धान्तों में हमसे विश्वास की आशा की जाती है उन दोनों का एक साथ विनियोग करना। इसका अर्थ हुआ स्वतन्त्र उद्यम को उपभोक्ता के रूप में जनता की जनवादी सहभागिता और नियन्त्रण के अनुकूल बनाना। और इसका अर्थ हुआ अपनी अर्थ व्यवस्था में आर्थिक सन्तुलन के पुनर्नियोजन और सर्वसाधारण जनता तथा राष्ट्र के आर्थिक हितों के आग्रह और रक्षण के लिए स्वतन्त्र जनता की हैसियत से अपने ही निजी प्रयत्नों के द्वारा बड़ी संस्थाओं में सहकारी संस्थाओं का संगठन, संवर्द्धन और उन्नयन करना।

इस तीसरे विकल्प का सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन-मूल्य को प्रभावित करने के अतिरिक्त एक लाभ और भी है। वह यह कि उपभोक्ता स्वामीत्व-कृत सहकारी व्यवसायों को उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण भी अवश्य करना होता है जिनकी उनके सदस्य-स्वामियों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि मकान, स्वास्थ्य-परिचर्या, विद्युत्, उधार पाने के लिए साख, उर्वरक, पेट्रोल के उत्पादन या किराना माल।

यह पुस्तक इन्हीं सब बातों के बारे में है। इसमें यह कहने की धृष्टता तो अवश्य नहीं की गई है कि सहकारी उद्यमों की आज जो प्रतियोगिता है वह संयुक्त राज्य में आर्थिक सन्तुलन को पुनः स्थापित कर देगी; लेकिन यह दिखलाने का साहस अवश्य किया गया है कि सहकारी उद्यम ने स्कैण्डिनेविया में ठीक यही कर दिखाया है, और काफी बड़ा और पर्याप्त शक्तिशाली होकर वह यहाँ भी इस काम को कर सकता है।

गृह-निर्माण, घरेलू आवश्यकताएँ, ग्रामीण विद्युत्, स्वास्थ्य-परिचर्या, पेट्रोल के उत्पादन, उर्वरक, उधार के लिए साख, और बीमा आदि कई क्षेत्रों में सहकारी उद्यमों की विद्यमानता और प्रतियोगिता के लाभदायी प्रभावों को दिखाने वाले

कई उदाहरण दिये गए हैं। हम यह देख आये हैं कि सहकारी उद्यमों द्वारा किये गए समझौतों के कारण और सीधे इन व्यवसायों में भी रोजगार की कितनी अधिक वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि उपभोक्ता स्वामीत्व कृत होने के कारण इन्हें हमेशा अर्थनीति-सगत न्यूनतम मूल्य पर पूरा-पूरा उत्पादन करना होता है। हमने यह भी देखा कि अर्थ व्यवस्था के जिन क्षेत्रों को लाभ-प्रेरित व्यवसाय छूते तक नहीं उन नये क्षेत्रों का भी ये सेवा-प्रेरित अथवा पारस्परिक सेवा-प्रेरित उद्यम किस तत्परता से आर्थिक विकास करते हैं। और हमने यह भी लक्ष्य किया कि परस्पर सम्बद्ध व्यवसायों में किसान के स्वामीत्व के अन्तर्गत सहकारियों का सशक्त एकीकृत विकास हमारी कृषि के उद्धार की अन्तिम और एकमात्र न सही बहुत अच्छी आशा तो अवश्य है।

संयुक्त राज्य में सहकारी उद्यम के वर्तमान परिमाण का तीन या चार गुना विस्तार, जिससे वह देश का दस से बारह प्रतिशत व्यापार करने लगे, आर्थिक विकास की पर्याप्त गति, अधिकतम रोजगार और मूल्य के स्थिरीकरण के सम्पादन की दिशा में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

हमारी अर्थ व्यवस्था के वर्तमान सकट का कारण है थोड़ी-सी, बड़ी-बड़ी उत्पादक इकाइयों के हाथ में बहुत अधिक आर्थिक शक्ति का केन्द्रित हो जाना। इतना ही नहीं; हमारी अर्थ प्रणाली के काफी बड़े हिस्सों पर उनका एकछत्र अधिकार हो गया है। उस अधिकार को बनाये रखने के लिए वे उत्पादन का नियन्त्रण, और सोमा-बन्धन भी करते हैं। उस अधिकार से लाभान्वित होने के लिए वे अपने उत्पादनों की कीमते 'व्यवस्थापन' के द्वारा, जो कि सरासर अनुचित है, निरन्तर तेजों की ओर ले जाते हैं। लेकिन सबसे गम्भीर बात तो यह कि वर्द्धमान औद्योगिकीय दक्षता के लाभदायी फलों का काफी बड़ा अंश वे स्वयं हड़प लेते हैं, जब कि राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता और स्वयं उनके अपने उद्योगों की उन्नति के लिए जनता में उसका व्यापक वितरण नितान्त आवश्यक है। एकाधिकार के रू में वास्तव में ये अर्थ-दानव स्वयं अपने ही सबसे बड़े शत्रु हैं।

सब के अन्त में केवल एक ही आर्थिक बल ऐसा है जो एकाधिकारी पद्धति से संगठित उत्पादकों की शक्ति को सन्तुलित कर सकता है। यदि कुरमुरे बिस्कुट बनाने का एकाधिकारी उद्योग अपने पूरे कारखाने को स्वचालित कर ले और

उसे एक भी मजदूर की जरूरत न रह जाए तब भी उन उत्पादित बिस्कुटों को खरीदने और खाने वाले लोगों की जरूरत तो उसे होगी ही, अन्यथा उसका वह सारा कारखाना ही एकदम बेकार हो जाएगा।

उपभोक्ता के रूप में जनता को संगठित क्रय-शक्ति ही औद्योगिक एकाधिकार को प्रतितुलित करने वाला अत्यन्त स्वाभाविक और एकमात्र प्रभावी बल है। सहकारिता जनता की उस क्रय-शक्ति को संगठित करने का एकमात्र न सही, पर श्रेष्ठ साधन तो अवश्य ही है। संगठित उपभोक्ता अपने नैसर्गिक, आर्थिक हितों का अनुसरण करते समय सहज भाव से राष्ट्रीय आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। क्योंकि अन्ततोगत्वा राष्ट्र ही जनता है और जो सारे राष्ट्र का सम्मिलित हित है वही तो उपभोक्ताओं का अपना हित भी है।

यह आवश्यक नहीं कि अमरीका की वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए सहकारी तेल परिष्करण शालाओं और उर्वरक सयन्त्रों के साथ-साथ सहकारी स्वामीत्वकृत मोटर के कारखाने और इस्पात मिले आदि भी खोली जाएँ। आवश्यक यह है कि विभिन्न एकाधिकार-निर्मित उत्पादनों के उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति को इस सीमा तक संगठित किया जाए जिससे उनकी आर्थिक मौलभाव करने की शक्ति उत्पादक कम्पनियों की शक्ति को समान हो जाए।

मानना ही होगा कि यह काम बड़ा कठिन है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखा जाए कि एक क्षेत्र में सहकारी उद्यम से उद्भूत पारस्परिक लाभ के अनुभव को वहीं संगठित जनसमूह बड़ी सरलता से दूसरे क्षेत्रों में भी नियोजित कर सकता है। भोजन जीवन की पहली आवश्यकता है। इसीलिए अधिकांश देशों में खाद्य-भण्डार को केन्द्र बनाकर उपभोक्ता क्रय-शक्ति के व्यापक संगठनों का निर्माण हुआ। लेकिन एक बार आरम्भ करके सहकारी आन्दोलन वहीं नहीं रुक जाता। वह आगे और निरन्तर आगे बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए स्कैंडिनेविया का नाम लिया जा सकता है, जहाँ गृहोपयोगी आवश्यकताओं को पूरा करने के सफल व्यापार की नींव पर उन्होंने अपने देश के अधिकांश बड़े एकाधिकारियों के समक्ष सहकारी उत्पादन के रूप में एक जबर्दस्त चुनौती खड़ी कर दी है।

जो वे कर सके, कोई कारण नहीं कि उसे हम अपने यहाँ न कर सके।

११ | कमजोरियाँ और गलतियाँ

पश्चिमी यूरोप के देशों में, जापान, कनाडा, प्यूर्टो रिको और कई दूसरे स्थानों में भी लोग 'सहकारी आन्दोलन' की बातें करते हैं, वे सभी इस आन्दोलन के उत्साही समर्थक नहीं होते। लेकिन उनमें से अधिकांश इस आन्दोलन को आदर की दृष्टि से देखते हैं। और जो लोग इस आन्दोलन के अन्दर हैं वे सामान्यतः एकता की भावना का और उसके कारण कुछ आत्मिक उन्नयन और नैतिक प्रेरणा का भी अनुभव करते हैं।

महाद्वीपीय विस्तार वाले संयुक्त राज्य में स्थिति भिन्न है; क्योंकि यहाँ सहकारी और पारस्परिक व्यापारों के विभिन्न प्रकार सारी दुनिया से अधिक संख्या में हैं; और निश्चय ही उनके उद्भव और अस्तित्व के यहाँ भिन्न-भिन्न कारण भी हैं। हमारे यहाँ भी लोग कभी-कभी 'अमरीकी सहकारी आन्दोलन' की बात करते हैं। लेकिन प्रायः ठीक से नहीं जानते कि वे इस पद के अन्तर्गत किन संस्थाओं अथवा किन व्यक्तियों का समावेश कर रहे हैं। बहुत से व्यक्ति और संस्थाएँ, जिनका समावेश कर लिया जाता है, इस बात को बिल्कुल पसन्द नहीं करते। उन्हें 'सहकारी आन्दोलन' पद ही पसन्द नहीं होता। वे इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि वे किसी 'आन्दोलन' का अंग नहीं हैं; वे तो अपने संरक्षक-स्वामियों और समुदायों के लिए सिर्फ व्यापार कर रहे हैं।

सहकारी संस्थाएँ जैसी बाहर से दिखाई पड़ती हैं वैसे अन्दर से नहीं होती। जनहित की दृष्टि से देखा जाए तो वे बाहर से सफेद, लेकिन केवल अपने हित की दृष्टि से देखा जाए तो काली दिखाई देती हैं। अन्दर से सहकारी संस्थाएँ और उनके कार्य अनेक आभाओं वाले दिखाई पड़ते हैं—स्वेताभ से लेकर गहरे धूसर तक रंग के कई क्रम विन्यास वहाँ होते हैं।

इन पंक्तियों के लेखक को लगभग दो दशान्दियों तक सहकारी संस्थाओं को अन्दर से देखने का अवसर मिला है। मैंने बहुत-सी प्रेरणात्मक बातें देखी हैं: हजारों लोगों की बड़ी-बड़ी वार्षिक सभाएँ—अर्थ व्यवस्था में अमरीकी

लोकतन्त्र को राजनीति के ही समान, बल्कि अनेक अंशों मे उससे भी अच्छी तरह कार्यान्वित करते हुए और अपने व्यापार के स्वामीत्व एवं नियन्त्रण के प्रति पूर्णतः सजग हजारों लोगो की सभाएँ। मैंने छोटे स्थानीय सहकारी सगठन भी देखे हैं—सुसंचालित व्यापार का निष्ठा से सम्पोषण-संवर्द्धन करते हुए, उस व्यापार के भविष्य के प्रति पूरी तरह आस्थावान, कुशल निःस्वार्थ नेतृत्व में साथ जुटे हुए सदस्यों वाले स्थानीय सहकारी सगठन।

लेकिन मैंने दूसरी बातें भी देखी हैं। मैंने ऐसे स्थानीय सहकारी सगठन देखे हैं जिनके सदस्यों को नीति-सम्बन्धी बहस मे अपनी बात सिद्ध करने की जितनी चिन्ता रहती है उसकी शतांश भी अपनी सस्था की सफलता के बारे मे नहीं। मैंने सहकारी सस्था के चुनावों मे 'लोकतन्त्र' के नाम पर सभी सदस्यों को 'व्यवस्थापक-पद के लिए' खड़े होते देखा है। ऐसे प्रसंगों की तह में पहुँच कर मैंने पाया है कि सदस्यों की शिक्षा और गैर-सदस्य संरक्षकों को सदस्य बनाने के कार्य की नितान्त अवहेलना ही होती रही है। बहस सहकारिता की स्थानापन्न नहीं है।

सहकारिता का अर्थ है कि हर आदमी अपने हिस्से का काम करे, यह नहीं कि दूसरे के काम को करने का प्रयत्न करता फिरे।

व्यवस्थापक का काम है प्रबन्ध करना। निदेशक का काम है सामान्य नीति निर्धारित करना और उसे कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्थापक को नौकर रखना और ज़रूरी हो जाए तो उसे निकाल बाहर भी करना। सदस्यों का काम है संरक्षक बनाना, सदस्यता-संख्या मे वृद्धि करना, शैक्षिक कार्यक्रमों को बनाना और कार्यान्वित करना, निदेशक-मण्डल को निर्वाचित करना और कभी-कभी पुनर्निर्वाचित नहीं भी करना।

मैं सफलता अर्जित करने वाले ऐसे स्थानीय सहकारियों को जानता हूँ जिनके सदस्य आत्म-सन्तोष के घेरौदे मे आराम से टाँगें पसारे पड़े रहते हैं और समूचे सहकारी व्यवसाय की उन्नति मे जरा भी उत्साह नहीं दिखाते। ऐसी स्थानीय सहकारी समितियाँ भी हैं जो अपने अड़ोस-पड़ोस मे सफलता पाकर फूल उठती हैं और यह भूल जाती हैं कि थोक संस्थाओं के प्रति भी उनका कोई कर्तव्य है, कि उनका संपोषण-संवर्द्धन स्थानिकों की जिम्मेवारी है, तभी वह दिन समीप

लाया जा सकता है जब राष्ट्रीय उत्पादन के काफी बड़े अंश पर जनता का अधिकार हो सकेगा और जनता अपनी सस्थाओं-अपने सहकारियों के माध्यम से काफी बड़ी मात्रा में स्वयं उत्पादन करने लगेंगी। स्थानीय समितियों और थोक सस्थाओं के बीच पूरा सहयोग होने पर ही थोक व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, नये भाण्डागार खोले जा सकते हैं, माल का पण्योपयोगन और अन्त में उत्पादन आरम्भ किया जा सकता है।

मैंने क्षेत्रीय सहकारियों के काम में यह कमजोरी पाई है कि कच्चे माल के स्रोतों के अधिग्रहण के लिए वे साथ मिलकर उतना काम नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए, न वे सम्मिलित होकर अपनी खरीदों का निकाय ही करते हैं; और सम्मिलित रूप से शक्तिशाली सहकारी वित्तीय सस्थाओं की स्थापना की बात, जिसकी सभी को इतनी अधिक आवश्यकता रहती है, शायद उनको सुहाती नहीं। मानी हुई बात है कि यदि सभी सहकारी क्षेत्रीय संस्थाएँ सम्मिलित होकर कच्चा माल खरीदे तो उनकी मोल-भाव करने की सामर्थ्य बहुत बढ़ जाएगी और वे अपने लिए लाभदायी भाव पर सौदा खरीद सकेंगी। संयुक्त होकर काम करने से उत्पादन क्षमता में भी काफी वृद्धि होगी और उत्पादन ही तो ऐसा काम है जिसमें उपभोक्ताओं के लिए काफी अधिक बचत की जा सकती है।

सबसे बुरी बात जो मुझे देखने को मिली वह है आपसी ईर्ष्या, व्यक्तिगत द्वेष, मनोमालिन्य और इतने गहरे पक्षपात जो कई सहकारी सदस्यों को सच्चे सहकारी कार्यों के सर्वथा अयोग्य कर देते हैं।

जिसे 'सहकारी चुनौती' कहा जाता है उसकी सफलता प्रथम कोटि के व्यवस्थापकों, उत्कृष्ट कोटि के वाणिज्य-व्यापार और सदस्यों की अडिग आस्था एवं क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। लेकिन सबसे अधिक वह जिस बात पर निर्भर करती है, वह है सहकारी संस्थाओं का आपसी सहयोग। आखिर सहकारिता का, यदि कुछ अर्थ हो सकता है तो वह इसके अतिरिक्त और है ही क्या कि सर्व सामान्य अच्छे उद्देश्यों के लिए साथ मिल कर काम किया जाए और हर निजी भावना, हर क्षुद्र विचार और सभी स्वार्थ पूर्ण प्रयोजनों से उन उद्देश्यों को ऊँचा और आगे रखा जाए।

सहकारी संस्थाएँ 'लोग' पहले हैं, व्यापार और संस्थाएँ बाद में। वे ऐसी संस्थाएँ हैं जिनकी स्थापना जन-समूहों द्वारा की जाती है और स्थापना करने वाले जन-समूह ही उनके स्वामी और नियन्त्रणकर्ता होते हैं और बहुत अंशों में संरक्षण-सम्पोषण करने वाले भी।

लोगों में कमजोरियाँ होती हैं और वे गलतियाँ भी करते हैं और सहकारी संस्था को तरह जो संस्थाएँ पूर्णतः जनवादी होती हैं उनमें ये दोनों दुर्गुण तत्काल सतह पर उभर आते हैं।

अनुदास्ता या रूढ़िवादिता का अतिरेक एक ऐसा ही दुर्गुण है जो अधिकांश सहकारी और पारस्परिक संस्थाओं में आमतौर पर पाया जाता है।

इसके अपवाद भी अवश्य हैं—खास तौर पर क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति सहकारी और नये नगर-उपभोक्ता सहकारी सगठनों में।

लेकिन सामान्यतः सहकारी संस्थाएँ जोखिम लेने से घबराती और नया कुछ करने से कतराती हैं।

यह सब है कि उन्होंने कुछ नये काम किये हैं, जो काफी महत्वपूर्ण भी हैं। ऐसे कामों में :

खुले सूत्र वाला उच्च विश्लेषण-युक्त उर्वरक;

प्रत्यक्ष विद्युत् चालक (Direct Power Take-off), उच्च गति परिषण (High Speed Transmission) और ट्रैक्टरों की हेड लाईटें;

उपभोक्ता-वस्तुओं पर उनके बारे में जानकारी देने वाले लेबल लगाना;

पारस्परिक निधि में रकबा लगाने की सुविधा सहित सस्ती दरों पर बीमा-व्यवस्था;

किसी भी समय (मुद्दत के बाद) बिना दण्ड के कर्ज बेबाक करने का अधिकार;

ये और इसी तरह के बहुत-से दूसरे काम सहकारी संस्थाओं ने ही सबसे पहले किये हैं।

लेकिन यह सूची काफी बड़ी होती, कम-से-कम अपने वर्तमान रूप से तिगुनी तो हो ही जाती यदि उत्पादन की जानेवाली वस्तुओं के क्षेत्र में थोड़ा अधिक अनुसन्धान और कुछ ज्यादा उत्पादनों एवं सेवाओं का साहस किया जाता।

पुराने जमाने के सहकारी संगठनों की नीति प्रायः यह होती थी कि 'जितना कर चुके हों उसी को निभाते रहो'; प्रगति के नये लक्ष्य निर्धारित करने और उन लक्ष्यों को पूरा किये बिना पूरे वर्ष को असफल और बेकार समझने की प्रवृत्ति उनमें होती ही नहीं थी। यह भ्रान्त धारणा अब तो काफी हद तक कम हो गई है—विशेषकर बड़े सहकारियों ने अपने को इससे बहुत सीमा तक मुक्त कर लिया है। इस गलत रूझान से मुक्ति दिलाने का एक बड़ा कारण प्रबन्ध-व्यवस्था को उन्नत और विकसित करने का कार्यक्रम भी है, जिसे प्रायः सभी बड़े सहकारी-संगठन अपनाते हैं, और जिसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन अत्यधिक सावधानी और फूँक-फूँक कर कदम रखने की पुरानी सनोवृत्ति अब भी बहुतों में घर किये हुए है।

कुछ गिने-चुने अपवादों के अतिरिक्त सहकारी संगठन यथेष्ट मात्रा में विज्ञापन भी नहीं करते और न टेलीविजन का उपयोग करते हैं। जनता को अपनी शक्ति-विधियों से अवगत रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में और प्रभावी ढंग के प्रचार कार्यक्रम भी नहीं अपनाये जाते। और जब कभी विज्ञापन आदि करते भी हैं तो बड़े ही घिसे-पिटे परम्परागत ढंग से-अपने उत्पादनों के गुण गा दिये और छुट्टी पाई। यह बताने की तो प्रायः कोशिश भी नहीं की जाती कि सहकारी उद्यम क्यों और कैसे एक भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं; न इसी विशेषता पर जोर दिया जाता है कि ये ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं को सुनना ही पड़ता है, क्योंकि वे उपभोक्ता ही उनके स्वामी भी होते हैं।

सहकारी उद्यमों की, कार्य-व्यापार की दृष्टि से, कुछ ऐसी बाधाएँ हैं जिन्हें उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनाया जा सकता है। इन बाधाओं का मुख्य कारण सहकारी संगठनों का जनवादी नियन्त्रण है, जो इनके अस्तित्व की अपरिहार्य शर्त है, अन्यथा वे सहकारी रह ही नहीं जाएँगे। लेकिन जनवाद के वास्तविक अर्थ को समझना और ग्रहण करना होगा। सच्चा जनवाद है एक सदस्य और एकमत, जो सर्वोपरि नियन्त्रण के लिए बहुत आवश्यक है और जिसके अभाव में सहकारी का अपना विशिष्ट स्वरूप ही नहीं रह जाएगा; क्योंकि इस तरह के जनवाद का होना एक सच्चे सहकारी के लिए नितान्त

आवश्यक होता है। और 'जनवाद' का विकृत रूप है प्रबन्ध एव कार्य संचालन में उसे जबर्दस्ती घुसेड़ना, जो सहकारी सहित किसी भी व्यापारी संस्था के लिए घातक होता है। लेकिन इस आवश्यक अन्तर को समझा नहीं जाता, न इसपर ध्यान दिया जाता है; मुश्किल तो यह है कि इधर के वर्षों में संयुक्त राज्य के सहकारी सगठनों द्वारा प्रबन्ध कौशल और व्यवस्था के विचार और विज्ञान में इतनी अधिक उन्नति कर लेने के बाद भी जनवाद के इस अन्तर का दुर्लक्ष्य किया जाता है।

फिर प्रगति की—उन्नति और विकास की समस्या है। यह समस्या अकेले सहकारी सगठनों की ही नहीं सभी स्वैच्छिक जनवादी सगठनों की समस्या है। यह निश्चय ही एक अच्छी समस्या है। लेकिन 'कस्बा-सभा' की पद्धति को कैसे चालू रखा जा सकता है जब 'कस्बे' के 'निवासियों' की संख्या पचीसों हजार या लाखों तक पहुँच जाए ? कुछ सहकारी उद्यमों के सच ही इतने अधिक सदस्य हैं। ऐसी अवस्था में जनवादी नियंत्रण और सदस्यों की सार्थक सहभागिता को सही रूप में बनाये रखने के लिए एक कार्य पट्टा शासनतंत्र की आवश्यकता होती है। फिर इतने अधिक सरक्षक-सदस्यों अथवा पालिसीधारियों में उत्तर-दायित्व की भावना, निष्ठा तथा परक रुचि और हित-चिन्ता को बनाये रखना भी एक समस्या है। और शैक्षिक कार्यों की समस्या भी कुछ कम नहीं है; इस दिशा में यथेष्ट तो कुछ भी नहीं किया जा रहा है, उल्टे, इधर के वर्षों में, कुछ स्थानों में, इसकी व्यर्थता पर ही जोर दिया जाने लगा है।

इसके अतिरिक्त जब संस्था की काफी उन्नति हो जाती है तो वह इतनी काम्य वस्तु बन जाती है कि उसपर अधिकार करने के लिए सदस्यों और नेताओं में लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं।

१९५० के बाद की दशाब्दी में साख-सघों का बन्दर बाँट करने और उनकी एकता को छिन्न-विच्छिन्न करने के लिए ऐसे ही संघर्ष छिड़ गए थे।

इस तरह के संघर्ष कुछ अशों में मत-वैषम्य के कारण भी होते हैं, जिनकी सच्चाई और ईमानदारी से इनकार नहीं किया जा सकता।

एक ओर ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि साख-सघों का काम केवल ऐसे छोटे और सुविधा जनक कर्जों के लेन-देन तक ही सीमित रहना चाहिए

जिन्हें आमतौर पर बैंके और दूसरी महाजनी सस्थाएँ करती। इन लोगों का यह आग्रह भी है कि साख-सघो का भावी विकास मालिकों द्वारा प्रायोजित साख-सघो के ही रूप में हो; और इसीलिए ये नहीं चाहते कि देश के बड़े सेवा-योजक निगमों को किसी भी तरह नाराज किया जाए।

दूसरी ओर वे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि अपने सदस्यों की उचित और अच्छे ढंग से जितनी अधिक-से-अधिक सेवा की जा सके साख-सघों को वह सब करनी चाहिए। वे साख-सघों को 'जनता की बैंके' मानते हैं, जिनका काम केवल छोटे कर्ज देना ही नहीं, जनता की वचर्ता को सुविन्यस्त कर उन्हें इतनी वित्तीय निर्भरता और शक्ति प्रदान करना है जिससे वह अपनी बहुत-सी आर्थिक समस्याओं को हल कर सके। ऐसे लोग साख-सघों को सेवा योजक कम्पनियों के बरदहस्त और प्रायोजन से मुक्त रखना चाहें, यह स्वाभाविक ही है; वे साख-सघों के भावी विकास की रूपरेखा पैरिश और चर्च के साख-सघों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, श्रमिक सघ के सदस्यों एवं सहकारी सगठन के सदस्यों के साख-सघों के रूप में अंकित करते हैं।

लेकिन सारी बात केवल इतनी ही नहीं है। अधिकार और आधिपत्य की लड़ाई भी है जो अन्दर-ही-अन्दर बड़े खुले रूप से लड़ी जा रही है। निरन्तर उन्नति कर रहे लगभग एक करोड़ बीस लाख सदस्य सख्या वाले सगठनों पर कब्जा करने को किसका जी न ललच उठेगा; इस सोने की मुर्गी को हथियाने के लिए कौन खम ठोक कर मैदान में न उतर आयेगा।

सघर्ष और भी कई स्थानों में है : कुछ क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति सहकारियों की पारस्परिक लाग-डॉट ने तो बड़ा ही गन्दा रूप धारण कर लिया है; कुछ बड़ी-बड़ी सहकारी बीमा कम्पनियों में 'उत्तराधिकार' का सघर्ष है; और कतिपय पुराने और योग्यतम नेताओं की कभी खत्म न होने वाली आपसी उठा-पटक तो चलती ही रहती है।

हाँ, सहकारियों में त्रुटियाँ भी हैं, क्योंकि सहकारी सबसे पहले लोग हैं, और लोग कभी त्रुटिहीन नहीं होते।

जहाँ तक वणिज-व्युपार और कारबार का सम्बन्ध है सहकारी एवं अन्य पारस्परिक सगठनों ने उतनी ही गलतियाँ की हैं जितनी अन्य प्रकार की संस्थाएँ

करती है। लेकिन आम खयाल यह है कि सहकारी सस्था को कभी गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए जब भी गलती होती है सहकारियों को अपने प्रति स्पर्द्धी संगठनों की अपेक्षा अधिक हानि उठानी पड़ती है और वह अपेक्षाकृत ज्यादा साफ और ज्यादा बड़ी दिखाई भी देती है।

सहकारी व्यवसायी को आरम्भ करना मुश्किल काम है और उन्हें सफलता से चलाना तो और भी टेढ़ी खोर है। बहुत से लोगों से थोड़ा-थोड़ा पैसा लगवा कर पूँजी खड़ी करना और तब व्यापार करना सरल नहीं होता। जिस व्यवसाय का हर ग्राहक मालिक हो और इसी नाते निदेशक-मण्डल का प्रभाव-शाली सदस्य भी, उसका प्रबन्ध करना आसान काम नहीं होता। जिस व्यवसाय के संरक्षक उसके स्वामी हों और उन्हें हर बात जानने का अधिकार हो उसको चलाना काँच के घर में बैठना है, जिसकी कोई बात किसी से छिपी नहीं रह सकती— हर भेद पूरी बस्ती को, सारे समुदाय को, यहाँ तक कि प्रति स्पर्द्धियों को भी मालूम हो जाता है।

ओछी पूँजी या कम पूँजी सहकारियों की चिरकालिक समस्या है। होगी ही; क्योंकि इनके हिस्से सदा दाम-के-दाम पर खरीदे-बेचे जाते हैं और केवल इनकी सेवाओं का उपयोग करनेवालों के ही काम के होते हैं। इसलिए मूल पूँजी हमेशा सदस्यों से ही आती है और उनमें अमीर तो शायद ही कोई हो। जब सहकारियों के पास कुछ अधिशेष जमा हो जाते हैं तो वे उनका उपयोग काम को तेजी से बढ़ाने-फैलाने में नहीं करते, सहेज कर बैठे रहते हैं। गाढ़ी कमाई का, सदस्यों का पैसा है, व्यवस्थापको और निदेशकों की उसे जोखिम में न डालने की सतर्कता समझ में आती है।

सहकारियों ने अपने वित्तीय साधनों का निकाय करना, वित्त-नियोजन के नये उपायों को विकसित करना और वित्तीय प्रबन्ध के लिए नई संस्थाएँ बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे इन स्रोतों के द्वारा आवश्यक पूँजी की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन प्रयत्न अभी आरम्भ ही हुआ है, आवश्यकता के अनुपात से बहुत छोटे हैं और मजिल काफी लम्बी है।

संयुक्त राज्य के सहकारी संगठनों को कई चीज़ों के व्यापार में अत्यन्त कुशल व्यापारियों की काफी कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है।

केवल यह बात कि सहकारिता बहुत अच्छा विचार है सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकती। सफलता के लिए अधिक न सही, कम-से-कम प्रतिस्पर्द्धियाँ—जैसा दक्षतापूर्ण कार्य-संचालन तो होना ही चाहिए। पश्चिमी यूरोप में एक ही व्यवसाय के विभिन्न अवयवों का एकीकृत संघटन सबसे पहले वहाँ के सहकारियों ने ही किया और उन्हीं ने वितरण की प्रथा में पहले-पहल सुधार भी। लेकिन हमारे यहाँ सहकारी जब तक नगर में आये, दूसरे व्यवसाय इस काम को उससे पहले कर चुके थे।

सहकारियों के सफल निर्माण का कार्य इतना श्रमसाध्य है कि यदि इस आन्दोलन के आरम्भ काल के नेताओं में वास्तविक महानता न होती तो हमारी बहुत-सी श्रेष्ठ सहकारी संस्थाओं का निर्माण असम्भव ही था। हर बुजुर्ग नेता ने अपनी-अपनी संस्था का बड़ी खूबी से निर्माण किया। अपनी संस्था से उनका लगाव बड़ा गहरा और सम्बन्ध एकदम व्यक्तिगत होते हैं। इन सम्बन्धों में व्यवधान लाने वाले किसी परिवर्तन की बात, जैसे कि सहकारी संस्थाओं में आपस में पूरा-पूरा सहयोग—वे कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज तो इस तरह का सहयोग, और कई प्रसंगों में विलयन भी, आर्थिक दृष्टि से नितान्त आवश्यक हो गया है।

कई नेता हैं जिन्होंने बड़ी मन्दी के काल में अपने भगीरथ प्रयत्नों से अमरीका में सहकारी आन्दोलन को परिपुष्ट किया। यहाँ उनके नाम गिनाने का प्रयत्न कदापि उचित न होगा। बहुत से ऐसे नाम जिनका उल्लेख आवश्यक है छोड़ देने पड़ेंगे। यदि उन्हें न छोड़ा जाए तो सूची पुस्तक के कलेवर को देखते बहुत लम्बी हो जाएगी।

वे सब अग्रवर्ती नेता थे—अमरीकी समाज के 'अन्तः प्रेरणा' वाले युग की विभूतियाँ। वे गहरी श्रद्धा और अटूट लगन वाले पुरुष थे—और उनमें से जो जीवित हैं उनकी श्रद्धा और लगन में आज भी कोई अन्तर नहीं आने पाया है। उन सबने अपनी धारणाओं और अपने विचारों के अनुरूप—यदि आदर्श न कहना चाहें—एक ज्यादा अच्छे समाज के निर्माण का भगीरथ प्रयत्न किया है।

लेकिन दो या तीन अपवादों को छोड़ कर वे स्वभाव से ही सारा काम स्वयं करनेवाले 'वीर वर' थे, और आज भी हैं—दल के साथ मिलकर बराबरी के

स्तर पर काम करने के वे अभ्यस्त नहीं थे, और आज भी नहीं है। उनके महान् गुणों ने उन्हें नेता के पद पर आसीन कर दिया था और प्रत्येक के आसपास भक्तों और श्रद्धालुओं को ला जुटाया था। लेकिन उस महानता का ही यह परिणाम हुआ कि प्रत्येक महा पुरुष को अपने-अपने सहकारी 'साम्राज्य' का बिलकुल एकाकी और अपनी समझ के अनुसार निर्माण करना पड़ा। उनके दमखम के दूसरे नेता की जहाँ गुजर नहीं थी और हो भी नहीं सकती थी।

सयुक्त राज्य में सहकारी उद्यम के आदर्श रूप के मूल तत्त्वों के निर्माण का सारा श्रेय उन्हीं को है। वे न होते तो आज का यह सुदृढ़ समर्थ सहकारी नमूना भी न होता। सहकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावी पीढ़ियाँ उनके महान् ऋण से कभी भी उऋण न हो सकेंगी।

लेकिन ऐसे पुरुषों के साथ यह बड़ी कठिनाई होती है कि वे अपने निर्मित मूल तत्त्वों को किसी सबल सुसमन्वित रूप में ग्रथित नहीं कर पाते। सही दृष्टि के साथ १९३३ में नेशनल कोऑपरेटिक्स को संगठित किया गया था। विचार यह था कि वह क्षेत्रीय थोक संगठनों का स्वामीत्व कृत, उनकी क्रय-शक्ति का निकाय कर राष्ट्र व्यापी स्तर का क्रेता और निर्माता सहकारी संगठन होगा। लेकिन नेशनल को क्षेत्रीय संगठनों के लिए खरीदारी करने की दक्ष संस्था से अधिक कुछ भी नहीं होने दिया गया। फिर १९४३ में कोऑपरेटिव फाइनेन्स एसोसिएशन बनाया गया; इसे सहकारियों की केन्द्रीय वित्त-प्रबन्धकारिणी संस्था के रूप में चलाने का विचार था। लेकिन करीब बीस वर्षों तक यह सोई पड़ी रही और तब नई पीढ़ी के नेताओं ने आकर इसे कार्यशील किया। यह नई पीढ़ी अवश्य उत्तराधिकारी होगी और इसे होना भी चाहिए। लेकिन इनके भी नाम हम यहाँ नहीं गिना रहे। इसलिए नहीं कि नामोल्लेख किये जाने वाले इसे पसन्द नहीं करेंगे, बल्कि इसलिए कि प्रधान व्यवस्थापकों और निदेशक-मण्डलों के अध्यक्षों की यह दूसरी पीढ़ी सामान्यतः स्थपतियों की नहीं न्यास-धारियों की है, रचयिताओं की नहीं प्रशासकों की है, अकेले-अकेले पहाड़ उठाने-वाले 'वीरवरों' की नहीं दल के साथ मिल कर काम करने वालों की है।

सहकारी नेताओं की इस नई पीढ़ी के सदस्य एक-जगह मिल सकते हैं और साथ मिलकर निर्णय भी कर सकते हैं, जो अग्नवर्ती नेताओं के लिए कठिन था।

इस नये नेतृत्व का निर्णय सामूहिक निर्णय होता है। वह ऐसा निर्णय भी हो सकता है जिससे हिस्सा लेनेवाले किसी नेता को अपना प्रधान व्यवस्थापक का पद खोना भी पड़ जाए। क्योंकि वे निर्णय अपने ही जैसी दूसरी सस्था से संबद्ध होने, समन्वित होने—यहाँ तक कि विलयन के भी हो सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका में सहकारिता का विकास नया-नया हो रहा है। यह ऐसे पुरुषों का कृतित्व और स्मारक है जिनमें से कई अभी जीवित हैं। नया होने के साथ-ही-साथ यह अपनी शक्ति के लिए अभी भी अधिकतर महान अग्रवर्ती नेताओं और उनके आसपास की मण्डली पर निर्भर करता है।

पश्चिमी यूरोप का 'सहकारी आन्दोलन' मुख्यतः उपभोक्ता-हितों के प्रति-रक्षक के रूप में विकसित हुआ है। पुरानी समाज व्यवस्थाओं में लोग धन्य कभी-कभी भी बदलते थे। उत्पादनकर्ता के रूप में उनका धन्य बड़ी सीमा तक तो वश-नरम्परा से निश्चित और निर्धारित हो जाता था, या फिर यह काम प्रशिक्षण से होता था। पारिवारिक आय के स्तरों में परिवर्तन की गति बहुत मन्द होती थी। इसलिए पारिश्रमिक की क्रय-शक्ति सारे समाज के लिए बड़ी चिन्ता का विषय बनी रहती और उपभोक्ताओं के रूप में जनता के आर्थिक हित सदैव अस्पष्ट और अकुलाहट पैदा करने वाले प्रतीत होते थे।

लेकिन नागरिक अमरीका में उपभोक्ता के रूप में जनता के सर्व सामान्य, सार्वजनिक हितों की ओर अभी-अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब कि अधिकांश सहकारी संस्थाएँ किसी-न-किसी रूप में उपभोक्ता सहकारी संस्थाएँ हो होती हैं। किसानों की विक्रय-सहकारियों और श्रमिकों के स्वामीत्व-कृत एवं उन्हीं के द्वारा संचालित कुछ कारखानों की छोड़कर वास्तव में बाकी की सभी उपभोक्ता सहकारी ही हैं। नगरवासी श्रमिकों ने भी अभी-अभी तक अपनी क्रय-शक्ति की रक्षा करने और उसे अधिक प्रभावी बनाने के उपायों में कोई रुचि नहीं दिखाई है। उत्पादनकर्ता के रूप में अपनी आय को ही वे अपनी सारी खुशहाली की बुनियाद मानते रहे हैं।

सहकारी नये होने के साथ-साथ 'भिन्न' भी हैं। ये उन व्यापारों से बिल्कुल ही भिन्न हैं जिनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। लेकिन अपने अग्रवर्ती पूर्वजों और स्वयं 'पश्चिमी' चलचित्रों के अनन्य प्रेमी होने के बावजूद

हम दूसरे महायुद्ध के परवर्ती काल में, सुविधाओं की अतिरेकता वाले अन्य सभी लोगों के समान सादृश्यतावादी हो गए हैं; और कोई भी काम करते समय हमारे प्राण इस विचार से सूखने लगते हैं कि कहीं दूसरे लोग हमें 'भिन्न' न समझ बैठें। इसके अतिरिक्त, हम बडेपन के इतने भक्त हो गए हैं कि यदि स्वयं कोई बड़ा काम नहीं कर सकते तो दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपना ही कोई छोटा काम खड़ा करने की जिम्मेवारी लेने के बजाय किसी बड़े काम-काज की सेवा करना पसन्द करते हैं।

इन्हीं दो बातों के कारण बीसवीं शताब्दी के इन मध्यवर्ती वर्षों में भी अमरीका नगरों के औसत निवासी के मन में सहकारी-संगठन घर नहीं कर पा रहा है। और जैसा कि कहा जा चुका है सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित करने, समझाने-बुझाने और अवगत रखने का काम तो प्रायः किया ही नहीं जा रहा है।

लेकिन इस सबके बावजूद कुछ खास तरह के सहकारी और पारस्परिक-सहायता संगठन भी अवश्य हैं जिन्होंने काफी प्रगति की और सुस्थापित संस्थाओं के रूप में ख्याति अर्जित कर ली है।

ऐसे संगठनों में किसानों और ग्रामवासियों के, लिए बिक्री व्यवस्था सम्भरण, विद्युत्, लेनदेन और बीमा का काम करने वाली सहकारी संस्थाओं के नाम गिनाये जा सकते हैं। यही बात साख-सघों के बारे में भी कही जा सकती है।

किसानों को सामान्यतः अपनी आजीविका और पेशे पर बड़ा अभिमान होता है। धरती से लेकर दूसरी सभी तरह की चीजों और सम्पत्तियों की मिल्कियत की भी वे बड़ी कद्र करते हैं। जब तक आर्थिक स्थितियाँ एकदम असहनीय नहीं हो जाती और जीना दूभर नहीं कर देती वे न तो स्थान बदलते हैं और न अपना धन्धा ही; समाज के दूसरे समूहों की तरह नहीं है कि आज यहाँ बसे कल वहाँ, आज यह धन्धा किया कल दूसरा। दूसरे उद्योगों की तुलना में लघु उत्पादनकर्ता होने के कारण खरीदने और बेचने के समय आर्थिक मोल-भाव की क्षमता को बनाये रखने के लिए सहकारी संस्थाएँ बनाना उनके लिए एक महती आर्थिक आवश्यकता हो जाती है। यही कारण है कि किसान सहकारिता के विचार को, सहकारी संस्था को और कृषि कार्यों से सम्बन्धित अन्य

व्यवसायों के सहकारी, संयुक्त स्वामीत्व को अधिक तत्परता से ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त अभी कुछ ही समय पूर्व तक स्वामी द्वारा संचालित स्वतन्त्र फारम हमारे सारे जनवादी समाज की आधार शिला माना जाता रहा है। इसलिए किसान की सहकारी संस्थाओं को सब ओर से समर्थन और स्वीकृति मिलती रही, क्योंकि वे किसान को आर्थिक प्रतिकूलताओं के बुरे-से-बुरे प्रभावों से बचाने का आवश्यक साधन थी—खासकर उन बुरे प्रभावों से जो किसान को अपनी उपज के प्राप्त होने वाले मूल्यों के या उत्पादन का नियन्त्रण न कर पाने का असमर्थता के परिणाम होते हैं।

अधिकांश उद्योगों के सामने ऐसे कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वे उत्पादन को नियन्त्रण में रखते हैं और उन्हें कीमते भी अच्छी मिल जाती है।

ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाओं और सहकारी कृषि साख समितियों ने तो साफ तौर से किसानों की ऐसी आवश्यकताओं को पूरा किया जो या तो बहुत महँगे दामों पर पूरी की जाती थी या बिल्कुल अन-पूरित थी; इसीलिए इन दोनों उद्यमों को आरम्भ से ही सारे समुदाय का समर्थन और सहयोग मिला। जब विद्युत सहकारी फारम-निवासियों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली देने का महँगा और मुश्किल काम काफी हद तक पूरा कर चुके और उनकी सेवाएँ सुनिश्चित हो गईं, तभी और केवल तभी व्यापारी बिजली कंपनियों का शोरगुल और कटु प्रचार सुनाई देने लगा।

साख-सघों की, प्रति वर्ष लगभग दो हजार नये संघों की गति से हो रही, प्रगति के कारण दूसरे हैं। सबसे पहले तो यह कि कार्य संचालन की दृष्टि से साख सघ बड़ी सरल और सीधी संस्था है। यह अपने सदस्यों की बचतें जमा करती है और बचतों के उस निकाय में से केवल अपने सदस्यों को ही कर्ज देती है। आवश्यक पूँजी सदस्यों को ही पाँच-पाँच डालर के हिस्से बेच कर इकट्ठी की जाती है। दूसरी बात यह कि सूदखोर किसको प्यारा होता है! सारा समाज सूदखोर महाजन से कतराता और उससे दूर रहना पसन्द करता है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से उद्योग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि लोगों को बराबर उधार मिलता रहे, क्योंकि इससे उन उद्योगों के हितों का सीधा सम्बन्ध होता है। इसलिए जब साख-सघ लोगों को सूदखोरी से मुक्त होने और तुरत

कर्ज पाने की सुविधाओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं तो कौन है जो उनका विरोध करेगा ! साख-सर्घों के आविर्भाव के पहले मध्य वित्त के परिवारों के लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से वे उचित ब्याज पर कर्ज पा सके। इसलिए साख सर्घों ने भी विद्युत सहकारियों की ही भाँति जनता की एक ऐसी आवश्यकता को पूरा किया है जो पहले से अनपूरित चली आती थी।

ऐसी ही परिस्थितियाँ हैं जिनमें सहकारी संस्थाएँ बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती हैं।

विभिन्न प्रकार के सहकारियों का असमान गति से उन्नति करते जाना ही उनकी पारस्परिक एकता के लिए बाधक हो गया। सफल और जाने-माने संगठन नये प्रकार के संगठनों से सम्बन्ध करते इसीलिए हिचकिचाते हैं कि इस प्रकार के सम्बन्ध कहीं उनकी सुरक्षित स्थिति को खतरे में न डाल दे।

फिर एकता की भावना के पूरी तरह विकसित और उत्कट न हो पाने का एक कारण यह भी है कि सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं के जीवन में पचास वर्ष की अवधि होती ही क्या है। संस्थाओं के विकास-क्रम में यह समय बहुत थोड़ा है और पच्चीस वर्ष की अवधि तो और भी कम।

जैसा कि हम देख आये हैं सहकारी और पारस्परिक उद्यम हमारे देश में आरम्भ से ही रहे हैं। हमारे जो पूर्वज आरम्भ में यहाँ बसने के लिए आये उनके जीवन के अधिकतर कार्य-कलाप उनके सहकारी प्रयत्नों पर ही निर्भर करते थे और वे अपने अधिकांश जीवन-व्यापार को सहकारी ढंग पर ही संगठित करते थे। वे मिल-जुल कर घर और खलिहान बनाते थे, मिल-जुल कर बीहड़ों और जंगलों को पार करते थे, सर्व सामान्य विपत्तियों में एक दूसरे की सहायता भी सम्मिलित रूप से ही करते थे। सदियों पहले १७५२ में बेजामिन फ्रैंकलिन ने फिलाडेल्फिया में पारस्परिक अग्नि-बीमा कम्पनी बनाई थी। १८०४ में कनेक्टिकट के दूध-उत्पादक किसानों ने दूध बेचने की अपनी सहकारी संस्था स्थापित की थी। उटाह के मरमोन्स लोगों ने सहकारी सिंचाई समितियाँ, सहकारी भण्डारों और सहकारिता के अन्य रूपों के सहारे ही अपने जीवन को विकसित किया। और जैसा कि हम देख आये हैं उन्नीसवीं-शती की ७वीं दशक में ग्रैंगरों ने अपने सदस्यों में सहकारी संगठनों के निर्माण के लिए कितने बड़े प्रयत्न किये थे !

लेकिन जिस तरह के सहकारी उद्यम आज हमारे देश में काम कर रहे हैं यदि उनके आरम्भ का इतिहास टटोले तो पाएँगे कि उन्हें स्थापित हुए अभी पूरे पचास वर्ष भी नहीं हुए हैं; और उस समय भी केवल गिनी-चुनी कृषि-विक्रय सहकारी संस्थाएँ ही बन पाई थीं या दो-एक दूसरी तरह की सहकारी संस्थाएँ होंगी, बस।

पहला साख संघ कानून मसाचुसेट्स की विधान सभा में १९०९ में पारित हुआ।

पहली क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति सहकारी संस्था १९१४ में स्थापित की गई और उसका नाम था फार्मर्स यूनियन स्टेट एक्सचेंज आफ नेब्रास्का।

उपभोक्ता वस्तुओं की पहली क्षेत्रीय थोक सहकारी संस्था १९१७ में विस-कोन्सिन में बनाई गई, जिसका नाम था सेण्ट्रल कोआपरेटिव होलसेल आफ सुपीरियर। इसके केवल एक वर्ष पहले, १९१६ में, न्यूयार्क में सहकारी लीग की स्थापना की गई थी।

१९२१ तक तेल के कारबार में एक भी सहकारी संस्था नहीं थी; उसी वर्ष मिन्नेसोटा राज्य के काटनबुड फाल्स के किसानों ने मिलकर तेल-उत्पादनों के स्थानीय वितरण के लिए एक छोटी-सी सहकारी कम्पनी खोली। १९२६ में मिडलैण्ड के स्थानीय सहकारियों ने मिलकर मिडलैण्ड कोआपरेटिव्स नाम की तेल का थोक काम करनेवाली पहली क्षेत्रीय सहकारी संस्था संगठित की। १९२६ में, न्यूयार्क सिटी में पहली सहकारी गृह निर्माण योजना बनाई गई, जिसे अमलगातेड क्लोदिंग वर्क्स ने प्रायोजित किया था।

पहला सहकारी अस्पताल या कह लीजिए कि स्वास्थ्य-योजना का १९२९ में ओक्लाहोमा राज्य के एल्कसिटी में वहाँ के सुप्रसिद्ध डाक्टर माइकेल शैडिड के सद् प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप स्थापना की गई।

तेल के पहलें सहकारी कुएँ में से सर्वप्रथम १९४० में तेल निकाला गया। इस कुएँ को कञ्जूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन ने कन्सास राज्य के फिलिप्स-वूर्ग के समीप लगवाया था।

अधिकांश शक्तिशाली फारम-आपूर्ति सहकारी संस्थाएँ जिनका कारबार आज सारे संयुक्त राज्य में फैला हुआ है इस शती की दूसरी या तीसरी दशान्दी

में शुरू की गई थी। बड़ी मन्दी के वर्षों में हमारे देश में सहकारी सस्थाओं का बहुत तेजी से विकास हुआ। हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य में 'सहकारी आन्दोलन' का श्रीगणेश बड़ी मन्दी के दिनों से ही होता है।

मन्दी के ही वर्ष थे जब लोग पहली बार सोचने के लिए, बार-बार, बहुत ज़ोरो से और जल्दी-जल्दी सोचने के लिए मजबूर हुए। ये ऐसे वर्ष थे जब प्रचलित व्यवस्था में छाती-ठोक विश्वास ढिगा और क्षीण होने लगा। ये ऐसे वर्ष थे जब लोगों ने नये साधनों की खोज की और उनको अपनाया, क्योंकि जिन पुरानों पर अभी तक निर्भर करते आ रहे थे वे असफल सिद्ध होने लगे थे। और ये ऐसे वर्ष थे जब अधिकांश अमरीकनो ने इस सच्चाई को पहचाना कि वे सब 'एक ही नाव में सवार हैं', उसकी मरम्मत आवश्यक है और अकेला कोई अपने से उसकी मरम्मत नहीं कर सकता।

१९०० की तीसरी दशाब्दी ही थी जब देश में इतने अधिक साख-संघ स्थापित हो चुके थे कि पहली बार उनका राष्ट्रीय संगठन बनाना संभव हो सका और राष्ट्रीय स्तर पर क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन संगठित किया गया। यह मन्दी की प्रतिक्रिया का ही परिणाम था कि ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाएँ शुरू की गईं। पच्चीस वर्षों की छोटी-सी अवधि में लोगों ने बीस हजार साख संघ बना डाले जिनकी कुल सदस्य संख्या एक करोड़ दस लाख और कुल आस्तियाँ पाँच अरब डालर हैं। इन्हीं पच्चीस वर्षों में लोगों ने एक हजार ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाएँ स्थापित की, जिनके ४५ लाख सदस्य हैं, और जो प्रति वर्ष पचहत्तर करोड़ डालर से भी अधिक मूल्य की बिजली बेचती हैं।

दस लाख लोगों को सर्वाङ्गीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की मोमा तक सहकारी स्वास्थ्य योजनाओं का विकास तो पूरा-का-पूरा दूसरे महायुद्ध के परवर्ती काल में ही हुआ है।

मन्दी के ही वर्षों में किसानों के छोटे स्थानीय विक्रेता सहकारियों ने सार्वधिक भण्डार और बिक्री करने के लिए दुकानों और सस्थाओं का निर्माण करना शुरू किया और इस तरह वे माल की किस्म और मूल्य दोनों ही को प्रभावित कर सके।

जहाँ तक नगरों के उपभोक्ता सहकारियों का प्रश्न है, इस सच्चाई से इनकार

नहीं किया जा सकता कि बीच-बीच में बहुत से छोटे भण्डार-खोले गए, लापरवाही से चलाये गए और उन्होंने कुछ वणिज-व्यापार भी किया; लेकिन इस प्रकार के सहकारी उद्यम की सफलता के आवश्यक तत्त्वों का निरूपण पूरी तरह इस सदी की पाँचवीं दशाब्दी में ही हो पाया और तभी कार्य-संचालन को इस तरह व्यवस्थित किया जा सका जिससे भावी प्रगति सुनिश्चित हो सकी।

सहकारी बीमा कम्पनियाँ कब आरम्भ हुई यह तय करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसे 'सहकारी बीमा' कहा जाता है उस काम को करनेवाली 'सहकारी' बीमा कम्पनियाँ केवल एक विशिष्ट दृष्टिकोण वाली पारस्परिक कम्पनियाँ हैं।

सहकारी बीमा के क्षेत्र में किसानों का अग्नि बीमा करने वाली फार्मर्स टाउनशिप म्यूचुअल्स का इतिहास, विशेषरूप से विसकोन्सिन-जैसे राज्यों में, काफी लम्बा और प्रशसनीय रहा है। इन म्यूचुअल्स का आविर्भाव इसलिए हुआ था कि दूसरी कम्पनियाँ किसानों का अग्नि-बीमा करने को तयार नहीं थी। लेकिन कई तरह का बीमा करने वाली सहकारी उद्देश्य और दृष्टिकोण वाली कम्पनियाँ की स्थापना तो इस शताब्दी के दूसरे दशक से ही होने लगी है।

एक प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि सयुक्त राज्य में सहकारी संस्थाओं का विकास तेजी से क्यों नहीं हुआ? इस प्रश्न का आंशिक उत्तर यह है कि विकास तो बहुत तेजी से हुआ है! पच्चीस वर्ष की छोटी-सी अवधि में आप और क्या चाहते हैं? हमारे देश में जितने भी महत्वपूर्ण सहकारी उद्यम हैं उनका सारा विकास इन पच्चीस वर्षों में ही तो हुआ है।

विशाल जन-आन्दोलन इतनी तेजी से कम ही विकसित होते हैं।

सयुक्त राज्य में सहकारियों के एक दर्जन के लगभग राष्ट्रीय संगठन हैं। अपने विशिष्ट अमरीकी ढंग के अनुसार हमारा सारा जोर काम को पूरा करने पर रहा; पद्धति, तर्क-संगति अथवा परिणाम की हमने कोई चिन्ता नहीं की। परिणामस्वरूप ऐसे राष्ट्रव्यापी संगठनों का रूप सामने आय जो अपने कार्यों में कभी-कभी एक-दूसरे पर छा जाते हैं, हावी हो जाते हैं। और समय को देखते पारस्परिक कार्यों में जितना ताल-मेल और उद्देश्य की जितनी एकता आवश्यक है वह स्थापित नहीं हो पा रही है।

देश में एक नहीं दो राष्ट्रीय सहकारी थोक संगठन हैं—मिन्नेसोटा राज्य

के एल्बर्टली नगर का नेशनल कोआपरेटिक्स और ओहियो राज्य के एलायन्स नगर का युनाइटेड कोआपरेटिक्स। युनाइटेड कोआपरेटिक्स फारम-आपूर्ति सहकारियों का स्वामीत्वकृत है और उन्हीं की सेवा करता है। नेशनल के सदस्यों में फारम-आपूर्ति और उपभोक्ता-वस्तु के क्षेत्रीय दोनों ही तरह की सहकारी संस्थाएँ हैं। इसी अन्तर के कारण विलयन के काफी तर्क-सगत कारण होते हुए भी सारे प्रयत्न बार-बार निष्फल होते आ रहे हैं।

कृषि सहकारी संस्थाओं के लिए शिक्षा, वैधानिक (कानूनी) सहायता और जन-सम्पर्क का काम करने वाले दो राष्ट्रीय संगठन हैं। अधिकांश विक्रेता और फारम-आपूर्ति क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा समर्थित अमरीकन इन्स्टीट्यूट आफ को-आपरेशन स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में 'कृषि में सहकारिता' विषय के शिक्षण-अध्यापन को बढ़ावा देने का काम करता है। इस काम के लिए वह सारे देश में शिक्षण शिविर (वर्कशाप) आयोजित करता है, एच-४ और भावी कृषकों के सर्वांगीण विकास के लिए बनाये गए 'फारमर फ्यूचर' संगठनों के साथ मिलकर काम करता है, अनुसन्धान कार्यों के अतिरिक्त प्रतिवर्ष एक वार्षिक ग्रन्थ प्रकाशित करता है, और एक वार्षिक पीठ चलाता है जिसमें सारे देश के सहकारी नेता एकत्रित होते हैं।

दूसरे संगठन का नाम है नेशनल कौन्सिल आफ फारमर कोआपरेटिक्स। अमरीकन इन्स्टीट्यूट की तरह अधिकांश कृषि विक्रेता और फारम-आपूर्ति क्षेत्रीय संस्थाएँ इसकी भी सदस्य हैं। इस नेशनल कौन्सिल से छब्बीस राज्य स्तरीय सहकारी कौन्सिलें सम्बद्ध हैं। यह वार्षिक संगठन में कृषक-सहकारी सभाओं के हितरक्षण का काम और सटिप्पण लेखाचित्रों वाले एक साप्ताहिक पत्र, 'दि वार्षिक गटन सिचुएशन' का प्रकाशन करती है। एक वार्षिक सभा का आयोजन इसके द्वारा भी किया जाता है, जिसमें फारम सहकारियों से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार होता है। नेशनल कौन्सिल इन सभाओं में कृषि सहकारियों के लिए नीति-निर्धारण का काम भी करती है—विशेषकर ऐसी नीतियों के निर्धारण का जो कृषि सहकारियों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विधि व्यवस्था को प्रभावित करनेवाली होती हैं; और यही वह क्षेत्र है जहाँ इन दोनों राष्ट्रीय संगठनों में एकता स्थापित हो सकती है।

नेशनल फेडरेशन आफ ग्रेन कोआपरेटिव्स अनाज-विक्रेता सहकारियों की जनसम्पर्क और विधायी संस्था है और अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम करती है। इसके कार्यकारी सचिव के साप्ताहिक वृत्त पत्र में अमरीकी कृषि के सम्बन्ध में काफी मूल्यवान और प्रचुर जानकारी रहती है।

नेशनल मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन अपने सहकारी दूध उत्पादकों के लिए ठीक इसी तरह के काम करता है।

साख-संघों ने प्रायः सभी राज्यों में अपने राज्य-संघ बना लिये हैं। ये राज्यस्तरीय संगठन साख-संघ आरम्भ करने के अभिलाषी नये जन-समूहों की सब प्रकार से सहायता करने के अतिरिक्त पुराने स्थापित साख-संघों को मलाहू और प्रोत्साहन एवं उनके निर्देशन का काम करते हैं; राजधानियों में विधायी कामों की देखभाल और जन-सम्पर्क भी करते हैं। साख-संघ आन्दोलन की केन्द्रीय संस्था का नाम है क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन, जिसे संक्षेप में 'कुना' कहते हैं। इसका प्रधान कार्यालय विसकोन्सिन राज्य के मेडिसन नगर में है। कुना अपना एक मुखपत्र प्रकाशित करता है, जिसका नाम 'दिब्रिज' है, साख-संघ से सम्बन्धित साहित्य का सम्भरण करता है और काँग्रेस में साख-संघों के हितों की देखभाल करता है। कुना से संयुक्त कुना सप्लाई कोआपरेटिव है, जो साख-संघों के लिए आवश्यक लेखन-सामग्री-लेखा पत्रक, जमा पुस्तिकाएँ, ऋण-याचना-पत्रक आदि अधिप्राप्ति की और उत्पादन का काम करता है। और कुना म्यूचुअल इन्श्यूरेन्स कम्पनी साख-संघों और उनके सदस्यों का ऋण-सुरक्षा बीमा, आजीवन-वचत बीमा और प्रत्यक्ष जीवन बीमा करती है।

ग्रामीण विद्युत् सहकारियों के संगठन का रूप बहुत-कुछ साख-संघों से मिलता-जुलता है। लगभग सभी राज्यों में राज्य स्तरीय संगठन हैं। राज्य स्तरीय संगठनों को इलाकों में गठित किया गया है। इलाके ही नेशनल रूरल इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव एसोसिएशन (ब्रेका) के निर्देशकों का चुनाव करते हैं। ब्रेका का प्रधान कार्यालय वाशिंगटन डी० सी० में है। यह काँग्रेस में विधायी कार्यों की देखभाल और 'दि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन' नामक मुखपत्र के प्रकाशन के अतिरिक्त प्रसार-प्रचार और शैक्षिक कार्य भी करता है।

कोआपरेटिव फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स आफ अमरीका फुटकर विक्रेताओं के

स्वामीत्वकृत किराना थोक सहकारियों के हितों की रक्षा और सबर्द्धना करने वाला बड़ा प्रभावशाली और समर्थ राष्ट्रीय सगठन है। 'दि कोआपरेटिव मर्केण्डाइज' नामक मुखपत्र के प्रकाशन के अतिरिक्त यह जन सम्पर्क का कार्य भी करता है।

देश की अधिकांश महत्वपूर्ण सामूहिक स्वास्थ्य योजनाएँ, श्रमिक स्वास्थ्य योजनाएँ और सहकारी स्वास्थ्य सघ ग्रूप हेल्थ एसोसिएशन आफ अमरीका (घ) की सदस्य हैं। यह सगठन निम्नलिखित कार्य करता है : सामूहिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन और वितरण; योजना को प्रारम्भ करने के अभिलाषी नये समूहों को परामर्श और मार्गदर्शन; सामूहिक स्वास्थ्य को वार्षिक राष्ट्रीय सभा का आयोजन; मासिक पत्र का प्रकाशन; सामूहिक स्वास्थ्य सघों से संयुक्त डाक्टरों के साथ भेद-भाव बरते जाने पर उनको रक्षा; विवि-व्यवस्था से सम्बन्धित—विशेष रूप से स्वैच्छिक स्वास्थ्य सगठनों के लिए प्रतिबन्धकारी कठिनाइयों को हटवाने के लिए वैधानिक कार-रवांइयाँ।

संयुक्त राज्य की सहकारी लीग (कोआपरेटिव लीग आफ दि युनाइटेड स्टेट्स) सारे देश में उपभोक्ताओं की सहकारिता के सभी रूपों की उन्नति के लिए १९१६ में स्थापित की गई और १९२२ में शासपत्रित हुई। जैसे-जैसे समय बीतता गया लीग का कार्यक्षेत्र भी व्यापक और विस्तारित होता गया। लीग का प्रधान कार्यालय शिकागो में और एक कार्यालय वाशिंगटन डी० सी० में भी है।

कई बड़े क्षेत्रीय फारम-आपूर्ति सहकारी, उपभोक्ता वस्तुओं के सभी बड़े क्षेत्रीय थोक सहकारी, कई पारस्परिक बीमा कम्पनियाँ, क्रेडिट यूनियन नेशनल एसोसिएशन, नेशनल रूरल इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव एसोसिएशन, विसकोन्सिन इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव, नेशनल कोआपरेटिव्स, युनाइटेड हाउसिंग फाउण्डेशन, और विभिन्न प्रकार के कई सहकारी सगठन लीग के सदस्य हैं।

लीग जिन संगठनों के कार्यों में सहायता और प्रायोजन करती है उनके नाम इस प्रकार हैं : कोआपरेटिव इन्व्यूरेन्स कान्फ्रेन्स, ग्रूप हेल्थ एसोसिएशन आफ अमरीका, नार्थ अमरीकन स्टूडेंट कोआपरेटिव लीग, रोशडेल इन्स्टीट्यूट,

कोआपरेटिव फाइनेन्स एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन आफ हाउसिंग कोआपरेटिव्स और दि फण्ड फार इण्टर नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेण्ट।

लीग सहकारिता की अन्तराष्ट्रीय संस्था इण्टर नेशनल कोआपरेटिव अलायन्स की अमरीकी सदस्य है। यह पैतालीस राष्ट्रों के सहकारी संगठनों का महासंघ है, जिनकी संयुक्त सदस्य संख्या पन्द्रह करोड़ से भी अधिक है।

लीग निम्नलिखित कार्य करती है: देश के सहकारिता से सम्बन्धित समाचार पत्रों के लिए खबरें इकट्ठी करने की केन्द्रीय सवाद एजेंसी, कोआपरेटिव न्यूज सर्विस, का संचालन; साहित्य का प्रकाशन और वितरण एवं फिल्म निर्माण; सहकारी संगठनों के जन-सम्पर्क कार्यों का समन्वय; धार्मिक, कृषि, श्रमिक और अन्य राष्ट्रीय संगठनों से सम्पर्क और संयुक्त कार्रवाई; और विधायी कार्य। लीग सम्मेलनों, पीठी और सभाओं के वार्षिक कार्यक्रम भी आयोजित करती है जिनका मुख्य प्रयोजन है सहकारी व्यवस्थापकों, सम्पादकों, शैक्षिक एवं कार्मिक कार्यकर्तियों की क्षताओं को बढ़ाना और उनके कार्यस्तर को उन्नत करना।

इस प्रकार सहकारी लीग संयुक्त राज्य के सभी प्रकार के सहकारियों का सर्वमान्य मिलन स्थल और सेवा संस्था की गरज पूरी करती है; लेकिन फिर भी इसको सदस्य संख्या देश के सभी सहकारी संगठनों की संयुक्त सदस्य संख्या से बहुत कम है।

राष्ट्रीय संगठनों की इस बहुलता के कई कारण हैं। देश में कई प्रकार के सहकारी उद्यम हैं और सब के हित और सब की आवश्यकताएँ अलग-अलग हैं। उन भिन्न हितों की रक्षा और भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति उनके अपने विशेषीकृत संघ ही अच्छी तरह कर सकते हैं। फिर स्पर्धा व्यापार का ही प्राण नहीं वह एक ही क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों के लिए दूसरों से ज्यादा अच्छी सेवा करने की दिशा में स्वस्थ प्रोत्साहन भी है।

लेकिन समस्या राष्ट्रीय संगठनों के बाहुल्य की उतनी नहीं है जितनी उनमें पारस्परिक समन्वय की कमी, प्रयोजन की एकोन्मुखता के अभाव और किसी-किसी मामले में भीड़ता की। कुछ बहुत बड़े और बहुत शक्तिशाली सहकारी व्यवसाय समूचे व्यापारिक समुदाय से स्वीकृति प्राप्त करने के इतने उत्पुङ्ग रहते हैं कि अपने सहकारी होने की बात को हर तरह से दबा-छिपाकर रखते हैं

और किसी पर भी प्रकट होने देना नहीं चाहते। अपने लिए 'सहकारी आन्दोलन' पद का प्रयोग उन्हें बिलकुल नहीं सुहाता; यही चाहते हैं कि लोग उन्हें एक परिपाटी बद्ध साधारण व्यवसाय ही समझते रहे और उनके काम-काज को कोई सामाजिक या आर्थिक महत्त्व न दिया जाए।

इस तरह की भावना के कारण मिले-जुले हैं, पर सभी बुरे हैं ऐसी बात भी नहीं है।

जब सहकारी उद्यमों के स्वामी स्वयं अपने बारे में, या दूसरे उनके बारे में, यह सोचा करते थे कि वे जन-समाज से भिन्न अथवा हमारे आर्थिक जीवन की मुख्य धारा से कटे-छटे विजातीय द्रव्य या कोई पन्थ हैं, वह जमाना तो कभी से बीत गया। सहकारी उद्यम हमारे आर्थिक जीवन से पृथक् तो कभी थे भी नहीं वस्तुतः वे हमारी स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्था के ही अविकल, महत्त्वपूर्ण और अंगीभूत तत्त्व हैं। भिन्न प्रयोजनों और भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से आविर्भूत कई प्रकार के व्यापारी संगठनों का समावेश होने के कारण 'स्वतन्त्र' अर्थ व्यवस्था सदैव मिश्रित अर्थ व्यवस्था भी होती है।

लेकिन यह तो मानना ही होगा कि सहकारी उद्यम दूसरे सभी प्रकार के उद्यमों से भिन्न होते हैं। उनमें अनुपम विशेषताएँ होती हैं और वे अनुपम योग दे सकते हैं। उनकी इन विशेषताओं को भुलाना नहीं चाहिए; और यह भी याद रखना चाहिए कि इन विशेषताओं में आस्था रखने वाले लोग अपने-जैसे दूसरे आस्थावानों के साथ सम्मिलित रूप से काम करने को प्रस्तुत होकर ही इन विशेषताओं को पूरी तरह निष्पादित कर सकते हैं।

जब इस तरह का सम्मिलित कार्य होने लगेगा—जिसके कि सकेत मिलने लगे हैं—तब अमरीका के कुछ लोगों में एक ऐसे शक्तिशाली, निश्चयात्मक और सुदृढ़ आन्दोलन का तत्त्व प्रस्फुटित होगा जिसे सही अर्थों में सहकारी कहा जा सकेगा—फिर उस आन्दोलन की अभिव्यक्ति के सगठनात्मक रूप और प्रतिरूप किसी भी तरह के कर््यों न हों और चाहे बिलकुल ही न हों।

यह नहीं हो पाया उसके दो प्रमुख कारण हैं।

पहला कारण है उन्नति की समस्या। सहकारी व्यवसाय के नेताओं को तुरत और लग कर जो काम करना होता है वह यह कि जिस तेज गति से

उनके प्रतिस्पर्द्धी उन्नति करते जा रहे हैं कम-से-कम वही गति उनके अपने सगठन की भी हो। इसके लिए शक्ति को और विशेष रूप से आर्थिक शक्ति को दृढ़ करने की, दूरदर्शितापूर्ण व्यवस्था की, श्रेष्ठतम अन्वेषण की, उत्कृष्ट जन-सम्पर्क को चरमावस्था तक ले जाने की और सदस्यों एवं सरक्षकों की अत्यन्त प्रगतिशील सेवाओं की आवश्यकता होगी।

इन सारे कार्यों को पूरा समय लगा कर, तन्मय हो कर करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही उन्नति होने लगती है एक नया प्रश्न उठ खड़ा होता है। वह यह कि क्या बड़े पैमाने के सहकारी उद्यम के निर्माण की प्रक्रिया में ही ऐसे तत्त्व समाये रहते हैं जिनके कारण कुशल व्यापारी नेता शिक्षा के द्वारा सदस्य-स्वामियों में आदर्शवाद, उद्देश्य परकता, और सक्रिय सहभागिता के पोषण का विरोध करने लग जायँ—उन्हीं सदस्य-स्वामियों में, जो सच्ची सहकारी संस्थाओं के प्राण, उनकी शक्ति का अमित स्रोत और किसी भी आन्दोलन की आधार शिला होते हैं ?

यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न आज भी अनुत्तरित है !

अमरीका में सहकारिता के शक्तिशाली न हो पाने का दूसरा कारण भी बहुत-कुछ पहले कारण की ही तरह सहकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित है। वह यह कि कई सहकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपने कार्य में—जिस कार्य में वे लगे हुए हैं उसी कार्य में जाग्रत विश्वास नहीं है। कुछ ही समय पहले विसकोन्सिन की एक फारम-आपूर्ति और उपभोक्ता सहकारी संस्था की वार्षिक सभा के समक्ष भाषण करते हुए शिकागो की एक बड़ी रसायनिक कम्पनी के, जो सहकारी नहीं है, व्यवस्थापक महोदय ने इस सम्बन्ध में बड़ी पते की बात कही थी। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं :

“आप लोग बड़े कारबार को तरह काम करने की धुन में बहुत अधिक लगे रहते हैं—उस दिशा में बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं।

“जब तक सहकारी बड़े व्यवसायों के तौर-तरीके अपनाते रहेंगे, उनकी नकल करते रहेंगे तब तक वे सहकारियों की ओर से निश्चिन्त हैं, क्योंकि उनके तरीकों पर चलकर सहकारी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आपके पास तो बड़े व्यवसाय से भी काफी बड़ी चीज है; वह है सातवाँ रोश-डेल सिद्धान्त : ‘निरन्तर शिक्षित करते रहो।’

“आपका आन्दोलन तो दुनिया के विशालतम आन्दोलनों में से है। आप इसको छोटा क्यों करते हैं, इसकी मर्यादा क्यों घटाते हैं ?

“दुनिया पुकार-पुकार कर सहकारी आन्दोलन से आर्थिक सहायता माँग रही है और सहकारी आन्दोलन जो सबसे बड़ी आर्थिक सहायता दे सकता है वह है ईसाइयत और विश्व के सभी महान धर्मों का आर्थिक भाष्य—आर्थिक क्षेत्र में उनपर आचरण। लेकिन मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ कि कोई उठे और इस बात को कहे तो सही।

“दुनिया अमरीका से घृणा क्यों करती है ?

“हमारे मिसनरी सारी दुनिया में ईसाई धर्म का उपदेश दे रहे हैं—उसका प्रचार कर रहे हैं, इसके साथ-ही-साथ हम दुनिया के लोगों को जो सबसे श्रेष्ठ आर्थिक ज्ञान—श्रेष्ठतम आर्थिक धर्म दे सकते हैं वह है प्रतियोगिता पूँजीवाद।

“आप किसी व्यवस्थापक से पूछिए कि आप किस तरहकी सहकारी संस्था है, तो वह तपाक से उत्तर देगे : ‘हमने गत वर्ष दस, बीस या तीस लाख डालर का व्यापार किया।’

“मुझे यह बात हमेशा परेशान करती रही है कि डेढ़ सौ वर्ष हो गए और उन मूल सात रोशडेल सिद्धान्तों में न तो हम कोई वृद्धि कर सके, न उनसे कुछ ले ही सके।

“प्रत्येक स्थानीय सहकारी संस्था द्वारा सहकारी लीग को शिक्षा के लिए अधिक धन और हर स्थानीय सहकारी संस्था में एक शिक्षा समिति सही दिशा में उचित कदम होंगे।

‘शिक्षा से प्रेरणा पाकर विस्तार और ज्यादा होगा, सेवा और अच्छी होगी।’

“विश्व को युवकों के विचारों और उनके उत्साह की आवश्यकता है और सहकारी आन्दोलन युवकों को सब कुछ दे सकता है।”

जब सहकारी नेता और सदस्य अपने काम और अपनी संस्था के मूल्य और महत्त्व को इतनी स्पष्टता से देख और समझ सकेंगे जितनी स्पष्टता से एक प्रतियोगिता व्यापारी कम्पनी के इस व्यवस्थापक ने देखा और समझा है तभी संयुक्त राज्य अमरीका में सहकारी विचार और सहकारी पद्धति अपना सही स्थान ग्रहण कर सकेंगे।

उसके पहले नहीं।

सहकारी उद्यम कितना ही बड़ा क्यों न हो ज़ूय तब भी नहीं !

१२ | वर्तमान और भविष्य

दूसरे महायुद्ध के समय हर चीज दुर्लभ हो गई। उस समय सयुक्त राज्य में केवल फोर्ट नाक्स का सोना ही एक ऐसी चीज थी जिसका कोई भी व्यावहारिक उपयोग किसी की समझ में नहीं आया। बाकी तो, कहते दुःख होता है, पर सचाई यही है कि युद्ध के समय हर व्यापार में, यहाँ तक कि जो अयोग्य और अक्षय थे उनमें भी खूब तेजी आई और सभी फले-फूले।

कुछ सहकारी संस्थाएँ काफी अच्छी तरह जम चुकी थी और बहुत अच्छी तरह चलाई जा रही थी। कुछ इतनी अच्छी नहीं भी थी; लेकिन युद्ध काल की तेजी में काम सभी काफी अच्छा कर रही थी, या कम-से-कम लगता तो यही था।

लेकिन जैसे ही शान्ति हुई छोटी और अयोग्य संस्थाओं की मुसीबत के दिन आ लगे। ईस्ट कोस्ट की तरफ बहुत-सी छोटी-छोटी उपभोक्ता सहकारी संस्थाएँ खतम हो गई। ईस्टर्न कोआपरेटिव होलसेल भी करीब-करीब ठप्प हो गया। यहाँ तक कि कुछ फारम-आपूर्ति सहकारी संस्थाएँ भी मुसीबत में पड़ गईं। नेशनल फार्म मशीनरी कोआपरेटिव का दिवाला पिट गया। नेशनल कोआपरेटिव्स को अपने कई कारखाने बेच देने पड़े और उन्नीस सौ की चाँची दशाब्दी में तो एक समय ऐसा भी आ गया था, जब उसका दिवाला पिटते-पिटते बचा।

जैसे ही सरकार ने युद्ध कालीन मूल्य-नियन्त्रण को रद्द किया निर्वाह-खर्च बढ़ने लगा। श्रमिक-संघ के हलकों में केस-लाट (Case-lot) प्रवृत्ति से चीजे खरीदने की रुचि और प्रवृत्ति ज़ोर पकड़ने लगी। डेट्रोइट क्षेत्र में आदर्शवादी सहकारी कार्यकर्ता, जो व्यवहारिकता में निपट कोरे होते थे, श्रमिक-संघ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर घडाघड़ उपभोक्ता सहकारी भण्डार खोलने लगे। उत्साह बहुत होता था, लेकिन योजना और उपाय काफी

कमजोर होते और अच्छी व्यवस्था तो प्रायः दुर्लभ ही होती थी। ऐसी स्थिति में कोई सहकारी भण्डार ज्यादा चलता भी कैसे ? कुछ ही दिनों में उसका टाट उलट जाता। और एक-एक कर सब इसी घाट उतर गए।

ऐसा लगता है कि युद्ध और युद्धोत्तर-काल में सहकारी आदर्शवादिता की अवलता और व्यावहारिकता की कई अशो में उपेक्षा सम्भवतः अवश्यम्भावी ही थी।

भूत काल में सयुक्त राज्य की सहकारी संस्थाओं में अतिरेकता की दुर्भाग्य-पूर्ण प्रवृत्ति रही है—वे घोर आदर्शवादिता और निरे व्यापार के दो ध्रुवों के बीच घड़ी के लोलक की तरह दोलायमान होती रही हैं। कुछ सहकारी नेता और कार्यकर्ता इस उद्यम को आर्थिक कार्य-व्यापार से अधिक, लोगों में सामाजिक सम्बन्धों को उन्नत करने, न्याय भावना को बढ़ाने और संसार को ज्यादा अच्छा बनाने का साधन मानते रहे हैं। दूसरे उतनी ही कट्टरता से इसे सदस्यों और सरक्षकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुँचाने वाला कार्यक्षम व्यावसायिक कारबार समझते रहे हैं; 'दुनिया के उद्धार' से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। इनमें से कभी एक समूह हावी हो जाता और कभी दूसरा।

दोनों छोरों का समन्वय कर एक मध्यम मार्ग का निष्पादन कठिन ही बना रहा। सरल होता भी कैसे ? रही कारबार के साथ सच्चे आदर्शवाद को जोड़ना उतना ही कठिन है जितना कि उच्च और व्यापक दृष्टिकोण के बिना केवल अच्छे व्यापार के सहारे सहकारिता के सफल होने की आशा करना। इन दोनों गुणों को न तो एक-दूसरे से अलग किया जा सकता है और न एक-दूसरे के विरोध में ही रखा जा सकता है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा फल-फूल नहीं सकता। आलंकारिक भाषा में कह सकते हैं कि व्यापार का अच्छा संचालन और सहकारिता के मूल्यों में सदस्यों का अकृत्रिम विश्वास स्वस्थ सहकारी शिशु के माता और पिता हैं।

आदर्शवादिता के अतिरेक की प्रतिक्रिया अवश्यम्भावी थी। १९५० में सहकारी लीग का शिकागो में जो द्विवार्षिक सम्मेलन हुआ उसमें एक प्रस्ताव पारित कर लीग से कहा गया कि 'वह जो भी करे उसके व्यवस्था-पक्ष पर पूरा-पूरा जोर दिया जाए।' सहकारी लीग के शैक्षिक कार्यों का कुछ दायित्व नेशनल

कोआपरेटिक्स को सौपने के जो प्रयत्न किये जा रहे थे उन्हें बन्द कर देना पड़ा; इसमें थोड़ी जल्दीबाजी अवश्य हुई, परन्तु वह निर्णय सर्वथा उचित ही था। सभाएँ करके बड़ी गम्भीरता से यह सोचा जाने लगा कि जो संस्थाएँ ठप्प हो गई हैं और जिनका कारबार ठीक-से नहीं चल रहा है उन्हें ठीक ठाक करने के क्या उपाय किये जाने चाहिए—सबसे अधिक सोच-विचार किराना भण्डारों के बारे में किया गया क्योंकि वे ही सबसे बड़ा सिर दर्द बने हुए थे।

इसी समय दुबले और दो अषाढ़ वाली कहावत भी चरितार्थ हुई। ठीक उन्ही दिनों अमरीका में सहकारी संस्थाओं का सुसंगठित विरोध आरम्भ हुआ। पश्चिमोत्तर में (नार्थवेस्ट) गल्ला सहकारियों की एक प्रतियोगी संस्था ने विरोधी आन्दोलन के लिए नेशनल टैक्स इक्विलिटी एसोसिएशन (एनटी—राष्ट्रीय कर-समता सघ) की स्थापना में आगे बढ़ कर हिस्सा लिया। 'एनटी' ने तरह-तरह के स्वरो से बहला-फुसला कर अमरीकी जनता के मन में यह धारणा बद्ध मूल करने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये कि 'सहकारी संस्थाएँ कर नहीं देती हैं।' सहकारी संस्थाओं के लिए इस झूठ का भण्डाफोड़ करना कोई कठिन काम नहीं था। लेकिन सहकारी संस्थाओं ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। झूठा वादी गला फाड़-फाड़ कर चिल्ला रहा था और लाखों लोग सुन रहे थे और सच्चा प्रतिवादी चुप था, वह सचाई किसी को भी नहीं बता रहा था।

'एनटी' बिल्कुल नया संगठन था, पर फिर भी उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी; निजी बिजली कम्पनियाँ, गल्ले की आढ़ते, तेल कम्पनियाँ, लौहखण्ड के थोक व्यापारी और सहकारियों के प्रतियोगी सारे कारबार चारों ओर से 'एनटी' पर पैसे की वर्षा कर रहे थे। फिर 'एनटी' अपने झूठ के प्रचार के लिए 'जन सम्पर्क' और प्रसार-प्रचार का काम करने वाली श्रेष्ठ और कुशलतम कम्पनियों को क्यों न लगाता ? उसने वही किया।

शीघ्र ही यह बात समझ में आई कि सहकारी संस्थाओं की व्यावसायिक दक्षता और कार्य क्षमता पर ही जोर देना आवश्यक नहीं है, जनता को अपने बारे में बताने का जन-सम्पर्क का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। या जैसा कि जन-सम्पर्क का कार्य करने वाली बिरादरी में कहा जाता है, सहकारियों

को 'पहले उस तरह रहने और तब उसके बारे में कहने' की जरूरत थी। और तब सहकारी सस्थाओं ने इस काम को १९५० में बड़ी मन्दगति से और काफी हिचकिचाते हुए शुरू किया।

द्वितीय महायुद्ध के बाद के पन्द्रह वर्षों में अमरीकी सहकारी सस्थाओं ने बड़े कड़वे अनुभवों के बाद जो सबक सीखे उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- १—कोई सहकारी व्यापार या सगठन एक जगह स्थिर नहीं रह सकता—वह या तो बढ़ता, फैलता और ऊँचा उठता है या मरने लगता है;
- २—निरे आदर्शवाद और उत्साह के सहारे जीवित रहने वाले छोटे सहकारी सगठनों के दिन लड़ गए; सहकारी व्यवसायों को प्रभावशाली बनाने के लिए समन्वयन, सघ बढ़ता और विलयन नितान्त आवश्यक हो गए हैं, कच्चे माल और मूल स्रोतों से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचने के सभी कार्य-व्यापारों के एकीकृत सघटन की पद्धति को अपनाया ही जाना चाहिए;
- ३—कार्य-विस्तार की सही पद्धति नई-नई सहकारी समितियों का निर्माण नहीं; सुस्थापित सस्थाओं का समुचित उन्नति करते जाना है, अर्थात् विस्तार शक्ति के केन्द्रों से होना चाहिए। शहरों में सहकारी गृह-निर्माण शक्ति का ऐसा ही केन्द्र है; ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहकारी सस्थाएँ शक्ति का केन्द्र हैं;
- ४—अच्छी व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है और सहकारी सस्थाओं का प्रबन्ध किसी भी अन्य व्यावसायिक सस्था के जैसा या उससे श्रेष्ठ हो सकता है,
- ५—किसी भी प्रकार के सहकारी की सेवाओं पर मनमाने प्रतिबन्ध लगाना जैसे कि केवल किसानों या जाति-विशेष या राष्ट्र-विशेष के समूहों या एकल-सदस्यता-सगठनों के सदस्यों तक सेवाओं को सीमित करना अव्यावहारिक ही नहीं सकटास्पद भी है। सभी को सदस्य बनाने की खुली सदस्यता सहकारिता का सिद्धान्त ही नहीं सहकारी संस्थाओं के कामकाज के लिए बहुत अच्छा नियम भी है;
- ६—सहकारी सस्थाओं की जितनी ही उन्नति और वृद्धि होती जाती है सदस्यों की शिक्षा और कार्यशीलता के कार्यक्रमों को उतना ही बढ़ाते जाने की जरूरत होती है, कम करने की तो जरा भी नहीं। उदाहरणार्थ पालिसी-

धारियों की सक्रिय सहभागिता और उनके नियन्त्रण को विकसित करने का उन्नतिशील सहकारी बीमा कम्पनियाँ जो प्रयत्न करती हैं वह उस संघर्ष के बहुत समीप हैं जो आधुनिक मानव अपनी नियति को अपने बस में रखने के लिए करता है, क्योंकि एक तो लोगों की वचते उनकी उन्नति का प्रवेश द्वार होती है और दूसरे वे इस तरह अपनी वचतो को बीमे में अधिकाधिक निवेशित करते हैं।

- ७—सहकारी सस्थाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए, जिससे वे अपने कर्तव्य को ठीक-ठीक निभा सके, जितनी पूँजी की आवश्यकता होती है उसे परम्परागत उपायों से प्राप्त करना अब सम्भव नहीं रह गया है; ८—अधिकांश अमरीका वासी बिल्कुल ही नहीं जानते कि सहकारी सस्थाएँ क्या हैं, वे क्यों बनाई गई हैं और अमरीकी जीवन-पद्धति को वे कौन से मूल्य और लाभ प्रदान कर सकती हैं; अतएव सहकारी सस्थाओं के लिए जन-सम्पर्क और प्रसार-प्रचार का काम भी करणीय है और इस कार्य का महत्त्व दूसरे किसी भी कार्य से जरा भी न्यून नहीं है।

इन बातों को केवल सैद्धान्तिक रूप से समझ कर ही नहीं छोड़ दिया गया, व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न भी किया गया।

१९५१ में कोआपरेटिव मैनेजमेण्ट डेवलपमेण्ट प्रोग्राम (सहकारी व्यवस्था विकास कार्यक्रम) आरम्भ किया गया। प्रबन्धन-प्रशिक्षण और कार्य-संचालन की क्षमता को विकसित करने वाले एक कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए सहकारी लीग की प्रेरणा से तीन क्षेत्रीय सहकारी सस्थाओं और दो सहकारी ढंग की पारस्परिक बीमा कम्पनियों में से प्रत्येक तीन-तीन हजार डालर लगाने को राजी हो गई, और पाँच हजार डालर स्वयं सहकारी लीग ने लगाये। इन सस्थाओं ने इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के निम्न कारण बताये:

संयुक्त राज्य की जिन सहकारी सस्थाओं की नींव काफी मजबूत हो चुकी है आज उनकी सबसे बड़ी और सबसे पहली आवश्यकता ऐसे प्रबन्ध कर्मचारियों को निरन्तर तैयार करते जाना है जो आधुनिक ढंग के प्रबन्धन में सक्षम और दक्ष हों। इस तरह के प्रबन्धक तैयार करने की दिशा में किसी सुव्यवस्थित कार्यक्रम का अभाव ही सम्भवतः आज

इस सदी की पाँचवी दशाब्दी में उन्नत प्रबन्धन, कार्यकर्ताओं के विकास और संगठनात्मक रूपों को ज्यादा अच्छा बनाने की रचि और प्रवृत्ति बढ़ी। कोआपरेटिव मैनेजमेण्ट डेवलपमेण्ट प्रोग्राम में कुछ बड़े संगठन और सम्मिलित हो गए और इस तरह हिस्सा लेने वाले सदस्यों की संख्या दस हो गई।

इसके वार्षिक पीठ, इन्स्टीट्यूट आफ माडर्न मैनेजमेण्ट में, 'जहाँ शिक्षण-शुल्क दो सौ डालर है, उपस्थिति-संख्या बढ़ते-बढ़ते एक सौ हो गई।

बीमा कम्पनियों और क्षेत्रीय थोक सहकारी संस्थाओं द्वारा सम्बद्ध स्थानीय संगठनों के व्यवस्थापकों और प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्य करनेवाले अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण और कार्य कुशलता-वृद्धि के कार्यक्रम आरम्भ किये गए।

विशेषज्ञों के परामर्शानुसार दुकानों, कार्यालयों एवं साधन-सुविधाओं का आधुनिकीकरण, एक रूपता और विज्ञापन, बाजारों का सर्वेक्षण, लम्बी अवधि की विस्तार योजनाएँ आदि कार्य प्रबन्धन के अध्ययन और शिक्षा-दीक्षा के बाद ही आरम्भ हुए।

अपने विषय के श्रेष्ठ परामर्शदाताओं को अच्छा पारिश्रमिक देकर संगठनात्मक रूपों में काफी परिवर्तन-परिवर्द्धन किये गए। निदेशक मण्डल और व्यवस्था-विभाग एवं विभागीय अध्यक्षों के 'प्रबन्धक दल' तथा 'व्यवस्था परिषद्' के सदस्यों में पारस्परिक समझ और अच्छे सम्बन्धों के विकास के लिए नये तरीके अपनाये गए और पहले से ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा।

इसी बीच नेशनल रूरल इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव एसोसिएशन ने प्रबन्धन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम आरम्भ किया जिसका कार्य क्षेत्र कुछ ही वर्षों में राष्ट्रव्यापी हो गया। वह ग्रामीण विद्युत् व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था। इसने विद्युत् सहकारी संस्थाओं के हजारों व्यवस्थापकों, विभागीय अध्यक्षों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान किया। इस योजना के अन्तर्गत व्यवस्थापकों और लाइन के अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी किया गया।

अमरीकन इन्स्टीट्यूट आफ कोआपरेशन की वार्षिक सभाएँ कृषि सहकारियों में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण-सत्रों का रूप धारण करने लगी।

इसी दशाब्दी में सहकारी लोग ने जनसम्पर्क-निदेशक, वित्त-अधिकारी, शैक्षिक निदेशक और सम्पादक आदि सहकारी कर्मचारियों के विशिष्ट समूहों के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग पीठों और सम्मेलनों का एक कार्यक्रम तैयार किया।

ऐसे ही कुछ सम्मेलनों में पेशेवर संगठनों की नींव पड़ी, जिनमें से एक कोआपरेटिव एडिटोरियल एसोसिएशन भी है। १९६० तक इसके दूध-विक्री से लेकर नगर-उपभोक्ता और साख-सघों तक सभी प्रकार के सहकारी प्रकाशन के एक सौ से भी अधिक सम्पादक सदस्य हो गए थे। सम्पादकों के इस संगठन की वार्षिक सभाएँ सहकारी पत्रकारिता के सक्षिप्त पाठ्यक्रम वाले लघु शिक्षा-सत्र ही होता है जहाँ सहकारी प्रकाशनों के सम्पादन का विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है।

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान शती की पाँचवीं दशाब्दी में सहकारी व्यवसाय ने व्यक्तता प्राप्त की।

कुछ मामलों में तो इसके विकास की गति दूसरे सभी प्रकार के व्यवसायों से तेज रही, जो आवश्यक भी थी, क्योंकि यह काफी पिछड़ रहा था और इसे उस पिछड़ेपन को बहुत थोड़े समय में पूरा कर लेना था।

और निश्चय ही इसन बरसों का काम महीनों में पूरा कर डाला।

इसका मुख्य कारण यही था कि सहकारी नेताओं की मनोवृत्ति में अब काफी परिवर्तन हो चुका था। सहकारी लोग और नेशनवाइड इन्श्यूरेन्स कम्पनीज के अध्यक्ष मरे डी लिंकन जैसे कुछ नेताओं ने आत्म सन्तोष की हानिप्रद मनःस्थिति से जमकर संघर्ष किया। वे इस बात की बराबर शिकायत करते रहे कि उन्नति नहीं हो पा रही है और सहकारी उद्यम अमरीकी अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंश बनने में बराबर असफल होता जा रहा है।

युद्धोत्तर काल के वर्षों में रचनात्मक असन्तोष क्रमशः आत्मसन्तोष का स्थान ग्रहण करता चला गया। यह धारणा दृढ़ होती गई कि अपने प्रतियोगियों से इक्कीस होकर ही सहकारी व्यवसाय जीवित रह सकता है और उन्नति कर सकता है।

सहकारिता का विचार और पद्धति निश्चय ही अच्छी और हितकर है।

लेकिन दूसरे महायुद्ध का अन्त होने तक यह विचार व्यापारिक सफलता से बँधाघिसटता रहा। सदस्यों से यह आशा की जाती थी कि वे संस्था की योग्यता-अयोग्यता और सेवाओं की उत्कृष्टता-न्यूनता एवं बहुलता विरलता का विचार किये बिना पूरी निष्ठा से अपनी सहकारी संस्था का सम्पोषण-मवर्द्धन करेंगे।

लेकिन पाँचवी दशाब्दी के संक्रान्ति काल ने एक नई मनोवृत्ति का विकास किया, जो पुरानी विचार धारा के विरुद्ध यह कहती थी कि अपनी सेवाओं में विस्तार और उन्नति करना सहकारी संस्थाओं के हाथ की बात है और यह उन्हें करना ही चाहिए जिससे न केवल पुराने सदस्यों का संरक्षण बना रहे, बल्कि हजारों की संख्या में नये सदस्य भी बनते रहे।

परिवर्तन उस समय की परिस्थितियों की माँग ही नहीं थी वास्तव में उन परिवर्तनों को घटित भी किया। कृषि उस समय बुरी तरह विपत्तग्रस्त थी, खासकर के मालिकों द्वारा संचालित छोटे और मझौले फार्मों के बहुत बुरे हाल थे। व्यापारी हित अपने कार्य-संचालन में किसानों को इस तरह समन्वित करते जा रहे थे कि वे अपनी स्वतन्त्रता और आत्मनिर्देशन सभी कुछ गँवाते जाते थे। पूरा समय खेती करने वाले पक्के-पूरे किसानों की संख्या तेजी से कम होती जा रही थी। पुराने ढर्रे से पूरी तरह नाता तोड़कर और नया ओजस्वी ढंग अपनाकर ही ग्रामीण सहकारी संस्थाएँ अपने में निहित विश्वास के उपयुक्त सिद्ध हो सकती थी। और नगरों की सहकारी संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित, विज्ञापन और सेवा-साधनों की उन्नति पर हजारों डालर खर्च करके व्यापार को हथियाने के लिए प्रस्तुत शक्तिशाली प्रतियोगियों की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था।

इसलिए पाँचवी दशाब्दी के अन्तिम वर्षों में सहकारी सदस्यों एवं संरक्षकों को नई, उन्नत और विस्तारित सेवाएँ प्रदान करने का विचार बड़ी तत्परता से धर करता गया।

सहकारी परिष्करण शालाओं का आधुनिकीकरण ही नहीं किया गया उन्हे इतना कार्यक्षम और उपयुक्त बनाया गया कि वे उत्पादन की उत्कृष्टता में देश-व्यापी स्तर पर किसी से भी टक्कर ले सकें। उदाहरणार्थ नेशनल कोऑपरेटिव रिफाईनिंग एसोसिएशन की परिष्करण शाला दक्षिण-पश्चिम (साउथ वेस्ट)

के सम्पन्न तेल क्षेत्र के केन्द्रीय नगर मेकफरसन (कन्सास) का गौरव बन गई। फारम-आपूर्ति सहकारी संस्थाओं ने प्रोपेन गैस और द्रव ईंधन का कारबार ग्रामीण ग्राहकों में ही नहीं कस्बे के निवासियों में भी चालू कर दिया। मिडलैण्ड कोआपरेटिव इनकारपोरेशन ने, जो मुख्यतः मिन्नेसोटा, विसकोन्सिन, इओवा और डकोटा के देहाती क्षेत्रों में काम काज करती है, सेवा-साधनों के आधुनिकीकरण, सुधार, क्षेत्रव्यापी एक रूपता और वृहद् विज्ञापन-अभियान का कार्यक्रम आरम्भ किया। इसने शहर और कस्बे के निवासियों में भी व्यापार बढ़ाने की नीति अपनाई। इसने अपने सारे क्षेत्र का बहुत बारीकी से सर्वेक्षण किया और जिन समुदायों में सहकारी सेवाएँ नहीं थी वहाँ उन्हें स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया। फुटकर बिक्री का काम करने वाली जो सहकारी संस्थाएँ इससे सम्बद्ध थी उनकी उपनगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल के पम्पों का अधिग्रहण करने में यह सहायता करने लगी। मिडलैण्ड ने मिनियापोलिस में एक नया भाण्डागार बनाया। मेडिसन में एक नया तेल गोदाम और कुशिंग (ओक्लाहोमा) की अपनी परिष्करण शाला की कार्यक्षमता का पूरा-पूरा विकास किया।

‘मिडलैण्ड कोआपरेटर’ नामक पत्र ने अपने १३ जून १९६० के अंक में ‘सहकारी का मुख्य बाजार में स्थानान्तर’ नामक एक लेख प्रकाशित किया था जिससे मिडलैण्ड के कार्यक्रमों के व्यापक प्रभाव पर काफी अच्छा प्रकाश पड़ता है। उक्त लेख के कुछ अंश इस प्रकार हैं :

“ओकली (मिन्नेसोटा) कोआपरेटिव आयल एसोसिएशन ने एक बड़ी तेल कम्पनी का सर्विस स्टेशन और लोहे के सामान का स्टोर खरीद लिया है और अपनी पुरानी जगह से उठकर कस्बे के मुख्य चौराहे पर चला आया है।

“मिन्नेसोटा के उस पश्चिमोत्तर जिले में जहाँ किसानों की हजारों एकड़ जमीन भूमि-बैंक में रखी हो, अवस्थित सहकारी संस्था के लिए यह प्रगति की दिशा में बहुत बड़ा कदम है।

“इस संस्था के प्रधान व्यवस्थापक एल्मर ओरासन का कहना है : ‘अब हम केवल किसानों की सहकारी संस्था नहीं रहे, सामूदायिक सहकारी संस्था बन गए हैं। बहुत-से लोगों ने आ-आ कर हमें बताया है कि उन्हें यह परिवर्तन पसन्द आया।’

“पिछले अप्रैल महीने में इस संस्था को ‘स्ट्रैण्ड्स सर्विस सप्लाई’ को खरीदने का मौका मिल गया। स्ट्रैण्ड की स्थापना नेल्सस्ट्रैण्ड ने १९३२ में की थी। उनके पुत्र जेराल्ड ने १९४६ में कारबार सँभाला; उन्होंने काफी-कुछ नया किया और काम को बढ़ाया।

“१९५७ में जेराल्ड ने लोहे का सामान रखना शुरू किया और मोटर का विभाग भी खोल दिया; लेकिन एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई।

“क्लिफर्ड ‘माइक’ स्ट्रैण्ड जो पिछले वर्ष तक इस कारबार को चला रहे थे, सब-कुछ बेच-बाचकर अपने पुराने निवास स्थान मिल्वाँकी लौट जाना चाहते थे।

“सहकारी संस्था के निदेशक-मण्डल को मुँह माँगी मुराद मिल गई। वे कारबार को बढ़ाने और नया सर्विस स्टेशन चालू करने का विचार कई दिनों से कर रहे थे। इसलिए एकमत से स्ट्रैण्ड कारबार को खरीदने का फैसला हो गया।

“२७ और २८ अप्रैल को जब संस्था का नये स्थान में शानदार उद्घाटन हुआ तो कम-से-कम दो हजार ग्राहकों की भीड़ तो रही ही होगी। उद्घाटन समारोह की पुरस्कार-प्रतियोगिता में पच्चास आदमियों ने मुश्किल इनाम जीते और ८६ व्यक्ति छोटे सरल इनामों में कामयाब रहे।

‘संस्था के प्रधान व्यवस्थापक ओल्सन का कहना है: ‘हम जिस दिन से इस नई जगह में आये हैं कारबार बढ़ता ही जा रहा है, दम मारने की फुरसत नहीं मिलती। इस नई जगह में रोज नये-नये ग्राहकों का ताँता लगा रहता है। अब हमारे किसान सदस्यों की तो चाँदी-ही-चाँदी है, क्योंकि कारबार को चलाने का खर्च ग्राहकों की बढ़ती हुई सख्या पर फैलता और बँटता जाता है।

“संस्था की यह नई इमारत कस्बे को खास सड़क पर ५० फुट चौड़ी और अन्दर की तरफ ९९ फुट लम्बी है।”

उधर ओहियो के फार्म व्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन ने ‘फुटकर संचालन’ के नाम से एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया। यह एक राज्य-स्तरीय थोक सहकारी संस्था है। इस नये कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त सम्बद्ध जिला संस्थाओं के लिए नई सेवा-सुविधाओं के निर्माण का काम हाथ में लिया गया जिससे स्थानीय सगठने अपनी चालू सेवाओं का आधुनिकीकरण और नये ग्राहकों को आकर्षित करने वाली नई सेवाएँ आरम्भ कर सकें।

कन्सास सिटी के कञ्जूसर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन ने सूअर पालने-वाले किसानों के लिए एक सम्पूर्ण समन्वित सेवा की योजना कार्यान्वित की जिसमें सूअरों के प्रजनन, परीक्षण एवं अनुसन्धान केन्द्र से लेकर बूचड़खाना, मांस के पण्योपयोगन और डिब्बों में बन्द करने का कारखाना और विक्री-व्यवस्था तक सारे कामों का समावेश था। इस एसोसिएशन ने १९६० में कई लाख डालर लागत के एक विशाल नाइट्रोजन उर्वरक कारखाने के निर्माण की घोषणा भी की, जो नेब्रास्का में लगाया जाएगा और कन्सास में इस ढग के पहले से चल रहे कारखाने की टक्कर का होगा।

इण्डियाना फार्म ब्यूरो कोआपरेटिव एसोसिएशन ने अपने से सम्बद्ध फुटकर विक्रेता भण्डारों के लिए रसायनों, उपकरणों और पेट्रोल-निर्मित वस्तुओं तक के दामों में भारी कमी कर दी। इसने पैंतीस मील लम्बी तेल की अपनी पाईप लाइन बनाई और चूजाघर का भी काफी विस्तार किया।

अनाज का कारबार करने वाली उन्नीस सहकारी सस्थाओं ने मिलकर गल्ले के संयुक्त निर्यात और विदेशी बाजारों में खपत बढ़ाने के लिए एक कम्पनी बनाई, प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्ट कम्पनी इसका नाम रखा गया। काम काज के पहले ही वर्ष में इस कम्पनी ने १४ देशों को कुल मिलाकर तीन करोड़ २० लाख बुशल गल्ला बेचा।

देश की अकेली सबसे बड़ी सहकारी सस्था कोआपरेटिव जोएलएफ एक्सचेंज ने अपने मुरगीखाने को इस तरह विकसित किया कि वहाँ की मेहनत केवल आधी रह गई; इस एक्सचेंज ने पशु खाद्य, चारा और उर्वरक किसानों को सीधे उनके फार्मों पर पहुँचाने की सेवा शुरू की और अपने फुटकरविक्रेता भण्डारों को 'इतने बड़े भण्डारों में परिवर्तित कर दिया जहाँ किसान अपनी जरूरत की हर चीज और हर सेवा प्राप्त कर सकता है।'

मिचीगन की फार्म ब्यूरो सर्विसेज ने अपने किसान सदस्यों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए अण्डों के श्रेणीकरण (दर्जाबन्दी) और सवेण्टन (पैकिंग) का कार्य शुरू किया।

पगेट साउण्ड की ग्रूप हेल्थ कोआपरेटिव के सीटल्लक्षेत्र में वहाँ की कुल जनसंख्या के पाँच प्रतिशत सदस्य हैं। अपने इन सदस्यों के लिए इस सामूहिक

स्वास्थ्य योजना ने एक बिल्कुल नया अधुनातन अस्पताल बनाया, जिसकी अन्तिम मजिल पर प्रसूतिगृह है; यह प्रसूतिगृह इतनी ऊँचाई पर है कि यहाँ से चारों ओर का दूर-दूर तक का दृश्य बड़ा ही मनोरम दिखाई देता है। और देश के उस छोर पर वॉशिंगटन डी० सी० में वहाँ की ट्रांजिजट वर्क्स यूनिशन ने अपने समस्त सदस्यों को सहकारी ग्रुप हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या—सेवा प्रदान करने का फैसला किया और इस काम की मुचास्ता के लिए एक नया बढ़िया अस्पताल भी बनवा दिया।

विसकोन्सिन राज्य में ला-क्रोसे की डेरोलैण्ड पावर कोआपरेटिव की बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि वह अपने एक लाख ग्राहक-स्वामियों को सस्ते-से-सस्ते मूल्य पर बिजली दे। १९५९ में उसकी यह अभिलाषा पूरी हुई और उसने अपनी बिजली की दरे प्रति किलोवाट घण्टा एक सेट से भी कम कर दी। इसका महत्त्व तब समझ में आता है जब इस तथ्य पर विचार किया जाए कि यह सहकारी संस्था जिस क्षेत्र में काम करती है वहाँ बिजली की दरे सारे देश में सबसे अधिक है।

ग्रीन बेल्ट कञ्जूमर सर्विसेज संयुक्त राज्य के नगर उपभोक्ता सहकारी संगठनों में सबसे बड़ी संस्था है। १९६० में यह सारे देश में विभिन्न स्थानों पर एक दर्जन से अधिक बाजार चला रही थी और साल भर में कुल मिलाकर दो करोड़ डालर का कारबार करने लगी थी।

शिकागो की हाइड पार्क कञ्जूमर्स कोआपरेटिव नगर का सबसे बड़ा सुपर३ मार्केट ही नहीं चला रही थी प्रति सप्ताह सैकड़ों नये सदस्य बना कर अपना विकास करने के साथ-साथ 'साउथ साइड' की घनी बस्ती के काफी बड़े-बड़े जन समूहों को 'अपने भण्डार' के स्वामी बनने का अधिकाधिक अवसर भी दे रही थी। इतना ही नहीं, अनेक जातियाँ और राष्ट्रों की समन्वित बस्तो साउथ साइड के पुनर्विकास के संघर्ष को संगठित और आयोजित करने का यह सहकारी संस्था सामूदायिक केन्द्र भी है।

इस दशब्दों में न्यूयार्क और मिचिगन के साख-संघों ने पूरी आर्थिक निर्भरता प्राप्त कर ली थी। वित्तीय असुरक्षा से वे पूर्णतः मुक्त हो चुके थे और अपने सदस्यों के लिए लेन-देन के अतिरिक्त अन्य सेवा भी सुलभ करने लगे

थे। वह उल्लेखनीय सेवा है अपने सदस्यों को सहकारी आधार पर अच्छे, सुन्दर और सुशोभन मकानों का मालिक बनाना। इसके लिए साख-सघ सहकारी गृह निर्माण योजनाएँ प्रायोजित करते हैं और इस प्रकार की चालू योजनाओं की सहायता भी करते हैं।

सेण्ट पाल की म्युचुअल सर्विस इन्श्यूरेन्स कम्पनीज ने तो बीमा-सेवा में युगान्तर करके यह दिखा दिया कि सहकारी बीमा कम्पनियाँ अपने पालिसी-धारियों की कम-से-कम मूल्य पर कितनी उत्कृष्ट-से-उत्कृष्ट और व्यापकतम बीमा सेवाएँ कर सकती हैं। इओवा के एक जिले के हताहत व्यवसाय में दूसरी व्यापारी बीमा कम्पनियों के मुकाबले ठीक उसी तरह के सात मामलों में म्युचुअल नेबीमकाक की जो बोलियाँ लगाई उनकी रकम आधे से भी कम थी। 'सहकारी बीमा कम्पनियों' में सब से बड़ी नेशन वाइड इन्श्यूरेन्स कम्पनीज ने नये प्रकार के हताहत बीमों और सामूहिक मोटर बीमों के प्रयोग किये। नेशनल ने सहकारी सामूहिक स्वास्थ्य योजनाओं के विकास में सहायता देने के लिए एक प्रतिष्ठान की स्थापना करने में भी आगे बढ़ कर हिस्सा लिया। और ग्रूप हेल्थ म्युचुअल नामक एक तीसरी सहकारी बीमा कम्पनी ने तो बिल्कुल नई तरह की जीवन-बीमा पालिसी शुरू की; इस पालिसी में यदि २७ वर्ष का कोई आदमी बीमा करवा कर मर जाए तो वह केवल २.५० डालर प्रति सप्ताह पर अपने बच्चों के ब्यस्क होने तक प्रति मास दो सौ डालर आय का निश्चित प्रबन्ध कर जाता है।

लेक सुपीरियर के आस पास के विपन्न और वीरान प्रदेश में सेण्ट्रल कोआपरेटिव्स इनकारपोरेशन ने 'इलाके के सबसे सुन्दर और सबसे श्रेष्ठ' बाजारों के निर्माण का क्षेत्र व्यापी कार्यक्रम बनाया और कुछ चुने हुए समुदाय में निर्माण-कार्य आरम्भ कर भी दिया।

पाँचवे दशक में अमरीकी सहकारी संस्थाओं में जिस नये दृष्टिकोण का क्रमशः विकास हो रहा था उसके ये कुछ उदाहरण हैं और ऐसे कई नये उदाहरण और भी दिये जा सकते हैं।

बीसवी शताब्दी के अन्तिम तृतीयांश के आरम्भ होने से पहले ही अमरीकी सहकारी नेताओं को भूतकाल की असफलताओं के कारणों का ठीक-ठीक ज्ञान हो गया और वे यह भी जान गए कि आगे सफलता किन बातों पर निर्भर करती

है। एक जबर्दस्त चुनौती सामने थी, जिसे उन्होंने देखा और स्वीकार किया। अब उनके कर्तृत्व की सार्थकता इसी में थी कि ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को बड़े और प्रभावशाली उद्यमों के स्वामीत्व और नियन्त्रण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के योग्य बनाएं, न कि छोटे आदर्शवादी लँगड़ाते उद्यमों के। उन्हें विश्वास हो चला था कि यदि इस काम को कर लिया गया तो अमरीकी लोकतन्त्र के सबसे दुर्बल अंग को पुनः शक्ति-सम्पन्न किया जा सकेगा।

लेकिन इस प्रतीति ने मार्ग की तीन बड़ी-बड़ी बाधाओं को और भी स्पष्ट कर दिया। वे थीं :

१—पर्याप्त धन की आवश्यकता, जो यों तो एक चिरकालिक समस्या थी लेकिन अब सेवाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और समन्वयन के भारी खर्चों के कारण तात्कालिक और चिन्तनीय हो उठी थी।

२—जनता का अज्ञान, न केवल सहकारियों के कर-दान के सम्बन्ध में बल्कि उनके उद्देश्यों, प्रयोजनों, उनसे होने वाले फायदों, उनके स्वरूप और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व के भी बारे में सामान्य जनता को समुचित ज्ञान नहीं था।

३—महकर्मिता का अभाव, महवारी संस्थाएँ पूरी तरह साथ मिलकर काम करने में सफल नहीं हो पा रही थी, जो स्वयं उनके अपने लिए और उनके सभी सदस्यों के लिए भी बहुत आवश्यक और उपयोगी था।

इसलिए १९६० के सितम्बर महीने में सहकारी लीग का शिकागो में जो इक्कीसवाँ द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें प्रतिनिधियों ने अपना पूरा समय केवल दो समस्याओं के ही विचार-विनिमय में लगाया : सहकारी संस्थाओं के बारे में जनता की समझ को बढ़ाना और वित्त के नये और बड़े स्रोतों का विकास करना। इसके साथ ही एक प्रस्ताव के द्वारा उस अधिवेशन ने पहले के चार सिद्धान्त में एक नये सिद्धान्त का समावेश और किया; वह पाँचवाँ सिद्धान्त था—“सहकारी संस्थाओं में सहकारिता।”

अभी तक इन अधिवेशनों के प्रतिनिधि केवल सैद्धान्तिक बहस-मुवाहसा ही करते आये थे; अबकी पहली बार उन्होंने व्यवहार और आचरण के क्षेत्र में कदम बढ़ाये, क्योंकि सिद्धान्तों को मूर्त रूप देने का कार्य आरम्भ हो चुका था।

इस अधिवेशन में प्रतिनिधियों को विमर्श और अभिस्वीकरण के लिए जन-सूचना पर एक सुचित्रित निर्देश पुस्तिका भेंट की गई, जो विशेष रूप से इसी अवसर के लिए प्रकाशित की गई थी।

इस बात का पता लगाने के लिए कि प्रचार के उद्देश्य पूरे क्यों नहीं हो पाते और औसत अमरीकावासी का सहकारी सस्थाओं से सम्बन्धित ज्ञान इतना अस्पष्ट और कभी-कभी प्रतिकूल क्यों होता है, १९५९ में सहकारी लीग ने एक जाँच-समिति नियुक्त की; और उसे स्वयं लीग एव लीग के सदस्य सगठनों के जन-सूचना कार्य की छान-बीन करने के आदेश दिये गए। इस समिति में सहकारी सस्थाओं के कुछ योग्यतम और चोटी के जन-सम्पर्क निदेशकों को लिया गया। समिति ने अपने काम में समाज शास्त्र, जन-सम्पर्क, विज्ञान और अभिप्रेरणात्मक अनुसन्धान के क्षेत्र में सलग्न चार श्रेष्ठ विशेषज्ञों की सेवाएँ भी ग्रहण की।

एक नहीं दो तथ्य अन्तर्निहित थे। इस बात पर ध्यान दिये बिना की बीसवीं शताब्दी के मध्य काल की अमरीकी जनता के विचार, मान्यताएँ और अभिरुचियाँ क्या हैं सहकारी सस्थाएँ उन्हें अपने बारे में सही-सही अवगत कर ही कैसे सकती थीं? अमरीकी जनता को सही रूप में जाने-समझे बिना उन्हें अपने बारे में बताना असम्भव ही था।

इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि आज के अमरीकावासी बीसवीं शताब्दी के दूसरे या तीसरे दशक के अमरीकावासियों से भिन्न हैं, किसी बहुत बड़े अनुसन्धान को आवश्यकता नहीं है। आज लोगों के मन में अपनी जो तसवीर है वह पहले से बहुत भिन्न है। आज के किसान अपने-आपको सूर्योदय से सूर्यास्त तक हल को मुठिया पकड़े और खेत-मजदूरों की टुकड़ी की रखवाली करते खेतिहर के रूप में नहीं देखते, और न पुराने फैशन के ओवराल पहनने वाले किसानों के ही रूप में। आज तो सयुक्त राज्य का प्रत्येक निवासी, उसकी आय अथवा पेशा कुछ भी क्यों न हो, अपने-आपको 'मध्यवर्ग' का व्यक्ति समझता है और यही समझा जाना पसन्द करता। किसी जमाने में लोग अपने संघर्षों और निम्न परिवारों में जन्म लेने पर गर्व किया करते थे, लेकिन आज नहीं करते। वे अपने को सफल, सुशिक्षित और नागरिक वातावरण के अभ्यस्त व्यक्ति के

रूप में देखना-सोचना पसन्द करते हैं। आज के अमरीकावासी स्वतन्त्रता का बड़ा आदर करते हैं, यद्यपि अधिकांश न तो स्वतन्त्रता के उत्तरदायित्वों को समझते हैं न स्वतन्त्रता द्वारा प्रस्तुत अवसरों को ही। वे कुल मिला कर उदार होते हैं और दूसरों की—यहाँ तक कि दूर-देश केवासियों की भी सहायता करने को उत्सुक रहते हैं। वे अपने-आपको आत्मनिर्भर और स्वार्थान समझना चाहते हैं, सचाई चाहे कुछ भी रहे।

इन जानकारीयों के आधार पर यह गलती समझ में आई कि सहकारी संस्थाएँ विज्ञापन और प्रचार कार्यों में कथ्य और कथन के जिस ढंग को अपनाती आई हैं वह पिछली दशाब्दियों के लिए तो ठीक था, पर आज के उपयुक्त नहीं है। जनता के मानसिक स्तर तक पहुँच कर ही जनता की भ्रान्तियों का निवारण किया जा सकता है।

समिति ने इस वास्तविकता को भी स्वीकार किया कि सारी जनता एक-जैसी नहीं है; और विशेषज्ञ, वे भी इससे सहमत थे। समिति ने पाया कि देश में कई तरह की 'अमरीकी जनता' रहती है। जन-संख्या का एक हिस्सा ऐसे लोगों का भी है जो झूठी तडक-भड़क वाली उस दुनिया से जरा भी सन्तुष्ट और सुखी नहीं है जिस पर अधिकांश अमरीकावासी याँ टूट पड़ते हैं। हाइड्रोजन बम का आतक हम में से कइयों को उद्विग्न किये रहता है। कई ऐसे हैं जो जीवन की सोद्देश्यता और क्रान्तिकारी आदर्श की अपने अन्तरतम में बड़ी तीव्र और गहन आवश्यकता अनुभव करते हैं, लेकिन आज के युग में तो इन आध्यात्मिक गुणों का नितान्त अभाव ही हो गया है। सहकारी संस्थाओं में ऐसे ही लोगों की अधिक रुचि हो सकती है और यही लोग उनके सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। भ्रातृ भाव, पारस्परिक सहायता, सामाजिक स्थितियों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुधारने, विश्व शान्ति को बनाये रखने आदि की आदर्शवादी पुराने ढंग की अपीलें ऐसे ही लोगों के लिए प्रभावकारी हो सकती हैं।

लेकिन इस समूह के अतिरिक्त विशाल जन-समूह भी हैं जिससे सहकारी संस्थाओं को अपने लिए असन्दिग्ध रूप से समर्थन और स्वीकृति प्राप्त करनी है; और व्यापक जन-सम्पत्ति को इस सीमा तक अपने पक्ष में कर लेना आवश्यक है कि उनकी वृद्धि और उन्नति का कम-से-कम विरोध तो नहीं ही किया जाए।

सहकारी सस्थाओं के जन-सूचना कार्यक्रमों पर नियुक्त इस विशेष समिति की काररवाई और सिफारिशों को अन्त में एक आकर्षक पुस्तिका में प्रकाशित कर दिया गया। उस पुस्तिका का नाम रखा गया “सहकारी सस्थाओं के शब्द”, लेकिन हमारे विचार में “सहकारी सस्थाओं के आठ शब्द” नाम रखना अधिक उपयुक्त होता। किसी भी प्रकार के सहकारी सगठन में जन-सम्पर्क अथवा जन-सूचना के कार्य में सलग्न व्यक्तियों के सन्दर्भ और निर्देश के लिए सहकारी लीग ने इसका प्रकाशन किया था।

पुस्तिका में इस बात का विशेष आग्रह किया गया कि अमरीकी जनता के समक्ष सहकारी सगठनों का चित्र अथवा स्वरूप निम्न अवधारणाओं के साथ या ‘सहकारी सस्थाओं के शब्दों’ में प्रस्तुत करना ही उचित है :

उद्यम—सदस्यों और सरक्षकों की आवश्यकताओं को कल्पना शक्ति, दूरदर्शिता और अधिक एवं श्रेष्ठ सेवाओं के द्वारा पूरा करने में।

दक्षता—लागतों को कम करने और वितरण-पद्धतियों को उन्नत करने में।
प्रतिस्पर्द्धा—न केवल अपने सदस्यों अपितु समस्त राष्ट्र के लाभ के लिए अर्थ-व्यवस्था पर एकाधिकारी जकड़बन्दी को तोड़ने के लिए।

प्रचुरता—मूल्य के स्तरों की रक्षा के लिए बनावटी अवरोधों या नकली कमी के बिना पूरा-पूरा उत्पादन करने में।

स्वतन्त्रता—स्वामी और सक्रिय सहभागी बन कर सामूहिक काररवाई से अपनी आर्थिक समस्या को हल करने में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए।

हिस्सेदारी—लोगों को मिल-जुल कर सामान्य आवश्यकताओं को पूरा और सामान्य सक्तों का सामना करने के योग्य बना कर और अपनी प्रचुरता को दूसरे देशवासियों के साथ बाँटने का मार्ग प्रशस्त कर के।

समझदारी—इसलिए कि सहकारी व्यवसाय ‘खुली किताब’ की तरह कार्य-संचालन करता है और अपने सदस्य-स्वामियों को अपने कार्य-संचालन के ही सम्बन्ध में नहीं जिन सिद्धान्तों पर कार्य किया जाता है उनकी भी पूरी-पूरी जानकारी देने का प्रयत्न करता है।

और हमारा—इसलिए कि सहकारी सस्थाएँ अपने सभी ग्राहकों को अपना स्वामी बनाती हैं और इसलिए भी कि सहकारी व्यवसाय स्वभाव से

ही स्थानीय स्वामीत्वकृत और अपने समुदायों, वस्तियों एवं क्षेत्रों के जीवन-व्यापार के अभिन्न अंग होते हैं।

दूसरे महायुद्ध के परवर्ती काल में सहकारी संस्थाओं ने जो प्रगतिशील कदम उठाये उनके बारे में इसी अध्याय में पहले बताया जा चुका है, उनसे पता चल जाता है कि ये आठों शब्द उनके कार्य संचालन के सर्वथा अनुरूप ही हैं और उनके कार्यों की व्याख्या भी करते हैं।

लेकिन इस बात को अमरीकी जनता का केवल एक छोटा अंश ही जानता है। सहकारियों ने 'उस तरह रहना' तो शुरू कर दिया है, लेकिन 'उसके बारे में कहने' का उनका काम अभी शेष है।

सहकारी लीग के इक्कोसवे सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने 'सहकारी के शब्द' नामक पुस्तिका पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा कर उसे अधिकृत निर्देशिका का रूप प्रदान कर दिया।

जहाँ तक वित्त-व्यवस्था की समस्या का प्रश्न है सहकारी लीग के दस सम्मेलन के दो ही दिन पहले एक नई पारस्परिक निधि की स्थापना की गई, जिसका उल्लेख दसवें अध्याय में किया जा चुका है। संघ और राज्य सरकारों को निधि के पजीपन की काररवाई का आवेदन भी कर दिया गया है। सहकारी लीग ने इस निधि को प्रायोजित किया है; और जो कम्पनी इसके निवेश के प्रबन्ध और हिस्से बेचने की हमी लेगी उसके लिए पूँजी की व्यवस्था को आप-रेटिव फाइनेन्स एसोसिएशन आफ अमरीका ने कर दी है। कई सुयोग्य और सुप्रसिद्ध व्यक्तियों ने इस निधि के निदेशक मण्डल का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया है और उन्होंने मिडलैण्ड कोआपरेटिव्स के व्यवस्थापक ए० जे० स्मावी को निधि का प्रथम सभापति भी निर्वाचित कर लिया है। इस निधि से दूसरे लाभ की आशाएँ की जाती हैं। एक तो यह निधि सभी सहकारी संस्थाओं, उनके सदस्यों और निवेशकर्ताओं के लिए अपने-अपने अधिशेषों और अपनी-अपनी बचतों के काफी बड़े अंश को निवेशित करने का आकर्षक, सुरक्षित और लाभदायी स्थान सिद्ध होगी; क्योंकि निधि में निवेश करके उन्हें अपनी पूँजी एक-साथ कई संस्थाओं में—बड़े-बड़े कई सहकारी संगठनों के साथ-साथ व्यापारी कम्पनियों की प्रतिभूतियों में लगाने का बढ़िया अवसर मिल जाएगा, जो इसके पूर्व

सम्भव नहीं था। दूसरे यह कि निधि के निवेशों का काफी अंश सुस्थापित सहकारी व्यवसायों की प्रतिभूतियों में किया जाएगा। इस प्रकार थोड़े समय में विस्तार के लिए आवश्यक पूँजी की कमी दूर हो जाएगी।

२१ वे अधिवेशन के प्रतिनिधियों ने पारस्परिक निधि के इस प्रस्ताव पर काफी बहस-मुवाहसा किया और अन्त में प्रबल बहुमत से इसको स्वीकृत कर पूरी-पूरी सहायता का अभिवचन दिया।

संयुक्त राज्य की सहकारी संस्थाओं की त्वरित प्रगति के मार्ग की तीसरी बड़ी बाधा यह है कि पारस्परिक लाभ के लिए जिस हद तक साथ मिल कर जितना काम करना चाहिए वे करती नहीं हैं। उदाहरण के लिए कुछ ही समय पहले एक सहकारी ढग की पारस्परिक बीमा कम्पनी के अध्यक्ष ने हिसाब लगा कर बताया था कि उनकी कम्पनी विभिन्न राज्यों के जिन सहकारी सगठनों की बीमा-सेवा करती है वे सभी यदि अपने बीमा-सम्बन्धी काम का आधा ही उनको दे दे तो उनकी कम्पनी का कारबार पाँच गुना बढ़ जाएगा। सचार्ड तो यह है कि अधिकांश सहकारी संस्थाएँ गैर-सहकारी बीमा कम्पनियों में बीमा करवाती हैं। साख-संधी के सम्बन्ध में पहले बताया ही जा चुका है कि उनमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी भी प्रकार के सहकारी अथवा पारस्परिक उद्यम की कोई सहायता नहीं करना चाहते। ऐसी स्थानीय सहकारी संस्थाएँ भी कई हैं जिनके अपने स्वामीत्वकृत थोक सहकारी भण्डार हैं लेकिन वे अपना अधिकांश माल खरीदती हैं ऐसी व्यापारी कम्पनियों से जिनसे उनके हित किसी भी रूप में जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसी सहकारी संस्थाएँ भी बहुत-सी हैं जिनमें से कोई खाद्योत्पादन का काम करती हैं तो कोई खाद्य के पण्योपयोगन का, कोई खाद्य के संवेष्टन का तो कोई वितरण का और कोई बिक्री व्यवस्था का। यदि ये सब अपनी क्रियाशीलताओं का समन्वय कर ले तो किसानों और उपभोक्ताओं के स्वामीत्व में खाद्य-उद्योग का इतने प्रभावी एकीकृत संघटन हो सकता है, जिससे जैसा कि पहले बताया जा चुका है, किसानों को प्राप्त होने वाली और उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतों के अन्तर की चौड़ी खाई बहुत हद तक पट जाएगी।

प्रबन्ध-परामर्श सेवाओं के लिए भी सहकारी संस्थाओं को प्रति वर्ष बहुत

घन खर्च करना पड़ता है। लेकिन समझ में नहीं आता कि अपने सदस्यों से बचत का आग्रह करने वाली सभी सहकारी संस्थाएँ अपनी एक निजी परामर्श कम्पनी खोल कर, स्वयं भी बचत क्यों नहीं करती? आखिर उन्हें कौन रोकता है?

लेकिन सबसे अपत्तिजनक बात तो यह है कि सभी सहकारी संस्थाओं ने सम्मिलित रूप से जन-सूचना और प्रचार का कोई समन्वित कार्यक्रम अभी तक भी आरम्भ नहीं किया है। इसका अनिष्टकारी परिणाम यह हो रहा है कि किसी भी सहकारी संस्था का प्रचारात्मक कार्य जरा भी प्रभावकारी नहीं हो पाता। कहना न होगा कि जिन पत्रों का राष्ट्र व्यापी प्रचार है यदि उनमें सीधे सरल ढंग से सहकारी उद्यम और अमरीकी जीवन तथा कल्याण कार्यों में उसके भूत, वर्तमान और भावी योगदानों का विज्ञापन किया जाए तो उससे जनमत पर कितना अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है! लेकिन इस तरह के लगातार विज्ञापन का भारी खर्च किसी एक संस्था के तो क्या एक ही प्रकार के सहकारी संगठनों के किसी अकेले सघ के बूते का भी नहीं है। केवल देश के समस्त सहकारी संगठन सम्मिलित रूप से ही इस खर्चीले काम को कर सकते हैं।

सहकारी नेताओं को ये तथ्य ज्ञात न हों सो बात नहीं; वे काफी समय से इन बातों को जानते हैं। अक्सर यह कहा जाता था कि किसानों की वित्रय उपभोक्ताओं की, गृह निर्माता, स्वास्थ्य योजनाओं वाली, फारम-आपूर्ति की, ग्रामीण विद्युत वाली सहकारी संस्थाओं के और साख-संघों के तथा पारस्परिक बीमा कम्पनियों के नेताओं को एक साथ लाना, एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल ही नहीं असम्भव है। ये लोग आपस में मिलने को राजी ही नहीं होते।

लेकिन आखिर इस असम्भव को भी सम्भव किया गया। १९५८ में देश के सभी सहकारी व्यवसायों के उन नेताओं को जो निर्णय करने का काम करते हैं, एक त्रि-दिवसीय बैठक में निमन्त्रित करने के एकांतिक उद्देश्य से अनौपचारिक समिति बनाई गई। और उस बैठक का उद्देश्य केवल इस बात पर विचार करना था कि विभिन्न प्रकार के सहकारी संगठन सर्व सामान्य उद्देश्यों के लिए एक साथ मिल कर किस तरह काम कर सकते हैं। उस बैठक में साठ से भी अधिक प्रधान व्यवस्थापक और अध्यक्ष सम्मिलित हुए। विभिन्न गोष्ठियों में, और उसके बाद जब भी कभी चार-पाँच व्यक्ति कहीं मिल कर बैठ जाते तो

जो चर्चाएँ हुई वे काफी जानदार और लाभदायी रही। विक्री-व्यवस्था वाली सहकारी सस्थाओं के व्यवस्थापकों ने थोक सहकारी सस्थाओं के व्यवस्थापकों से नये व्यापारी सम्बन्ध बनाने के बारे में बातें की। सहकारी गृह निर्माताओं ने सहकारी बीमा कम्पनियों के अध्यक्षों से वित्त-प्रबन्ध की सम्भावनाओं पर चर्चाई की। जन सम्पर्क और नेशनल टैक्स इन्विलिटी एसोसिएशन के आक्रमण की बात तो प्रायः सभी की जवान पर थी। समापन के दिन सभी ने एक स्वर और एक मत से यह निश्चय किया कि इस तरह की बैठकें प्रति वर्ष होनी चाहिए। सर्वसम्मति से इन बैठकों का नामकरण भी हो गया—कन्सल्टेशन आन कोआपरेटिव्स अमग कोआपरेटिव्स सहकारियों का सहकारिता परामर्श। बैठकों के आयोजन और निर्देशन के लिए एक समिति चुन ली गई। इस समिति का महत्व और प्रभावोत्पादकता इसी से सिद्ध हो जाती है कि यह अमरीकन इन्स्टीट्यूट आफ कोआपरेशन के अध्यक्ष, नेशनल रूरल इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव एसोसिएशन के प्रधान व्यवस्थापक, नेशनल फेडरेशन आफ ग्रैन कोआपरेटिव्स एव नेशनल मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन में से प्रत्येक के कार्यकारी सचिव और सहकारी लीग के कार्यकारी निदेशक को लेकर बनाई गई थी।

१९५९ में कन्सल्टेशन का उपनाम रखा गया 'समिट मीटिंग' और इस नाम से बुलाई गई बैठक भी काफी सफल रही। १९६० की बैठक भी सफल रही और यह निश्चय किया गया कि अब यह बैठक प्रति वर्ष होती रहे। किसी भी बैठक में कोई निर्धारित काम करने का निर्णय या विचार नहीं किया गया। इन बैठकों का प्रयोजन केवल अनौपचारिक विचार-विनिमय और चर्चाओं के ही लिए है।

सहकारी लीग के १९६० वाले अधिवेशन की ही भाँति कन्सल्टेशन भी प्रतीक है उस नई चेतना का जो संयुक्त राज्य की सहकारी संस्थाओं में इन दिनों प्रबल वेग से प्रवाहित हो रही है। बच्चों का खेल समझ कर या उदासीन भाव से चलाये जाने वाले भण्डारों और कृषक सहकारी सस्थाओं के दिन अब लड़ चुके। यह दिन है आधुनिक सहकारी उद्यम का, जो कृतसंकल्प है आते कल की सच्ची और न्यायपूर्ण अर्थ व्यवस्था के विकास की गति को सार्थक ढंग से सन्तुलित बनाये रखने का।

१३ | सहकारिता और शान्ति की आशा

शान्ति आज मनुष्य-जाति की जबरदस्त आवश्यकता है। आज की दुनिया की हर सस्था, हर पद्धति और हर कोशिश को सबसे पहले इसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए कि विश्व-शान्ति की सम्भावनाओं पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है।

यदि शान्ति स्थायी न हो सकी और तीसरा महायुद्ध छिड़ ही गया तो स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, जन-कल्याण आदि समस्त मानवी मूल्य जिनका हम सम्पोषण, सम्बर्द्धन और संरक्षण करते हैं नष्ट-भ्रष्ट हो जाएंगे। श्रेष्ठ मानवी गुणों का मूल्य और महत्त्व तभी है जब तक शान्ति बनी रहे; शान्ति का मोल देकर हम जो भी पाएंगे वह एकदम व्यर्थ होगा।

आज शान्ति की अधिकांश बातें राजनयिकों के वार्तालापों और सन्धि-चर्चाओं, संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाइयों या राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकातों में केन्द्रित होकर रह गई हैं।

लेकिन शान्ति की आशा मूलतः निर्भर करती है इस बात पर कि भीड़-भरो, बुरी तरह बटी और तेजी से बदलती हुई दुनिया में लोग मिल-जुल कर रहना कितनी जल्दी सीखते हैं।

अमरीका की सबसे बड़ी गलती, जिसका दण्ड हम १९६० तक विश्व के नेतृत्व-पद से वंचित होकर भुगत रहे हैं, यह थी कि हमने स्वतन्त्रता और स्वतन्त्र मनुष्यों की गौरव-गरिमा पर मोटर, टेलीविजन और अन्तरिक्ष राकेट को प्रधानता देने का प्रयत्न किया। हम ऐसा आचरण करते रहे मानो उच्च कोटि के साधनों-उपकरणों की विपुलता और भौतिक वस्तुओं का सुख-भोग ही विश्व के नेतृत्व पद का मूल मन्त्र हो।

अस्थायी रूप से ही क्यों न हो, अभी तो हम अपने राष्ट्रीय पथ से भटक गए हैं।

हम उसी जाल में फँस गए हैं जिसमें विश्व साम्यवाद की शक्तियाँ हमें फँसा हुआ देखना चाहती थी। असल में हम अर्थवाद के गोरखधन्धे में उलझ गए हैं और साम्यवाद की भी सारी प्रेरणा आर्थिक प्रेरणा ही होती है। साम्यवाद पीड़ितों और सकट ग्रस्तों से कहता है : “हमारी प्रणाली को अपनाओ और अपने जीवन-मानों को जल्दी से उन्नत कर लो। अपनी स्वतन्त्रता की चिन्ता मत करो। अपने धर्म को भी भूल जाओ। आत्म-निर्भरता की सारी आशाओं को छोड़ दो। अपना जीवन राज्य को सौंप दो और बदले में खूब खाना लो, खूब कपड़े लो।”

युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों में अमरीका ने सबसे बड़ी गलती यह की कि दुनिया के लोगों के मस्तिष्क के नेतृत्व की लड़ाई जिस भूमि पर लड़ी जाने की थी उसका चुनाव साम्यवादियों को कर लेने दिया।

हम बिल्कुल ही भूल गए कि एशिया और मध्य-पूर्व का जनता की आर्थिक से भिन्न मूल्यों, सांस्कृतिक दाय और मूलतः धार्मिक आदर्शों में शक्ति ही वहाँ के देशों में साम्यवाद के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा रही है।

जो लोग अभी तक गरीब हैं उनके लिए आर्थिक प्रगति और जीवन-मानों में उन्नति का अवश्य बहुत अधिक महत्त्व है। और ये दोनों चीजें वास्तव में शान्ति की बुनियादी शर्तें भी हैं। यदि अमरीका चाहता है कि विश्व-नेतृत्व का खोया हुआ पद फिर से मिल जाए तो हमें दूसरे देशों के लोगों के जीवन-मानों को उन्नत करने के लिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए और अभी तक उनकी जितनी सहायता करते रहे हैं उससे कहीं अधिक करनी चाहिए। हमें इस क्षेत्र में रूसियों से ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए। हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे हमारी कृषि-उपज के कथित अधिशेषों का विश्व की क्षुधा के निवारण में उपयोग किया जा सके और देश में उन अधिशेषों को शान्ति और स्वतन्त्रता की राष्ट्रीय नीति का सबल अस्त्र बनाया जा सके।

शान्ति और स्वतन्त्रता से हमारा अभिप्राय है, ऐसी शान्ति जो लागू की जा सके और ऐसी स्वतन्त्रता जो व्यावहारिक और समस्याओं को हल करने वाली हो।

संयुक्त राज्य ही सारी दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ महान् आर्थिक सम्भावना

बनाएँ और स्वतन्त्रता की संस्थाएँ भी हैं—स्वतन्त्रता की ऐसी संस्थाएँ और प्रथाएँ जो मनुष्य की गौरव-गरिमा को सम्भव करती हैं। हमारे पास देने को बहुत कुछ है। राष्ट्रपति केनेडी के ससार के नव विकासशील देशों में काम करने के लिए शान्ति मेना के प्रस्ताव का अच्छा स्वागत-समर्थन हुआ—खास तौर पर युवकों की ओर से। यह एक नये ढंग के नेतृत्व की निशानी है और उनकी विजय में भी इसका कुछ हाथ है।

विश्व का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए आज दुनिया के सामने अमरीका की जो तसवीर है, हमें उसमें दो परिवर्तन करने होंगे।

सबसे पहले तो हमें मानव-जीवन और विश्व की समस्याओं के क्षेत्र अर्थात् युद्ध और शान्ति के क्षेत्र में अपने वर्तमान व्यवहार और आचरण को बदलना होगा। क्योंकि आज इसी क्षेत्र में धरती के हर स्त्री, पुरुष और बच्चे की आशाएँ और आकाक्षाएँ केन्द्रित हैं और यही—इसी क्षेत्र में न केवल यह निर्णीत होने जा रहा है कि मनुष्य जाति अच्छी तरह से और स्वतन्त्र रहेगी, बल्कि यह भी कि क्या वह जीवित भी रहेगी।

सबसे अधिक इसी क्षेत्र में निर्भीक, साहसपूर्ण और नैतिक बल-युक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। लेकिन हम हैं कि रूसियों को बार-बार निरस्वीकरण और शान्ति के प्रश्न पर व्यापक और साहसपूर्ण, परन्तु साथ ही लच्छेदार और प्रचारात्मक प्रस्तावों और अपीलों के द्वारा चुनौती का अवसर देते आये हैं। सयुक्त राज्य ने उनकी हर अपील और हर प्रस्ताव का जवाब बार बार इनकार में ही दिया है और जो प्रावैधिक कारण बताये गए उनको समझ पाना तो मुश्किल ही है।

परिणाम यह हुआ कि हम ससार के समक्ष मानव-जाति को उसके अपने ही हाथों की मृत्यु से बचाने की उत्कट अभिलाषा वाले राष्ट्र के रूप में नहीं आ सके। अब हमें यह काम करना चाहिए। अब हमें सयुक्त राष्ट्र में विश्व-शान्ति और न्याय पर निर्भीक और सभी दृष्टियों से परिपूर्ण ऐसी योजनाओं का ताँता लगा देना चाहिए कि रूस सहित कोई भी राष्ट्र किसी भी तर्क-बल से उन्हें परास्त और अस्वीकार न कर सके। ऐसी योजनाओं की विस्तृत रूपरेखाएँ बन भी चुकी हैं। अब तो हमारे देश द्वारा उनको अपनी प्रमुख नीति के रूप में अपनाये जाने की ही देर है।

यदि हम अपनी सभी राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यों में मानव-जीवन की रक्षा को सर्वोपरि स्थान देने के लिए राजी हो जाएँ तो हम विश्व के नेता बन सकते हैं। और विश्व के नेता बनने के लिए हमें अपने विरोधी को वहाँ पकड़ना होगा जहाँ वह सबसे कमजोर पड़ता है। नैतिक आधार की कमी ही उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसके साथ-साथ हम राष्ट्रीय सोद्देश्यता की पुनरुपलब्धि भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसी भ्रान्ति में पड़े रह गए कि अन्तरिक्ष में हमारे उपग्रहों को और स्नानागारों में हमारे 'फर'-बिछे वाथ टबों को देखकर दुनिया हमारा अनुसरण करेगी तो इन दोनों में से एक भी बात न हो पाएगी।

दुनिया के सामने आज अमरीका की जो तसवीर है उसमें दूसरा परिवर्तन हमारी अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित है।

हम 'जनता के पूँजीवाद' का बहुत अधिक प्रचार करते हैं। दूसरे देशों में जहाँ-जहाँ भी विश्व मेले लगे और विश्व प्रदर्शनियाँ हुई वहाँ सभी जगह तरह-तरह के अनोखे और नाटकीय ढंग अपना कर हमने इस विचार को प्रदर्शित और प्रचारित किया है। लेकिन इस बात का जीता-जागता प्रमाण कि सयुक्त राज्य में वास्तव में 'जनता का पूँजीवाद' है, हम हर बार घर पर ही छोड़ जाते हैं।

हम लोगों को यह दिखला सकते हैं कि अमरीकी जनरल मोटर्स, युनाइटेड स्टेट्स स्टील और स्टैंडर्ड आयल पर ही गर्व करने वाला राष्ट्र नहीं है। अमरीका ऐसा राष्ट्र भी है जहाँ एक करोड़ चालीस लाख परिवार अपनी स्वतन्त्रता और अपने अपेक्षाकृत छोटे साधनों का अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को सीधे-सीधे पूरा करने वाली अपनी आर्थिक संस्थाएँ बनाने में उपयोग करते हैं। अमरीका ऐसा राष्ट्र भी है जहाँ एक करोड़ दस लाख परिवारों की अपनी जन-बैंके हैं जो साख-सघ कहलाती हैं और इन बैंकों के द्वारा ये परिवार अपनी बचतों को अपनी आर्थिक सुरक्षा में नियोजित करते हैं। अमरीका ऐसा देश भी है जहाँ के दो तिहाई किसान और ग्रामीण जनता अपने ही तेल कुओं, पाइप लाइनों, परिष्करण शालाओं और विद्युत् प्रदाय के स्वामी हैं। अमेरिका ऐसा राष्ट्र भी है जहाँ के कई लाख लोगों ने यह भेद जान लिया है कि वे बड़ी-बड़ी बीमा कम्पनियाँ—सही अर्थों में 'पारस्परिक' कम्पनियाँ संगठित कर सकते हैं, उनके स्वामी बन सकते हैं और उनका नियन्त्रण-परिचालन भी कर सकते हैं।

अमरीका ऐसा राष्ट्र भी है जहाँ के लोग सामान्य नर और नारी की मानवी गरिमा को अत्यधिक व्यावहारिक ढंग से स्थापित कर सकते हैं, और कंड अमरीकी जन है जो ऐसा कर भी रहे हैं।

अगर, जैसा कि डाक्टर रोल्लोमे का कहना है, शक्ति का केन्द्रीकरण ही हमारे समाज की वर्तमान दुर्बलता का कारण है तो हम यह भी दिखला सकते हैं कि हमारे पास ऐसा प्रतीकारात्मक उपाय भी है जिससे औसत नागरिक की उत्तरदायित्व भावना और आशा को पुनः स्थापित किया जा सकता है।

प्रतीकार का वह सीधा-सा उपाय है सहकारिता—परस्पर सहायता की पद्धति।

धरती पर कही भी कोई भी जनसमूह उम उपाय को,—सहकारिता की पद्धति को अपना कर अपने जीवन-मानों को उन्नत कर सकता है, अपनी स्वतन्त्रता में वृद्धि कर सकता है और अपनी मानवी गरिमा को निखार सकता है।

यह एक ऐसा चित्र है जिसे कोई भी समग्रवादी देश आलेखित नहीं कर सकता। यह एक ऐसा चित्र है जो सुचारुता से मानवी जीवन को न कि निष्प्राण वस्तुओं को, सँवारने के उपार्यों में, परिकल्पना, निष्ठा और लगन को जाग्रत और नियोजित कर सकता है। यह चित्र है मोक्षेश्य लोगों का।

और यह चित्र है ऐसे लोगों का जो साथ मिलकर रहना और इस प्रकार शान्तिपूर्ण विश्व की नींव रखना सीख रहे हैं।

सहकारी लीग के शिकागो कार्यालय में कई फाइलों में 'सामूदायिक सह-भागिता' विषय पर ढेरों सामग्री भरी पड़ी है। उस सामग्री में सहकारी संस्थाओं को अपने समुदायों में रचनात्मक, सक्रिय और सहायता देने वाली संस्था बनाने में 'सामूदायिक सहभागिता' के महत्त्वपूर्ण योगदान पर अनेक विवरणात्मक व्याख्याएँ हैं। कई निर्देश पत्रों में यह बताया गया है कि सहकारी संस्थाओं को अपने सदस्यों का अधिकाधिक समर्थन और सामूदायिक सहभागिता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक सम्मेलनों का आयोजन किस प्रकार करना चाहिए।

युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों में ऐसे कई सम्मेलन आयोजित किये गए थे। उनका कुछ प्रभाव भी हुआ।

प्रबन्धन विकास कार्यक्रमों का सम्भवतः कुछ अधिक प्रभाव हुआ।

कुल मिलाकर परिणाम अच्छे रहे। आज सहकारी संस्थाओं के सदस्य-निदेशक-मण्डल और व्यवस्था विभाग अपने सदस्यों की आर्थिक उन्नति के ही लिए प्रयत्न करके नहीं रह जाते बल्कि जहाँ व्यापार करते हैं उन क्षेत्रों, राज्यों और समुदायों के जनजीवन में अपने सर्वांगीण योगदान की भी सजग, सक्रिय-चिन्ता करते रहते हैं।

इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण हचिकर होंगे :

मिन्नेसोटा राज्य का फ्लोकेट एक छोटा-सा नगर है, जो कभी सम्पन्न खनि-प्रदेश का केन्द्रस्थल था। लेकिन अब वहाँ की खानें बहुत कुछ रीत चली हैं और खनि-कर्म से उतना उत्पादन नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। वहाँ नये उद्योगों और नये प्रकार के रोजगार की आवश्यकता है। नगर की आबादी कम हो सकती है, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। इसका एक कारण तो यह है कि बरसों पहले जिन आप्रवासियों द्वारा स्थापित नगर के प्रमुख सहकारी संगठन ने वहाँ एक बहुत खूबसूरत बाजार बना दिया है। इस बाजार की चहल-पहल और रीत से सारे संयुक्त राज्य का कोई भी बाजार टक्कर नहीं ले सकता। जिस दिन उद्घाटन हुआ वह क्लोकेट और उसके विस्तार को बस्तियों के लिए शानदार उत्सव से कम न था। इस बाजार के पास अब नई इमारतें बन रही हैं। जो व्यापारी और व्यवसाय घरकर बस्ती छोड़ गए वे अब हाथ मलते हैं। लेकिन सहकारी संस्था तो छोड़कर जा नहीं सकती। जिनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिनकी सेवा करती है सहकारी संस्था उन्हीं की, अर्थात् स्थानीय लोगों की होती है। वह अपने स्वामियों-संरक्षकों को छोड़कर कहाँ जा सकती है। सहकारी संस्था तो लोगों को जहाँ वे हैं वही साथ मिलकर रहना सिखाती है।

शिकागो के ठीक मध्य भाग में अनेक जातियों वाले जाति-वर्ण-मिश्रित हाइडपार्क का सहकारी भी वहाँ से नहीं गया, यद्यपि दूसरे कई व्यापार जन-संख्या की अदला-बदली और हालते कुछ बिगड़ जाने से सैकड़ों की तादाद में वहाँ से चले गए। ऐसी स्थिति में हाइडपार्क को आपरेटिव सुसाइटो के सदस्यों ने वहीं डटे रहकर हालत का मुकाबला करने और हाइडपार्क की नये सिरे से विकसित

करने का फैसला किया। इस निर्णय ने जादू का-सा काम किया। इस सहकारी को केन्द्र बनाकर नई सामुदायिक चेतना विकसित होने लगी। पुनर्विकास की एक योजना तैयार की गई। वही को खस्ताहाल इमारतों के कुछ हिस्सों में एक बाजार बनाने का निश्चय किया गया। उस बाजार में सुपर मार्केट खोलने और चलाने की जिम्मेवारी सहकारी समिति को सौंपी गई। समिति ने इतना बड़ा और अच्छा सुपर मार्केट बनाया जिसकी टक्कर का सारे शिकागो में दूसरा नहीं है। इस सुपर मार्केट का एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड है। उस पूरे शहर नुमा इलाके के लोग उस नोटिस बोर्ड पर अपनी आवश्यकताएँ लगा देते हैं—किसी को बच्चे रखने वालों की जरूरत है तो किसी को बावा गाड़ियों की : फरनोचर, कैलिफोर्निया की यात्राएँ आदि सब-कुछ; और यह तुलनात्मक आँकड़े थी कि इस तरह की चीजों और सेवाएँ दूसरों से किस दाम पर मिल रही हैं। उस नोटिस बोर्ड पर सूचित किये बिना हाइडपार्क क्षेत्र में कोई सभा नहीं होती और और न हो ही सकती है। और बहुत-सी सभाएँ तो सहकारी समिति के सभा भवन में ही होती हैं।

हाइड पार्क कई जातियाँ के लोगों के शान्तिपूर्ण और रचनात्मक सहजीवन (साथ मिलकर जीवित रहने) के लिए अमरीका के संघर्ष का प्रतीक है। इस दिशा में हाइड पार्क समिति ने अपना योगदान बहुत पहले और बड़े ही यथार्थ-वादो ढंग से आरम्भ कर दिया था। उसका व्यावहारिक रूप था समिति के कर्मचारियों का 'एकत्रीकरण', अर्थात् कर्मचारियों को सेवा नियोजित करने में यह नीति अपनाई गई कि हाइड पार्क क्षेत्र में जितनी जातियाँ और प्रजातियाँ बसती हैं उन सब का प्रतिनिधित्व हो सके। शुरू-शुरू में इस काम में बड़ी कठिनाइयाँ पेश आई। कुछ सदस्य सम्बन्ध-विच्छेद भी कर गए, परन्तु बाद में पुनः सम्मिलित हो गए।

१९५८ में हाइडपार्क कोआपरेटिव समिति के प्रधान व्यवस्थापक को शिकागो कौन्सिल आन ह्यूमैन रिलेशन्स (मानवी सम्बन्धों की परिषद्, शिकागो) का नगर-पुरस्कार दिया गया; सारे शिकागो शहर में उन्होंने मानवी सम्बन्धों के सुधार की दिशा में सबसे अच्छा काम किया था।

लोग साथ मिलकर शान्ति से रहना सीखने हैं।

मध्योत्तर (नार्थ सेट्रल) कन्सास के मिचेल काउण्टी के निवासियों को अपने सबसे बड़े सहकारी पर बड़ा अभिमान है। यह सस्था किसानों के अनाज के सग्रह और पोत-लदान के लिए आधा दर्जन समुदायों में अन्नागारों की व्यवस्था करती है। शहर का सबसे बड़िया किराना भण्डार इसी सस्था का है। यह किसानों और नगरवासियों, दोनों की पेट्रोल-सम्बन्धी हर माँग को पूरी करती है। यह पशु-खाद्य और चारा, बीज, उर्वरक और फारमो के लिए आवश्यक दूसरा सामान बेचती है। लेकिन यह सस्था इन व्यापारी कामोंके अतिरिक्त और भी बहुत से काम करती है। इसके व्यवस्थापक बरसों से जिला बोर्ड के सदस्य और सामुदायिक अस्पताल के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष हैं। स्थानीय कम्युनिटी चेस्ट (सामुदायिक निधि-सग्रह) अभियान के सभापति पद को कभी व्यवस्थापक महोदय और कभी सहकारी सस्था के निदेशक मण्डल के कोई सदस्य सुशोभित करते हैं। यह सस्था युवक-युवतियों के लिए नृत्य का आयोजन और बालचर दलों के लिए वाहनादि का प्रवन्ध करती है। यदि व्यापारी सस्थाओं के लिए कोई 'सुनागरिक' पद, पदक अथवा पुरस्कार होता तो मिचेल काउण्टी निश्चय ही उसे अपनी इस सहकारी सस्था को प्रदान करती।

उचित भी होता, क्योंकि मिचेल काउण्टी की सहकारी सस्था किसी एक आदमी की नहीं उस जिले के हजारों व्यक्तियों की अपनी, अपने स्वामित्व की सस्था है।

मिचिगन क्रेडिट यूनियन लीग जो एक साख-सघ है, अपने सदस्यों की बचतों की रक्षा और जरूरत पड़ने पर उन्हें उधार देने का ही काम नहीं करती, उनकी और भी कई आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। उन आवश्यकताओं को सारे समुदायों की आवश्यकताओं से अलग नहीं किया जा सकता। लोगों की-सामर्थ्य का मकान ऐसी ही आवश्यकता है। इसलिए मिचिगन लीग के नेताओं ने मकान के लिए ऋण संच की स्थापना की और विधि-विधान इस तरह का बनाया जिससे हिस्सों की बिक्री से अर्जित धन साख-सघ की अधिशेष निधि में निवेशित किया जा सके। शीघ्र ही उन्हें एक जन-हितैषी ठेकेदार भी मिल गया। यह मकान के लिए ऋण सघ दस हजार डालर या इससे कम लागत मूल्य के मकानों के लिए उधार देता है। मिचिगन में इस योजना के

अन्तर्गत कई मकान बन भी गए और उनका कर्ज भी चुका दिया गया। डेट्रो-इट टीचर्स क्रेडिट यूनियन अमरीका का सबसे बड़ा साख-सघ है, इसने अपने सदस्यों को मकान बनाने के लिए कर्ज दिया जिससे उन्होंने अपने सहकारी-स्वामीत्व की बहुत ही सुन्दर रिहायशी इमारत बनाई।

लोग साथ मिल कर रहना सीख रहे हैं।

डेरिलैण्ड पावर कोआपरेटिव दक्षिण-पूर्वी मिन्नेसोटा, उत्तर-पूर्वी इओवा और पश्चिमी विसकोन्सिन के एक लाख किसानों की स्वामीत्वकृत सस्था है। यह इन एक लाख किसानों के विभिन्न सहकारी विद्युत् प्रदायों को उस क्षेत्र में सबसे न्यून मूल्य पर थोक बिजली ही नहीं देती और भी बहुत कुछ करती है। विसकोन्सिन के लाक्रोसे का सबसे प्रमुख उद्योग है डेरी लैण्ड। इसका मासिक मुखपत्र प्रति वर्ष अक्तूबर महीने में लाक्रोसे कम्युनिटी चैस्ट अभियान का जुड़वाँ पृष्ठी पर विज्ञापन प्रकाशित करता है। उसमें पाठकों को विस्तार से बतलाया जाता है कि कम्युनिटी चैस्ट की सस्थाएँ क्या-क्या काम करती हैं। उसमें डेरी-लैण्ड के उन कर्मचारियों के नाम भी दिये जाते हैं जो अपने साथियों से निधि जमा करेंगे और यह भी बता दिया जाता है कि हर कर्मचारी को कितनी रकम देनी चाहिए।

अलग-अलग प्रकार की बीमारियों के लिए भिन्न-भिन्न निधियों की संख्या हमारे देश में गणनातीत हो गई है। हृदय-निधियाँ, कैंसर-निधियाँ, पोलियो-निधियाँ, ल्यूकेमिया (रक्त में श्वेताणुओं की संख्या वृद्धि और उससे होनेवाली विकृतिर्यों का रोग) निधियाँ, मनः स्वास्थ्य-निधियाँ—जितने भी रोगों का मनुष्य को ज्ञान है उन सब की अनन्त निधियाँ हैं। नहीं है तो एक मर्दी-जुकाम की निधि जिसकी हमारे देश और सारी मनुष्य जाति को सबसे अधिक आवश्यकता है। लेकिन ये सभी निधियाँ साथ मिलकर सामुदायिक पद्धति पर धन-संग्रह के लिए तैयार नहीं होती। सब का यही दावा है कि अलग-अलग इकट्ठा करने से उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। बहुत-सी जगहों के लिए उनकी बात सच हो सकती है। लेकिन एक जगह ऐसी भी निकली जहाँ उनका यह दावा गलत साबित हुआ। न्यूयार्क के निचले ईस्ट साइड के सहकारी ग्राम (कोआपरेटिव विलेज) में जो परिवार रहते हैं, उन्होंने एक बार यह माँग की कि उन्हें

अलग-अलग आधा दर्जन धन-संग्रह अभियानों के बदले अपने ग्रामवासियों से एक संयुक्त चन्दा कर लेने दिया जाए। विभिन्न निधियों के अध्यक्ष पहले तो हानि की आशका से राजी नहीं हुए, परन्तु बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया। परिणाम यह हुआ कि सहकारी ग्राम के निवासियों ने स्वेच्छा से जी खोल कर धन दिया और कुल निधियों की अपेक्षित जोड़ से कहीं अधिक पैसा जमा हो गया।

इन परिवारों ने साथ मिलकर रहना सीख लिया था।

विसकोन्सिन के एक मझौले नगर की सामूदायिक सहकारी संस्था के व्यवस्थापक नये प्रकार के मिशनरी के रूप में पाँच वर्ष के लिए भारत जाने का विचार कर रहे हैं। उन्हें चर्च बोर्ड आफ एग्रीकल्चरल मिशनर्स वहाँ भेजेगा। वे वहाँ धर्मोपदेश नहीं देंगे; लोगों को पारस्परिक सहायता पर आधारित स्वावलम्बी आर्थिक संस्थाओं का संगठन करना सिखाएँगे। उन्हें भेजने वाला मिशन बोर्ड इस काम को ईसाई धर्म प्रचारकों के सर्वथा उपयुक्त ही मानता है।

लेकिन ये व्यवस्थापक महोदय एक ठोड़ी समस्या का हल अभी तक नहीं निकाल पाये हैं। वह समस्या है अपने समुदाय से छूटो पाने की। यदि वे भारत चले गए तो स्कूल समिति, गिरजाघर के प्रबन्ध मण्डल और वाणिज्य मण्डल (चेम्बर आफ कामर्स) में उनकी जगह कौन काम करेगा? स्कूल की उच्च क्रक्षाओं के छात्रों को प्रति वर्ष अपने नगर के व्यापार और उद्योग पर कौन आषण देगा? अपने-आप को 'अपरिहार्य और अत्यावश्यक' समझने की इनकी आदत जरा भी नहीं है। ये भले ही न समझे परन्तु अधिकांश नागरिकों का यह खयाल है कि उनके चले जाने से बहुत से काम रुक जाएँगे। इसलिए वे उन्हें छोड़ने को राजी नहीं होते, यह जानते हुए भी कि वे भारत जाकर वहाँ के लोगों को साथ मिल कर जीना सिखा सकते हैं, क्योंकि विसकोन्सिन में वे इस काम को कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं।

विश्व में शान्ति की स्थापना के लिए इन सारे कामों का जरा भी महत्त्व नहीं रह जाता यदि दुनिया के करीब-करीब हर देश में ठीक इसी तरह के काम न हो रहे हों। लेकिन जहाँ संयुक्त राज्य में सहकारी संस्थाओं को हर कदम पर अपने समाज के विरोधी दलों से संघर्ष करना पड़ता है, नवविकसित देशों

मे, बिना एक भी अपवाद के, सहकारी संस्थाओं को आधार शिला बनाकर ही वहाँ की जनता के जीवन-मानों का निर्माण किया जा रहा है। आज एशिया, अफ्रीका और इधर-उधर तो लैटिन भाषी अमरीकी देशों में भी 'सहकारी' वहाँ के सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य और सर्व स्वीकृत शब्दों में है।

इन देशों में साम्यवाद का विकल्प सहकारिता है, आर्थिक पूँजीवाद नहीं।

उदाहरण के लिए भारत को पचवर्षीय योजनाओं में उस महान देश की अर्थ व्यवस्था के 'सहकारी क्षेत्र' को समूची योजना के एक दृढ़ आधार के रूप में विकसित करने की बात बहुत जोर के साथ कही गई है।

यदि इण्डोनेशिया साम्यवाद से बच सकेगा तो केवल इसीलिए कि वहाँ के निवासी अपने गाँवों और नगरों में बड़ी तेजी से सहकारी संस्थाओं को विकसित कर रहे हैं जो उनके जीवन-मानों को उन्नत करने के साथ-साथ सारे देश की जनता को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। यह प्रसन्नता की बात है कि वहाँ इस दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है।

मिस्र अपने लिए जितने पेट्रोल का उपयोग करता है उसका चालीस प्रतिशत एक सहकारी संस्था द्वारा उपलब्ध किया जाता है।

पेरू में एंडोज के ऊँचे पहाड़ों में कैथोलिक पादरियों का एक सगठन वहाँ के निवासियों को जिनमें विशुद्ध इंडियनों की संख्या अधिक है, साख-सर्घों को संगठित करना और चलाना सिखला रहे हैं। इन प्रयत्नों से वहाँ के लोगों की हालतों में जो आश्चर्यजनक उन्नति हुई उसकी कहानियाँ किसी परी कथा से कम नहीं हैं। कोलम्बिया के सहकारियों ने १९६० में अपना एक राष्ट्रीय सघ बना लिया है। इस सघ में किसानों के विक्रय और सम्भरण साख-सघ, गृह-निर्माता, उपभोक्ता और अन्य प्रकार के कई सहकारी हैं। संयुक्त राज्य की सहकारी लीग, कैरीबीयन कोऑपरेटिव कान्फेडरेशन और मेक्सिको के नेशनल फेडरेशन आफ कोऑपरेटिव्स ने अपनी १९६० की बैठकों में जिस पहले अखिल-अमरीकी सहकारी महा सम्मेलन को आयोजित करने का प्रस्ताव किया है वह या तो पेरू या कोलम्बिया में से कहीं पर होगा और उसमें सस्काट्चेवान से पैटागोनिया तक के सगठन सम्मिलित होंगे।

संयुक्त राज्य के सहकारियों के प्रतिनिधिगण भारत, कैरीबीयन और वियतः

नाम में काम कर रहे हैं। उन देशों के सहकारी सगठनों के निमन्त्रण पर वे वहाँ गये हैं। वे वहाँ के लोगों का ऐसी आर्थिक सस्थाएँ विकसित करने में तकनीकी सहायता देने के लिए गए हैं जो सदैव वहाँ के निवासियों के अधिकार में बनी रहेंगी। १९६० में संयुक्त राज्य की सहकारी लोग का जो बाईसवाँ द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ उसकी प्रमुख वक्ता एक सुप्रसिद्ध भारतीय महिला थी, जो अपने देश की नेता और भारतीय सहकारी सघ का अध्यक्षा भी हैं। उस अधिवेशन में बर्माई का जो सबसे महत्वपूर्ण सन्देश प्राप्त हुआ वह पश्चिमी नाइजीरिया की सहकारी यूनियन द्वारा तार से भेजा गया था। जापानी उपभोक्ता सहकारियों के दो युवक अधिकारी १९५९ में अमरीका आये और उन्होंने छह महीने कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय और कैलीफोर्निया की सहकारी सस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका सारा खर्च कैलीफोर्निया की दो सहकारी सस्थाओं और सहकारी लीग ने उठाया। संयुक्त राज्य के सहकारियों ने अपने जिस व्यक्ति को वियतनाम भेजा था मुख्यतः उन्हीं के प्रयत्नों से वहाँ पर सहकारी नेताओं, व्यवस्थापकों और सदस्यों की शिक्षा-दीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया।

जिस इण्टरनेशनल कोऑपरेटिव पेट्रोलियम एसोसिएशन के हावर्ड काऊडेन प्रमुख मस्थापक हैं, वह संयुक्त राज्य, स्वीडन, मिस्र, युगोस्लाविया, फ्रान्स, नारवे, हालैण्ड, जर्मनी, इसराइल और दूसरे एक दर्जन देशों के सहकारी सगठनों की स्वामीत्वकृत अन्तर्राष्ट्रीय सस्था है। यह सस्था खरीदारों की संरक्षण-धन वापसियों की अदायगी के आधार पर पेट्रोल का कारबार करती है। इसका उद्देश्य मुट्ठी-भर स्टॉकधारियों के लिए लाभ कमाना नहीं लोगों के जीवन-मानों को उन्नत करना है। सार्वलौकिक आवश्यकता की अन्य वस्तुओं का व्यापार करने वाली इसी तरह की दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वणिज सस्थाओं की स्थापना की दिशा में यह पेट्रोलियम सघ पथ प्रदर्शक बन सकता है।

इण्टरनेशनल कोऑपरेटिव अलायन्स का इनकोसवाँ त्रिवार्षिक अधिवेशन १९६० की पतझड़ में स्विट्जरलैण्ड में हुआ। मनुष्य को जितने भी आर्थिक कार्य-व्यापार मालूम हैं उनमें लगे पन्द्रह करोड़ परिवारों के प्रतिनिधि अपने-अपने देशों से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आये थे और वहाँ चर्चा का

मुख्य विषय था कि अमरीका और यूरोप के मुस्थापित सहकारी सगठन नव-विकासशील देशों के सहकारियों की अच्छी-ते-अच्छी ओर ज्यादा-न-ज्यादा सहायता किस प्रकार कर सकते हैं।

इस प्रकार शान्ति के सेतु निर्मित होते हैं।

विश्व के सहकारी सगठन, संयुक्त राष्ट्र मन्त्र के घोषणापत्र को शान्ति-स्थापन के प्रभावशाली अस्त्र के रूप में न तो फिर से लिखेंगे और न निर-स्त्रीकरण कार्यक्रमों का व्योरा ही तैयार करेंगे।

लेकिन वे इन कामों को करने के लिए भूमि अवश्य तैयार कर देंगे, जिसका कि किया जाना बहुत आवश्यक है।

जो लोग देश में अपने पड़ोसियों के साथ शान्ति से रहना सोख लेते हैं, उनमें दूसरे देशों के इसी तरह के अनुभव-प्राप्त जन-समूहों को समझने और उनसे मैत्री करने की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। वे पारस्परिक समझ, शान्ति और एक प्रकार के व्यवहारिक भाई चारे के पुल बनाते जाते हैं; राष्ट्रों के बीच शान्ति के लिए निर्मित ऐसे पुलों के दूर व्यापी महत्त्व का मूल्यांकन कठिन ही है।

दूसरे महायुद्ध के समय जब इस पुस्तक का लेखक कैलीफोर्निया में कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपने देश की सेवा कर रहा था तब एक आधी रात को उसने निम्न पक्तियाँ लिखी थी :

वाशिंगटन का अनुभव मेरे लिए कई तरह से शिक्षाप्रद रहा; कहना चाहिये कि जिन बातों पर पहले मेरा केवल विश्वास था उन्हें इस अनुभव ने मन पर अमिट रूप से अंकित कर दिया।

मैंने सीखा कि मानवी सद्गुणों में विनय ही सबसे महान गुण है—यह प्रेम से भी महान है, क्योंकि प्रेम स्वयं विनय से उद्भूत है और वही उसका एकमात्र स्रोत है। मैंने यह भी सीखा कि ईश्वर के अस्तित्व और उसकी उपस्थिति के चेतन ज्ञान के बिना जीवन निस्सार और निरानन्द है—बिना किसी आशा और अर्थबोध के, नितान्त भयावना। मैंने यह भी सीखा कि नैराश्य के भँवर में पड़ कर और उससे उबर कर भी जो दोनों को कोई महत्त्व नहीं देता आशा का यत्किंचिद् वरदान उसी के हिस्से आता है। मैंने यह भी सीखा कि जिसे मूख्यतः समझने रहे उसके अधिकार से वंचित हो जाने की स्थिति को अनुभव और अंगीकार के ही जीवन के हर दिन को, भय विकम्पित हुए बिना अन्तिम दिन

मान कर, नई समर्पणशीलता, नई अनुरक्ति और नई तत्परता से ग्रहण किया जा सकता है।

हम यहाँ भेजे गए हैं सफलता के लिए नहीं निर्भीक प्रयत्न के लिए, असाध्य कार्यों को साध्य करने के लिए नहीं यथाशक्ति कर्म करने के लिए, जीवित रहने के लिए नहीं अच्छी तरह मरने का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मूर्खतापूर्ण आशावादिता के लिए नहीं निराशा की उस चरमावस्था के लिए जो अन्ततः मृत्यु की अनिवार्यता के ज्ञान से सौन्दर्यपूरित हो उठती है।

और दुनिया में जितना ही अन्धकार घिरता जाता है मेरा यह विश्वास उतना ही दृढ़ होता जाता है कि वह अन्धकार ही सब-कुछ और अन्तिम सत्य नहीं है; सच्चे प्रयत्नों में निराशा का मुझे जितना ही अनुभव होता जाता है उनकी अन्तिम विजय में मेरी आशा उतनी ही दृढ़ होती जाती है; अनिष्टकारी शक्तियों को जितना ही बढ़ते देखता हूँ उनके द्वारा अपने ही विनाश के बीज स्वयं बोते जाने के बारे में मैं उतना ही आश्वस्त होता जाता हूँ।

मैं इसे समझा नहीं सकता। लेकिन मुझे कोई भय नहीं है—शायद इसलिए कि मेरे मन पर भय पूरी तरह आच्छादित हो गया है। और मैं फिर भी आशावान हूँ—शायद इसलिए कि मेरे मन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं बचा रह गया।

इन पक्तियों को लिखे बीस बरस होने आये। आज भी लिखना ही तो इसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं करूँगा।

लेकिन इसमें कुछ जोड़ अवश्य दूँगा।

हमारे युग की सकटापन्न स्थिति में भी मानव जाति के भविष्य में मेरा विश्वास क्यों नहीं डिगा इसके दो सारगर्भित कारण आज, संयुक्त राज्य की सहकारी संस्थाओं में पन्द्रह वर्ष काम कर चुकने के बाद, मैं बता सकता हूँ।

पहला कारण यह है।

मैंने देखा है कि जब लोगों का एक समूह वक्तों की सर्व सामान्य निधि में अपने पाँच-पाँच डालर के हिस्से का निकाय करता है तो कैसे एक प्रकार की व्यावहारिक सहकारिता आरम्भ होती है। मैंने देखा है कि जब लोग बिजली या स्वास्थ्य-परिचर्या या मकान या सिचाई की अपनी एक-सी आवश्यकता को समझ कर उसे पूरा करने के लिए स्वयं को और अपने साधनों को संगठित करने लगते हैं तो किस प्रकार नये सम्बन्ध आरम्भ होते और बढ़ने लगते हैं। मैंने देखा है कि इस तरह के परस्पर सहायता के उद्यमों का प्रयोग करने वाले लोग कोई भी क्यों नहीं और किसी भी देश में क्यों न रहते हों पारस्परिक

समझ के दृढ़ सूत्रों में किस तरह बंधे होते हैं और कैसे उम स्नेह बन्धन का सतत अनुभव करते रहते हैं। और इस तरह मैंने देखा है कि लोग अपनी एक-जैसी समस्याओं के द्वारा व्यावहारिक और शान्तिपूर्ण ढंग से एक साथ मिल कर रहना किस तरह सीखते हैं। और साथ मिल कर रहना सीखने का यह काम यदि दुनिया के अधिकतर गाँवों और फार्मों में, देशों और नगरों में किया जा सके—परस्परावलम्बन और परस्पर सहायता के विचार यदि अधिकतर देशों में अधिकतर लोगों को अनुप्राणित कर सके—तो राष्ट्रीय के बीच शान्ति का बिरवा विश्व-जन समुदाय में सुदृढ़ता से आरोपित किया जा सकता है।

तो यह है मेरी आशा और मेरे विश्वास का पहला कारण जो मर्तोरम कल्पनाओं, स्वप्नों या राजनयिकों की चर्चाओं पर नहीं स्वयं अपने और अपने पड़ोसी के लिए भोजन और छाजन प्राप्त करने की एक अच्छी पद्धति पर आधारित है।

दूसरा कारण है नई पीढ़ी में मेरी आस्था, जिसे मैं इस तरह व्यक्त करना चाहूँगा :

पहले महायुद्ध के बाद की घटनाओं, बड़ी मन्दी और पिछली पीढ़ी के आशातिरेकपूर्ण उदारवाद की परम्परा से प्रभावित और निर्मित मेरी अपनी पीढ़ी के मोचने-विचारने का ढंग अब सामयिक नहीं रह गया और अकेले उससे काम चल भी नहीं सकता। हम आज की दुनिया को बीते कल की प्रथाओं और मस्थाओं में बाँध रखने का प्रयत्न करते हैं। यह चल नहीं सकता और कोई अच्छी बात भी नहीं।

फिर अच्छा क्या है ? ठीक-ठीक तो सम्भवतः कोई नहीं जानता।

आदमी की आज की जिन्दगी को अनथक परिश्रम और सतत प्रयत्नों से इस तरह पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है जिससे मानव-जीवन और आशा, प्रेम और संवेदनाएँ सजीवन हो सके, वाण पा सकें। इस तरह के निर्माण के उपयुक्त सक्षम उपस्करों का जिन्हें सम्भवतः धुँधला-सा आभास है और जिन्हें उनका उपयोग करना है वे अभी इनके बड़े और बयस्क नहीं हो पाये हैं कि नेतृत्व का अपना दावा पेश कर सके। मेरी पीढ़ी उन्हें अनश्वर मूल्यों का—विशुद्ध धार्मिक आस्था, प्रभु के शाश्वत नियमों की प्रतीति, जन-जन में व्याप्त

परस्पर-सहायता-भावना और मानव-आत्मा की अमर पुष्करिणी आशा का दान दे सकती है। प्राण और मन और बुद्धि और चेतना और प्रकृति के नियम आज भी उतने ही नट्य और अद्भुत और अलौकिक हैं जितने दम हजार या एक सौ या पच्चीस वर्ष पूर्व थे।

इन शाश्वत मूल्या का दाय देने के अतिरिक्त मेरी पीढ़ी के लिए उचित तो यही है कि भावों पीढ़ों जिस साफ, मजबूत और चमकीली दुनिया को गढ़ रहे। हे उसे समझने का प्रयत्न करे और अपने अधिक साहसी और अधिक यथार्थ-वादी बच्चों को वागडोर थामने का अवसर देने के लिए यथाशीघ्र रास्ते से हट जाए।

बशर्तकि हम तो उतनी अच्छी तरह नहीं जानते पर वे जानते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी की राजनीति और अर्थनीति को बीसवीं शताब्दी के विज्ञान के साथ गड्ड मड्ड करने में ऐसा विस्फोटक द्रव बन जाएगा जो इस दुनिया को ही उड़ा देगा। हमने अधिक वे इस बात का जानते हैं कि बीसवीं शताब्दी के विज्ञान को निरस्त नहीं किया जा सकता, और यह भी कि मनुष्य जाति के भविष्य की आशा बीसवीं शताब्दी के अनुरूप राजनैतिक और आर्थिक सस्थाओं के विकास में ही निहित है।

वे किस प्रकार की सस्थाएं होंगी ? वे हागी पारस्परिक सहायता की पीठिका पर प्रस्थापित विभिन्न रूपों-प्रकारों वाली सस्थाएं, मात्र इसीलिए कि आज समूची मानवजाति शब्दिक और लाक्षणिक दोनों ही अर्थों में 'एक ही नाव में सवार' है। या तो हम सब मरते हैं, या हममें स्वार्थ-वृत्तियों पर विजय पाने की वृद्धि शेष रही तो नवोपलब्ध शक्तियों का उपयोग सभी के जीवन को ज्यादा सुन्दर और ज्यादा अच्छा बनाने में करते हैं।

